संपादकीय

नई दिल्ली, सोमवार 13 मई 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. माया राम सुरजन

नये मुद्दों के साथ चौथे चरण का मतदान

18वीं लोकसभा के लिये सम्पन्न हो चुके तीन चरणों के मतदान के बाद अब चर्चा यह नहीं हो रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिये 370 सीटों का और अपने गठबन्धन नेशनल डेमोक्रेटिक एलाएंस के साथ मिलकर 400 सीटें हासिल करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उसे पाने की स्थिति में वह है या नहीं। अब तो यह सवाल किया जाने लगा है कि भाजपा सत्ता में वापसी करेगी या नहीं और नरेन्द्र मोदी, जो दो कार्यकालों के बहुत से अधूरे कामों को पूरा करने के लिये तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बनने को आतुर हैं, अपने लक्ष्य को पाने में सफल होते हैं या नहीं। इसका कारण केवल इतना नहीं है कि पहले तीन चरणों में ही भाजपा और नरेंद्र मोदी दोनों पस्त दिख रहे हैं। तीनों चक्रों में हुआ अपेक्षाकृत कम मतदान भाजपा के लिये खतरे की घंटी बतलाई जा रही है जिसकी पुष्टि कई राजनीतिक पर्यवेक्षक, मत सर्वेक्षण एवं विश्लेषण एक स्वर में कर रहे हैं। कम मतदान किसी निश्चित परिणाम की ओर इंगित नहीं करता परन्तु कम मतदान के साथ अनेक ऐसे तथ्य गिनाए जा रहे हैं जिनके आधार पर लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं।

प्रतिपक्षी गठबन्धन 'इंडिया' का सतत मजबूत होना, लोगों का कांग्रेस के 'न्याय पत्र' से प्रभावित होना, युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजातियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदि वर्गों का कांग्रेस से जुड़ाव, भाजपा विरोधी स्थानीय क्षत्रपों का प्रभावशाली प्रचार अभियान आदि ऐसे कारण हैं जो सत्तारुढ़ भाजपा को चरण-दर-चरण कमजोर करते चले जा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स और ईवीएम जैसे गम्भीर मसलों के साथ चुनाव के प्रथम चरण में प्रवेश करने वाली भाजपा के सामने चौथे चक्र तक पहुंचते हुए कई नयी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। इन्हें लेकर लोगों का मानना है कि इनसे एक ओर तो पार्टी का सीटों के लिहाज से भारी नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ खुद श्री मोदी पहले के मुकाबले और भी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। पहले तीन चरणों में 283 सीटों पर मतदान हुआ है जिनमें कई राज्य तो पूरे ही निपट चुके हैं, वहीं अब 260 सीटों पर मतदान होना है। इनमें से सोमवार को 10 राज्यों के 96 निर्वाचन क्षेत्रों के लिये मतदान होगा जिसके बाद तेलंगाना व कर्नाटक का चुनाव पूरा हो जायेगा। इस चरण के साथ 18 राज्यों एवं 4 केन्द्र शासित प्रदेशों की सभी सीटों के लिये मतदान पूरा हो जायेगा।

संगठन के रूप में भाजपा जिन समस्याओं के साथ अगले चरण के मतदान में प्रवेश कर रही है उनमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि लाख प्रयासों के बाद भी वह मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में असमर्थ दिखाई दे रही है। इसका पहला कारण तो यह है कि देश भर में, उन राज्यों व क्षेत्रों समेत जहां मतदान होगा- गर्मी कम होने के कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते। दूसरे, भाजपा को लेकर जो बड़ी नाराज़गी है वह है कोविशील्ड सम्बन्धी खुलासा, जिसके बारे में यह बात सामने आई है कि कोरोना की इस वैक्सीन का जो फार्मूला है उसकी मालिक एस्ट्राजेनेका कंपनी ने स्वीकार किया है कि इसे लगवाने वालों का खून गाढ़ा हुआ है। कई लोगों को दिल का दौरा व ब्रेन हेमरेज होने का यह कारक बना है। भारत में यह सबसे ज्यादा लोगों को लगाया गया था। यहां इसका निर्माण करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट से भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिये 52 करोड़ रुपये लिये हैं। इसे मोदी से व्यक्तिगत रूप से भी इस लिहाज से जोड़ा जा रहा है कि उन्होंने न केवल लोगों को यह टीका लेने के लिये प्रेरित किया बल्कि उसे लेने वालों को जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उन पर अपनी फोटो भी छपवाई थी जो मामले का खुलासा होने के बाद हटा दी गई।

इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पौत्र प्रज्ज्वल रेवन्ना के लिये मोदी द्वारा यह कहकर वोट मांगना, कि 'प्रज्ज्वल को मिलने वाला हर वोट उन्हें (पीएम को) मजबूत करेगा', इसलिये भारी पड़ गया क्योंकि हासन से जनता दल (सेक्यूलर) का सांसद व फिर से उसकी टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रज्ज्वल के करीब 3000 अश्लील वीडियो वायरल हो गये जिनमें वह महिलाओं के साथ दुष्कर्म में कथित तौर पर संलिप्त है। आस्ट्रेलिया के प्रमुख अखबार 'हेराल्ड सन' ने मोदी की फोटो लगाकर खबर छापी है जिसका शीर्षक है- 'इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ लिंक्स विद मास रेपिस्ट' (भारतीय प्रधानमंत्री के सामूहिक बलात्कारी के साथ सम्बन्ध हैं)। इससे मोदी को छवि के साथ सीटों का भी नुकसान होना तय है।

इसी बीच सियासत की दृष्टि से देश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीटों- अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार का हुआ प्रवेश बड़ा फर्क पैदा करेगा। वायनाड से लोकसभा के निवर्तमान सांसद तथा वहीं से फिर चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी ने उनकी मां सोनिया गांधी की छोड़ी हुई सीट रायबरेली से नामांकन भर दिया है। दूसरी तरफ अमेठी में, जहां राहुल को अपने खिलाफ मैदान में उतरने के लिये ललकारती केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रणनीति को मात देते हुए इसी परिवार के बहुत नज़दीकी किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने उतारकर बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। इसका असर न केवल इन दो सीटों पर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जोरदार पड़ेगा। देश की राजनीति में इन दो सीटों के साथ उप्र का महत्व किसी को बतलाये जाने की ज़रूरत नहीं है। चौथे चरण के पहले शराब कांड में ईडी की गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजे गये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों की जमानत मिली है। वे अब मोदी व भाजपा के खिलाफ जबर अभियान चलाये हुए हैं। ये सारे हालात भाजपा के लिए चुनावी समीकरण उलझा चुके हैं और चौथे दौर में भाजपा के लिए मुश्किल बन गए हैं।

केजरीवाल मोदी पर मोदी की तरह ही हमला कर रहे हैं

अरविन्द केजरीवाल का बाहर आना मोदी जी के लिए मुसीबत बन गया। उनका प्रचार कि मैं जो चाहे कर सकता हूं, पांच सौ साल में मुझसे ताकतवर आदमी कोई नहीं हुआ कि हवा निकल गई। मोदी जी, भाजपा, भक्त और उनके मीडिया को यकीन ही नहीं था कि जिस केजरीवाल पर मोदी जी की आंख टेढ़ी है उसे जमानत भी मिल सकती है। सारा प्रचार तो यही था कि जिस पर मोदी जी ने हाथ डाल दिया वह खत्म। इसी डर से कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हो रहे थे। ऐसा भय का माहौल बना दिया था कि किसी के भी खिलाफ कुछ भी हो सकता है।

आज वह माहौल टूट गया। झूठी ताकत की पूरी कहानी ध्वस्त हो गई। इसलिए आज भाजपा को सफाइयां देने पड़ रही हैं कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। 2029 तक भी और उसके बाद भी।

केजरीवाल से लोगों की चाहे जितनी शिकायतें हों, खासतौर से उनका किसी एक स्टैंड पर नहीं टिकने को लेकर मगर यह सही है कि मोदी को मोदी की ही शैली में जवाब वे ही दे सकते हैं। राहुल की शराफत, उनका आदर्शवाद, सिद्धांत उन्हें दूसरों के बारे में कुछ भी कहने नहीं देता। पिछले दस साल में मोदी जी ने इतने आरोप लगाए, खराब भाषा बोली, जो मुंह में आया बोला मगर राहुल ने मर्यादा बनाए रखी। प्रियंका जरूर कुछ तीखे शब्द बाण चला रही हैं। उनके भाषण हिट भी बहुत हो रहे हैं। मगर मर्यादा उन्होंने भी बना रखी है।

लेकिन केजरीवाल मोदी जी की तरह ही राजनीति करते हैं। जिनमें साधन नहीं साध्य ही प्रमुख होता है। इसलिए इंडिया गठबंधन में वे सबसे आखिरी में आए और गठबंधन खासतौर से कांग्रेस ने भी उन्हें बहुत सोच-समझ कर यस कहा।

दरअसल केजरीवाल और कांग्रेस दोनों यह समझ गए थे कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट! पहले मोदी को हटाना जरूरी है। बाद की बाद में देखेंगे।

और इसलिए जमानत पर बाहर आते ही केजरीवाल ने मोदी की तरह ही बड़ा धमाका किया कि जीत भी जाएं तो भी मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जिस तरह उन्होंने आडवानी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन को 75 साल की उम्र का वास्ता देकर मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया वैसे ही अब उन्हें भी जाना पड़ेगा। अगले साल वे 75 के हो रहे हैं। यह बिल्कुल मोदी जी वाली ही शैली है। जैसे वे दूसरी पार्टियों के बारे में कहते हैं वैसी ही। कांग्रेस खतम हो जाएगी। सोनिया गांधी ऐसी, नेहरू ऐसे, राहुल ये! या आम आदमी पार्टी क्या है, केजरीवाल आतंकवादी! सब पर बोला लालू जी, तेजस्वी, अखिलेश, ममता, उद्धव ठाकरे, शरद पवार किस को छोड़ा?

मगर चौथी पास किसी ने नहीं कहा। यह केजरीवाल ही कह सकते हैं। राहुल भी कह रहे हैं कि अब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मगर उनका आकलन यह है कि भाजपा एक सौ चालीस से ज्यादा ही नहीं पाएगी तो प्रधानमंत्री बनने का सवाल ही नहीं।

मगर केजरीवाल मोदी की स्टाइल में ही खेलते हैं। वे यह कहकर भाजपा के अंदर हलचल मचा देते हैं कि अगर जीत भी गए तो अमित शाह बनेंगे। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को हटाया जाएगा। जो केजरीवाल चाहते थे वह काम हो गया। खुद अमित शाह जिनके प्रधानमंत्री बनने की बात कही गई उन्हें सफाई देना पड़ी। राजनाथ सिंह जिनका सबसे ज्यादा अवमूल्यन किया गया उन्हें भी कहना पड़ा कि नहीं बनेंगे तो मोदी जी। राजनाथ केन्द्र की राजनीति में भाजपा के सबसे पुराने नेता हैं। सीनियर। दो बार के अध्यक्ष हैं। मगर सबसे ज्यादा डरे वे ही रहते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही उनके बेटे पंकज सिंह पर जिस तरह पुलिस से वसूली के आरोप लगाए गए थे। उसके बाद से पंकज सिंह का राजनीतिक भविष्य तो रुक ही गया खुद राजनाथ अपना आत्मविश्वास खो बैठे। आज की तारीख में भाजपा के सबसे दयनीय नेताओं में वे हैं। जैसे बसपा का बड़े से बड़ा नेता भी कोई अधिकार नहीं रखता मगर कहता यही है कि नहीं ऐसा नहीं है। बहन जी ने हमें पूरी छूट दे रखी है पानी की बोतल कौन सी खरीद कर पीना है यह हम खुद तय करते हैं। वैसे ही राजनाथ के पास भी तय करने के इतने ही अधिकार हैं। भले आदमी हैं मगर सबसे ज्यादा डरे हुए।

ऐसे नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। सब इंतजार में बैठे हैं। केजरीवाल ने मोदी के रिटायरमेंट की घोषणा करके सबकी उम्मीदों को हरा कर दिया। भाजपा में लोग कहने लगे कि कांटा ही कांटे को निकाल सकता है। केजरीवाल को वहां भी मोदी की तरह ही लोग व्यक्तिवादी नेता मानते हैं। जो खुद को स्थापित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।

कांग्रेस के कई समर्थकों को कष्ट है यह कि केजरीवाल से समझौता क्यों किया? लेकिन कांग्रेस जानती है कि यह समय छोटे विरोधी से लड़ने का नहीं। राजनीति का पुराना सिद्धांत है कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त! कांटा कांटे को निकालता है। आज भी यह सवाल है कि अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो सबसे पहले विवाद की शुरूआत कहां से होगी? हो सकता है कहीं और से हो या न हो लेकिन सबको केजरीवाल की महत्वाकांक्षा पर सबसे ज्यादा शक है।

लेकिन यह समय इन सब बातों पर विचार करने का नहीं है। क्योंकि जनता भी नहीं कर रही है। जनता का भी अब जो मूड सामने आ चुका है वह यही है कि सबसे पहले उसे बेरोजगार करने वाले को हटाना है। बेरोजगारी आज सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। और मोदी का इस पर एक शब्द भी नहीं बोलना जनता की इस आशंका को सही साबित कर रहा है कि मोदी जी के लिए यह कोई मुद्दा ही नहीं है। लगता है जो वह बड़ी-बड़ी बातें करते हैं जिसे अब जनता भी फेंकना कहने लगी है उस पर वे खुद भी यकीन करने लगे हैं।

मनोविज्ञान में ऐसी चीज होती है कि आप झूठ बोल बोलकर खुद उस पर यकीन करने लगते हैं। लगता है मोदी जी को यकीन है कि उन्होंने अपने वादे जिसे अब वह गारंटी कहने लगे हैं के अनुरूप दो करोड़ रोजगार हर साल दिए हैं। और फिर भी अगर कुछ लोग बचे रह गए तो वह उनके कहे मुताबिक पकौड़े तलकर रोजगार पा रहे हैं।

इसलिए जनता भी इसमें बिल्कुल नहीं उलझ रही कि अगर इंडिया जीता तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अब लोग कहते हैं कि मोदी जी ने इंडिया जीता कहकर यह तो मान लिया है कि वे नहीं जीत रहे। बाकी बहुत नेता हैं वहां और अगर मोदी जी चाहेंगे तो उनसे पूछ लेंगे! वहां बीजेपी में तो कोई उनसे पूछने वाला होगा नहीं। हार के बाद क्या होगा इसकी कल्पना भी मोदी जी के लिए भयावह होगी। खुद बीजेपी और संघ के लोग उन्हें बख्शेंगे नहीं। दस साल में पार्टी और संघ कहीं नहीं है। मोदी सरकार, मोदी तीसरी बार, मोदी परिवार सब मोदी ही मोदी है। भाजपा और संघ का कहीं नाम नहीं है।

इसलिए केजरीवाल का यह दांव कामयाब हो गया। इंडिया गठबंधन से मोदी का ध्यान हट गया। अब वे यही सोच रहे हैं कि पार्टी में कौन क्या करेगा। उनके सबसे बड़े समर्थक अमित शाह को केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पद के सपने दिखा दिए। दूसरे बड़े नेता योगी को चेतावनी दे दी कि अगले निशाने पर आप हो। कोई भाजपा नेता इसकी सफाई भी नहीं दे रहा है। मतलब केजरीवाल की तीर सही निशाने पर लगा है। भाजपा में हचलच मच गई।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार है)

शकील अख्तर

> **जनता भी नहीं कर रही है। जनता का भी अब जो मूड सामने आ चुका है वह यही है कि सबसे पहले उसे बेरोजगार करने वाले को हटाना है। बेरोजगारी आज सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। और मोदी का इस पर एक शब्द भी नहीं बोलना जनता की इस आशंका को सही साबित कर रहा है कि मोदी जी के लिए यह कोई मुद्दा ही नहीं है। लगता है जो वह बड़ी-बड़ी बातें करते हैं जिसे अब जनता भी फेंकना कहने लगी है उस पर वे खुद भी यकीन करने लगे हैं।**

हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव, लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर असर

■ डॉ. ज्ञान पाठक

25 मई को छठे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 9 मई को नामांकन वापस लेने से पहले हरियाणा की राजनीति में काफी बदलाव आया। चुनाव की पूर्व संध्या पर भाजपा के मुख्यमंत्री के बदले जाने की पृष्ठभूमि में चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। 12 मार्च को एनडीए में फूट पड़ गई, जिससे सहयोगी दल भाजपा और जेजेपी अलग हो गये, और दो महीने से भी कम समय में राज्य में नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में आ गई, जब 7 मई को तीन निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। यह निश्चित रूप से भाजपा के लिए अशुभ है, क्योंकि पार्टी का लक्ष्य राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतना है, जो उसने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता चाह रहे हैं इसलिए वह किसी भी सीट का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते।

पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिनकी जगह दूसरे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आये, करनाल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। सैनी सरकार से समर्थन वापस लेने वाले तीनों विधायकों ने अब कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। उन्होंने पहले तो कहा कि खट्टर उनके नेता हैं, लेकिन जब वह सत्ता की कुर्सी पर नहीं हैं, तो उनका सैनी से कोई लेना-देना नहीं है। इससे संकेत मिलता है कि भाजपा के भीतर दो खेमों-खट्टर और सैनी के बीच दरार थी, हालांकि, बाद में निर्दलीय विधायकों ने भी अपने चुनाव अभियानों में अपमानित होने के लिए खट्टर पर हमला किया। यह एक नया विकास है, जो दर्शाता है कि राज्य में खट्टर भी अपना व्यक्तिगत समर्थन आधार खो रहे हैं।

> **पांच साल बाद 2024 में, पीएम मोदी को लगा कि भाजपा अपनी लोकसभा सीटों को अपने सहयोगी जेजेपी के साथ साझा नहीं कर सकती है, और इसलिए जेजेपी को गठबंधन छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए अपमानित किया गया। मार्च में गठबंधन टूट गया। भाजपा नेतृत्व ने सोचा कि जेजेपी के अलग से चुनाव मैदान में होने पर भाजपा, इंडिया ब्लॉक और जेजेपी के बीच मुकाबला त्रिकोणीय हो जायेगा।**

यह स्पष्ट था जब खट्टर अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे और अपना रोड शो कर रहे थे, जहां बहुत अधिक उत्साही लोग नहीं दिख रहे थे - न तो सड़क पर, न ही सड़क के किनारे दर्शक या घरों की छतों पर दर्शक। सब कुछ सामान्य ही लग रहा था और लोगों में चुनाव को लेकर कोई उत्साह नहीं दिख रहा था। इसे मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया है।

2014 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा खट्टर को हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य में लाकर उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। मोदी का विचार सिर्फ राज्य की राजनीति में जाटों के वर्चस्व को तोड़ना था। राज्य की राजनीति में कोई महत्वपूर्ण जाट नेता न होने के कारण मोदी अपने उद्देश्य में सफल रहे। हालांकि, 2019 के राज्य चुनाव में, दुष्यंत चौटाला की जेजेपी जाट समर्थन आधार के साथ उभरी। यह भाजपा नेतृत्व के लिए एक झटका था, क्योंकि पार्टी ने कुछ महीने पहले ही राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटें जीती थीं। भाजपा की इतनी राजनीतिक किस्मत का गिरना अप्रत्याशित था और पार्टी को मुख्यमंत्री खट्टर के नेतृत्व में राज्य सरकार बनाने के लिए जेजेपी के साथ गठबंधन करना पड़ा।

पांच साल बाद 2024 में, पीएम मोदी को लगा कि भाजपा अपनी लोकसभा सीटों को अपने सहयोगी जेजेपी के साथ साझा नहीं कर सकती है, और इसलिए जेजेपी को गठबंधन छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए अपमानित किया गया। मार्च में गठबंधन टूट गया। भाजपा नेतृत्व ने सोचा कि जेजेपी के अलग से चुनाव मैदान में होने पर भाजपा, इंडिया ब्लॉक और जेजेपी के बीच मुकाबला त्रिकोणीय हो जायेगा, जिससे उनकी जीती हुई 10सीटों को बरकरार रखने की संभावना उज्ज्वल हो जायेगी। हालांकि, यह राज्य में उभर रही एक जटिल राजनीतिक स्थिति का एक बहुत ही सरल दृष्टिकोण था।

भाजपा नेतृत्व इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि राज्य में पंजाबी समुदाय मनोहर लाल खट्टर से खुश नहीं है, जो खुद एक पंजाबी हैं। उन्होंने राज्य में ओबीसी समुदाय को भी नाराज कर दिया था। ओबीसी राजनीति की खोज में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खट्टर की जगह ओबीसी राजनेता सैनी को ले लिया है। हालांकि, ऐसा लगता है कि यह उल्टा हो गया है। पंजाबी और ओबीसी दोनों अब भाजपा नेतृत्व से इतने खुश नहीं हैं, क्योंकि दोनों समुदायों के कई लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए तैयार हैं।

समर्थन वापस लेने वाले तीन निर्दलीय विधायकों ने बताया है कि उन्होंने किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों और युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी के अलावा अपने आत्मसम्मान के लिए ऐसा किया है। जहां तक जेजेपी का सवाल है, उसने राज्य की अल्पमत भाजपा सरकार को गिराने के लिए प्रस्ताव लाने पर कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की है।

90सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में भजपा के पास केवल 40 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 30 और जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। दो सीटें खाली हैं, क्योंकि खट्टर ने करनाल से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, और रणजीत सिंह चौटाला ने रानिया से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इस्तीफा दे दिया है। रणजीत हिसार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस प्रकार विधानसभा में प्रभावी सदस्य संख्या केवल 88 है। भाजपा के पास केवल 3 विधायकों का समर्थन है और इसलिए सरकार अल्पमत में आ गई है। देखना यह है कि राज्य में भाजपा की अल्पमत सरकार रहते हुए लोकसभा चुनाव कराया जाता है या नयी सरकार बनती है।

इसके विपरीत कांग्रेस और आप ने लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में हाथ मिलाया है। आप कुरूक्षेत्र से चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस बाकी 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जेजेपी और कांग्रेस ने अल्पमत भाजपा सरकार को हटाने के लिए राज्यपाल से मांग की है और अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के पुनरुत्थान के साथ, इंडिया ब्लॉक भाजपा को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

फरवरी 2024 के हालिया किसान आंदोलन और खट्टर सरकार द्वारा उसके क्रूर दमन ने पूरे किसान समुदाय को नाराज कर दिया है। उनका विरोध इतना था कि किसान आंदोलन शुरू होने के एक महीने के भीतर ही पीएम मोदी को खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा। हालांकि पूर्व सीएम खट्टर ने विश्वास जताया है कि 2024 के चुनावों में भाजपा फिर से सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेगी, विश्लेषकों का मानना है कि उन्हें खुद करनाल में कड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है, अपनी सीट बरकरार रखना भी बहुत मुश्किल है।

ध्यान रहे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 58.21 फीसदी वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 28.51 फीसदी वोट मिले थे। हालांकि, कुछ ही महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और जेजेपी के साथ त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा सिर्फ 36.49 फीसदी वोट ही हासिल कर पायी। कांग्रेस को 28.08 फीसदी और जेजेपी को 14.80 फीसदी वोट मिले थे। भाजपा जाहिर तौर पर अपनी सीटें बरकरार रखने में बहुत मुश्किल स्थिति में है, खासकर तब जब उसके साथ कोई सहयोगी नहीं है, पार्टी गुटबाजी में बंटी हुई है और उसका समर्थन आधार अब बिखरता नजर आ रहा है। इस बार भाजपा के लिए अपनी खोई जमीन वापस पाना आसान नहीं होगा।

गुरवाणी विचार

साथे न चालै बिन भजन बिखिया सगलि छार

हरि जेठि नुडंदा लोड़िये- जिस अगे सभि निवनि
हरि सजन दावणि लगिआ- किसे न देई बनि
मानक मोती नाम प्रभु- उन लागै नाही सनि
रंग सभै नारायणै- जेते मनि भावनि
जो हरि लोड़े सो करे- सोई जीअ करनि
जो प्रभु कीते आपणे सेड़ी कही अहि धनि
आपण लीया जे मिले विछुड़ि किउ रोवंनि।
साधु संग परापते नानक रंग माणांनि
हरि जेठु रंगीला तिस धणी-जिस कैभागु मंथनि

बारह माह में जेठ महीने द्वारा पांचवे नानक गुरु अर्जुन देव मानव मन को समझाइश देते हुए फरमा रहे हैं कि जिस प्रभु परमात्मा के आगे सारे शीश निवाते हैं। जेठ माह में उसकी सिमरन भक्ति मे जुट जाना चाहिए। वैसे भी पति के बड़े भाई को जेठ कहते हैं और उसका सब छोटे आदर करते हैं। ठीक इसी तरह प्रभु जो जेठों का भी जेठ है अर्थात सब से बड़ा है। उसका आदर करने पर अर्थात उसकी सिमरन बंदगी करने पर ही हमारा कल्याण हो सकता है। अगर हम प्रभु परमात्मा से जुड़ गए तो फिर यमराज भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता तभी तो गुरवाणी द्वारा हमें समझाया गया है कि-

मेरे रामराय तूं संता का संत तेरे
सेवक को भऊ नहीं लागे जम नहीं आवै नेड़े।

आजकल लोग हीरे मोती इत्यादि कीमती आभूषणों के पीछे पड़े रहते हैं उनका संचय करते रहते हैं पर वे इस बात को भूल जाते हैं कि ये हीरे मोती इत्यादि उनके पास क्षणिक भर रहने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा रह भी जाए तो हमारे मरने के बाद तो हमें सब कुछ यहीं छोड़ कर जाना है। यहां तक कि हमारा यह जो तन है वह भी साथ जाने वाला नहीं है साथ में हमारे वही जाने वाला है जो हमने प्रभु सिमरन में कर सांचा धन इकट्ठा किया है-

साथे न चालै बिन भजन बिखिया सगलि छार।
हरि हरि नाम कमावना नानक ऐहो धन सार।।

हीरे मोती इत्यादि धन तो चोरी हो सकता है पर प्रभु सिमरन करने पर प्राप्त साचा धन न कोई चोर चोरी कर सकता है और न ही अग्नि,पानी द्वारा नष्ट किया जा सकता है। न हमसे कोई छीन सकता है। फिर जिस ने भी सिमरन भक्ति कर प्रभु परमात्मा से मन रमाया है वह परमात्मा की प्रसन्नता का पात्र बन जाता है-

नाम देव कबीर त्रिलोचना सधना सैन तरै।

वह प्रभु दरबार में तो उजले मुख से जाता ही है। इस संसार में भी उसकी अच्छाइयां या गुणगान होता रहता है। नाम धन संचित करने के कारण वह सब को प्यारा लगने लगता है चाहे वह किसी भी जाति का हो भक्त रविदास जी जाति के चमार थे परन्तु प्रभु सिमरन करते-करते ऐसे प्रभु प्यारे हो गए कि आज सारा संसार उनके गुण गान करता है इसीलिए गुरदेव हमें समझा रहे हैं कि जिस इंसान के किए गये अच्छे कर्मों के कारण और संचित किये गए सिमरन भक्ति द्वारा प्राप्त धन के कारण जेठ महीना जो काफी गर्मी भरा रहता है,भी उसे सुहावना और आनंददायक लगने लगता है। वह सत कर्म करते हुए और सिमरन भक्ति करते हुए अपनी जीवन नौका को सुचारू रूप से खेकर प्रभु परमात्मा के सांचे दरबार में स्थान प्राप्त कर लेता है।

इंदर सिंह आहुजा

आपके पत्र

सफलता-असफलता जीवन के दो अहम पहलू

असफलता को झेलने के लिए आत्मविश्वास की परम आवश्यकता होती है। असफलता ऐसा स्वाद है जिसे हर व्यक्ति ने जीवन में कभी ना कभी जरूर चखा होगा। असफल होने से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। महापुरुषों ने कहा है कि असफलता यह दर्शाती है कि आपने प्रयास पूरे मन से नहीं किया है अत: असफलता के बाद सफलता के लक्ष्य को निर्धारित कर पूर्ण मनोयोग से कर्म की वेदी पर अपना शीश नवाना चाहिए। जीवन में असफलता किसी लक्ष्य को स्थापित करने का ही परिणाम है, इसीलिए इसे बड़े ही सौजन्यता से, सहज तरीके से आत्मसात करना चाहिए। सकारात्मक तरीके से आत्मविश्वास के साथ स्वीकार की गई असफलता मनुष्य को बड़े लक्ष्य की ओर प्रयास करने के लिए संकेत देती है। बिना असफलता के सफलता कोई भी आस्वाद नहीं देती है। असफलता के बाद ही सफलता के के लिए किए गए प्रयासों का महत्व मनुष्य को अपने जीवन में पता लगता है। शायर फैज अहमद फैज ने कहा है-

दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है,
लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है।

असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है और यह सामान्य मानवीय कृत्य भी है। असफल होने के कारणों का पता लगाकर सफलता के लिए प्रयास हमेशा हमें दोगुना कर देना चाहिए। यह भी जरूरी नहीं है कि एक बार सफल होने के बाद मनुष्य सदैव सफल ही होता रहे इसके लिए मनुष्य को लगातार चिंतनशील, आत्म विश्वासी, साहसी और सतर्क होना पड़ेगा। सफल होने के लिए हमें हमेशा हुनरवान होना होगा जिससे इसी हुनर से हमें सफलता का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। यह सर्वविदित सच्चाई है कि हमें सफलता के लिये साहस और हुनर का उपयोग कर सदैव अग्रसर होते रहना होगा। सफलता एक लक्ष्य और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव सफलता की सीढ़ी चढ़कर हमें वहां पहुंचने की आवश्यकता है।

आत्मविश्वास का अर्थ शक्ति और ऊर्जा तो है और यह संपूर्ण रूप से हमारे प्रयासों हमारे संकल्प और साहब से जुड़ा हुआ प्रतिफल भी है।

देश के नौजवानों को हमारे सफल महापुरुषों से शिक्षा लेकर सफलता के लिए अनंत तक आत्मविश्वास के साथ निरंतर श्रम करना चाहिए जिससे न सिर्फ उनका भला हो बल्कि पूरे समाज और पूरे देश का भला हो सके और देश पूरे विश्व में सीना तान कर अपने आसपास और सफलता की गाथा सुना सके। यह देखा गया है कि मानव अहंकार को ही आत्मविश्वास समझने की भूल कर देते हैं किंतु आत्मविश्वास घमंड और अहंकार मैं बहुत बड़ा फर्क है। आत्मविश्वास अहंकार विहीन विनम्रता के साथ परिश्रम और संयम संकल्प लेकर सफलता के लक्ष्य की ओर पदार्पण ही है। फलस्वरूप अहंकार को त्याग कर संपूर्ण विश्वास को लेकर देश हित में सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए।

संजीव ठाकुर

https://t.me/AINewsPaperPdf

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

संपादकीय

एक समय में एक काम करो, ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। -स्वामी विवेकानंद

विशाल घरेलू बाजार ही भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत है, जिसके बारे में यूबीएस सिक्यूरिटीज का अनुमान है कि अगले दो वर्षों में यह जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार हो सकता है।

बड़े बाजार की ताकत

आर्थिक अनिश्चितताओं और वैश्विक युद्धों के बीच यूबीएस सिक्यूरिटीज की रिपोर्ट का यह कहना कि भारत 2026 तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार हो सकता है और इस क्रम में इसके 2024 में जर्मनी और 2026 में जापान को पीछे छोड़ने की उम्मीद है, देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था के प्रति आश्वस्त करता है। पिछले एक दशक में भारत में खपत लगभग दोगुनी होकर 21 खरब डॉलर तक पहुंच चुकी है, और, 2023 में तो यह चीन, अमेरिका और जर्मनी से भी तेज गति से बढ़ी है, तो इसका श्रेय नीतिगत पहलों व संरचनात्मक सुधारों के अलावा, देश के विशाल घरेलू बाजार को भी जाता है, जिसमें उत्पादन को खपाने की विराट क्षमता मौजूद है। राजनीतिक व आर्थिक मोर्चे पर चीन ने जिस तरह से दुनिया का भरोसा खोया है, उससे चीन पर से आपूर्ति शृंखला की निर्भरता को कम करने की वैश्विक प्रवृत्ति ही दिखती है, जो भारत के लिए फायदेमंद साबित हुई है। रिपोर्ट बताती है कि देश में समृद्ध तबके (सालाना करीब साढ़े आठ लाख रुपये से ज्यादा कमाने वाले) की आबादी अगले पांच वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। लोगों के पास पैसा आएगा, तो खर्च भी होगा। एनारॉक की रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है, जिसके अनुसार, पिछले पांच वर्षों में देश में महंगे घरों की बिक्री तिगुनी हुई है। इसके अलावा, देश की करीब 33 फीसदी आबादी 20 से 33 वर्ष आयु वाले उपभोक्ताओं की है, जो स्वाभाविक ही ज्यादा खर्चीले होते हैं। बढ़ता शहरीकरण भी एक अन्य वजह है, जिससे बड़ी-बड़ी कंपनियां आसानी से उपभोक्ताओं तक पहुंच रही हैं। फिच सॉल्यूशंस कंपनी बीएमआई ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि प्रति उपभोक्ता व्यय के मामले में भारत जल्द ही इंडोनेशिया, थाईलैंड व फिलीपीन जैसी सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को पछाड़ देगा। देश में पिछले एक दशक में प्रति उपभोक्ता व्यय अवश्य ही गांवों व शहरों में दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। पर चिंता की बात यह है कि इसमें

गैर-खाद्य उत्पादों पर व्यय बढ़ा है, जबकि खाद्य उत्पादों पर घटा है। इसके अलावा, सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट भी कहती है, उपभोक्ताओं में घरेलू बचत कम करने और ज्यादा व्यय करने की भौतिकतावादी प्रवृत्ति बढ़ी है। कुल मिलाकर देखें, तो भारत में आपूर्ति को खपाने के लिए पर्याप्त मांग है। और यही चीज इसे दूसरे एशियाई और उभरते प्रतिस्पर्धी बाजारों की तुलना में महत्वपूर्ण लाभ देती है। लेकिन उपभोग में बढ़ोतरी को बनाए रखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार सृजन की जरूरत होगी, जिस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

क्या बाइडन हार की ओर बढ़ रहे हैं

बुजुर्ग बाइडन के चुनावी अभियान के साथ समस्या यह है कि उसे ऐसे चलाया जा रहा है, मानो वह पहले स्थान पर हों। मानो वह उस बढ़त की रक्षा कर रहे हों, जो उनके पास है ही नहीं। ट्रंप को हराने के लिए ट्रंप जैसा होना जरूरी नहीं।

फरवरी में इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि बढ़ती उम्र और डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले कमजोर प्रतीत होते राष्ट्रपति बाइडन को क्या लड़ाई से हट जाना चाहिए। इस पर मैंने एक कॉलम लिखा था, लेकिन कुछ लोगों का तर्क था कि बाइडन को चुनावी दौर से हटने पर विचार करना चाहिए, जिसमें मतदान विशेषज्ञ नैट सिल्वर और मेरे सहयोगी एजरा क्लेन भी शामिल थे। विशेष वकील रॉबर्ट हूर की रिपोर्ट भी, जिसमें राष्ट्रपति को याददाश्त की समस्या का संकेत दिया गया था, बहस का हिस्सा थी। हालांकि, फिर स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के बाद बाइडन के मतदान प्रतिशत में मामूली सुधार हुआ, जिसे डेमोक्रेटिक पक्ष के आशावादियों ने लपक लिया और बाइडन के चुनाव से हटने की चर्चा दब गई।

रॉस डॉट
द न्यूयॉर्क टाइम्स

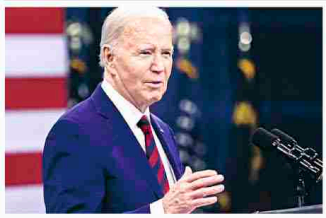

अब मई आ गया है और चुनाव में छह महीने ही बचे हैं, लेकिन मूल बहस अब भी कायम है। बाइडन की बढ़त मामूली ही थी। वह राष्ट्रीय मतदान में अब भी थोड़ा पीछे ही हैं और जॉर्जिया, मिशिगन, एरिजोना, नेवादा, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में ट्रंप से पीछे चल रहे हैं, जिसने पिछली बार डेमोक्रेट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में जीत दर्ज की थी। हालांकि अंतर कम हैः संभवतः तीन या चार पॉइंट। लेकिन यह लगातार जारी है। पिछली गिरावट के बाद से दोनों उम्मीदवारों के बीच बहुत कम फासला है।

हालांकि इस स्थिरता के प्रति डेमोक्रेट की प्रतिक्रिया अकारण विश्वास को अकारण भाग्यवाद से जोड़ती है। एक तरफ यह विश्वास है कि ट्रंप की बढ़त टिकाऊ नहीं है, क्योंकि उनकी भी एक सीमा है और वह 50 फीसदी से आगे बढ़ नहीं सकते (पर क्या कई प्रतिष्ठित तीसरे पक्ष के उम्मीदवारों के साथ दौड़ में यह बात मायने रखती है?), क्योंकि मतदाता अब भी बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं (लेकिन क्या वे दोनों उम्मीदवारों को पहले से अच्छी तरह से नहीं जानते हैं)। अप्रैल, 2020 में बाइडन ने 538 मतदान औसत में लगभग पांच अंकों से बढ़त हासिल की। उन्होंने

4.4 प्रतिशत की गिरावट के साथ लोकप्रिय वोट जीता, क्योंकि ट्रंप के मुकदमों का अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है। लेकिन अगर वह बरी हो गए, तो?

दूसरी तरफ 'हम क्या कर सकते हैं' जैसी चिढ़ रखने वाले लोग कहते हैं कि बाइडन को अब तक की अपनी नीति एवं राजनीतिक नजरिये से हट जाना चाहिए। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। जनता बस कृतघ्न है या भ्रमित है, मीडिया द्वारा गुमराह है या पक्षपात में अंधी है! उन्हें 10 अंकों से ऊपर होना चाहिए! यदि वह इस रिकॉर्ड के साथ नहीं जीत सकते, तो अमेरिका को जो मिलेगा, वह उसी का हकदार है!

बाइडन की स्थिति का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण है। एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि यदि आप चुनाव में ट्रंप को लगातार हराना चाहते हैं, तो आपको सतर्क रहना होगा, अपने मूल सिद्धांतों पर टिके रहकर वोट पाने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और हर अवसर पर सामान्य स्थिति दर्शानी होगी। डेमोक्रेट्स ने 2018 और 2020 में यही किया था, जब वे ट्रंप को हराने में सफल रहे थे।

दूसरी तरफ यदि आप (बाइडन) ट्रंप से हार रहे हैं, तो आप उन घटनाओं या ट्रंप के थकने पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहें, कि वे जादुई रूप से आपके बचाव में आएंगी। इसके बजाय आपको एक ऐसी रणनीति बनाने की जरूरत है, जो चुनौतियों के अनुरूप हो और ट्रंप की असामान्यता से निपटने के लिए राजनीति के सामान्य नियमों को तोड़ने के लिए तैयार रहे (जैसा कि ट्रंप के रिपब्लिकन विरोधी 2016 और 2020 में करने में विफल रहे)।

बाइडन के अभियान के साथ समस्या यह है कि उसे ऐसे चलाया जा रहा है, मानो वह पहले स्थान पर हों। मानो वह उस बढ़त की रक्षा कर रहे हों, जो उनके पास है नहीं। यानी उन्हें उन बड़े कदमों को नकारना होगा, जिसका आग्रह क्लेन और अन्य लोगों ने किया था, जिसमें शारीरिक एवं राजनीतिक सीमाओं की देशभक्तिपूर्ण पहचान अलोकप्रिय शासक को किनारे हटने के लिए प्रेरित करती है और उसकी पार्टी को चुनाव की शर्तों को फिर से निर्धारित करने का मौका देती है। इसका मतलब छोटे टिकट परिवर्तन से बचना है, जिसमें कमला हैरिस एक उम्रदराज राष्ट्रपति के लिए सबसे खराब संभावित सहयोगी हैं, उपराष्ट्रपति पद के लिए वह वास्तव में आश्वस्त करने वाली हैं और लोकप्रिय भी हो सकती हैं।

और इसका मतलब है प्रशासन की नीति-निर्धारण प्रक्रिया को स्वचालित ढंग से चलने देना। क्या एक नियामक योजना शुरू की जा सकती है, जिसका लक्ष्य गैसोलीन से चलने वाली कारों को धीरे-धीरे समाप्त करना है? बिल्कुल वही, जो वे मध्य पश्चिमी प्रांत चाहते हैं। देशभर के स्कूलों में लैंगिक भेदभाव मिटाने के लिए उनकी नीतियां चुनावी वर्ष के बिल्कुल मुफीद हैं। नया छात्र ऋण माफी कार्यक्रम, जिसकी लागत उच्च मुद्रास्फीति के बावजूद 10 खरब डॉलर से ज्यादा हो सकती है, युवा मतदाता को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि हाल ही में हार्वर्ड यूथ पोल में छात्र ऋण को 16 मुद्दों में से 16वें स्थान पर रखा गया था। क्या आव्रजन पर नया आक्रामक कार्यकारी आदेश यह साबित करने के लिए जारी किया जाएगा कि यदि रिपब्लिकन सहयोग नहीं करते हैं, तो बाइडन सीमा सुरक्षा में सुधार के लिए एकतरफा कार्य करेंगे? भविष्य में इस पर विचार किया जा सकता है।

बाइडन के पास अब भी चुनाव जीतने का मौका है, क्योंकि कुछ अंकों की कमी पूरी की जा सकती है। वह अंतिम क्षण में कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं, जिस पर मतदाता ज्यादा ध्यान देंगे। मुद्रास्फीति पर सकारात्मक खबरों और पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम से उन्हें बढ़त मिल सकती है। ट्रंप को दोषी साबित हो सकते हैं और पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में दो प्रतिशत का महत्वपूर्ण अंक गंवा सकते हैं। केनेडी के समर्थन का वामपंथी हिस्सा बाइडन के पाले में आ सकता है, जबकि ट्रंप हितैषी हिस्सा तीसरे पक्ष से चिपका रह सकता है। ट्रंप के असंतुष्ट एवं मतदान के अनिच्छुक समर्थक मतदान के दिन गायब रह सकते हैं। पर हरके कुछ महीने पर वास्तविकता की जांच करना अच्छा होगा कि वास्तव में ट्रंप को रोकने वाले उस अभियान का क्या हो रहा है, जिसे बाइडन ने तय किया था और जिसे केवल वही चला सकते हैं। फिलहाल जो हो रहा है, वह यह है कि बाइडन हार की ओर बढ़ रहे हैं।

जीवन धारा

शिवानी दीदी

अपने अतीत को भूल जाएं। इसे जितना याद रखेंगे, उतने ही अधिक परेशान होंगे। भूत को भूलने के लिए मन को स्थिर करना होगा, और यहां काम आएगा-ध्यान यानी मेडिटेशन।

कड़वी यादों को भूलना सीखें

कभी-कभार कोई हमारे सामने या हमसे जुड़ी कुछ ऐसी बात बोल देता है, जिसे भूलना अत्यंत कठिन हो जाता है। वह तो यह बात दो मिनट में कह जाता है, लेकिन हमें उसे भूलने में दो महीने या दो साल तक लग जाते हैं। दो मिनट में कुछ भी होता है, आप उसे हमेशा के लिए याद रख लेते हैं। आप अपने दिमाग में उस बात को दोहराते रहते हैं। जब किसी से बात होती है, तब भी आप उस घटना का जिक्र करते हैं। आप अपने मस्तिष्क में उस दृश्य का चित्रण हर समय करते ही रहते हैं। आप हर समय उस घटना का विभिन्न दृष्टिकोण से विश्लेषण करते रहते हैं और उसे सही-गलत-बुरा-दुखद आदि जैसी बातों से जज करने लगते हैं। आप जितनी बार उस घटना पर विचार करेंगे, उतनी ही बार और उतना ही ज्यादा आप नए-नए निष्कर्षों तक पहुंचेंगे। इनमें से अधिकांश बातों का स्वभाव नकारात्मक ही होता है।

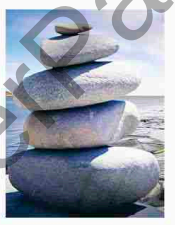

ऐसा करने से आप अपने मस्तिष्क में मौजूद इस घटना को और मजबूती प्रदान करते हैं। पहले वह आपके अवचेतन मन में रहती है और धीरे-धीर वह आपकी चेतना में घर कर जाती है। ऐसी स्थिति में वर्षों बाद भी आपको उनके द्वारा कही गई बातें याद रहती हैं। जबकि जिस व्यक्ति ने वह बात कही थी, वह तो कब का उसे भूलकर आगे बढ़ चुका है। यह कुछ ऐसा है कि आपका पड़ोसी अपने घर का कूड़ा निकालकर आपके घर में फेंककर भूल जाता है कि उसने कुछ किया था। अब उस कूड़े को साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है। वह तो ऐसा करके अपने घर को साफ कर चुका है। कोई आपसे अपशब्द कहता है और फिर इसे भूल जाता है, परंतु उन अपशब्दों का आपके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है।

हमें यह समझना चाहिए कि अतीत अब बीत चुका है। उसके साथ जुड़ी यादें भी बीत चुकी हैं। आपके पास अगर कुछ है, तो वह है वर्तमान, जिसे जीना और अपने लिए उसे खुशगवार बनाना आपकी जिम्मेदारी है।

हमें सबसे अधिक काम वर्तमान को लेकर करना चाहिए, सबसे ज्यादा सावधानी वर्तमान के प्रति रखनी चाहिए। इसी अवस्था में जीवन जीवंत है।

भूतकाल में जीवन के साथ यादें हैं, भविष्य में जीवन एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान में जीवन जिंदा है। जिंदगी को जिंदा देखना हो, तो वर्तमान को ठीक से जीना सीखना होगा। वैसे तो मुर्दे के पास भी एक जिंदगी होती है। आखिरी सांस लेने के बाद जलाए या दफनाए जाने तक जो समय होता है, वह मुर्दे की जिंदगी है। हमने यदि वर्तमान को नहीं समझा, तो हमारी जिंदगी भी मुर्दे की तरह है। वर्तमान कितना बारीक है, थोड़ा इसे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान तुरंत अतीत में बदल जाता है और भविष्य शीघ्र वर्तमान में उतर आता है। अपने अतीत को भूल जाएं। इसे जितना याद रखेंगे, उतने ही अधिक परेशान होंगे। भूत को भूलने के लिए मन को स्थिर करना होगा, और यहां काम आएगा-ध्यान यानी मेडिटेशन। जब हम ध्यान में उतरते हैं, तो अपने भूतकाल को भूल रहे होते हैं।

कल से ऊंचा आज...

सूत्र

भविष्य के प्रति सबसे बड़ी सावधानी तो यह रखना है कि हमारा भविष्य भूत और वर्तमान से हमेशा ऊंचा ग्राफ लिए हो। यानी आने वाला कल, जो कि कुछ समय बाद हमारा आज बन जाएगा, इसके ग्राफ में हमेशा ऊंचाई लिए हो। सीधी-सी बात है, हर आने वाला कल आज से ऊंचा होना चाहिए। इसको लेकर बहुत सावधान रहिए।

दूसरा पहलू

बड़ी संख्या में सैनिकों की गुमशुदगी यूक्रेन के लिए बड़ा धक्का है। इससे यूक्रेनी समाज और राष्ट्रपति जेलेंस्की पर भी दबाव बढ़ा है।

लापता सैनिक और परेशान परिजन

दो यूक्रेनी सैनिकों के शव महीनों तक एक खेत में पड़े थे। उनके परिजनों को ड्रोन द्वारा लिए गए फुटेज से उनके बारे में पता चला। दूसरी ओर, यूक्रेन की सेना चार महीने बाद भी उन दो सैनिकों की तलाश में लगी थी! मारे गए दो सैनिकों में से एक जेरेटेस्की की पत्नी कहती हैं कि मोर्चे पर मारे जाने पर ब्रिगेड कमांडर को चाहिए था कि वह इस बारे में उन दो सैनिकों के परिजनों को सूचित करें। यूक्रेन की सेना के इस रवैये से वे लोग परेशान हैं, जिनके परिजन मोर्चे पर लड़ रहे हैं।

सरकार ने अब तक नहीं बताया है कि कितने सैनिक लापता हैं। हालांकि विगत फरवरी में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मृत सैनिकों का आंकड़ा लगभग 31,000 बताया, जबकि अमेरिकी आकलन के मुताबिक, करीब 70,000 यूक्रेनी सैनिक तो विगत अगस्त तक ही मारे गए थे। यूक्रेनी सैनिकों की मौत के आंकड़ों में सबसे ज्यादा दुखद यह है कि इनमें से बड़ी संख्या में सैनिकों के शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्योंकि अनेक जगह खाइयों में लड़ते हुए मारे जाने के बाद शव वहीं पड़े रहते हैं, और कई बार तो वे नजर भी नहीं आते। इसके अलावा माना जाता है कि अनेक यूक्रेनी सैनिक रूस के कब्जे में हैं। लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में सीनियर फेलो बेन बैरो कहते हैं, 'बड़ी संख्या में सैनिकों की गुमशुदगी यूक्रेन के मनोबल के लिए धक्का तो है ही, इससे वहां के समाज, उसके सैन्य नेतृत्व और राष्ट्रपति जेलेंस्की पर भी दबाव बढ़ा है। यह एक भीषण समस्या है।' मारे गए या गायब सैनिकों के मामले में सेना और सरकार के रवैये से नागरिकों का धैर्य चुक रहा है। क्षुब्ध नागरिकों ने पिछले अक्तूबर में राजधानी कीव में एक विशाल रैली की। उसके बाद भी नागरिकों ने कई बार विरोध प्रदर्शन कर कहा कि सरकार को ज्यादा पारदर्शिता बरतनी चाहिए। हालांकि इस मामले में जेलेंस्की सरकार की भी परेशानियां हैं, क्योंकि रूस कब्जे में आए यूक्रेनी सैनिकों के बारे में कोई सूचना नहीं देता। इससे सबसे ज्यादा परेशानी सैनिकों के परिजनों को होती है। अल्योना बोंदर का सैनिक भाई विगत सितंबर से लापता है। सेना के रवैये से हताश अल्योना ने एक ज्योतिषी की मदद ली, जिसने भाई के जीवित होने की बात कही। 'क्या मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए', हताश अल्योना कहती हैं। कुल मिलाकर, लंबे चलते युद्ध में रूस से पिछड़ने के अलावा सैनिकों के परिजनों का क्षोभ भी यूक्रेन और राष्ट्रपति जेलेंस्की को परेशान कर रहा है।

मारिया वरन्निकोवा

फरवरी में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मृत सैनिकों का आंकड़ा 31,000 बताया। अमेरिका के मुताबिक, करीब 70,000 यूक्रेनी सैनिक तो विगत अगस्त तक ही मारे गए थे।

मारे गए या गायब सैनिकों के मामले में सेना और सरकार के रवैये से नागरिकों का धैर्य चुक रहा है। इस मामले में जेलेंस्की सरकार की भी सीमाएं हैं, क्योंकि रूस कब्जे में आए यूक्रेनी सैनिकों की सूचनाएं साझा नहीं करता।

आंकड़े

चौथे चरण का मतदान

आज चौथे चरण में लोकसभा की 96 सीटों पर मतदान के साथ कुल 70 फीसदी राष्ट्रीय वोटों का मतदान संपन्न हो जाएगा।

चरण 1	19%
चरण 2	35%
चरण 3	52%
चरण 4	70%
चरण 5	79%
चरण 6	90%
चरण 7	100%

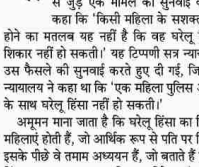

सौ फीसदी मतदान सातवें चरण में पूरा होगा।

स्रोत : ECI

राजा ने उस मंत्री को खोजने के लिए कहा, जो हर बात पर कहता कि भगवान की कृपा है। राजा को एहसास हो गया कि जो होता है, वह भले के लिए होता है।

भगवान की बड़ी कृपा है

अंतर्यात्रा
संकलित

एक राजा का मंत्री भगवान का भक्त था। कोई भी बात होती, तो वह कहता कि भगवान की बड़ी कृपा है। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा है।

राजा को गुस्सा आया, पर वह चुप रहा। एक बार तलवार से राजा की उंगली कट गई, मंत्री ने फिर कहा, भगवान की बड़ी कृपा है। राजा ने गुस्से में मंत्री को राज्य से बाहर निकाल दिया।

एक बार राजा जंगल में शिकार करने गए, तो अकेले पड़ गए। डाकुओं ने दल ने राजा को पकड़ लिया और काली माता के सामने बलि देने के लिए ले गए। बलि देने से पहले डाकुओं के पुरोहित ने पूछा, क्या तुम्हारा बेटा जीवित है। राजा ने कहा, नहीं, तो पुरोहित बोला, इसका तो हृदय जला हुआ है, इसकी बलि कैसे दे सकते हैं? डाकुओं ने कहा, हो सकता है, यह मरने के डर से झूठ बोल रहा हो। तब पुरोहित ने राजा के अंगों की जांच की, तो उंगली कटी पाई। पुरोहित ने कहा, इसका अंग भंग है, इसकी बलि नहीं दे सकते। इसे छोड़ दो।

इसके बाद राजा को उस मंत्री की याद आई, जो कहा करता था, ईश्वर की बड़ी कृपा है। राजा ने उस मंत्री को ढूंढकर लाने के लिए कहा, क्योंकि उसे यह बात समझ में आ गई कि जो कुछ होता है, वह भले के लिए होता है।

आज का इतिहास

स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र 13 मई1952 को आयोजित

भारत के इतिहास में 13 मई का अपना खास मकाम है। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में यह दिन एक मील का पत्थर है। स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र 13 मई, 1952 से आहूत किया गया था। तीन अप्रैल, 1952 को पहली बार उच्च सदन यानी राज्यसभा का गठन किया गया और इसका पहला सत्र 13 मई, 1952 को आयोजित किया गया। इसी तरह 17 अप्रैल, 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया जिसका पहला सत्र 13 मई, 1952 को आहूत किया गया। 1830 में इक्वाडोर गणराज्य की स्थापना, जुआन जोस फ्लोरेंस पहले राष्ट्रपति बने। 1846 में अमेरिका और मैक्सिको के बीच पिछले एक साल से टैक्सास को लेकर चल रहे तनाव के बीच कांग्रेस ने अपने इस पड़ोसी देश के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया।

एक महिला आईपीएस और घरेलू हिंसा

यह सोच गलत है कि घरेलू हिंसा का शिकार केवल वही महिलाएं होती हैं, जो आर्थिक रूप से पति पर निर्भर रहती हों।

ऋतु सारस्वत | समाज

बीते दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 'किसी महिला के सशक्त पद पर होने का मतलब यह नहीं है कि वह घरेलू हिंसा का शिकार नहीं हो सकती।' यह टिप्पणी सत्र न्यायालय के उस फैसले की सुनवाई करते हुए दी गई, जिसमें सत्र न्यायालय ने कहा था कि 'एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ घरेलू हिंसा नहीं हो सकती।'

अमूमन माना जाता है कि घरेलू हिंसा का शिकार वे महिलाएं होती हैं, जो आर्थिक रूप से पति पर निर्भर हों। इसके पीछे वे तमाम अध्ययन हैं, जो बताते हैं कि घरेलू हिंसा का सामना ज्यादातर निम्न आर्थिक एवं सामाजिक स्तर की महिलाओं को करना पड़ता है। परंतु आज तक कोई भी शोध यह दावा नहीं कर पाया है कि कामकाजी

व सशक्त महिलाएं घरेलू प्रताड़नाओं से मुक्त हैं। एबिगेल बीट्जमैन का अध्ययन 'विमेन ऐंड मेन्स रिलेटिव स्टेट्स ऐंड इंटिमेट पार्टनर वायलेंस इन इंडिया' बताता है कि जिन परिवारों में महिलाएं कामकाजी और पति से अधिक कमाने वाली हैं, उन्हें भी घरेलू हिंसा सहनी पड़ती है। बीट्जमैन कहती हैं कि घर की शक्ति-नियंत्रण की गतिशीलता पितृसत्तात्मक ढांचे में कुछ इस तरह आत्मसात हो चुकी है कि नियंत्रण रखने की मानसिकता इससे जरा भी प्रभावित नहीं होती है कि महिला आर्थिक रूप से सक्षम है या नहीं। अंतर सिर्फ इतना है कि आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएं कई बार प्रताड़नाओं का विरोध कर पाती हैं। दुनिया भर के विभिन्न समाजों में महिलाओं को उनकी लैंगिक भूमिकाओं के अनुरूप समाजीकृत किया जाता है और यह प्रक्रिया आधुनिकीकरण के तमाम दावों के बीच भी सफल वैवाहिक जीवन के निर्वहन का समस्त दायित्व स्त्री के कंधों पर डालती है और बड़ी ही निष्ठुरता से यह स्वीकार करती है कि वैवाहिक जीवन के उतार-चढ़ावों के बीच महिला का धैर्य और त्याग विवाह के स्थायित्व की नींव बनता है। इस 'धैर्य' की परिभाषा में मौखिक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार को सहजता से स्वीकारना भी शामिल है। स्पष्ट है कि यह नियम कामकाजी महिलाओं पर भी लागू होता है। पुरुष के आक्रामक व्यवहार पर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत तर्क देता है कि पुरुष अपनी भावनात्मक असुरक्ष व तनाव की भरपाई करने के लिए अति पुरुषोचित व्यवहार करता है। आवेगी स्वभाव, आक्रामकता, विषाक्त पुरुषत्व, नियंत्रण की प्रवृत्ति और असुरक्षा जैसे कारक पुरुषों को जीवनसाथी को प्रताड़ित करने के लिए उकसाते हैं। सवाल यह है कि दुनिया भर में महिलाएं क्यों खामोशी से घरेलू हिंसा को स्वीकारती आ रही हैं। निस्संदेह इसके पीछे सामाजिक व पारिवारिक प्रतिष्ठा धूमिल होने का भय है। महिलाएं शुरू में यह सोचकर प्रताड़ना सहती हैं कि यह अल्पावधि के लिए है। भविष्य में उसके साथी का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन जैसे-जैसे पीड़िता अपमानजनक व्यवहार को स्वीकार करती है, मौखिक या मनोवैज्ञानिक प्रताड़ना उसके मस्तिष्क में मजबूत हो जाती है, जिससे उसके लिए समय के साथ दुर्व्यवहार की गंभीरता को पहचानना मुश्किल हो जाता है। अल्बर्ट बंडूरा की 'सोशल लर्निंग थ्योरी' परिवार के भीतर हिंसा के कई पीढ़ियों तक संचरण की चर्चा करती हैं। इसके अनुसार बच्चे अंतरंग साथी के बीच हिंसा को पारिवारिक वातावरण में देखने और नकल करने की प्रक्रिया के जरिये 'हिंसक व्यवहार' को आत्मसात कर लेते हैं। घरेलू हिंसा राष्ट्र के विकास को प्रभावित करती है तथा समाज के आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण को बाधित करती है। शोधों से पता चलता है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की लागत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दो प्रतिशत हो सकती है। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम पर प्रतिक्रियाएं ध्रुवीकृत हैं।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 65 ■ अंक 87 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2022-24 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

सम्पादकीय

कलक्टरों की रेंकिंग अच्छा प्रयास लेकिन पत्रावली निस्तारण की कोई तो गाइडलाइन बनें, देरी पर कार्रवाई हो

मुख्य सचिव सुधांश पंत प्रशासनिक सुधार के लिए अपनी कुर्सी संभालने के बाद से ही जुटे हुए हैं। विभिन्न विभागों के औचक निरीक्षण और कर्मचारी अधिकारियों पर अनुपस्थिति के दौरान कार्रवाई करके उन्होंने सुधार की मुहिम को आगे बढ़ाया है। इसी कड़ी में सुधांश पंत की पहल पर लागू ई फाइलिंग सिस्टम के बाद प्रदेश के कलक्टरों की पत्रावलियों के निपटाने की गति को लेकर रेंकिंग जारी करने का काम शुरू किया गया है। 47 जिलों के कलक्टरों की पत्रावली निपटारे की समय सीमा देखी गई जिसमें से 3 कलक्टर का फाइल निपटाने का काम मुख्य सचिव सुधांश पंत के स्तर पर काफी नाराजगी वाला रहा है। इन तीनों जिला कलेक्टरों को रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। रेड लिस्ट को ब्यूरोक्रेसी में चिंताजनक स्थिति की लिस्ट माना जाता है। यह तीन जिले हैं राजसमंद, बीकानेर और चित्तौड़गढ़। इन तीनों जिलों में भंवरलाल, नमृता वृष्णि और आलोक रंजन कलक्टर हैं। इनमें से भंवरलाल 13 घंटे 22 मिनट, नमृता 15 घंटे 2 मिनट और रंजन 22 घंटे 22 मिनट का समय लेकर एक फाइल निपटा रहे हैं। रेंकिंग में पता चला है कि नवगठित जिलों में तैनात कलक्टर सबसे तेज गति में फाइलों का निपटारा कर रहे हैं। सलूंबर कलक्टर सबसे तेज हैं, वे अपने कार्यालय में आने वाली एक फाइल 11 मिनट में निपटा रहे हैं। टॉप-10 जिलों में पहली बार बनने वाले 7 जिले सलूंबर, शाहपुरा, ब्यावर, केकड़ी, सांचौर, गंगापुर सिटी और खैरथल-तिजारा शामिल हैं। इनमें से भी तीन जिले सलूंबर, शाहपुरा और सांचौर लगातार टॉप-1, 2, 3 स्थान पर है। ये प्रयास अपने आप में अनूठा प्रयास है लेकिन इससे प्रशासनिक हलके में कितना सुधार हो पाएगा ये बड़ा सवाल है। जिला कलक्टरों को तो आप सुधार लेंगे। रेड लिस्ट में ले लिया। उनको शोकॉज नोटिस भी दे देंगे लेकिन क्या इन सबसे उनके काम में सुधार होगा। रेंकिंग जारी होने के बाद सबसे पहले रेड लिस्ट में शामिल तीनों जिलों के कलक्टरों को बदलना चाहिए और उन्हें ऐसी पोस्ट पर पोस्टिंग देनी चाहिए जो ठंड की पोस्ट को ताकि दूसरे जिला कलक्टरों को सबक मिले और जनता के कामों को तुरन्त प्रभाव से निपटाए। इसके अलावा निचले स्तर के कर्मचारियों पर भी फाइल निपटाने के लिए समय सीमा तय होनी चाहिए।

गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान से कर्जदाताओं ने भी मुहं मोड़ा

कर्ज का यह जंजाल अभी और गहरा हो गया जब पाकिस्तान ने आईएमएफ से एक और बेलआउट पैकेज मांगा था। साथ ही देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल भी नहीं आ पा रहा था। हाल ही में हुए आम चुनाव में देश में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला. ऐसे में पाकिस्तान इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मोर्चे पर असफल होता दिखाई दे रहा है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, यह स्थिति बनने की सबसे बड़ी वजह बाहरी कर्ज और ब्याज के पेमेंट हैं. आईएमएफ , एफडीआई और अन्य जगहों से मिले कर्ज 26.17 फीसदी बढ़कर 33.611 ट्रिलियन रुपये हो गए हैं। सिर्फ आईएमएफ का कर्ज ही 24.17 फीसदी बढ़कर 2.142 ट्रिलियन रुपये पहुंच गया है ।

अशोक भाटिया

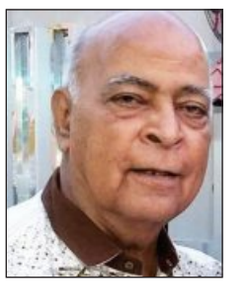

गले तक कर्ज में डूबे और सातवें आसमान पर पहुंच चुकी महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। अब उसे और कर्ज मिलने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी चरमरा चुकी है. मुल्क पर कर्ज के कुचक्र में फंस चुका है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जानकारी के अनुसार उसका कुल कर्ज और देनदारी दिसंबर, 2023 तक 27.2 फीसदी बढ़कर 81.2 ट्रिलियन रुपये (131 अरब डॉलर) पहुंच गई है. पिछले एक साल में ही देश पर कर्ज 17.4 ट्रिलियन रुपये की वृद्धि हुई है. पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 63.83 ट्रिलियन रुपये था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी कहा है कि पाकिस्तान को कर्ज चुकाने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही वैश्विक वित्तीय निकाय ने नकदी की कमी से जूझ रहे देश की कर्ज चुकाने की क्षमता पर संदेह किया जा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में शनिवार को यह जानकारी दी गई। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में वाशिंगटन बेस्ड बैंक का आकलन ऐसे वक्त में आया है, जब आईएमएफ सहायता दल शुक्रवार को पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए पहुंचा है।

इस्लामाबाद ने विस्तारित फंड सुविधा के तहत नए राहत पैकेज का अनुरोध किया था। आईएमएफ का दल इस अनुरोध पर चर्चा के लिए आया है। जियो न्यूज ने इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान पर जारी अपनी स्टाफ रिपोर्ट में आईएमएफ के हवाले से कहा कि कर्ज चुकाने की पाकिस्तान की क्षमता गंभीर जोखिमों के अधीन है और यह नीतियों को लागू करने तथा समय पर बाहरी फंडिंग पर निर्भर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विशेष रूप से सुधारों को अपनाने में देरी, उच्च सार्वजनिक ऋण और सकल वित्त पोषण की जरूरतें और सामाजिक-राजनीतिक कारक - नीति कार्यान्वयन को खतरे में डाल सकते हैं।

आईएमएफ स्टाफ रिपोर्ट में कहा गया, डाइनसाइड रिस्क असाधारण रूप से ऊंची बनी हुई है। जबकि नई सरकार ने स्टैंडबाय अरेंजमेंट पॉलिसीज को जारी रखने के अपने इरादे का संकेत दिया है। वहां राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। यह अनिश्चितता पॉलिसी मेकिंग पर गहरा असर डाल सकती है, खासकर जीवनयापन की ऊंची लागत और अन्य राजनीतिक जटिलताओं को देखते हुए। इसमें चेतावनी दी गई है कि यह अनिश्चितता पॉलिसी मेकिंग पर गहरा असर डाल सकती है, खासकर जीवनयापन की ऊंची लागत और अन्य राजनीतिक जटिलताओं को देखते हुए। जियो न्यूज ने पाकिस्तान पर इस महीने की शुरुआत में जारी अपनी स्टाफ रिपोर्ट में वाशिंगटन स्थित ऋणदाता के हवाले से कहा है कि फंड चुकाने की पाकिस्तान की क्षमता महत्वपूर्ण जोखिमों के अधीन है और नीति कार्यान्वयन और समय पर बाहरी वित्तपोषण पर गंभीर रूप से निर्भर है। असाधारण रूप से उच्च जोखिम - विशेष रूप से सुधारों को अपनाने में देरी, उच्च सार्वजनिक ऋण और सकल वित्तपोषण की जरूरतें, कम सकल भंडार और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) की शुद्ध एफएक्स व्युत्पन्न स्थिति, प्रवाह में गिरावट और सामाजिक-राजनीतिक कारक - नीति कार्यान्वयन को खतरे में डाल सकते हैं। और पुनर्भुगतान क्षमता और ऋण स्थिरता को नष्ट कर देता है ऐसा रिपोर्ट में कहा गया इसमें आगे कहा गया है कि पाकिस्तान की फंड चुकाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए बाहरी व्यवहार्यता बहाल करना महत्वपूर्ण है, और यह मजबूत नीति कार्यान्वयन पर निर्भर करता है, जिसमें बाहरी संपत्ति संचय और विनिमय दर लचीलापन शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि भू-राजनीतिक अस्थिरता जोखिम का एक अतिरिक्त स्रोत है, भले ही पिछली समीक्षा के बाद से वैश्विक वित्तीय स्थितियों को लेकर अनिश्चितता में कुछ हद तक गिरावट आई है।वैश्विक ऋणदाता ने कहा कि देश को अगले पांच वर्षों के दौरान 123 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल वित्तपोषण की आवश्यकता है, साथ ही कहा कि पाकिस्तान को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2025-26 में 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग करने की उम्मीद है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि संकटग्रस्त देश को 2026-27 में 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 2027-28 में 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2028-29 में 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उम्मीद है।मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, वैश्विक ऋणदाता की एक सहायता टीम देश की वित्तीय टीम के साथ अगले दीर्घकालिक ऋण कार्यक्रम के पहले चरण पर चर्चा करेगी।सूत्रों ने कहा कि अग्रिम दल बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंच चुका है जबकि आईएमएफ मिशन 16 मई को पहुंचेगा। टीम विभिन्न विभागों से डेटा प्राप्त करेगी और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ वित्तीय वर्ष 2025 (एफवाई2025) के आगामी बजट पर चर्चा करेगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि टीम 10 दिनों से अधिक समय तक पाकिस्तान में रहेगी।पाकिस्तान ने जलवायु वित्तपोषण के माध्यम से वृद्धि की संभावना के साथ ईईएफ के तहत तीन वर्षों के लिए 6 और 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अगले बेलआउट पैकेज की मांग की थी । आईएमएफ के एक बयान में पहले कहा गया था, अब सुधारों में तेजी लाना कार्यक्रम के आकार से अधिक महत्वपूर्ण है, जो सुधार के पैकेज और भुगतान संतुलन की जरूरतों द्वारा निर्देशित होगा। इस बीच, पाकिस्तान ने अपने बाहरी वित्तपोषण में 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारी अंतर को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में चीन जैसे प्रमुख सहयोगियों से लगभग 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लेने का फैसला किया है क्योंकि संघीय सरकार का लक्ष्य बजट लक्ष्यों को प्राप्त करना है। आईएमएफ टीम के देश में अपेक्षित आगमन से पहले ।वित्त मंत्रालय के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, सऊदी अरब से 5 अरब अमेरिकी डॉलर, संयुक्त अरब अमीरात से 3 अरब अमेरिकी डॉलर और चीन से 4 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद ली जाएगी, साथ ही कहा गया है कि अगले वित्तीय वर्ष में चीन से और नए वित्तपोषण का अनुमान भी शामिल किया जाएगा। पर यह मिलेगा कि नहीं इस बात पर अब शंका जताई जा रही है ।

पाकिस्तान को नए ऋण कार्यक्रम के तहत आईएमएफ से 1 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक प्राप्त होना था जबकि विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से नए वित्तपोषण को भी अनुमानित बजट में शामिल किया गया था । ज्ञात हो कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और एक करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का यह अनुमान 1.8 प्रतिशत की सुस्त आर्थिक वृद्धि दर के साथ बढ़ती महंगाई पर आधारित है, जो चालू वित्त वर्ष में 26 प्रतिशत पर पहुंच गयी है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान तीन साल तक घाटे में रह सकता है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि करीब 9.8 करोड़ पाकिस्तानी पहले से ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। वही, गरीबी की दर लगभग 40 प्रतिशत पर बनी हुई है। गरीबी रेखा के ठीक ऊपर रह रहे लोगों के भी नीचे आने का जोखिम है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पाकिस्तान में महंगाई दर 30 फीसदी से ऊपर थी।

आज का इतिहास

13 मई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- चिली में 1643 में आए विनाशकारी भूकंप में सेंटियागो की एक तिहाई आबादी खत्म हुई।
- दिल्ली में लाल किले का निर्माण 1648 में पूरा हुआ।
- इक्वेडोर गणराज्य की 1830 में स्थापना।
- भारत ने 1918 में राजस्थान के पोखरण में दो परमाणु परीक्षण किये।
- स्वतंत्र भारत की पहली संसद का सत्र 1952 में शुरू हुई।
- जार्डन और इराक ने 1958 में अरब फैडरेशन की स्थापना की।
- देश का पहला ध्वजवाहक जहाज 1978 में आईएनएस दिल्ली सेवामुक्त हुआ।
- चीन में लगभग 2000 छात्रों ने थियान अन मन चौक पर भूख हड़ताल 1989 में शुरू की।
- चेल्सी स्मिथ मिस यूनिवर्स 1995 बनीं।
- भारत ने पोखरण में दो परमाणु परीक्षण 1998 में किए।
- अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1998 में परमाणु परीक्षण के विरोध में भारत के ख़िलाफ़ कड़े प्रतिबंध की घोषणा की।
- जापान ने 1998 में भारत को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगायी।
- जापानी छात्र के नागुयी 1999 में विश्व की सात सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र (25 वर्षीय) का पर्वतारोही बना।
- मिस इंडिया लारा दत्ता ने 2000 में साइप्रस में सम्पन्न प्रतियोगिता में मिस यूनीवर्स का ख़िताब जीता।
- रियाद में 2003 को आत्मघाती हमलों में 29 व्यक्ति मारे गये।
- पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के सभी नौ मंत्रियों ने जजों की बहाली के मुद्दे पर इस्तीफ़ा 2008 में दिया।
- भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता इला भट्ट को 2010 के निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित 2010 में किया गया।
- दुनियाभर में वॉनाक्राय रैनसमवेयर से 100 से अधिक देश प्रभावित 2017 में रहा।

13 मई को जन्मे व्यक्ति

- स्वतंत्रता सेनानी मथुरा प्रसाद मिश्र वैद्य का जन्म 1901 में हुआ।
- भारत के पांचवे राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली अहमद का जन्म 1905 में हुआ।
- हिंदी फ़िल्मों के हास्य अभिनेता असित सेन का जन्म 1917 में हुआ।
- 'भरतनाट्यम' की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना टी. बालासरस्वती का जन्म 1918 में हुआ।
- अमेरिकी हास्य अभिनेत्री (मौड ऐंड गोल्डन गर्ल्स) बीट्रिस आर्थर का जन्म 1922 में हुआ।
- मध्य प्रदेश सरकार में 'भारतीय जनता पार्टी' के राजनेता कैलाश विजयवर्गीय का जन्म 1956 में हुआ।
- आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना करने वाले आध्यात्मिक नेता श्री श्री रवि शंकर का जन्म 1956 में हुआ।

13 मई को हुए निधन

- मध्यकालीन भारत के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ मलिक अम्बर का निधन 1626 में हुआ।
- लखनऊ के प्रसिद्ध शायर हसरत मुहानी का निधन 1951 में हुआ।
- अंग्रेज़ी में लिखने वाले उत्कृष्ट भारतीय लेखकों में से एक आर. के. नारायण का निधन 2001 में हुआ।

विशेष आलेख

भारत में अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक असंतुलन चिंताजनक

हृदयनारायण दीक्षित।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने मुस्लिम संख्या वृद्धि के तथ्य उद्घाटित किए हैं। सलाहकार परिषद स्वतंत्र निकाय है। यह समय-समय पर तथ्य व आंकड़ों के आधार पर भिन्न-भिन्न विषयों पर परामर्श देती है। परिषद ने दुनिया के 167 देशों के जनसांख्यकीय चरित्र का अध्ययन किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के किसी भी देश में बहुसंख्यक आबादी की बढ़त नहीं दिखाई पड़ी है लेकिन कई देशों में अल्पसंख्यक आबादी की बढ़त पाई गई है। भारत में मुस्लिम आबादी की संख्या बढ़ी है। मुस्लिम संख्या वृद्धि के ताजा आंकड़ों को लेकर देश में खासी बहस चल रही है।

भारत में हिन्दू-मुस्लिम सहअस्तित्व सामाजिक पुनर्गठन की बड़ी चुनौती रहा है। गांधी जी ने हिन्दू-मुस्लिम सहअस्तित्व के लिए आजीवन काम किया और अंत में कहा कि इस प्रश्न पर मेरी हार हुई। मुस्लिम राजनीति अन्य पंथों पर आक्रामक रही है। मुस्लिम साम्प्रदायिकता के कारण ही भारत का विभाजन हुआ था। गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना से पाकिस्तान की मांग न करने और साथ-साथ रहने का आग्रह किया था। इस सम्बंध में उन्होंने जिन्ना को (15 सितंबर 1944) पत्र लिखा था। उन्होंने जिन्ना से पूछा था कि, मजहब के अलावा हिन्दू और मुसलमान में क्या कोई और भी भेद है? मुसलमान शेष भारतवासियों से क्यों अलग हैं? जिन्ना ने जवाबी पत्र (17 दिसम्बर 1944) में लिखा था, हम मानते हैं कि मुसलमान और हिन्दू देश की किसी भी परिभाषा के आधार पर अलग-अलग कौमें हैं। हमारी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, साहित्य, कला, कानून, परम्परा व इतिहास अलग-अलग है। जीवन के प्रति हमारा नजरिया भी अलग है। हम किसी भी अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर अलग राष्ट्र हैं। यह मुस्लिम लीग और जिन्ना का घोर साम्प्रदायिक दृष्टिकोण था। इस साम्प्रदायिकता के दृष्टिकोण को माने तो हिन्दू-मुसलमान जब मिलकर रहते थे, तब भी मुसलमान अलग राष्ट्र थे। भारत के भीतर दो राष्ट्र थे। यह सोच अलगाववादी थी। वस्तुत: भारत प्राचीन काल से ही एक संस्कृति आधारित राष्ट्र है। साम्प्रदायिक राजनीति स्वयं को अलग राष्ट्र मानती रही है। मजहब आधारित जनसंख्या में बढ़त इसीलिए चिन्ता का विषय है। मजहब के आधार पर अलग राष्ट्र की मांग करना, इसके लिए लाखों लोगों की हत्या हिंसा किसी भी सूरत में उचित नहीं हो सकता। यह मानवता के विरुद्ध अपराध है। जनसंख्या के आधार पर ही मुस्लिम लीग ने अलग देश मांगा। भयंकर रक्तपात हुआ। इसलिए साम्प्रदायिक आबादी की बढ़त की कोई भी सूचना देश को चिन्ता में डाल देती है। आंकड़ों के निष्कर्ष सत्य के उद्घाटन के लिए पर्याप्त हैं। अविभाजित भारत की अंतिम जनगणना 1941 में हुई थी। तब हिन्दू आबादी 84.44 प्रतिशत थी और मुस्लिम 13.38 प्रतिशत थे। मुसलमानों की इस संख्या में आज के पाकिस्तान और बांग्लादेशी मुस्लिम भी सम्मिलित थे। फिर देश का बंटवारा हुआ। भारत स्वतंत्र हुआ। कुल मुस्लिम आबादी की संख्या में पाकिस्तानी व बांग्लादेशी मुस्लिम जनसंख्या घट गई। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई। तब पाकिस्तानी व बांग्लादेशी मुस्लिम जनसंख्या नहीं रही। इसलिए हिन्दू जनसंख्या का अनुपात 87.24 हो गया। मुस्लिम आबादी घटकर 10.43 हो गई। लेकिन 50 वर्ष बाद 2001 की जनगणना में हिन्दू घटकर 84.21 प्रतिशत हो गए। मुस्लिम आबादी का अनुपात अविभाजित भारत के 13.38 प्रतिशत से भी ज्यादा हो गया। आबादी के इसी अनुपात पर मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग की थी और पाकिस्तान अस्तित्व में आया था। इस तरह की जनसंख्या बढ़त से एक और मजहबी साम्प्रदायिक देश की जनसंख्या तैयार हो गई है।

साम्प्रदायिक राजनीति आर्थिक नीतियों से जुड़े गरीबी-अमीरी, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि मूलभूत प्रश्नों को महत्व नहीं देती। वे राजनीति में भी कट्टरपंथी मजहबी अलगाववाद चलाते हैं। साम्प्रदायिक अलगाववादी जिस देश में रहते हैं, उस देश की संवैधानिक व्यवस्था से भी टकराते हैं। राजनीति वोट बैंक के तुष्टीकरण के कार्यक्रम बनाती है। कट्टरपंथी मजहबी राजनीति की मांगें खतरनाक हैं। वे तुष्टीकरण की साम्प्रदायिक राजनीति को सेकुलर कहते हैं। वस्तुत: सेकुलर विचार में आस्था और अंधविश्वास नहीं होने चाहिए। मजहबी राजनीति सेकुलर हो ही नहीं सकती। इस्लामी विचारधारा के अंतरराष्ट्रीय विद्वान प्रोफेसर डेनियल पाइप के अनुसार, दूसरे पंथों के विपरीत इस्लाम में सामाजिक जीवन के परिचालन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। दूसरे पंथ केवल मौलिक मूल्यों के ही उपदेश देते हैं और भौतिक विषयों पर समय अनुसार विधान और नियम बनाने का काम समाज पर छोड़ देते हैं। इस्लामी राजनैतिक चिन्तन सुस्पष्ट ध्येय निर्धारित करता है। सभी मुसलमानों को इन नियमों का पालन अनिवार्य है। दूसरे पंथों में राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए लिखित आदेश नहीं है। मुस्लिम विश्वास में ईश्वर पर विश्वास के साथ ही उनके पवित्र कानून भी हैं। यह कानून 'शरिया' कहा जाता है। यह राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करता है। इस्लामी राजनीति में मजहब की प्रचंड प्रेरणा है। गांधी जी हिन्दू-मुसलमान की साझा राष्ट्रीयता चाहते थे। वे असफल रहे। डॉक्टर आम्बेडकर हिन्दू-मुसलमान के पक्ष पर गांधी जी से असहमत थे। डॉ. आम्बेडकर ने लिखा है, गजनी के मोहम्मद ने भारत पर अपने अनेक हमलों को जेहाद छेड़ने की संज्ञा दी थी। मोहम्मद के इतिहासकार अल उतबी ने उसके हमले के बारे में लिखा था, उसने मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा और इस्लाम की स्थापना की। उसने शहरों पर कब्जा किया, नापाक कमीनों को मार डाला। मूर्ति पूजकों को तबाह किया और मुसलमानों को गौरवान्वित किया।

पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन, क्या आजादी का समय आ गया है?

रामस्वरूप रावतसरे

कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान की हालत चिंताजनक हो गई है। वहाँ दैनिक उपयोग की चीजों की कीमत आसमान छू रही थी, जिसके कारण वहाँ गृहयुद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में महंगाई को लेकर हो रहा प्रदर्शन हिंसक हो गया। उसके बाद कुछ पुलिसकर्मियों की मॉब लिंचिंग हो गई। प्रदर्शन के दौरान आजादी के नारे भी जमकर लगे। दरअसल, खस्ताहाल पाकिस्तान में महंगाई के कारण रोजमर्रा की चीजें नहीं मिल रही हैं। बिजली बिल आसमान छू रहे हैं। सरकार द्वारा अधिक कर लगाया जा रहा है। इसको लेकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों ने आवामी ऐक्शन कमिटी नाम के संगठन के नेतृत्व में शुक्रवार (11 मई 2023) को मुजफ्फराबाद में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। इस विरोध प्रदर्शन के समर्थन में इलाके के लोगों ने दुकानें बंद कर दी और सड़कों को जाम कर दिया। इसको पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दमन करना शुरू कर दिया। पुलिस ने मस्जिदों और लोगों के आसपास आँसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने स्थानीय नेताओं के घरों पर छापेमारी करके उन्हें गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इसके बाद लोग भड़क उठे। देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया। इस दौरान पुलिस ने हवा में गोलियाँ भी चलाईं। वहीं, प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। कुछ पुलिसकर्मियों को भीड़ ने लिंचिंग कर दी। इसके कई वीडियो भी सामने आए हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है को लोग लाठी डंडों से पुलिस वालों को पीट रहे हैं और जमीन पर पुलिसकर्मी खुद को बचाने का प्रयास कर रहा है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, पीओके कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी कर रही है और झड़पों में कम से कम दो लोग मारे गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हिंसा में एक पुलिस की मौत हो गई, जिसे कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों ने पीट-पीटकर मार डाला। मिर्जा ने भारत सरकार से हस्तक्षेप करने की माँग करते हुए कहा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है और केंद्र इससे अलग नहीं रह सकता। उन्होंने कहा, फ़स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। यह वास्तव में पहले से ही हाथ से बाहर है। भारत को अब अपना सारा ध्यान पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर पर केंद्रित करना चाहिए और गिलगित-बाल्टिस्तान सहित इस कब्जे वाले क्षेत्र की स्वतंत्रता में मदद करनी चाहिए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार (11 मई 2024) को कहा कि अगर भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की फिर से सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेगा। उन्होंने कहा पीओके भारत का है और भारत उसे हर कीमत पर वापस लेगा।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारम्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें सताए और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष

किसी तरह का आर्थिक लाभ भी हो सकता है। हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर उतार-चढ़ाव बना रहेगा। गृह एवं संतान सम्बंधी शुभ समाचार आप को मिलेंगे। पुराने और बचपन के दोस्तों से मुलाकात हो सकती है।

वृष

मित्रों का सहयोग भी आप को प्राप्त होगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए निरर्थक वाद-विवाद न करें। धन और प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। आप की रचनात्मकता में सकारात्मक वृद्धि होगी।

मिथुन

सुबह का समय दोस्तों के साथ घूमने-फिरने, खान-पान एवं मनोरंजन में बीत सकता है। पार्टनरशिप काम में ध्यान रखें। व्यापार में ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं है। दोपहर के बाद आप को प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है।

कर्क

आज वाणी पर संयम रखें. स्नेहीजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा। किसी उलझन में दिन गुजरेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। आप नए काम का आरंभ कर सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है।

सिंह

व्यापार में किसी तरह का लाभ होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पूंजी निवेश में सावधानी बरतें। धार्मिक काम के पीछे धन खर्च हो सकता है। कोर्ट-कचहरी के विषय में संभलकर चलें।

कन्या

स्वभाव में उग्रता हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। दोपहर के बाद आप आप मनोरंजन की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। मित्रों और स्नेहीजनों के साथ प्रवास या पर्यटन का योग है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रह पाएंगे। स्नेहीजनों के साथ घनिष्ठता बढ़ेगी।

तुला

अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखना आपके ही हित में रहेगा। आज आपकी नौकरी और व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा। संतान की चिंता आपको हो सकती है।

वृश्चिक

आज के दिन बौद्धिक काम, नए सृजन और साहित्यिक गतिविधि में आप उलझे रहेंगे। किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है। व्यापार में लाभ का अवसर मिलेगा। आज आपको कार्यालय और व्यापार में थोड़ा संभलकर चलना होगा।

धनु

मानसिक रूप से आप में भावुकता की मात्रा अधिक रहेगी। किसी बात को लेकर ज्यादा विचलित ना हों। अपनी कल्पनाशक्ति से साहित्य-सृजन में आप नवीनता ला पाएंगे। सुख-शांति बनी रहेगी। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी।

मकर

दवाई खरीदने या अस्पताल की फीस पर आकस्मिक खर्च हो सकता है। आज दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ हर काम को आसानी से बना पाएंगे। गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।

कुंभ

स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोपहर के बाद पारिवारिक जीवन में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा। आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। पिता से आपको लाभ होगा। ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बनी रहेगी।

मीन

आज का आपका दिन लाभकारी है। पारिवारिक और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर-परिवार में आनंद का वातावरण आप को खुश रखेगा। बहुत दिनों से अटके सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। दोस्तों के साथ मुलाकात होगी।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हमीदपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतीक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान*। प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 92140488888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

देश में भ्रष्टाचार का खंड बन गया है झारखंड

गैरभाजपा राजनीतिक दलों के लिए देश में व्याप्त भ्रष्टाचार कोई चुनावी मुद्दा नहीं रह गया है। यही वजह है कि खासतौर से क्षेत्रीय दलों की सरकारों में बेशर्मी से लूटने की होड़ मची हुई है। झारखंड में एक मंत्री के निजी सहायक के नौकर के घर से मिले करीब 35 करोड़ रुपए मिलने पर किसी भी दल ने कठोर कार्रवाई की मांग तो दूर बल्कि इस भारी-भरकम भ्रष्टाचार के लिए अफसोस तक जाहिर नहीं किया। यह पहला मौका नहीं है जब इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की असलियत उजागर हुई हो। इससे पहले भी असीम सुर्खियों में रहे भ्रष्टाचार के मामलों में क्षेत्रीय दलों की सत्तारूढ़ सरकारों के काले कारनामे सामने आ चुके हैं।

भ्रष्टाचार के मामले सामने आने पर क्षेत्रीय दलों का प्रयास यही रहता रहा है कि इसे केंद्र की भाजपा सरकार की साजिश करार दिया जाए। कांग्रेस ने इन दलों के भ्रष्टाचार के मामलों में संरक्षक की भूमिका निभाई है। कारण स्पष्ट है यदि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के भ्रष्टाचार के मामले उठाती है तो उसे अपनी गिरेबां में भी झाकना होगा। इससे ये दल एक-दूसरे के भ्रष्टाचार के मामलों में छिछालेदार करने लगेंगे। ऐसी हास्यादपद स्थिति से बचने के लिए ये दल एक-दूसरे के भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं करते हैं। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मामलों में मौन साधे रखा है। यहां तक की कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार का जिक्र तक करना जरूरी नहीं समझा। कांग्रेस को अंदाजा था कि इसका जिक्र करते ही भाजपा गठबंधन खिल्ली उड़ाने से चूकेगा नहीं। यही वजह रही कि कांग्रेस घोषणा पत्र में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खात्मे को लेकर कोई वादा नहीं किया। आश्चर्य यह है कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू सहयोगी जहांगीर के यहां छापा मार कर प्रवर्तन निदेशालय ने 35 करोड़ रुपए बरामद किए। इस पर भी मंत्री आलम ने त्याग पत्र देना जरूरी नहीं समझा। झारखंड में सत्ता में शामिल कांग्रेस ने आलम के इस्तीफे की मांग तक नहीं की। अलबत्ता कांग्रेस ने इससे अपना दामन बचाने की कोशिश जरूर की। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में आयोजित राहुल गांधी की सभा में मंच पर कांग्रेस कोटे से ग्रामीण विकास मंत्री बने आलमगीर आलम को जगह नहीं मिली। कांग्रेस ने आलमगीर को महज यह संदेश देकर औपचारिकता निभाई की पहले जांच से बरी होकर आओ। इससे पहले झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन भी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। सोरेन को जमानत नहीं मिल सकी है। पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन 6 अक्टूबर 2023 को नई हेमंत सोरेन को कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जैसा कि अक्सर होता है हर भ्रष्टाचारी ऐसे मामलों को फसाने की साजिश करार देता है, इसी तर्ज पर सोरेन ने भी आरोप से इनकार किया। कांग्रेस ने सोरेन की गिरफ्तारी की निंदा की और इसे संघवाद के लिए झटका बताया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा था कि भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा लोकतंत्र को नष्ट करने का अभियान चला रही है।

कांग्रेस यह भूल गई कि पिछले साल दिसंबर में भी झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स ने 350 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश बरामद किया था। इस पर साहू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि छापेमारी में जो कैश बरामद किया गया है, वो मेरी शराब की कंपनियों का है। शराब का कारोबार नकदी में ही होता है और इसका कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से 290 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश मिला था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साहू से जुड़े ओडिशा और झारखंड के उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान विभाग को अलमारी में करोड़ों रुपये भरे हुए मिले। धीरज साहू के पास कितना कैश बरामद हुआ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगातार तीन दिन छापेमारी करने पर नोट गिनने पड़े। आलम ये रहा है कि नोट गिनने के लिए लाई गई मशीनों की क्षमता कम पड़ गई। नोट गिनने के लिए तीन दर्जन मशीनों को मंगाया गया था, जो कम पड़ गई। पीएम मोदी ने ओडिशा की रैली में किया नकद बरामदगी का जिक्र चुनाव प्रचार के लिए ओडिशा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नकद बरामदगी का जिक्र भी किया। उन्होंने केंद्र द्वारा जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर विपक्ष के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि पड़ोसी राज्य झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। मोदी ने कहा कि अब आप ही बताइए, अगर मैं उनकी चोरी, उनकी कमाई, उनकी लूट बंद कर दूं, तो क्या वे मोदी को गाली देंगे या नहीं? गालियों के बावजूद, क्या मुझे आपका पैसा नहीं बचाना चाहिए। झारखंड और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ है। संयुक्त बिहार में ही झारखंड मे हुए चारा घोटाले से शुरू हुई थी और बड़े भ्रष्टाचार की कहानी आज भी बदस्तूर जारी है। चारा घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आया था। इस घोटाले में पशुओं के चारे की चोरी की गई। 950 करोड़ के इस घोटाले मे 53 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि कुल 170 आरोपी बने गए थे। इस मामले का खुलासा 1996 में हुआ था। इसके बाद मधु कोड़ा के मुख्यमंत्री काल मे शैल कंपनियों के जरिए काली कमाई को सफेद करने का मामला सामने आया। करीब 4 हजार करोड़ का ये घोटाले अपने आप मे देशभर के बड़े घोटालों में से एक था। आज भी मामला अदालत मे है। मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद जेल भी जाना पड़ा था। अलग झारखंड राज्य की मांग को अटल बिहारी वाजपेयी की तत्कालीन सरकार ने वर्ष 2000 में पूरा तो कर दिया था। लेकिन जिस मकसद से अलग राज्य की मांग हो रही थी, वह मकसद पीछे छूट गया। झारखंड में लूट का सिलसिला शुरू हो गया। बिहार से अलग झारखंड बनाने की मांग इसलिए हो रही थी कि इसका समुचित विकास अपने ही संसाधनों से सुचारू ढंग से हो पाएगा। इसकी झलक भी पहले बजट में दिखी थी। राज्य सरकार का शुरुआती बजट सरप्लस था। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद जिस विकास और खुशहाली का सपना लोगों ने देखा था, वह तो पूरा नहीं हुआ, उल्टे यहां लूट की संस्कृति दिन प्रतिदिन मजबूत होती गई। हाल के तीन साल में जिस तरह नौकरशाहों और नेताओं के घर से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को तीन नोटों का जखीरा बरामद करती आ रही है, उससे तो झारखंड का अघोषित नाम लूटखंड हो गया है। गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी तीन दक्षिणी राज्यों तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की भी जांच कर रही है। सभी नेताओं ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। क्षेत्रीय दल चाहे झारखंड का हो, दिल्ली, तमिलनाडु, या फिर पश्चिम बंगाल के, सब आकंठ तक भ्रष्टाचार के मामलों में डूबे हुए हैं। इन राज्यों के विपक्षी दलों के करीब एक दर्जन नेता जेलों में बंद हैं। इनमें से ज्यादातर की जमानत तक नहीं हो सकी है। इसी से विपक्षी दलों का यह आरोप कमजोर पड़ जाता है कि केंद्र में सत्तारुढ़ भाजपा जांच एजेंसियों को दुरुपयोग राजनीतिक रंजिश के कारण कर रही है। अभी तक किसी भी न्यायालय ने नेताओं के भ्रष्टाचार के भी मामले में यह निर्णय नहीं दिया कि केंद्रीय एजेंसियों ने दुर्भावनावश कार्रवाई की है। कांग्रेस इस मुद्दे पर मुंह इसलिए नहीं खोल सकती है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास और वर्तमान भी भ्रष्टाचार के आरोपों से रंगा हुआ है। -योगेन्द्र योगी

गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान से कर्जदाताओं ने भी मुहं मोड़ा!

अशोक भाटिया

गले तक कर्ज में डूबे और सातवें आसमान पर पहुंच चुकी महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। अब उसे और कर्ज मिलने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं क्योकिं पाकिस्तान की इकोनॉमी चरमरा चुकी है. मुल्क पर कर्ज के कुचक्र में फंस चुका है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जानकारी के अनुसार उसका कुल कर्ज और देनदारी दिसंबर, 2023 तक 27.2 फीसदी बढ़कर 81.2 ट्रिलियन रुपये (131 अरब डॉलर) पहुंच गई है. पिछले एक साल में ही देश पर कर्ज 17.4 ट्रिलियन रुपये की वृद्धि हुई है. पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 63.83 ट्रिलियन रुपये था। कर्ज का यह जंजाल अभी और गहरा हो गया जब पाकिस्?तान ने आईएमएफ से एक और बेलआउट पैकेज मांगा था . साथ ही देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल भी नहीं आ पा रहा था . हाल ही में हुए आम चुनाव में देश में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला. ऐसे में पाकिस्तान इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मोर्चे पर असफल होता दिखाई दे रहा है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, यह स्थिति बनने की सबसे बड़ी वजह बाहरी कर्ज और ब्याज के पेमेंट हैं. आईएमएफ , एफडीआई और अन्य जगहों से मिले कर्ज 26.17 फीसदी बढ़कर 33.611 ट्रिलियन रुपये हो गए हैं. सिर्फ आईएमएफ का कर्ज ही 24.17 फीसदी बढ़कर 2.142 ट्रिलियन रुपये पहुंच गया है ।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी कहा है कि पाकिस्तान को कर्ज चुकाने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही वैश्विक वित्तीय निकाय ने नकदी की कमी से जूझ रहे देश की कर्ज चुकाने की क्षमता पर संदेह किया जा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में शनिवार को यह जानकारी दी गई। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में वाशिंगटन बेस्ड बैंक का आकलन ऐसे वक्त में आया है, जब आईएमएफ सहायता दल शुक्रवार को पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए पहुंचा है।

इस्लामाबाद ने विस्तारित फंड सुविधा के तहत नए राहत पैकेज का अनुरोध किया था। आईएमएफ का दल इस अनुरोध पर चर्चा के लिए आया है। जियो न्यूज ने इस महीने की शुरूआत में पाकिस्तान पर जारी अपनी स्टाफ रिपोर्ट में आईएमएफ के हवाले से कहा कि कर्ज चुकाने की पाकिस्तान की क्षमता गंभीर जोखिमों के अधीन है और यह नीतियों को लागू करने तथा समय पर बाहरी फंडिंग पर निर्भर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विशेष रूप से सुधारों को अपनाने में देरी, उच्च सार्वजनिक ऋण और सकल वित्त पोषण की जरूरतें और सामाजिक-राजनीतिक कारक - नीति कार्यान्वयन को खतरे में डाल सकते हैं। आईएमएफ स्टाफ रिपोर्ट में कहा गया, 'डाइनसाइड रिस्क असाधारण रूप से ऊंची बनी हुई है। जबकि नई सरकार ने स्टैंडबाय अरेंजमेंट पॉलिसीज को जारी रखने के अपने इरादे का संकेत दिया है। वहां राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। यह अनिश्चितता पॉलिसी मेकिंग पर गहरा असर डाल सकती है, खासकर जीवनयापन की ऊंची लागत और अन्य राजनीतिक जटिलताओं को देखते हुए।' इसमें चेतावनी दी गई है कि यह अनिश्चितता पॉलिसी मेकिंग पर गहरा असर डाल सकती है, खासकर जीवनयापन की ऊंची लागत और अन्य राजनीतिक जटिलताओं को देखते हुए।

जियो न्यूज ने पाकिस्तान पर इस महीने की शुरूआत में जारी अपनी स्टाफ रिपोर्ट में वाशिंगटन स्थित ऋणदाता के हवाले से कहा है कि फंड चुकाने की पाकिस्तान की क्षमता महत्वपूर्ण जोखिमों के अधीन है और नीति कार्यान्वयन और समय पर बाहरी वित्तपोषण पर गंभीर रूप से निर्भर है।

असाधारण रूप से उच्च जोखिम - विशेष रूप से सुधारों को अपनाने में देरी, उच्च सार्वजनिक ऋण और सकल वित्तपोषण की जरूरतें, कम सकल भंडार और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) की शुद्ध एफएक्स व्युत्पन्न स्थिति, प्रवाह में गिरावट और सामाजिक-राजनीतिक कारक - नीति कार्यान्वयन को खतरे में डाल सकते हैं। और पुनर्भुगतान क्षमता और ऋण स्थिरता को नष्ट कर देता है ऐसा रिपोर्ट में कहा गया ।इसमें आगे कहा गया है कि पाकिस्तान की फंड चुकाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए बाहरी व्यवहार्यता बहाल करना महत्वपूर्ण है, और यह मजबूत नीति कार्यान्वयन पर निर्भर करता है, जिसमें बाहरी संपत्ति संचय और विनिमय दर लचीलापन शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

इसमें यह भी कहा गया है कि भू-राजनीतिक अस्थिरता जोखिम का एक अतिरिक्त स्त्रोत है, भले ही पिछली समीक्षा के बाद से वैश्विक वित्तीय स्थितियों को लेकर अनिश्चितता में कुछ हद तक गिरावट आई है ।वैश्विक ऋणदाता ने कहा कि देश को अगले पांच वर्षों के दौरान 123 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल वित्तपोषण की आवश्यकता है, साथ ही कहा कि पाकिस्तान को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2025-26 में 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग करने की उम्मीद है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि संकटग्रस्त देश को 2026-27 में 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 2027-28 में 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2028-29 में 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उम्मीद है ।मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, वैश्विक ऋणदाता की एक सहायता टीम देश की वित्तीय टीम के साथ अगले दीर्घकालिक ऋण कार्यक्रम के पहले चरण पर चर्चा करेगी ।सूत्रों ने कहा कि अग्रिम दल बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंच चुका है जबकि आईएमएफ मिशन 16 मई को पहुंचेगा।

टीम विभिन्न विभागों से डेटा प्राप्त करेगी और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ वित्तीय वर्ष 2025 (ऋ2025) के आगामी बजट पर चर्चा करेगी ।सूत्रों ने यह भी बताया कि टीम 10 दिनों से अधिक समय तक पाकिस्तान में रहेगी ।पाकिस्तान ने जलवायु वित्तपोषण के माध्यम से वृद्धि की संभावना के साथ ईईएफ के तहत तीन वर्षों के लिए 6 और 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अगले बेलआउट पैकेज की मांग की थी ।

आईएमएफ के एक बयान में पहले कहा गया था, ₹अब सुधारों में तेजी लाना कार्यक्रम के आकार से अधिक महत्वपूर्ण है, जो सुधार के पैकेज और भुगतान संतुलन की जरूरतों द्वारा निर्देशित होगा ।₹इस बीच, पाकिस्तान ने अपने बाहरी वित्तपोषण में 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारी अंतर को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में चीन जैसे प्रमुख सहयोगियों से लगभग 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लेने का फैसला किया है क्योंकि संघीय सरकार का लक्ष्य बजट लक्ष्यों को प्राप्त करना है। आईएमएफ टीम के देश में अपेक्षित आगमन से पहले ।वित्त मंत्रालय के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, सऊदी अरब से 5 अरब अमेरिकी डॉलर, संयुक्त अरब अमीरात से 3 अरब अमेरिकी डॉलर और चीन से 4 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद ली जाएगी, साथ ही कहा गया है कि अगले वित्तीय वर्ष में चीन से और नए वित्तपोषण का अनुमान भी शामिल किया जाएगा। पर यह मिलेगा कि नहीं इस बात पर अब शंका जताई जा रही है।

पाकिस्तान को नए ऋण कार्यक्रम के तहत आईएमएफ से 1 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक प्राप्त होना था जबकि विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से नए वित्तपोषण को भी अनुमानित बजट में शामिल किया गया था ।

ज्ञात हो कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और एक करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का यह अनुमान 1.8 प्रतिशत की सुस्त आर्थिक वृद्धि दर के साथ बढ़ती महंगाई पर आधारित है, जो चालू वित्त वर्ष में 26 प्रतिशत पर पहुंच गयी है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान तीन साल तक घाटे में रह सकता है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि करीब 9.8 करोड़ पाकिस्तानी पहले से ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। वही, गरीबी की दर लगभग 40 प्रतिशत पर बनी हुई है। गरीबी रेखा के ठीक ऊपर रह रहे लोगों के भी नीचे आने का जोखिम है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पाकिस्तान में महंगाई दर 30 फीसदी से ऊपर थी।

मनुष्य के कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले भगवान चित्रगुप्त

हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष चौबीस एकादशियाँ होती हैं। जब अधिकमास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन ही यह त्यौहार भी मनाया जाता है। यह खासकर कायस्थ वर्ग में अधिक प्रचलित है। उनके ईष्ट देवता ही चित्रगुप्त जी हैं। जो भी प्राणी धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है क्योकि यही विधि का विधान है। विधि के इस विधान से स्वयं भगवान भी नहीं बच पाये और मृत्यु की गोद में उन्हें भी सोना पड़ा। चाहे भगवान राम हों, कृष्ण हों, बुध और जैन सभी को निश्चित समय पर पृथ्वी लोक आ त्याग करना पड़ता है। मृत्युपरान्त क्या होता है और जीवन से पहले क्या है यह एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई नहीं सुलझा सकता। लेकिन जैसा कि हमारे वेदों एवं पुराणों में लिखा और ऋषि मुनियों ने कहा है उसके अनुसार इस मृत्युलोक के ऊपर एक दिव्य लोक है जहां न जीवन का हर्ष है और न मृत्यु का शोक वह लोक जीवन मृत्यु से परे है। इस दिव्य लोक में देवताओं का निवास है और फिर उनसे भी ऊपर विष्णु लोक, ब्रह्मलोक और शिवलोक है। जीवात्मा जब अपने प्राप्त शरीर के कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों को जाता है। जो जीवात्मा विष्णु लोक, ब्रह्मलोक और शिवलोक में स्थान पा जाता है उन्हें जीवन चक्र में आवागमन यानी जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है और वे ब्रह्म में विलीन हो जाता हैं अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलकर परमलक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जो जीवात्मा कर्म बंधन में फंसकर पाप कर्म से दूषित हो जाता हैं उन्हें यमलोक जाना पड़ता है। मृत्यु काल में इन्हे आपने साथ ले जाने के लिए यमलोक से यमदूत आते हैं जिन्हें देखकर ये जीवात्मा कांप उठता है रोने लगता है परंतु दूत बड़ी निर्ममता से उन्हें बांध कर घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। इन आत्माओं को यमदूत भयंकर कष्ट देते हैं और ले जाकर यमराज के समक्ष खड़ा कर देते हैं। इसी प्रकार की बहुत सी बातें गरूड़ पुराण में वर्णित है। यमराज के दरवार में उस जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा होता है। कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान हैं चित्रगुप्त। यही भगवान चित्रगुप्त जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त जीवों के सभी कर्मों को अपनी पुस्तक में लिखते रहते हैं और जब जीवात्मा मृत्यु के पश्चातयमराज के समझ पहुचता है तो उनके कर्मों को एक एक कर सुनाते हैं और उन्हें अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नर्क में भेज देते हैं। भगवान चित्रगुप्त परमपिता ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं और यमराज के सहयोगी हैं। इनकी कथा इस प्रकार है कि सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से जब भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से सृष्टि की कल्पना की तो उनकी नाभि से एक कमल निकला जिस पर एक पुरूष आसीन था चुंकि इनकी उत्पत्ति ब्रह्माण्ड की रचना और सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से हुआ था अतः ये ब्रह्मा कहलाये। इन्होंने सृष्ट की रचना के क्रम में देव-असुर, गंधर्व, अप्सरा, स्त्री- पुरूष पशु-पक्षी को जन्म दिया। इसी क्रम में यमराज का भी जन्म हुआ जिन्हें धर्मराज की संज्ञा प्राप्त हुई क्योंकि धमार्नुसार उन्हें जीवों को सजा देने का कार्य प्राप्त हुआ था। धर्मराज ने जब एक योग्य सहयोगी की मांग ब्रह्मा जी से की तो ब्रह्मा जी ध्यानलीन हो गये और एक हजार वर्ष की तपस्या के बाद एक पुरूष उत्पन्न हुआ। इस पुरूष का जन्म ब्रह्मा जी की काया से हुआ था अतः ये कायस्थ कहलाये और इनका नाम चित्रगुप्त पड़ा। भगवान चित्रगुप्त जी के हाथों में कर्म की किताब, कलम, दवात और करवाल है। ये कुशल लेखक हैं और इनकी लेखनी से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलती है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भगवान चित्रगुप्त की पूजा का विधान है। इस दिन भगवान चित्रगुप्त और यमराज की मूर्ति स्थापित करके अथवा उनकी तस्वीर रखकर श्रद्धा पूर्वक सभी प्रकार से फूल, अक्षत, कुमकुम, सिन्दूर एवं भांति भांति के पकवान, मिष्टान एवं नैवेद्य सहित इनकी पूजा करें। और फिर जाने अनजाने हुए अपराधों के लिए इनसे क्षमा याचना करें। यमराज और चित्रगुप्त की पूजा एवं उनसे अपने बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगने से नरक का फल भोगना नहीं पड़ता है।

- सुरेश सिंह बैस शाश्वत

बिना असफलता के सफलता का कोई आस्वाद नहीं होता

संजीव ठाकुर

असफलता को झेलने के लिए आत्मविश्वास की परम आवश्यकता होती है'असफलता ऐसा स्वाद है जिसे हर व्यक्ति ने जीवन में कभी ना कभी जरूर चखा होगा। असफल होने से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। महापुरुषों ने कहा है कि असफलता यह दशार्ती है कि आपने प्रयास पूरे मन से नहीं किया है अतः असफलता के बाद सफलता के लक्ष्य को निर्धारित कर पूर्ण मनोयोग से कर्म की वेदी पर अपना शीश नवाना चाहिए। जीवन में असफलता किसी लक्ष्य को स्थापित करने का ही परिणाम है, इसीलिए इसे बड़े ही सौजन्यता से, सहज तरीके से आत्मसात करना चाहिए। सकारात्मक तरीके से आत्मविश्वास के साथ स्वीकार की गई असफलता मनुष्य को बड़े लक्ष्य की ओर प्रयास करने के लिए संकेत देती है। बिना असफलता के सफलता कोई भी आस्वाद नहीं देती है। असफलता के बाद ही सफलता के के लिए किए गए प्रयासों का महत्त्व मनुष्य को अपने जीवन में पता लगता है। शायर फैज अहमद फैज ने कहा है

दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है,

लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है।

असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है और यह सामान्य मानवीय कृत्य भी है। असफल होने के कारणों का पता लगाकर सफलता के लिए प्रयास हमेशा हमें दोगुना कर देना चाहिए। यह भी जरूरी नहीं है कि एक बार सफल होने के बाद मनुष्य सदैव सफल ही होता रहे इसके लिए मनुष्य को लगातार चिंतनशील, आत्म विश्वासी, साहसी और सतर्क होना पड़ेगा। सफल होने के लिए हमें हमेशा हुनरवान होना होगा जिससे इसी हुनर से हमें सफलता का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। यह सर्वविदित सच्चाई है कि हमें सफलता के लिये साहस और हुनर का उपयोग कर सदैव अग्रसर होते रहना होगा। सफलता एक लक्ष्य और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव सफलता की सीढ़ी चढ़कर हमें वहां पहुंचने की आवश्यकता है।

आत्मविश्वास का अर्थ शक्ति और ऊर्जा तो है और यह संपूर्ण रूप से हमारे प्रयासों हमारे संकल्प और साहब से जुड़ा हुआ प्रतिफल भी है।

आज भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है। हमारे देश के लाखों, करोड़ों युवाओं का जीवन लक्ष्य हीन है वे बहुत सारी इच्छाएं और महत्वकांक्षी रखते तो हैं पर उसके पीछे कड़ी मेहनत पक्का इरादा नहीं रखने की भूल कर देते हैं और यही कारण है कि वे जीवन में इधर उधर भटक कर अत्यंत निराश होकर अपने जीवन को नशे और अन्य निराशाजनक मार्ग को अपना लेते हैं। प्रयास तथा कठिन परिश्रम की कमी ही युवा वर्ग की भटकाव की स्थिति की परिणति है।

आज का युवा बिना सुनियोजित प्रयास के लक्ष्य की प्राप्ति की आकांक्षा रखने लगे हैं और असफल होने के बाद उसका मूल्यांकन ना कर असफल होकर किसी अन्य मार्ग को चुनने के लिए बाध्य हो जाते युवाओं की यह मानसिक स्थिति बड़ी आया हुआ है जो समाज के लिए निर्णायक साबित होती है और एक बड़ा युवा वर्ग गलत मार्ग की ओर प्रशस्त हो जाता है। ऐसे में युवाओं का जीवन बहुत ही कष्टदायक हो सकता है। युवा वर्ग को चाहिए कि लक्ष्य निर्धारित कर उसके लिए निरंतर कोशिश है और निरंतर श्रम करना चाहिए इसके बाद भी यदि असफलता मिलती है तो सम्यक मूल्यांकन कर असफलता के कारणों को दूर कर दुगनी रफ़्तार से मेहनत कर उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज युवा आगे बढ़कर देश का जिम्मेदार नागरिक बनेगा ऐसे में युवाओं को सदैव लक्ष्य प्राप्ति और सफलता प्राप्ति के लिए निरंतर कठिन श्रम प्रयास संकल्प और अपनी जीवनी को नियमित रखना होगा जिससे घर, समाज और राष्ट्र की उन्नति भी होगी। उल्लेखनीय है की असफलता से ही सफलता की तमाम शिक्षा हमें प्राप्त होती है। विवेकानंद जी ने कहा है कि

ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे ही भीतर ही है यह हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहते हैं कि अंधेरा है।

मनुष्य के जीवन में आत्मविश्वास ही ऐसा गुण है जिससे हम संकल्पित होकर बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर जीवन में सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी और सबसे बड़े सफलता के और आत्मविश्वास के उदाहरण महात्मा गांधी ही हैं जिन्होंने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से देश को आजादी दिलाने का महान कार्य किया है। फिर ऐसा क्या है कि देश के युवा वर्ग की बड़ी जनसंख्या हाथ में हाथ धरे सफलता का बैठे-बैठे इंतजार करना चाहती है।

देश के नौजवानों को हमारे सफल महापुरुषों से शिक्षा लेकर सफलता के लिए अनंत तक आत्मविश्वास के साथ निरंतर श्रम करना चाहिए जिससे न सिर्फ उनका भला हो बल्कि पूरे समाज और पूरे देश का भला हो सके और देश पूरे विश्व में सीना तान कर अपने आसपास और सफलता की गाथा सुना सके। यह देखा गया है कि मानव अहंकार को ही आत्मविश्वास समझने की भूल कर देते हैं किंतु आत्मविश्वास घमंड और अहंकार मैं बहुत बड़ा फर्क है। आत्मविश्वास अहंकार विहीन विनम्रता के साथ परिश्रम और संयम संकल्प लेकर सफलता के लक्ष्य की ओर पदार्पण ही है। फल स्वरुप अहंकार को त्याग कर संपूर्ण विश्वास को लेकर देश हित में सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए।

भारत के पास तिब्बत के रूप में है ऐसा ब्रह्मास्त्र, चीन की सारी चालबाजियों को पल भर में कर देगा परास्त

चीन आजकल परेशान है। बताया जा रहा है कि वह भारत के रवैये से डरा हुआ है। दुश्मन का डरा होना और परेशान रहना ज्यादा बेहतर है। इससे वह अपनी समस्या सुलझाने में लगेगा। अपने दुश्मन देशों को तंग नहीं करेगा। उन पर दबाव-धौंस नहीं दिखाएगा। कभी चीन का व्यवहार हमें परेशानी कर रहा है। वह सीमापर घुसपैठ करता। क्षेत्र के अंदर आए भारत के भाग में जमता और सौदेबाजी करता। किंतु अब ये बदलता भारत है। बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारत दुश्मन को उसके घर में घुसकर मार रहा है। परिणाम है कि आज चीन की आंखों में आंखे डालकर बात की जा रही है। सूचनाएं हैं कि चीन भारत की ब्रह्मोस से डरा हुआ है जब से भारत का शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल चीन के करीब तैनात की हैं और चीन के दुश्मन फिलीपींस को दी हैं, तबसे चीन दहशत में हैं। चीन ब्रह्मोस का काट नहीं निकाल पा रहा है। वह जानता है कि उसके सारे हथियार भी एक बार फायर की गई ब्रहमोस को नहीं रोक सकते।

ब्रह्मोस की काट निकालने के लिए चीन फिलीपींस को डराने के की कोशिश में जुटा है। चीन ने फिलीपींस के बेहद करीब अपने ड्रोन को भेजा है ताकि फिलीपींस डर जाए। लेकिन चीन का ये कदम बताता है कि असली डर फिलीपींस को नहीं बल्कि चीन को है क्योंकि अब साउथ चाइना सी के बिल्कुल करीब अमेरिकी सेनाएं भी आ गई हैं। भारत पहले ही चीन के शत्रु देश वियतनाम की पीपुल्स नेवी को अपना आधुनिक युद्धपोत आईएनएस कृपाण का हस्तांतरण कर चुका है। इस युद्ध पोत पर आधुनिक मिसाइल तैनात हैं। दरअसल अब तक चीन भारत को घेरने में लगा था। वह भारत के दुश्मन देशों को आधुनिक अस्त्र-शस्त्र की आपूर्ति करने में लगा था। अब ऐसा उसके साथ हो रहा है तो वह परेशान है। चीन भारत में अशांति फैलाने वाले नक्सलाइड, मिजों एव अन्य आंतकियों को आधुनिक शस्त्रों की आपूर्ति करता रहा है। सूचनाएं रही हैं कि उन्हे प्रशिक्षण भी दे रहा है। ऐसे में समय की मांग है कि भारत अब चीन के विरूद्ध चल रहे तिब्बत के पूर्ण स्वतंत्रता के आंदोलन का खुलकर समर्थन करें। जरूरत पड़ने पर तिब्बती के आजादी के आंदोलन के लड़ाकों को शस्त्र के साथ प्रशिक्षण भी दे।

भारत की नहीं चीन के रवैये से दुनिया के लगभग सभी देश परेशान हैं। इसी कारण फिलीपींस और अमेरिकी सेना का साझा युद्धाभ्यास हाल में शुरू हुआ। इस मिलिट्री ड्रील में जापान की सेनाएं भी शामिल हो रही हैं। 16000 हजार सैनिक साझा युद्धभ्यास में शामिल हैं। सबसे बड़ी बात कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के सैनिक भी कुछ दिन में इस ज्वाइंट एक्सरसाइज से रहेंगे। मतलब पांच देश चीन को घेरने के लिए एक साथ होंगे। इस ड्रील में समुद्री और हवाई हमलों का अभ्यास किया जाएगा। भारत के ब्रह्मोस देने के बाद से चीन परेशान है। अभी तो ब्रह्मोस तैनात भी नही हुई होंगी कि चीन परेशान है। वह फिलीपींस पर द्रोण उड़ाकर उसे धमका रहा है। सवाल है कि क्या ड्रोन के जरिए चीन ब्रह्मोस के बारे में जानकारी जुटाना चाहता है। सवाल तो ये भी है कि क्या चीन उस ठिकाने का पता लगाना चाहता है, जहां फिलीपींस ब्रह्मोस को तैनात करेगी। चीन ने ड्रोन के अलावा समंदर में मिलिट्री ड्रील के जरिए भी फिलीपींस को आंख दिखाने की कोशिश की है। चीन की नौसेना ने साउथ चाइना सी में लड़ाकू विमानों और युद्धपोत से मिसाइलें दागकर फिलीपींस को डराने की कोशिश की।

दो दिन के अंदर चीन के ये ये कदम बताते हैं कि चीन ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती से भयभीत है। चीन के टेंशन इस बात की है कि अब भारत चीन सीमा के साथ चीन-फिलीपींस सीमा पर भी ब्रह्मोस तैनात होगा। अब तो चीन के एक और दुश्मन और पड़ोसी वियतनाम ने भी ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखाई है, जो चीन के लिए खतरे की घंटी है।

फिलीपींस में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पहुंच गई है और वहां की सैना उसकी तैनाती करेगी। फिलीपींस में अमेरिका ने अपनी नई टायफून मिसाइल प्रणाली तैनात कर रखी है। फिलीपींस में अमेरिका को चार बेस का एक्सेस मिला हुआ है। चीन के करीब जापान पर भी अमेरिका का बेस है। ऑस्ट्रेलिया-सिंगापुर में अमेरिका ने अपना बेस बना रखा है। थाईलैंड और साउथ कोरिया में अमेरिकी सेनाएं तैनात हैं। चीन के करीब गुआम में भी अमेरिका का बेस है। इन जगहों से वक्त पड़ने पर कभी भी अमेरिका चीन पर हमला कर सकता है। चाइना सी के बिल्कुल करीब अमेरिकी सेनाएं भी आ गई हैं। चीनी सेना के प्रवक्ता ने फिलीपीन्स को ब्रह्मोस देने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग में इस बात का ख्याल रखा जाए कि इससे किसी तीसरे पक्ष के हितों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने कहा कि ह्यचीन हमेशा मानता है कि दो देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग से किसी तीसरे पक्ष के हितों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरा नहीं होना चाहिए। कर्नल वू कियान ने कहा कि एशिया-प्रशांत में अमेरिका की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती का हम कड़ा विरोध करते हैं। अमेरिका का यह कदम क्षेत्रीय देशों की सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डालते हुए क्षेत्रीय शांति को खतरा पैदा करता है। आज चीन को याद आ रहा है कि दो देशों के रक्षा सहयोग से तीसरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, किंतु जब वह खुद ऐसा करता है, तब उसे कुछ याद नहीं आता। लंबे समय से वह पाकिस्तान को आधुनिकतम युद्धक शस्त्र देने में लगा हुआ है। वह नहीं जानता कि पाकिस्तान इन शस्त्रों का प्रयोग किस देश के विरूद्ध करेगा। वह अच्छी तरह से जानता और समझता है। किंतु अपने हित में उसे कुछ याद नहीं आता। अब उसके दुश्मन देश भारत, अमेरिका और फ्रांस आदि ऐसा ही कर रहे हैं तो उसे याद आ रहा है तीसरे राष्ट्र को नुकसान न पहुंचे।

भारत फिलीपीन्स को ही ब्रह्मोस मिसाइल नहीं दे रहा। वियतनाम भी इस मिसाइल को खरीदने में रूचि दिखा रहा है। यह तो है कि वियतनाम भी खरीदता है तो भारत उसे ब्रह्मोस देगा। प्रथम वरीयता पर देगा। भारत अपना आधुनिकतम युद्धपोत खुखरी वियतनाम को पहले ही उपहार में दे चुका है। ये आधुनिक युद्धास्त्रों से सज्जित युद्धपोत है। भारत की ये कार्रवाई दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये को लेकर चिंताओं के बीच यह भारत और वियतनाम में बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दशार्ता है। अधिकारियों ने कहा भी कि भारत ने पहली बार किसी मित्रवत देश को कोई सेवारत पोत उपहार में दिया है। भारतीय नौसेना ने कहा कि पोत पूरी हथियार प्रणाली के साथ वियतनाम पीपुल्स नेवी (वीपीएन) को सौंपा गया है। आईएनएस कृपाण, 1991 में सेवा में शामिल किए के बाद से भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक अभिन्न अंग रहा और पिछले 32 वर्षों में कई ऑपरेशन में भाग लिया। लगभग 12 अधिकारियों और 100 नाविकों द्वारा संचालित, जहाज 90 मीटर लंबा और 10.45 मीटर चौड़ा है।

भारत जैसे का तैसा की नीति पर चल चुका है। अब वह कमजोर भी नही है। दुश्मन से आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। ऐसे में अब चीन में घाव पर पूरी ताकत से हथौड़ा मारने का समय आ गया। चीन की बड़ी कमजारी है तिब्बत। तिब्बत पर उसने कब्जा किया हुआ है। तिब्बत की अस्थाई सरकार के धर्मशाला नगर में चल रही है। भारत के रूख के कारण तिब्बती अभी तक शांतिपूवर्क आदोलन कर रहे हैं। भारत ने तिब्बत की आजादी की लड़ाई का कभी समर्थन नहीं किया। अब समय आ गया है कि भारत इस आंदोलन का समर्थन करें। तिब्बत सरकार को मान्यता दें। तिब्बती आंदोलनकारी को शस्त्र और युद्ध प्रशिक्षण दे। जब तक दुश्मन को उसके घर में ही नही घेरा जाएगा, तक तक वह नही मानने वाला। घर में घिर कर वह अपने में उलझ जाएगा और दूसरों को तंग करना बंद कर देगा। चीन सरकार वहां बसे उइगुर मुसलमानों पर बेइतहां जुल्म करने में लगी है। मुस्लिम देश चुप हैं। भारत अपने परिचित मुस्लिम देश और संगठनों से उइगुर मुसलमान की आजादी और कल्याण के लिए आवाज बुलंद कराएं।

- अशोक मधुप

https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक इबादत
सम्पादकीय

जनता की अदालत में केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीति को अक्षय तृतीया के दिन जमानत के रूप में नवजीवन मिल गया। जमानत अंतरिम है और केजरीवाल को 2 जून को दोबारा अदालत के समक्ष समर्पण करना होगा,लेकिन वे अपनी जमानत की अवधि में अठारहवीं लोकसभा के लिए होने वाले शेष चार चरणों के चुनाव में खुलकर न सिर्फ प्रचार कर पाएंगे बल्कि भाजपा की उन तमाम साजिशों को भी बेनकाब भी कर पाएंगे जो दस साल से विपक्ष के खिलाफ की जा रहीं हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छा हुआ की वे 50 दिन की जेल यात्रा कर आये। स्वाधीनता से पहले जेल यात्राओं को एक तरह का बलिदान माना जाता था। आजादी के बाद जेल यात्राओं का रंग ही बदल गया। अब नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाते हैं। जनांदोलनों के चलते जेल जाने वालों की संख्या लगातार घटी है। केजरीवाल हालांकि आंदोलन की कोख से निकले हो नेता हैं,,लेकिन हैं तो पुराने नौकरशाह। इसीलिए वे भाजपा के मोदी और शाह से टक्कर ले पा रहे हैं। उन्हें जेल भी शायद इसीलिए जाना पड़ा लेकिन कानून ने उनकी मदद की और अंततः अंतरिम जमानत दिला दी। लोकसभा चुनाव के चार चरण अरविंद केजरीवाल के बिना सम्पन्न हो गए। विपक्षी आईएनडीआईए गठबंधन को केजरीवाल से जो लाभ मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिल पाया। लेकिन जमानत पर आने के बाद वे बीस दिन में इतना कुछ काम कर लेंगे की भाजपा सरकार को चुनौती दी जा सके। अरविंद पहले भाजपा की बी टीम समझे जाते थे किन्तु बाद में वे इस छवि से बाहर निकल आये। उन्हें शराब घोटाले में अपने आपको लपेटे जाने के बाद भाजपा के खिलाफ कमर कास ली थी। केजरीवाल और उनकी पार्टी की हैसियत इस समय कांग्रेस को छोड़ दीगर क्षेत्रीय दलों से कहीं ज्यादा है। उनकी अकेली ऐसी पार्टी है जिसकी एक से अधिक राज्यों में सरकारें हैं। आम आदमी पार्टी को केजरीवाल एंड कम्पनी दिल्ली से बाहर पहले पंजाब तक ले गयी और वहां से उसने गोवा, गुजरात में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा को अपदस्थ करने के महाअभियान में शामिल है। आपको पता ही है की भाजपा की इस समय सिट्टी-पिट्टी गुम है। भाजपा अपने घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने के बजाय उन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है जो की उसे कॉंग्रेस ने दिए हैं। भाजपा अब मोदी जी के चेहरे और मोदी जी की गारंटियों पर चुनाव नहीं लड़ रही। चुनाव जीतने के लिए भाजपा को हारकर हिन्दू-मुसलमान पर आना पड़ा। मतदाताओं को अल्पसंख्यक मुसलमानों से आतंकित करने के लिए पहले मंगलसूत्र छीने जाने,बाद में विरासत पर कार लगाए जाने और सबसे बाद में अंकल सैम पित्रोदा के निजी बयानों का इस्तेमाल करने पर विवश होना पड़ा। केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद अब भाजपा कौन से हौवा खड़ा करेगी ये कहना कठिन है। अरविन्द भ्रष्ट हैं या नहीं इसका प्रमाण पत्र तो उन्हें अदालत और जनता की अदालत से मिलेगा, लेकिन ये जन नेता हैं इसका प्रमाण पत्र उन्हें शायद नहीं चाहिए।अब वे मोशा के सिर पर सवार दूसरे राजनीतिक भूत हैं, जो भाजपा की विजय यात्रा को ग्रहण की तरह लग चुके हैं।4 जून 2024 तय करेगा कि जनता जीती या हारी ?

कांग्रेस का लगातार भट्ठा बैठाने के बाद सैम पित्रोदा को आखिर हटना पड़ा

– अशोक भाटिया

अपनी नस्लवादी टिप्पणी को लेकर चल रहे विवाद के बीच सैम पित्रोदा ने बुधवार को अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। उनके इस फैसले को सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वीकार कर लिया है। यह पहली बार नहीं था कि सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी की हो. इसके पहले भी अपने विवादास्पद बयान से वे कांगेस का भट्टा बैठा चुके है व बाद में कांग्रेस को उन बयानों पर लीपा पोती करके अपने को संभालना पड़ा है। अक्सर राहुल गांधी के करीबी सहयोगी माने जाने वाले पित्रोदा ने हालिया बयान में कहा कि भारत के पूर्व में लोग चीनी जैसे दिखते हैं और दक्षिण में लोग अफ्रीकियों जैसे दिखते हैं। पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह भारत के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की तुलना इस तरह करते नजर आ रहे हैं जिससे कोई भी नाराज हो सकता है। पित्रोदा कहते हैं कि 'भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले श्वेतों की तरह और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। हम सभी भाई-बहनें हैं। वे कहते हैं कि हम अलग-अलग भाषाओं, धर्मों और रीति-रिवाजों का सम्मान करते हैं। ये वही भारत है, जिस पर मेरा भरोसा है, जहां हर किसी का सम्मान है और हर कोई थोड़ा-बहुत समझौता करता है।' देखा जाए तो यह बहुत सामान्य सी बात है। हम लोग आम जीवन में इस तरह की तुलनात्मक बातें करते रहते हैं पर जब कोई शख्स आम के बजाय खास बन जाता है तो उसकी बातचीत के कई मतलब निकाले जाते हैं और जब चुनाव चल रहे हैं और आप देश की सबसे बड़ी पार्टी में से एक के जिम्मेदार सदस्य हैं तो आपकी जवाबदेही और बनती है कि आप क्या बोल रहे हैं? शायद यही कारण है कि सैम पित्रोदा का बयान वायरल होते ही भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। तेलंगाना के वारंगल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस और राहुल गांधी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि %आज मैं बहुत गुस्से में हूं। शहजादे के एक अंकल ने आज ऐसी गाली दी है जिसने मुझे गुस्से में भर दिया है। संविधान सिर पर रखने वाले लोग देश की चमड़ी का अपमान कर रहे हैं।'

आखिर प्रधानमंत्री को कांग्रेस पर हमला करने का मौका किसने दिया? इससे पहले कांग्रेस नेता पित्रोदा ने विरासत कर के बारे में बात करके विवाद खड़ा कर दिया था जिसे भाजपा ने चुनावी मुद्दा बना लिया। पित्रोदा ने कांग्रेस के घोषणापत्र में संपदा के पुन- वितरण के मुद्दे पर बात करते हुए अमेरिका में विरासत कर का उल्लेख किया था। इसके बाद भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। पित्रोदा ने 6 अप्रैल 2019 को कहा था कि मध्यम वर्ग को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। उन्हें ज्यादा टैक्स देने के लिए कमर कस लेना चाहिए। इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी सकते में आ गई। पार्टी को सफाई देनी पड़ी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो मध्य वर्ग पर कोई अतिरिक्त कर का बोझ नहीं डालेगी। कांग्रेस में अकसर ऐसा देखा गया है कि किसी खास मुद्दे पर ठीक एक दूसरे से विरोधी विचार सामने आते हैं और एक साथ आते हैं। द्रमुक नेता उदयनिधि मारन के सनातन को डेंगू मलेरिया कहने के बाद कांग्रेस में एक साथ कई विचार आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पुत्र प्रियांक खरगे को उदयनिधि मारन की बातों में कोई बुराई नहीं दिखी पर ठीक उसी समय मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इसका खंडन किया। देशभर में दर्जनों ऐसे नेताओं के बयान आए जो मारन की बातों से यकीन नहीं रखते थे तो बहुत से लोगों ने सीधे मारन और खरगे को सपोर्ट किया। इसी तरह राम मंदिर के मुद्दे पर पूरी पार्टी में अलग-अलग विचार सामने आते रहे। कोई समर्थन में था तो कोई इसके विरोध में। कोई भी पार्टी इस तरह के विचारों पर एक मत नहीं है तो निश्चित है कि उसके समर्थकों में कन्फ्यूजन पैदा होगा पर कांग्रेस नेताओं को लगता है कि इस तरह एक ही मुद्दे पर अलग-अलग विचार करके सभी विचार वालों को पार्टी चुनावों में साध लेगी पर जब जनता के सामने विकल्प को रूप मे ऐसी पार्टियां रहेंगी जो एक विचार पर पूरी शिद्दत से लगी हुई हैं तो जनता ऐसे ढुलमुल विचार वाले के साथ क्यों जाएगी। (मुंबई)

हमारे भगवान के स्वरूप सड़कों पर नचाने के लिए नहीं हैं !

हनुमान अमर अजर अविनाशी हैं जिन्हें अष्ठ सिद्धी और नव निधि का वरदान माता सीता से मिला है और हमारे आस्था के सबसे जीवंत पावन पवित्र स्वरूप है। उनके स्वरूप को भी घुंघरू बांध कर भक्त लोग जागरण रथ यात्राओं शोभायात्राओं में सड़क पर नचाने लगे हैं। यह श्रद्धा भक्ति और आस्था का कैसा प्रकटीकरण है?

– मनोज कुमार अग्रवाल

इन दिनों भगवान के स्वरूपों को पंडालों शोभायात्रा संकीर्तन यात्रा में सड़कों पर नचाने का नया रिवाज चल निकला है क्या यही है हमारे अपने मान बिंदुओं के प्रति आस्था के प्रदर्शन का तरीका? यह क्या हो रहा है हमारे हिन्दू समाज को खासकर सनातन धर्म में जितनी मनमानी लोग कर रहे हैं शायद ही किसी अन्य धर्म के श्रद्धालु इस तरह की मनमानी भरी क्रियाकलाप करते हैं। आपको बता दें कि करीब छह सौ साल पहले 1486 में जन्मे चैतन्य महाराज ने भक्ति का नृत्य से समन्वय कर हिन्दू सनातन समाज को श्रद्धा भक्ति और आस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया था। भाव विभोर भक्तों का सुध बुध खो कर हरे कृष्णा का संकीर्तन करते हुए गांव गांव भक्ति की रसधारा का प्रवाह किया। आपको बता दें कि हमारे यहां भगवान श्रीकृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित घटनाओं का रासलीला में चित्रण करने की परम्परा भी कई सौ साल पहले 1776 में शुरू हुई। शुरुआत में बृज क्षेत्र के मंदिरों धर्म शालाओं व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भगवान के रूप और गुण का गुण गाने करने के लिए रासलीला का सिलसिला शुरू हुआ। क्योंकि हजारों वर्ष से मथुरा वृंदावन बरसानाबृज क्षेत्र में भगवान के धाम व लीला स्थलो को देखने के लिए श्रद्धालु देश भर से आते थे उन श्रद्धालुओं के हृदय में भक्ति और आस्था की रसधार प्रवाहित करने के लिए मथुरा वृंदावन के गुसाईं ब्राह्मण परिवार भगवान के स्वरूप बना कर रासलीला दर्शाते थे कालांतर में यह रासलीला बृज क्षेत्र की सीमाओं से बाहर निकल कर देश भर में आयोजित की जाने लगी। रासलीला के दौरान भगवान कृष्ण राधा के पात्रों को झांकी पावन चरित्रों को आमजन तक पहुंचाने के लिए दर्शायी जाती थी मथुरा वृंदावन बरसाने के छल कपट से दूर सात्विक भोजन व मर्यादित आचरण करने वाले ब्राह्मण परिवार के सदस्य बच्चों समेत देश भर में घूम घूम कर रासलीला का मंचन करते। यही इन सैकड़ों हजारों परिवार की रोजी-रोटी जरिया था। फिर एक और दौर आया करीब ढाई सौ साल पहले 1860 में रामलीलाओं का आयोजन करने का सिलसिला शुरू किया गया इस की शुरुआत चित्रकूट वाराणसी लखनऊ से हुई। तुलसी लिखित रामचरित मानस पर आधारित ऐतिहासिक पौराणिक मान्यताओं के अनुरूप रामलीला का चित्रण किया जाता था इस का उद्देश्य भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के पावन चरित्र के उदात्त प्रसंगों का चित्रण कर आम जनमानस को श्री राम के चरित्र से प्रेरणा लेने के लिए आकर्षित करने का था धीरे-धीरे यह रामलीला आयोजन भारी विस्तार ले गए और श्री राम लीला उत्तर भारत के हर गांव कस्बे शहर में आयोजित की जाने लगी और धीरे-धीरे यह रामलीला आयोजन मेला बन गए। इसी दौरान करीब 50-60 साल पहले रामलीला के दौरान दर्शकों को मनोरंजन के लिए धनुष यज्ञ और राम बारात आदि में नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे इसके बाद तमाम गांव कस्बों की छोटी-बड़ी ज्यादातर रामलीलाओं में इस तरह का सिलसिला चल निकल की रामलीलाओं के मंचों पर नृत्य डांस के प्रोग्राम होने लगे इनमें कुछ स्थानों पर फूहड़ डांस भी किए जाने लगे। शुरू में पुरूष कलाकार ही महिला स्वरूप बना कर नृत्य पेश करते लेकिन धीरे-धीरे महिला कलाकारों को नृत्य के लिए बुलाया जाने लगा। अब स्थिति इस हद तक पहुंच गई है कि इन मेलों में बार बालाएं भी स्टेज पर डांस के लिए बुलाया जाने लगा।

वही रासलीला में भगवान कृष्ण और राधा सुदामा सरीखे पात्रों को नृत्य करते दिखाए जाने लगा उधर बीते चार पांच दशक में माता के जागरण का आयोजन किया जाने लगा। शहर कस्बों में अनेक जागरण मंडलियों आरकेस्ट्रा ग्रुपों द्वारा फिल्मी गीतों की तर्ज पर माता के गुणगान का सिलसिला शुरू किया गया जो धीरे-धीरे भगवान के स्वरूप की झांकी और फिर स्वरूपों के नृत्य प्रस्तुतियों में तब्दील हो चला है इसी के साथ बीते दो दशक में माता के जागरण की तर्ज पर ही खाटू श्याम संकीर्तन भी बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाने लगे हैं इन आयोजनों के साथ ही माता की चौकी बालाजी संकीर्तन के आयोजन निजी व संस्थाओं के माध्यम से बड़ी तादाद में हर शहर कस्बे में किए जाने लगे हैं। इस में कुछ भी बुरा नहीं है लेकिन चैतन्य महाप्रभु की भाव विभोर नृत्य वाली भक्ति अब सिर्फ मनोरंजन और दिखावे वाले मनमाने नृत्य में बदल गई है यह सिलसिला तमाम रथ यात्राओं और दूसरे धार्मिक आयोजनों में चल निकला है सड़कों पर नाचते गाते लोग भगवान के स्वरूप को नचाने लगे हैं भक्त नाचे तो यह चलेगा लेकिन सड़कों पर गरिमा का बिना ध्यान किए भगवान के स्वरूप को नचाने का सिलसिला यकीनन शर्मसार करने वाला है यानि हम नाच रहे हैं तो आप भी नाचिए। तमाम शोभा यात्रा में इस तरह के भगवान के स्वरूप को नृत्य करते हुए प्रदर्शन किया जाने का सिलसिला शुरू हो गया पिछले 30-40 साल में कावड़ यात्रा एक बड़ा आयोजन बन गई इसमें भी गौरा और शिव के स्वरूप को नचाने का सिलसिला चल निकला कावड़ यात्रा के दौरान तमाम तरह की भोजपुरी व हरियाणवी लोक संगीत में गीतों की कैसेट सीडी आने लगी जिन पर भगवान शिव और गौरा के स्वरूप को केंद्र में रखकर बेहद आपत्तिजनक बोल तैयार किए गए और देखते ही देखते इन पर गौरा शिव का स्वरूप धारण कर कलाकार सड़कों पर मटकते लगे यह सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं था काली और महाकाल भी सड़कों पर खिलाए जाने लगे हद तो तब हो गई जब गाना तैयार किया गया छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना हनुमान जो भगवान रूद्र के ग्यारहवें अवतार हैं नवरूद्रो में से एक हैं।

हनुमान अमर अजर अविनाशी हैं जिन्हें अष्ठ सिद्धी और नव निधि का वरदान माता सीता से मिला है और हमारे आस्था के सबसे जीवंत पावन पवित्र स्वरूप है उनके स्वरूप को भी घुंघरू बांध कर भक्त लोग जागरण रथ यात्राओं शोभायात्राओं में सड़क पर नचाने लगे हैं यह श्रद्धा भक्ति और आस्था का कैसा प्रकटीकरण है? हम अपने मनोरंजन के लिए भगवान के पावन स्वरूपों को मल मूत्र से सनी सड़कों पर अमर्यादित गानों के भोंडे बोल पर शोभायात्रा में नचाकर आनंदित हो रहे हैं। आप को बता दें कि पूर्व में रासलीला और रामलीला में जो कलाकार अभिनय करते थे वह इन आयोजनों के दौरान शुद्ध सात्विक भोजन तमाम तरह के व्यसन का त्याग और भूमि पर शय्या लगा कर सोते थे इन स्वरूप में भारतीय आम जन मानस साक्षात भगवान के दर्शन महसूस करता था। लेकिन कहाँ से चल कर अब कहाँ आ पहुंचे हैं हम। हम जिन अपने आदर्श भगवान के चरित्रों को शराब व गुटका खाए कलाकारों को सड़कों व पंडालों में नचाकर इसे सनातन धर्म का हिस्सा मानकर गर्व और गौरव महसूस कर रहे हैं क्या हमारे पतित पावन मान बिंदु चरित्र मनोरंजन के लिए है? भगवान के पावन स्वरूप का इस तरह का अमर्यादित गलत इस्तेमाल करने को कैसे उचित कहा जा सकता है? ऐसे लोगों की बुद्धि पर शरम का अनुभव किया जाए हम सनातन धर्म के अनुयायियों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई आचार संहिता तैयार करनी होगी ताकि हमारे मान बिंदुओं का इस तरह का मनोरंजन के माध्यम बनाने का खेल तत्काल रुकना चाहिए। हम शाश्वत और चिरंतन हैं हम हिन्दू सत्य सनातन हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

धन का अतिरेक विकास की दिशा को दिग्भ्रमित करता है

– संजीव ठाकुर

स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि 'सत्य में वह शक्ति है जो मानव को असीमित शक्ति और अतुल्य बल प्रदान कर सकती है'। यह तो सच बात है कि मानव सभ्यता का सतत विकास उसकी अदम्य जिज्ञासा, उत्कट उत्साह, जिजीविषा, निरंतर उन्नति की भूख और आशावादिता का प्रतिफल है। सभ्यता और संस्कृति की सुविधा के विभिन्न सोपानो में समय-समय पर मूल्यों का स्थापना और पुराने मूल्यों का विस्थापन एक सास्वत सत्य की तरह है। परिवर्तन प्रकृति का आधारभूत नियम है। विकास में धन की आवश्यकता अवश्य होती है पर और धन का अतिरेक विकास की दिशा को दिग्भ्रमित भी कर सकता है। इसके अलावा परिस्थितियों, आवश्यकताओं, दर्शन तथा अर्थ एवं धार्मिक स्थापनाओं के अनुरूप ही समकालीन समाज का दृष्टिकोण और जीवन दर्शन निरंतर विकासवान होता है। आदिकाल से विकास के क्रम में धन के प्रयोग को बड़ा प्रबल माना गया है। शाश्वत मूल्य की मीमांसा एवं उसकी निरंतरता मानवी जीवन से जुड़े अंतरंग पहलुओं को उजागर करती है। सत्य को सिद्धांत के रूप में भी देखा गया है। मानवी जीवन दर्शन में धन और सत्य दोनों कारकों का प्राचीन काल से ही पर्याप्त महत्व रहा है। धन का महत्व है पर धनबल सब कुछ नहीं है। सत्य एक सार्वभौमिक जीवन दर्शन है, इसे धन बल की मिथ्या कभी नष्ट अथवा विलोपित नहीं कर सकती है। धन बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं। सत्य सिद्धांत के बिना धन की विवेचना में मीमांसा अधूरी तथा महत्वहीन है। गलत तरीके से कमाया गया धन मनुष्य के चरित्र में उजियारे दिन के बाद घनघोर तमस की तरह है। सत्य जीवन का सार्वकालिक उजाला है। यह बात भी महसूस की गई है कि निवृत्ति, त्याग, संयम, सन्यास के स्थान पर भोग विलास को प्राथमिकता दिए जाने के कारण धन पर सत्य व नैतिक मूल्यों को बरीयता दी जाने की परंपरा रही है। वेद तथा पुराणों पर भी सत्य एवं नैतिकता के व्यवहारिक पक्ष को उजागर करते हुए लिखा गया है कि 'सत्य का सुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, धन जब मुखर होता है तो सत्य नेपथ्य में होता है। सत्य तब मुखर होता है जब धनबल का अतिरेक होने लगता है। धनबल मिथ्या है, सत्य शाश्वत और परंपरागत अनुवांशिक शक्ति है। भारतीय संस्कृति एवं परंपरा सत्य के मूल्य को सर्वोत्कृष्ट है उस सर्वोच्च मानती है। इसे मन वचन और कर्म में अद्वैत के स्तर तक निश्चित अकाट्य और सदैव अपरिवर्तनीय ही माना गया है, लोक जीवन का 'सांच को आंच नहीं' जैसी कहावतें और मूल्य जनजीवन में अंतरतम तक समाए हुए है। मुंडक उपनिषद में उल्लेखित 'सत्यमेव जयते' आज भारतीय गणतंत्र का आदर्श वाक्य है, जो भारतीय दर्शन और जीवन की अभिव्यक्ति भी है। यह उल्लेखनीय है कि वैदिक दर्शन से लेकर जैन व बौद्ध दर्शन तक इस्लाम ईसाई धर्मों से लेकर सिख गुरुओं तक सत्य का महत्व और निर्विवाद सर्वोच्च स्थान सर्वमान्य रूप से स्वीकार्य किया गया है। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद तो भोग दर्शन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और आर्थिक तत्व का महत्व वैश्विक तथा आंतरिक जीवन का सबसे प्रमुख निर्धारक तथ्य बनने लगा। पश्चिमी देशों में पूंजीवादी, उदारवादी संस्कृति के विकास का प्रभाव पूरे विश्व पर पर्याप्त मात्रा में पड़ा और वैश्विक स्तर पर मूल्यों में नैतिक स्तर पर परिवर्तन आने लगे।

आधुनिक युग वैश्वीकरण, उदारीकरण और आर्थिक विकास का युद्ध इस युग में अर्थ अथवा धनबल अपनी अकूत शक्ति के बल पर पूरी सभ्यता व व्यवस्था का केंद्रीय तत्व बनकर उभरा है। धन बल पर आधारित इस युग में स्थिति यह बन गई है कि राजनीति, समाज, धर्म, अध्यात्म, अंतरराष्ट्रीय संबंध, पर्यावरण, ज्ञान विज्ञान, जीवन दर्शन सभी अर्थ व धन के निर्देशों के अनुरूप ही चलन में आ गए हैं। धन के बल पर आज पारिवारिक संबंधों सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा राजनैतिक शक्ति, संतुलन, आध्यात्मिक स्तर पर प्रभाव नैतिक स्तर पर सहमति एवं अंतरराष्ट्रीय संबंधों को केवल प्रभावित ही नहीं कर रहे हैं अपितु उन्हें लगभग खरीदने की ताकत रखने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके बावजूद सत्य के मूल्य को और उसकी सार्वभौमिकता को दबाना या शांत करना या उसके दमन के लिए उसे विवश करना लगभग असंभव है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर दिखने वाली बराबरी अनेक बार सत्य को दबाकर दादागिरी के बल पर अमीर देशों की जिद की भेंट चढ़ जाती है। अमीर देशों की धन के दम पर दादागिरी कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों में दिखाई देती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर होने वाले वैश्विक सम्मेलन इसीलिए भी असफल होते दिखाई दिए हैं। क्योंकि अमीर देश कार्बन उत्सर्जन की मात्रा की जिम्मेदारी ज्यादा जनसंख्या वाले विकासशील देशों के सिर पर डाल देते हैं। सत्य की मनमानी व्याख्या आधुनिक युग की सच्चाई है सत्य का दमन इस स्तर पर पहुंच चुका है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर दिन में कितनी बार धनबल के दबाव में अपने अंत:करण से समझौता कर अपनी सहज प्रवृत्ति का दमन करने से नहीं चूकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा यदि तुम अखंड सत्य का पालन करो तो कोई भी तुम्हें रोकने में समर्थ नहीं है, यह तो सत्य है कि सत्य की शक्ति अत्यंत व्यापक एवं सर्वकालीन है।

कविता

आस्तीन के सांप

आस्तीन के सांप बन न डसा करो
अपने हो तो अपने बन ही रहा करो।

किसी वन के विषधर की तरह
दांतों में विष छुपा न रखा करो
जैसे हो वैसे ही बन रहा करो।

सभ्यता का मोल नहीं मिलेगा
तुम्हें असभ्यता ढोकर कर कभी।

होना है सभ्य तो सभ्यता ओढ़
तुम ज़रा सा चला करो।

धोना है हृदय में पड़ी कालखि को
तो मन को मंदिर बन रखा करो।

न मिलेगा मुकाम तुम्हें कभी
आस्तीन के सांप बन कर।

वन के मृग की तरह दहाड़ कर
अपने मुकाम की ओर
ज़रा चला करो।

डॉ. राजीव डोगरा
(युवा कवि व लेखक, गांव जनयानकड़, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश)

बसपा के मामले में,पार्टी के पतन को नए दलित नेताओं के उदय ने भी तेज किया है। पार्टी का वोट शेयर लगातार गिर रहा है। इस बात की संभावना कम ही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा उत्तर प्रदेश में कोई उल्लेखनीय परिणाम हासिल कर सकेंगी। अब उत्तर से पंजाब की ओर चलते हैं। बसपा की ताजा ताकत को जानने के लिए पंजाब के समीकरणों को जानना जानना जरूरी है,क्योंकि; बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय कांशीराम जी पंजाब के रोपड़ शहर से ही थे।

हाशिये पर जाती बहुजन समाज पार्टी

– आर.के. सिन्हा

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटा दिया है। छह महीने पहले ही उन्होंने आकाश को धूम - धाम से अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। उन्होंने कहा कि आकाश तब तक उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं बन सकते, जब तक वे 'पूरी तरह परिपक्व' नहीं हो जाते। आकाश आनंद बीते उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शुरुआती दो चरणों में बसपा के प्रचार अभियान का मुख्य चेहरा थे। उनके भाषणों में भाजपा और समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखे हमले किए गए थे। अप्रैल में सीतापुर में एक चुनावी रैली के दौरान कथित रूप से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। मायावती को लगता है कि ये भाषण पार्टी द्वारा निर्धारित नियमों और नीतियों से भटक गए थे। मायावती के इस तरह के अचानक फैसले पहले भी देखे गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इसका पार्टी और उनके दलित आंदोलन पर क्या असर होगा। बसपा के संस्थापक कांशी राम ने अपने परिवार को पार्टी से दूर रखा था और मायावती को उनके नेतृत्व कौशल के कारण ही अपना उत्तराधिकारी चुना था। इस रणनीति ने पार्टी को 2007 में उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सत्ता दिलाई, जहाँ दलित समाज आबादी का लगभग 21% हिस्सा हैं। हालांकि, मायावती बसपा को एक व्यापक बहुजन समाज की पार्टी के रूप में विकसित करने में विफल रहीं। पार्टी के कई संस्थापक नेता, जो ओबीसी, अल्पसंख्यक और दलित समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे, मायावती के नेतृत्व शैली से असंतुष्ट होकर पार्टी छोड़ गए। आज बसपा अपने पुराने अखिल भारतीय दलित संगठन के रूप में अपनी पहचान लगभग खो चुकी है, भले ही मायावती कहने को तो आज भी देश की सबसे बड़ी दलित नेता बनी हुई हैं। मायावती द्वारा बसपा के आंदोलनकारी चरित्र को नजरअंदाज करने और अपने परिवार के भीतर नेतृत्व को मजबूत करने के उनके फैसले ने पार्टी के विकास को नुकसान तो पहुँचाया ही है। दुर्भाग्य से, कई अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने भी यही रास्ता अपनाया है, जिनमें वे दल भी शामिल हैं जो वैचारिक रूप से शक्तिशाली आंदोलनों से उभरे थे। इसमें तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलनों से विकसित हुई डीएमके और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार की राष्ट्रीय जनता दल शामिल है, जो लोहियावादी समाजवादी परंपरा और मंडल राजनीति की विरासत का दावा करती हैं। बसपा के मामले में, पार्टी के पतन को नए दलित नेताओं के उदय ने भी तेज किया है। पार्टी का वोट शेयर लगातार गिर रहा है। इस बात की संभावना कम ही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा उत्तर प्रदेश में कोई उल्लेखनीय परिणाम हासिल कर सकेंगी। अब उत्तर से पंजाब की ओर चलते हैं। बसपा की ताजा ताकत को जानने के लिए पंजाब के समीकरणों को जानना जानना जरूरी है, क्योंकि; बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय कांशीराम जी पंजाब के रोपड़ शहर से ही थे। आप जब चंडीगढ़ से रोपड़ शहर में प्रवेश करते हैं तो आपको समूचे शहर की फिजाओं में लोकसभा चुनावों का रंग घुला हुआ मिलता है। सारा माहौल गुलजार है। आमतौर पर इधर बातचीत का मुख्य बिन्दू यही है कि राज्य की 13 लोकसभा सीटों में किस दल के हक के कितनी सीटें जाएंगी। पर यह एक दुर्भाग्य ही है कि बसपा दूर-दूर तक कहीं चर्चा में नहीं है।

सभी को यह हैरान करता है। रोपड़ बसपा के संस्थापक कांशी राम का यह अपना शहर है। इधर ही उनका बचपन बीता, इधर के ही सरकारी कॉलेज से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। आप चाहें तो और हैरान हो सकते हैं कि उनके कॉलेज के आसपास भी बसपा का कोई झंडा तक दिखाई नहीं दिया। कुल मिलाकर यहां पर आकर चिराग तले अंधेरे वाली कहावत सच साबित होती दिखी। आखिरी़ पंजाब के चुनावी समर में भी बसपा या कांशीराम की कोई भारी-भरकम उपस्थिति रोपड़ या पंजाब में क्यों नजर नहीं आ रही? पंजाब के कुछेक समाज शास्त्रियों से बातचीत के बाद हमें अपने सवाल का जवाब मिला। इन सभी की राय थी कि चूंकि पंजाब में सिख धर्म और आर्य समाज के प्रभाव के चलते दलितों को उस तरह से सामाजिक स्तर पर प्रताडित नहीं होना पड़ा, जैसे अन्य राज्यों में उन्हें झेलना पड़ा। इन दोनों मज़बूत धार्मिक संस्थाओं ने जाति के कोढ़ पर हल्ला बोला। नतीजा यह हुआ कि पंजाब के समाज में दलितों का उत्पीड़न कम हुआ। इस पृष्ठभूमि की रोशनी में ही पंजाब का दलित अपने को बसपा से जोड़कर नहीं देखता। आपको पंजाब में जगह-जगह दलितों के गुरुद्वारे तो देखने को मिल जाएंगे। उनके बाहर गुरुमुखी और कइयों के बाहर हिन्दी में भी लिखा रहता 'मजहबी', 'रामगढ़िया' या 'संत रविदास' गुरुद्वारा। और तो और, चंडीगढ़ में भी आपको इस तरह के गुरुद्वारे मिल जाएंगे। यह अन्य गुरुद्वारे से भव्यता के स्तर पर कतई उन्नीस नहीं हैं। ये कहीं न कहीं उनकी आर्थिक सेहत को भी रेखांकित करते हैं। यानी कि पंजाब का दलित उस तरह से पिछड़ा, दबा-कुचला नहीं है, जिस तरह से वो देश के बाकी भागों में या कम से कम उत्तर भारत के अन्य सूबों में हैं। जाहिर है, इसलिए ही चुनावों में पंजाब में दलित बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में खड़े नजर नहीं आते। संभवत: इसलिए ही बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम पंजाब से संबंध रखने के बाद भी बसपा को अपने ही गृह प्रदेश में मजबूत आधार देने में कामयाब नहीं हुए। पंजाब में कुल 30 फीसद मतदाता दलित है, यानि उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा ! देश के किसी भी अन्य सूबे में इतने अधिक दलित वोटर कहीं नहीं हैं। देश से बाहर बड़ी संख्या में जाने के फलस्वरूप पंजाब के दलितों के हालात सुधर गए। जो बाहर गए, वे भारत में अपने परिवारों को अच्छी-खासी रकम भेजते रहे। पंजाब से बाहर रोटी-रोजी कमाने के लिए जाने वालों में दलित सिख सर्वाधिक रहे हैं। आपको अफ्रीका में भी दलितों के गुरुद्वारे मिल जाएंगे। एक दौर में पंजाब में कांग्रेस के पास ज्ञानी जैल सिंह और बूटा सिंह के रूप में दंबग दलित नेता थे, पर साल 1984 में पहले स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के कत्लेआम के बाद पंजाब में पार्टी कमजोर हुई। उसे उपर्युक्त दोनों दिग्गज दलित नेताओं के केन्द्र की राजनीति करने के कारण रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए भी कोई नया नेता सामने नहीं आया। जैल सिंह तो देश के राष्ट्रपति ही बन गए। बहरहाल, बसपा की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए काफी संख्या में उम्मीदवार खड़े हुए हैं। कुछ समय पहले तक अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में मंत्री रहे राजकुमार आनंद भी नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली से बसपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि लगता नहीं कि बसपा कहीं भी अपना असर छोड़ेगी। इसकी बड़ी वजह मायावती का कमजोर नेतृत्व और उनके ऊपर लगे तमाम आरोप ही हैं।

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

संपादकीय

मुद्दों की भटकन

हम कहते नहीं थकते कि देश का विकास कुलांचे भर रहा है। हम दुनिया की सबसे तेज गति वाली अर्थव्यवस्था हैं। अभी पांचवें स्थान पर हैं व जल्दी ही तीसरे स्थान पर होंगे। ये ज्ञान की सदी है। 21वीं सदी भारतीय युवाओं की है। हम चांद पर पहुंचे। हमने मंगल के दरवाजे पर दस्तक दी। हमारी ओलंपिक में उपलब्धियां रहीं। पैरा ओलंपिक में हमारे मेडलों का सैकड़ा पहली बार आया। अकसर ये हमारे मीडिया की सुर्खियां हुआ करती थीं। लेकिन सवाल है कि आम चुनाव के तीसरे चरण तक आते-आते देश का राजनीतिक विमर्श इतना नकारात्मक क्यों हो गया? आखिर क्यों हम देश की जनता को सकारात्मक मुद्दों पर चुनाव में मतदान करने के लिये प्रेरित नहीं कर सकते? अब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, मुद्दों में नकारात्मकता व आक्रामकता क्यों है? क्यों राजनीतिक दलों के नेता आमने-सामने बैठकर अपने कार्यकाल की उपलब्धियों व भविष्य के एजेंडे को लेकर जनता से रूबरू नहीं होते? अमेरिका व अन्य विकसित देशों में शीर्ष राजनेताओं द्वारा लंबी बहसों से जनता को समझाने का प्रयास किया जाता रहा है। आखिर अमृतकाल के दौर में पहुंचकर भी देश में मतदाता इतना जागरूक क्यों नहीं हो पाया है कि उसे क्षेत्रवाद, धर्म-संप्रदाय, जातिवाद और अन्य संकीर्णताएं न लुभा सकें? क्यों चुनाव आयोग की मुहिम में बरामद रिकॉर्ड मूल्य की वस्तुओं में आधा मूल्य नशीले पदार्थों का होता है? क्यों छोटे-छोटे प्रलोभनों के जरिये मतदाता बहकते हैं? कहीं न कहीं हमारे नेताओं ने देश के जनमानस को पूरी तरह लोकतंत्र के प्रति जागरूक करने के बजाय संकीर्णता के शार्टकट से अपना उल्लू सीधा करना चाहा है। निस्संदेह, देश में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है। सोशल मीडिया के जरिये समाज में जागरूकता आई है। लोग सार्वजनिक विमर्श में अखबार व अन्य मीडिया की भाषा बोलते नजर आते हैं। तो फिर वे मतदान करते समय क्यों बहक जाते हैं? आखिर क्यों कहा जाता है कि फलां जगह पचास प्रतिशत या साठ प्रतिशत मतदान हुआ है? आखिर पचास प्रतिशत या चालीस प्रतिशत वोट न देने वाले लोग कौन हैं?

यहां एक तथ्य यह भी है कि यदि आम चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग धर्म, सांप्रदायिकता, क्षेत्र, जाति व अन्य संकीर्णताओं का सहारा ले रहे हैं तो कहीं न कहीं एक वजह यह भी है कि आजादी के साढ़े सात दशक बाद भी लोग इन मुद्दों की तरफ आकर्षित होते हैं? कई जगह सत्ता पक्ष के खिलाफ चुनावों में नाराजगी दिखाई देती है तो जनता फिर दूसरे राजनीतिक दल को सत्ता सौंप देती है। यह उसके पास विकल्प न होने की स्थिति होती है, लेकिन फिर दूसरा दल भी उन्हीं संकीर्णताओं को अपना एजेंडा बनाकर चुनाव मैदान में आ जाता है। सवाल यह है कि किसी दल ने अपने कार्यकाल में जो उपलब्धियां हासिल की हैं क्यों नहीं उन्हें चुनावी मुद्दा बनाया जाता है? क्या दल विशेष को अपनी बखान की गई उपलब्धियों की जमीनी हकीकत का अहसास होता है? भारत एक विविधता की संस्कृतियों का देश है। हर क्षेत्र की अपनी विशेषता और जरूरतें हैं। उत्तर भारत के राजनीतिक रुझान और दक्षिण भारत के राजनीतिक रुझान में हमेशा अंतर देखा गया है। जिसका लाभ एक क्षेत्र में पिछड़ने वाला राजनीतिक दल दूसरे क्षेत्र में उठाता है। हाल के दशकों में ऐसे कद्दावर नेता कम ही हुए हैं जिनकी राष्ट्रव्यापी स्वीकार्यता रही हो। लेकिन देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिये जरूरी है कि सत्ता की रीतियां-नीतियां पूरे देश के मनोभावों के अनुकूल हों। राजनेताओं की कार्यशैली और घोषणाएं संकीर्णताओं से मुक्त हों। यदि देश में नकारात्मक मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं तो पूरी दुनिया में कोई अच्छा संदेश नहीं जाएगा। जिसका असर हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता पर भी पड़ेगा। यदि राजनीतिक परिदृश्य में सकारात्मकता का प्रवाह नहीं होता तो हम कैसे दावा कर सकते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बड़े लोकतंत्र का बड़प्पन हमारे राजनेताओं में भी नजर आना चाहिए और मतदाताओं में भी। यदि हम संकीर्णताओं के पक्ष में मतदान कर रहे होते हैं तो कहीं न कहीं हम कमजोर व अयोग्य लोगों को ऊंची कुर्सी पर बैठाकर लोकतंत्र का अवमूल्यन कर रहे होते हैं।

पाकिस्तान में फलस्तीन, जर्मनी के राजदूत को इसलिए करना पड़ा कड़े विरोध का सामना

वह भी यह जानते थे कि ऐसे व्यवधान को हमेशा आयोजक या तो शांत करा देते हैं या प्रदर्शनकारी को हॉल छोड़कर चले जाने के लिए मना लेते हैं। लेकिन ऐसा करने के बजाय जर्मन राजदूत बेहद नाराज हो गए और अपनी बांहें फड़काते हुए प्रदर्शनकारी की तरफ इशारा करते हुए गुस्से में बोले, %यदि तुम चिल्लाना चाहते हो, तो बाहर चले जाओ, वहां तुम चिल्ला सकते हो, लेकिन चिल्लाना विमर्श नहीं है।

पाकिस्तान में इस्राइल के विरोध का आलम यह है कि शांति कार्यकर्ता अस्मा जहांगीर की स्मृति में होने वाले शांतिपूर्ण वार्षिक सम्मेलन में भी इस्राइल समर्थक जर्मनी के राजदूत को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल जर्मन राजदूत की उग्र प्रतिक्रिया के भी कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी गीतिका श्रीवास्तव समेत इस्लामाबाद में एक दर्जन से ज्यादा महिला राजदूत हैं। इन राजनयिकों की मौजूदगी से यह संदेश जाता है कि पाकिस्तान किस तरह से महिला राजनयिकों की सुरक्षा करता है। राजदूतों के अलावा हरेक दूतावास में कई विदेशी एवं स्थानीय महिलाएं कार्यरत हैं। आम तौर पर ये राजनयिक तब भी सुरक्षित महसूस करती हैं, जब वे बैठकों या कार्यक्रमों में पाकिस्तानियों से मिलती हैं। आम पाकिस्तानी स्वभाव से विनम्र होते हैं और यहां आने वाले विदेशी या भारतीय पर्यटक इस बात को समझते हैं और इसकी पुष्टि भी करते हैं। लेकिन इस हफ्ते लाहौर में यह सब कुछ बदल गया, जहां दुनिया की प्रसिद्ध वकील और शांति कार्यकर्ता अस्मा जहांगीर की याद में उनकी लॉ कंपनी और उनकी बेटियों ने एक बेहद लोकप्रिय सालाना कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पिछले पांच वर्षों से अस्मा जहांगीर की स्मृति में होने वाला यह आयोजन दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया है, जिसमें पाकिस्तानी प्रतिभागी, विदेशी राजदूत और विदेशी प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। इस वर्ष भारतीय मीडिया का एक प्रतिभागी भी शामिल था। यह सम्मेलन इसलिए भी प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि यह ऐसी दुर्लभ जगह है, जहां असंतुष्ट और वैसे लोग भी, जिन्हें बोलने का अवसर या स्थान नहीं मिलता, स्वतंत्र रूप से खुलकर अपनी बात रख सकते हैं, जिन्हें दुनिया सुनती है। अतीत में कई बार सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं एवं यहां तक कि न्यायाधीशों के भाषण के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा बाधा डाली गई है। यही इस सम्मेलन की खूबसूरती है, जहां हर कोई बोलने के लिए स्वतंत्र है। इस बार कार्यक्रम में %दक्षिण एशिया में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा% विषय पर एक सत्र था और प्रतिभागियों में जर्मन राजदूत अल्फ्रेड ग्रेनास भी थे, जो इस्लामाबाद में सबसे वरिष्ठ राजनयिक हैं। इन दिनों जर्मनी गाजा युद्ध में इस्राइल के समर्थन के लिए चर्चा में है। पाकिस्तान और अन्य मुल्कों में भी जर्मनी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और उस पर इस्राइल का समर्थन करके फलस्तीनियों के नरसंहार में सहयोग करने का आरोप लगाया जा रहा है। हर जगह, विशेष रूप से अमेरिका में छात्र सरकारी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, विशेषकर उन नीतियों का, जो इस्राइल का समर्थन कर रही हैं। इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि सम्मेलन में युवा छात्र प्रदर्शनकारियों ने जर्मन राजदूत के भाषण में बाधा डाली। एक युवा प्रदर्शनकारी ने चिल्लाकर कहा, %माफ कीजिएगा राजदूत महोदय, मैं आपके इस दुस्साहस से हैरान हूं कि आप यहां नागरिक अधिकार की बात करने आए हैं, जबकि आपका मुल्क फलस्तीनियों के अधिकारों के लिए बोलने वालों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहा है।% उसकी इस बात का कई लोगों ने समर्थन किया। यूरोपीय देशों के कई राजदूतों ने भी उसी मंच से भाषण दिया, लेकिन उनके भाषणों में कोई बाधा नहीं डाली गई। उनमें कई महिला राजदूत भी थीं। कई लोगों ने अपनी सीट से खड़े होकर कहा, %नदी से समुद्र तक% फलस्तीन को स्वतंत्र करो। असल में %नदी से समुद्र तक% एक राजनीतिक वाक्यांश है, जो जॉर्डन नदी और भूमध्यसागर के बीच के क्षेत्र को बताता है, जिसे फलस्तीन माना जाता है। लेकिन जर्मन राजदूत की प्रतिक्रिया सबसे हैरान करने वाली थी, जैसे यह उनके लिए अविश्वसनीय था कि कोई उनके भाषण में रुकावट डालेगा और गाजा युद्ध में जर्मनी की भूमिका के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। कोई सोच सकता था कि जर्मन राजदूत रुककर थोड़ा मुस्कराएंगे और फिर प्रदर्शनकारी से विनम्रता से बैठने के लिए कहेंगे और सवाल-जवाब के सत्र में सवालों का स्वागत करेंगे। वह भी यह जानते थे कि ऐसे व्यवधान को हमेशा आयोजक या तो शांत करा देते हैं या प्रदर्शनकारी को हॉल छोड़कर चले जाने के लिए मना लेते हैं। लेकिन ऐसा करने के बजाय जर्मन राजदूत बेहद नाराज हो गए और अपनी बांहें फड़काते हुए प्रदर्शनकारी की तरफ इशारा करते हुए गुस्से में बोले, %यदि तुम चिल्लाना चाहते हो, तो बाहर चले जाओ, वहां तुम चिल्ला सकते हो, लेकिन चिल्लाना विमर्श नहीं है। यदि तुम विमर्श करना चाहते हो, तो यहां आओ। हम चर्चा करेंगे, लेकिन चिल्लाओ मत। चिल्लाना कोई अच्छी बात नहीं है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मंच पर बैठे हुए कुछ राजदूतों और अन्य लोगों ने जर्मन राजदूत से शांत होने और अपना भाषण आगे बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन वह इतने ज्यादा गुस्सा थे कि सुन ही नहीं रहे थे। चूंकि इस सम्मेलन का लाइव प्रसारण हो रहा था, इसलिए पूरे पाकिस्तान ने उनका भयावह गुस्सा देखा और जर्मन राजदूत का व्यवहार देखकर लोग हैरान थे। तुरंत आयोजकों ने उस प्रदर्शनकारी को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अचानक जर्मन राजदूत की उग्र प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और पाकिस्तानियों ने पूछा कि क्या यह जर्मनी है, जो किसी को बाहर जाने के लिए कहता है। एक्स पर एक व्यक्ति ने टिप्पणी की, %जर्मन कूटनीति के लिए यह अच्छी बात नहीं है। पश्चिमी देशों में इस तरह के व्यवधान अपवाद नहीं, बल्कि आदर्श बन जाएंगे।% सभी टीवी चैनलों एवं अगले दिन अखबारों ने भी इस घटना को प्रमुखता से जगह दी। युवा पाकिस्तानी इतिहासकार और कार्यकर्ता अम्मार अली जान भी जर्मन राजदूत के व्यवहार से बहुत नाराज थे-'जर्मन राजदूत पाकिस्तानियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर व्याख्यान देते हैं, जबकि जर्मनी सरकार गाजा पर किसी भी चर्चा को प्रतिबंधित करती है।' कराची में भी ब्रिटिश उच्चायुक्त के आवास पर भी एक अन्य घटना घटी। पाकिस्तानी शास्त्रीय नृत्यांगना एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता सीमा केरमानी ने गाजा में संघर्ष विराम के लिए आवाज उठाई, तो उन्हें कार्यक्रम छोड़ने के लिए कहा गया और बाहर निकाल दिया गया। जो मुल्क गाजा युद्ध में इस्राइल का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें लगातार ऐसे विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ेगा और दुनिया भर में उनके राजदूतों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ेगा।

आज का इतिहास

- चिली में 1643 में आए विनाशकारी भूकंप में सेंटियागो की एक तिहाई आबादी खत्म हुई।
- दिल्ली में लाल किले का निर्माण 1648 में पूरा हुआ।
- इक्वेडोर गणराज्य की 1830 में स्थापना।
- भारत ने 1918 में राजस्थान के पोखरण में दो परमाणु परीक्षण किये।
- स्वतंत्र भारत की पहली संसद का सत्र 1952 में शुरू हुई।
- जार्डन और इराक ने 1958 में अरब फैडरेशन की स्थापना की।
- सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में देश के दूसरे राष्ट्रपति बने।
- देश का पहला ध्वजवाहक जहाज 1978 में आईएनएस दिल्ली सेवामुक्त हुआ।
- चीन में लगभग 2000 छात्रों ने थियान अन मन चौक पर भूख हड़ताल 1989 में शुरू की।
- चेल्सी स्मिथ मिस यूनिवर्स 1995 बनीं।
- भारत ने पोखरण में दो परमाणु परीक्षण 1998 में किए।
- अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1998 में परमाणु परीक्षण के विरोध में भारत के ख़िलाफ़ कड़े प्रतिबंध की घोषणा की।
- जापान ने 1998 में भारत को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगायी।
- जापानी छात्र के नागुयी 1999 में विश्व की सात सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र (25 वर्षीय) का पर्वतारोही बना।
- मिस इंडिया लारा दत्ता ने 2000 में साइप्रस में सम्पन्न प्रतियोगिता में मिस यूनीवर्स का ख़िताब जीता।
- रियाद में 2003 को आत्मघाती हमलों में 29 व्यक्ति मारे गये।
- पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के सभी नौ मंत्रियों ने जजों की बहाली के मुद्दे पर इस्तीफ़ा 2008 में दिया।
- भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता इला भट्ट को 2010 के निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित 2010 में किया गया।
- दुनियाभर में वॉनाक्राय रैनसमवेयर से 100 से अधिक देश प्रभावित 2017 में रहा।
- स्वतंत्रता सेनानी मथुरा प्रसाद मिश्र वैद्य का जन्म 1901 में हुआ।
- भारत के पांचवे राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली अहमद का जन्म 1905 में हुआ।
- हिंदी फ़िल्मों के हास्य अभिनेता असित सेन का जन्म 1917 में हुआ।
- 'भरतनाट्यम' की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना टी. बालासरस्वती का जन्म 1918 में हुआ।
- अमेरिकी हास्य अभिनेत्री (मौड ऐंड गोल्डन गर्ल्स) बीट्रिस आर्थर का जन्म 1922 में हुआ।
- मध्य प्रदेश सरकार में 'भारतीय जनता पार्टी' के राजनेता कैलाश विजयवर्गीय का जन्म 1956 में हुआ।
- आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना करने वाले आध्यात्मिक नेता श्री श्री रवि शंकर का जन्म 1956 में हुआ।
- मध्यकालीन भारत के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ मलिक अम्बर का निधन 1626 में हुआ।
- लखनऊ के प्रसिद्ध शायर हसरत मुहानी का निधन 1951 में हुआ।
- अंग्रेज़ी में लिखने वाले उत्कृष्ट भारतीय लेखकों में से एक आर. के. नारायण का निधन 2001 में हुआ।
- प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक हेमलता गुप्ता का निधन 2006 में हुआ।

दिखावे के जाल में फंसकर ऐश्वर्य का प्रदर्शन करता समाज

दिखावे के चक्कर में लोग दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं। अपनी मौलिकता और बुनियाद भूल जाना भी उन्हें परेशान नहीं करता। जबकि जितनी कोशिश हम दूसरों के जैसा बनने की करते हैं, उतनी कोशिश अगर खुद को संवारने में करें तो ज्यादा अच्छा हो। जेब खाली है, लेकिन समाज के लोग, रिश्ते-नातेदार क्या सोचेंगे, इसकी चिंता कुछ लोगों को सताए जा रही है। ऐसे लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि उनके यहां जो काम है, वह सामान्य तरीके से करें या समाज में लोगों की परवाह करते हुए दिखावा करते हुए करें। दिखावे के चक्कर में रुपया ज्यादा खर्च होगा और जो काम है, वह बहुत कम खर्च में हो जा सकता है। मगर क्या करें कि आज की तारीख में लोगों के लिए दिखावा ज्यादा जरूरी हो गया है। सामान्य तरीके से कोई काम कराने के बजाय जिसे देखो वही दिखावा करने में लगा हुआ है। दिखावे के इस शौक की सीमा आखिर कहां है? पड़ोस के घर में जब से एक सामाजिक काम होना तय हुआ था, तब से उस घर के लोगों से काम के कदम-कदम पूछे जा रहे थे। यह भी पूछा जा रहा था कि वह काम साधारण तरीके से किया जाएगा या शानो-शौकत के साथ। उस घर के व्यक्ति ने बताया कि काम साधारण तरीके से किया जाए, तो उसके बाद लोगों के हाव-भाव बदल गए और उनकी टीका-टिप्पणियों में अंतर आ गया। लोग बताने लगे कि आजकल तो साधारण से साधारण लोग भी 'अच्छे से' काम करते हैं, और आप तो समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं। अगर आप ही ऐसे साधारण तरीके से करेंगे तो फिर दूसरे लोग क्या करेंगे! लोगों का विचार सुनने के बाद उस घर के लोगों के दिमाग में अपने खानदान और पूर्वजों की शान की याद उमड़ने-घुमड़ने लगी। उनके नाम के 'कीर्तिमान' याद आने लगे। उसके बाद आपस में यह बात हुई कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारी मान-मर्यादा क्या रह जाएगी। पहले की शानो-शौकत के बरक्स आज नौबत कर्ज लेने की थी, मगर घर के लोग इसके लिए तैयार हो गए। उन्हें समाज में रहने के लिए दिखावे का रास्ता अपनाना जरूरी लगा। यह मामला एक उदाहरण भर है। आज की तारीख में हमारे इर्द-गिर्द इस तरह के हजारों लोग हैं, जो स्वेच्छा से या मजबूरी में दिखावा करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें लंबे समय तक आसपास के लोगों की आलोचनाएं सुननी पड़ेंगी। ऐसे में वे कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं। जबकि यह समझने की बात है कि दिखावा और उद्देश्य की पूर्ति, दो अलग-अलग चीज है। हर किसी के घर में समय-समय पर कोई न कोई काम होता रहता है। लोगों की माली हालात जैसी भी हो, लेकिन ज्यादातर कामों पर दिखावा हावी होता है। हालांकि अगर हम अपनी जरूरत को समझें और सिर्फ काम पूरा करने उद्देश्य की पूर्ति पर जोर दें तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसके लिए सोच में बदलाव की जरूरत है। जब हम किसी के यहां जाते हैं तो उसके बारे में अगले कुछ समय तक हमारे मनो-मस्तिष्क में बातें चलती रहती हैं। अगर हम उनका जीवन वैभव या विलासितापूर्ण देखते हैं तो हम भी उन्हीं की तरह जीना चाहते हैं। मन ही मन हम तुलना करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम भी उनके जैसा बनें। उनके घर में कोई सामान देखा तो अपने घर में भी वैसा ही चाहते हैं। यह सामाजिक हैसियत का विषय हो जाता है। इस चक्कर में कई लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है और परिवार में खटपट भी होती है। लोग दूसरे को बताते हैं कि हमारे पास वह सामान है और मैंने वह वहां से लिया है। उसकी यह खासियत हैઙ कीमत इतनी है। हो सकता है कि जिस व्यक्ति के पास वह सामान है, उसे उसकी जरूरत होगी। जिसके पास वह नहीं है, उसे उसकी जरूरत नहीं होगी। सिर्फ किसी के घर में कोई सामान देख कर बिना जरूरत के हम वही चीज अपने लिए अलग से लेते हैं तो यह दिखावा ही है। अगर व्यक्ति अपनी हैसियत और जरूरत के हिसाब से कदम उठाए तो वह कई परेशानियों से बच सकता है। हमारे आसपास अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो बताते रहते हैं कि हमने वह सामान इतने में खरीदा है और वह उतने में। यह बताने की कोई जरूरत हो या नहीं, फिर भी वे लोगों को बताते हैं। लोग भी ऐसे लोगों की बातों को काफी ध्यान से सुनते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। बताने वाले को शायद लगता है कि हमें अपना ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना चाहिए और सुनने-देखने वाले को लगता है कि हमें उनका दिखावा देखना चाहिए।

इसके बाद लोग सोचने लगते हैं कि अगर मेरे पास वह सामान नहीं होगा या हम उनके जैसा कपड़े नहीं पहेंगे तो शायद हमारी सामाजिक स्थिति कमतर हो जाएगी। हालांकि यह समझने की जरूरत है कि कपड़े या कोई चीज होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो समाज को चाहिए कि वह इस फर्क को समाप्त करे। कई बार तो लगता है कि यह दिखावा एक रोग है, जिसे हर हालात में बदलना चाहिए।

इस दिखावे के चक्कर में लोग दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं। अपनी मौलिकता और बुनियाद भूल जाना भी उन्हें परेशान नहीं करता। जबकि जितनी कोशिश हम दूसरों के जैसा बनने की करते हैं, उतनी कोशिश अगर खुद को संवारने में करें तो ज्यादा अच्छा हो। आखिर हम अपने हिसाब से जीवन जीना क्यों नहीं पसंद करते हैं? हम दूसरों के हिसाब से जीवन क्यों जीने लगते हैं? क्या हमारे जीवन जीने का तौर-तरीका कोई बाहरी व्यक्ति तय करेगा? यह हमें तय करना चाहिए। यह निर्धारित करने का अधिकार हमारा होना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें अंदर से खुशी मिलेगी जो बाहरी और कृत्रिम खुशी से कई हजार गुणा अच्छी होगी।

राजनीतिक दलों को आपराधिक छवि के लोगों को चुनावी मैदान में उतारने से परहेज करने की जरूरत

वे उसी को उम्मीदवार बनाते हैं, जिसके जीतने की संभावना अधिक होती है, चाहे वह आपराधिक छवि का ही क्यों न हो। माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को चुनाव मैदान में नहीं उतारेगी। इसे लेकर उसमें ऊहापोह भी देखी जा रही थी। मगर लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार उसने उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दे दिया।

बृजभूषण शरण सिंह पर बेशक अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, मगर जिस तरह महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए और जांचों से भी उनके खिलाफ तथ्य सामने आए, उससे उन्हें फिलहाल निरपराध नहीं कहा जा सकता। अब यह उजागर है कि प्रत्याशी के चुनाव में राजनीतिक दलों से साफ-सुथरी छवि का ध्यान रखने की चाहे जितनी अपेक्षा और मांग की जाए, पर उनका मकसद एक ही होता है। वे उसी को उम्मीदवार बनाते हैं, जिसके जीतने की संभावना अधिक होती है, चाहे वह आपराधिक छवि का ही क्यों न हो। माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को चुनाव मैदान में नहीं उतारेगी। इसे लेकर उसमें ऊहापोह भी देखी जा रही थी। मगर लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार उसने उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दे दिया। बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप में अदालत की सुनवाइयों का सामना कर रहे हैं। उनकी वजह से भाजपा को खासी किरकिरी झेलनी पड़ी। यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ ने भी बृजभूषण शरण सिंह पर अंगुली उठाई थी, जिसके चलते उन्हें कुश्ती महासंघ के चुनाव से अलग रहना पड़ा। मगर उन्होंने कुश्ती महासंघ पर अपना दबदबा कायम रखने की नीयत से अपने एक करीबी को अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया और उसे ही विजय भी मिली। उस पर भी अंगुलियां उठनी शुरू हुईं, तो खेल मंत्रालय को आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह के करीबी को अध्यक्ष पद से हटाना पड़ा। यह समझना मुश्किल है कि भाजपा के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी, जो उसने बृजभूषण शरण सिंह से अपना पल्ला छुड़ाना उचित नहीं समझा। उनकी जगह उनके बेटे को टिकट दे दिया। इससे बृजभूषण शरण सिंह को लेकर उठ रहे सवाल शांत नहीं हो जाएंगे। इसके पीछे एक वजह तो यह बताई जाती है कि उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज लगातार भाजपा पर आरोप लगा रहा था कि वह राजपूत समाज के प्रत्याशियों का टिकट काट रही है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि बृजभूषण का टिकट कटने से उनके बगावत करने और उस सीट से भाजपा के हारने की आशंका हो सकती थी। मगर इस तरह समझौता करके भाजपा अगर अपनी एक सीट बचा भी ले, तो इससे उसके सिद्धांतों पर सवाल तो उठेंगे ही। लंबे समय से मांग की जा रही है कि राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करते हुए उनकी छवि का ध्यान रखें। निर्वाचन आयोग ने भी कहा था कि राजनीतिक दल आपराधिक छवि के लोगों को चुनावी मैदान में उतारने से परहेज करें। अगर वे किसी ऐसे प्रत्याशी को टिकट देती हैं, तो उन्हें इसका स्पष्टीकरण देना होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या उसकी जगह कोई और प्रत्याशी नहीं मिला। बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे को टिकट देकर बेशक भाजपा इस जवाबदेही से बच गई है, पर यह तो जाहिर है कि वह चुनाव उनका बेटा नहीं, एक तरह से वे खुद लड़ेंगे। बृजभूषण शरण सिंह पर बेशक अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, मगर जिस तरह महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए और जांचों से भी उनके खिलाफ तथ्य सामने आए, उससे उन्हें फिलहाल निरपराध नहीं कहा जा सकता। यह भी छिपी बात नहीं है कि उनके खिलाफ आंदोलन पर उतरी महिला खिलाड़ियों को किस तरह दमन के जरिए आंदोलन से हटाया गया। इन सबको लेकर लगातार सरकार के रवैये पर सवाल उठते रहे हैं। इसके बावजूद उनकी जगह उनके बेटे को टिकट देकर भाजपा ने एक तरह से एक नए विवाद को गले लगा लिया है। इसे लेकर विपक्षी दलों और महिला खिलाड़ियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है।

ओडिशा की पुरी सीट से लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संदेश

लोकसभा या विधानसभा चुनावों में एक प्रत्याशी को कितना खर्च करना है, इसकी सीमा तो है, लेकिन पार्टियों के खर्च की कोई सीमा नहीं है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक उम्मीदवार अधिकतम 90 लाख और विधानसभा चुनाव के लिए अधिकतम 40 लाख खर्च कर सकता है, कुछ छोटे राज्यों के लिए यह सीमा 70 लाख और 28 लाख रूपए है।

ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने यह कहते हुए टिकट लौटा दी है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए धन नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के उम्मीदवार पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, इसलिए वह उनका मुकाबला नहीं कर सकती। सुचारिता मोहंती का यह संदेश कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है कि चुनाव प्रणाली पर धनाढ्य लोगों का कब्जा हो गया है और लोकतंत्र पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। सुचारिता ने भारतीय लोकतंत्र की सच्चाई को नंगा करके रख दिया है कि राजनीति अब सेवा नहीं, अमीरों का व्यवसाय बन चुकी है। चुनावों में धन का बढ़ता प्रभाव लोकतांत्रिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रहा है। अब बड़े राजनीतिक दल बहुत मजबूरी में ही अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट देते हैं। पिछले एक दशक में कार्यरत और रिटायर्ड नौकरशाहों का बड़े पैमाने पर राजनीति में प्रवेश हो रहा है।ઙ वे किसी भी राजनीतिक दल में प्रवेश पाते ही टिकट पा लेते हैं, और जीवन भर किए गए भ्रष्टाचार से एकत्र कमाई का इस्तेमाल करके चुनाव जीत भी जाते हैं। ज्यादातर पार्टियां एक आदमी या परिवार के नाम पर चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी सिर्फ मोदी के नाम पर चलने वाली पार्टी बनती जा रही है। कांग्रेस के सोनिया-राहुल हैं, सपा के अखिलेश यादव हैं, बसपा की मायावती हैं, आम आदमी पार्टी के अरविन्द केजरीवाल हैं, जदयू के नीतीश कुमार हैं, राकांपा के शरद पवार हैं, राजद के लालू हैं, शिवसेना (यूबीटी) के उद्धव ठाकरे हैं, डीएमके के स्टालिन हैं आदि आदि7 इन पार्टियों के भीतर कोई लोकतंत्र नहीं है। ये सारी पार्टियां प्रोपराइटरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रही हैं। लाखों-करोड़ों लेकर टिकट बेचती हैं और दावा करती हैं कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है। क्या कारण है कि राजनीतिक दल अपने समर्पित कार्यकर्ता का टिकट काट कर या हक मार कर भ्रष्ट नौकरशाह को टिकट थमा देते हैं। सच यह है कि अपने काले धन के बूते भ्रष्ट लोग राजनीतिक दल को अपनी काली कमाई का एक हिस्सा देकर टिकट हासिल करते हैं, तो वे एक तरह से राजनीति में निवेश कर रहे होते हैं कि जीत कर अपने निवेश का कई गुना वसूल करेंगे। ऐसे नौकरशाहों को पहली बार लोकसभा में पहुंचते ही मंत्री बनते और फिर अगली बार टिकट कटते भी देखा जा रहा है। सुचारिता ने कांग्रेस पार्टी को अपना टिकट लौटाकर देश को बताया है कि राजनीति और चुनावों में काले धन के बढ़ते इस्तेमाल से देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में आम लोगों की भूमिका लगभग खत्म हो गई है। करीब दस साल पहले दक्षिण एशियाई देशों के एक सम्मेलन में इस विषय पर गहन चर्चा हुई थी। इस सम्मेलन में कहा गया था कि अगर चुनावों में धन बल का इस्तेमाल न रोका गया तो निष्पक्ष चुनाव करवाना मुश्किल हो जाएगा। एडीआर ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि चुनाव सुधारों के मद्देनजर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से किए जाने वाले खर्च में अपारदर्शिता का मुद्दा बहुत चिंतनीय विषय है।

लोकसभा या विधानसभा चुनावों में एक प्रत्याशी को कितना खर्च करना है, इसकी सीमा तो है, लेकिन पार्टियों के खर्च की कोई सीमा नहीं है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक उम्मीदवार अधिकतम 90 लाख और विधानसभा चुनाव के लिए अधिकतम 40 लाख खर्च कर सकता है, कुछ छोटे राज्यों के लिए यह सीमा 70 लाख और 28 लाख रूपए है। सच्चाई यह कि उमीदवार तो अपने काले धन से करोड़ों रूपए खर्च करते ही हैं, राजनीतिक दल भी अलग से करोड़ों रूपए खर्च कर देते हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले मार्च के शुरू में कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कांफ्रेंस करके कहा था कि आयकर विभाग ने उसके खाते सील कर दिए हैं और उसके पास चुनाव लड़ने के लिए कोई पैसा नहीं बचा। सुचारिता मोहंती ने उसी की पुष्टि की है, जब उन्होंने टिकट लौटाते हुए अपनी चिठ्ठी में लिखा कि जब उन्होंने उड़ीसा के चुनाव प्रभारी अजय कुमार से इलेक्शन फंडिंग के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए उन्हें खुद ही पैसा जुटाना होगा। इससे यह भी जाहिर हुआ कि अगर मजबूरी में कोई राजनीतिक दल किसी कार्यकर्ता को टिकट दे भी देता है, तो उसके खुद के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वह चुनाव लड़ सके। उसे अपने राजनीतिक दल पर निर्भर रहना पड़ता है, सुचारिता ने यही सोचा था कि जैसे हमेशा से कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार को चुनाव में खर्च करने के लिए सूटकेस भेजती है, वैसे उसे भी सूटकेस मिलेगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

विकास की दर तेज गति से आगे बढ़ रही

दिनांक 1 मई, 2024 को अप्रैल, 2024 माह में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संग्रहण से संबंधित जानकारी जारी की गई है। माह अप्रैल 2024 के दौरान जीएसटी का संग्रहण पिछले सारे रिकार्ड तोड़ते हुए 2.10 लाख करोड़ रु पये के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो निश्चित ही, भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शा रहा है। वित्त वर्ष 2022 में जीएसटी का औसत कुल मासिक संग्रहण 1.20 लाख करोड़ रु पये रहा था, जो वित्त वर्ष 2023 में बढक़र 1.50 लाख करोड़ हो गया एवं वित्त वर्ष 2024 में 1.70 लाख करोड़ रु पये के स्तर को पार कर गया। अब तो अप्रैल, 2024 में 2.10 लाख करोड़ रु पये के स्तर से भी आगे निकल गया है। इससे आभास हो रहा है कि देश के नागरिकों में आर्थिक नियमों के अनुपालन के प्रति रु चि बढ़ी है, अर्थव्यवस्था का तेजी से औपचारीकरण हो रहा है एवं भारत में आर्थिक विकास की दर तेज गति से आगे बढ़ रही है। भारत में वर्ष 2014 के पूर्व ऐसा समय था जब केंद्रीय नेतृत्व में नीतिगत फैसले लेने में हिचकिचाहट रहती थी और अर्थव्यवस्था विश्व की हिचकोले खाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल थी, परंतु केवल 10 वर्ष पश्चात केंद्र में मजबूत नेतृत्व एवं मजबूत लोकतंत्र के चलते वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। आज भारत आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक मंच पर नित रिकार्ड बना रहा है। वैश्विक स्तर पर विदेशी प्रेषण के मामले में भारत प्रेषण प्राप्तकर्ता के रूप में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। भारत में सबसे बड़ा सिंक्रोनाईजड बिजली ग्रिड है। बैंकिंग क्षेत्र में वास्तविक समय लेन देन की सबसे बड़ी संख्या आज भारत में ही संपन्न हो रही है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है एवं विश्व में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सडक़ नेट्वर्क है। मात्रा की दृष्टि से भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल्स उद्योग है। भारत में विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेट्वर्क है।

भारत में गरीबी उन्मूलन पर पूर्व में गम्भीरता से ध्यान ही नहीं दिया गया

आरती कुमारी

भारत में हाल ही के वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या में आई भारी कमी के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं विकसित देशों के कई वित्तीय एवं आर्थिक संस्थानों ने भारत की आर्थिक नीतियों की मुक्त कंठ से सराहना की है। यह सब दरअसल भारत में तेज गति से हुए वित्तीय समावेशन के चलते सम्भव हुआ है। याद करें वर्ष 1947, जब देश ने राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उस समय देश की अधिकतम आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर थी। जबकि, भारत का इतिहास वैभवशाली रहा है एवं भारत को 'सोने की चिड़िया' कहा जाता था। परंतु, पहिले अरब से आक्रांताओं एवं बाद में अंग्रेजों ने भारत को जमकर लूटा तथा देश के नागरिकों को गरीबी की ओर धकेल दिया। भारत में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत से 'गरीबी हटाओ' के नारे तो बहुत लगे परंतु, गरीबी नहीं हटी। 'गरीबी हटाओ' के नारे के साथ राजनैतिक दलों ने कई बार सता हासिल की किंतु देश से गरीबी हटाने के गम्भीर प्रयास शायद कभी नहीं हुए और गरीब वर्ग को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना को वर्ष 2014 में लागू किया गया जिसके माध्यम से आम नागरिकों के बैंकों में बचत खाते खोले गए, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की गई, धन के प्रेषण की सुविधा, बीमा तथा पेंशन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इस योजना के अंतर्गत जमाराशि पर ब्याज मिलता है, हालांकि बचत खाते में कोई न्यूनतम राशि रखना आवश्यक नहीं है। एक लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी मिलता है। साथ ही, इस योजना के माध्यम से दो लाख रुपए का जीवन बीमा उस लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों पर मिलता है। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना को सफलता पूर्वक लागू करने के बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (Direct Benefit Transfer Scheme) को भी लागू किया गया जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गरीब वर्ग के हितार्थ चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि को सीधे ही हितग्राहियों के बचत खातों में जमा कर दिया जाता है। इससे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 100 प्रतिशत लाभ की राशि सीधे ही उनके हाथों में पहुंच जाती है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के अंतर्गत, वर्ष 2013 के बाद से 31 मार्च 2022 तक, 24.8 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे ही लाभार्थियों के बचत खातों में जमा की जा चुकी है, इसमें अकेले वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही 6.3 लाख करोड़ रुपए की राशि लाभार्थियों के बचत खातों में हस्तांतरित की गई थी। वर्ष 2014 के पूर्व तक जब इन लाभार्थियों के बचत खाते विभिन्न बैंकों में नहीं खुले थे तब तक कांग्रेस एवं अन्य सरकारों के शासनकाल के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि सामान्यतः नकद राशि के रूप में इन लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाती थी। आपको शायद ध्यान होगा कि एक बार देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि के एक रुपए में से केवल 16 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंच पाते हैं। शेष 84 पैसे इन योजनाओं को चलाने वाले तंत्र की जेब में पहुंच जाते है। अब आप स्वयं आंकलन करें कि यदि बैंक में 50 करोड़ लाभार्थियों के बचत खाते नहीं खुले होते और यदि उक्त वर्णित केवल 8 वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न लाभार्थियों को नकद राशि के रूप में उपलब्ध कराई जाती तो इन लाभार्थियों के पास केवल 4 लाख करोड़ रुपए की राशि ही पहुंच पाती एवं शेष 21 लाख करोड़ रुपए की राशि इन योजनाओं को चलाने वाले तंत्र के पास ही रह जाती। अब आप आगे एक और कल्पना कर लीजिये कि पिछले 70 वर्षों के दौरान कितनी भारी भरकम राशि इन गरीब हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पाई होगी। इस राशि का आकार शायद आपकी कल्पना से भी परे है। सहायता की यह राशि यदि गरीबों तक पहुंच गई होती तो शायद हो सकता है कि देश से अभी तक गरीबी भी दूर हो चुकी होती। अब जब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के अंतर्गत सहायता की राशि हितग्राहियों के खातों में सीधे ही पहुंच रही है तो देश से गरीबी भी तेजी से कम होती दिखाई दे रही है, जिसकी तारीफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुक्त कंठ से हो रही है। पिछले 10 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय बैंकों के माध्यम से इस दृष्टि से बहुत ठोस कार्य किया गया है। न केवल 50 करोड़ से अधिक बचत खाते विभिन्न भारतीय बैंकों में खोले गए हैं बल्कि आज इन बचत खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी जमा हो गई है और बचत की यह भारी भरकम राशि बैंकों द्वारा देश के आर्थिक विकास में उपयोग की जा रही है। इस प्रकार, भारत का गरीब वर्ग भी इन बैंक खातों के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान देता हुआ दिखाई दे रहा है। उक्त 50 करोड़ से अधिक बचत खातों में 50 प्रतिशत खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं, अर्थात अब भारतीय महिलाएं, ग्रामीण महिलाओं सहित, भी आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। भारी मात्रा में खोले गए इन बचत खातों के माध्यम से गरीब वर्ग के नागरिकों का बैंकिंग सम्बंधी इतिहास भी धीरे धीरे विकसित हो रहा है, जिससे इस वर्ग के नागरिकों को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने में आसानी होने लगी है। केंद्र सरकार द्वारा बैकों के माध्यम से लागू की जा रही विभिन्न प्रकार की ऋण योजनाओं का लाभ भी अब गरीब वर्ग को मिलने लगा है। कोरोना महामारी के तुरंत बाद जब देश में स्थितियां सामान्य बनने की ओर अग्रसर हो रहीं थीं तब केंद्र सरकार ने खोमचा वाले, रेहड़ी वाले एवं ठेलों पर अपना सामान बेचकर छोटे छोटे व्यवसाईयों द्वारा अपना व्यापार पुनः प्रारम्भ करने के उद्देश्य से एक विशेष ऋण योजना प्रारम्भ की थी। इस योजना के अंतर्गत उक्त वर्णित छोटे छोटे व्यवसाईयों को बैंक द्वारा आसानी से ऋण प्रदान किया गया था क्योंकि इस वर्ग के नागरिकों के पूर्व में ही बैकों में बचत खाते खुले हुए थे। बैकों द्वारा यह ऋण बगैर किसी व्यक्तिगत गारंटी के प्रदान किया गया था। और, हजारों की संख्या में छोटे छोटे व्यवसाईयों ने निर्धारित समय सीमा में इस ऋण को अदा कर, पुनः बढ़ी हुई राशि के ऋण बैंकों से लिए थे और अपने व्यवसाय को तेजी से आगे बढ़ाया था। बैंकों में खोले गए बचत खातों से गरीब वर्ग को इस प्रकार के लाभ भी हुए हैं। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने देश के हर गरीब नागरिक को वित्तीय मुख्य धारा से जोड़ा है। समाज के अंतिम छोर पर बैठे गरीबतम व्यक्तियों को भी इस योजना का लाभ मिला है। आजादी के लगभग 70 वर्षों के बाद भी भारत के 50 प्रतिशत नागरिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ अर्थात बैकों से नहीं जुड़े थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाताधारकों को प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं का लाभ भी भारी मात्रा में नागरिकों ने उठाया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 15.99 करोड़ नागरिक जुड़ गए हैं, इनमें 49 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं, इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का जीवन बीमा केवल 436 रुपए के वार्षिक प्रीमीयम पर उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 33.78 करोड़ नागरिक जुड़ गए हैं, इनमें 48 प्रतिशत महिला लाभार्थी हैं, इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा केवल 20 रुपए के वार्षिक प्रीमीयम पर उपलब्ध कराया जाता है। अटल पेंशन योजना से 5.20 करोड़ नागरिक जुड़ गए हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत 40.83 करोड़ नागरिकों को ऋण प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना अपने प्रारम्भिक समय से ही वित्तीय समावेशन के लिए एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत खोले गए बचत खातों में से लगभग 67 प्रतिशत बचत खाते ग्रामीण एवं अर्धशहरी केंद्रों पर खोले गए हैं, जिसे मजबूत होती ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था को आसान बनाने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने का कार्य भी सफलतापूर्वक किया गया है। इस योजना के अंतर्गत खोले गए बचत खाताधारकों को रूपे डेबिट कार्ड प्रदान किया गया है। यह रूपे कार्ड उपयोगकर्ता द्वारा समस्त एटीएम, पोस टर्मिनल एवं ई-कामर्स वेबसाइट पर लेनदेन करने की दृष्टि से उपयोग किया जा सकता है। वर्ष 2016 में 15.78 करोड़ बचत खाताधारकों को रूपे कार्ड प्रदान किया गया था एवं अप्रेल 2023 तक यह संख्या बचकर 33.5 करोड़ तक पहुंच गई है।

गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान से कर्जदाताओं ने भी मुहं मोड़ा!

अशोक भाटिया

गले तक कर्ज में डूबे और सातवें आसमान पर पहुंच चुकी महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। अब उसे और कर्ज मिलने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी चरमरा चुकी है. मुल्क पर कर्ज के कुचक्र में फंस चुका है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जानकारी के अनुसार उसका कुल कर्ज और देनदारी दिसंबर, 2023 तक 27.2 फीसदी बढ़कर 81.2 ट्रिलियन रुपये (131 अरब डॉलर) पहुंच गई है. पिछले एक साल में ही देश पर कर्ज 17.4 ट्रिलियन रुपये की वृद्धि हुई है. पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 63.83 ट्रिलियन रुपये था । कर्ज का यह जंजाल अभी और गहरा हो गया जब पाकिस्तान ने आईएमएफ से एक और बेलआउट पैकेज मांगा था . साथ ही देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल भी नहीं आ पा रहा था . हाल ही में हुए आम चुनाव में देश में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला. ऐसे में पाकिस्तान इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मोर्चे पर असफल होता दिखाई दे रहा है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, यह स्थिति बनने की सबसे बड़ी वजह बाहरी कर्ज और ब्याज के पेमेंट हैं. आईएमएफ , एफडीआई और अन्य जगहों से मिले कर्ज 26.17 फीसदी बढ़कर 33.611 ट्रिलियन रुपये हो गए हैं. सिर्फ आईएमएफ का कर्ज ही 24.17 फीसदी बढ़कर 2.142 ट्रिलियन रुपये पहुंच गया है । अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी कहा है कि पाकिस्तान को कर्ज चुकाने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही वैश्विक वित्तीय निकाय ने नकदी की कमी से जूझ रहे देश की कर्ज चुकाने की क्षमता पर संदेह किया जा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में शनिवार को यह जानकारी दी गई। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में वाशिंगटन बेस्ड बैंक का आकलन ऐसे वक्त में आया है, जब आईएमएफ सहायता दल शुक्रवार को पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए पहुंचा है। इस्लामाबाद ने विस्तारित फंड सुविधा के तहत नए राहत पैकेज का अनुरोध किया था। आईएमएफ का दल इस अनुरोध पर चर्चा के लिए आया है। जियो न्यूज ने इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान पर जारी अपनी स्टाफ रिपोर्ट में आईएमएफ के हवाले से कहा कि कर्ज चुकाने की पाकिस्तान की क्षमता गंभीर जोखिमों के अधीन है और यह नीतियों को लागू करने तथा समय पर बाहरी फंडिंग पर निर्भर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विशेष रूप से सुधारों को अपनाने में देरी, उच्च सार्वजनिक ऋण और सकल वित्त पोषण की जरूरतें और सामाजिक-राजनीतिक कारक - नीति कार्यान्वयन को खतरे में डाल सकते हैं। आईएमएफ स्टाफ रिपोर्ट में कहा गया, 'डाइनसाइड रिस्क असाधारण रूप से ऊंची बनी हुई है। जबकि नई सरकार ने स्टैंडबाय अरेंजमेंट पॉलिसीज को जारी रखने के अपने इरादे का संकेत दिया है। वहां राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। यह अनिश्चितता पॉलिसी मेकिंग पर गहरा असर डाल सकती है, खासकर जीवनयापन की ऊंची लागत और अन्य राजनीतिक जटिलताओं को देखते हुए।' इसमें चेतावनी दी गई है कि यह अनिश्चितता पॉलिसी मेकिंग पर गहरा असर डाल सकती है, खासकर जीवनयापन की ऊंची लागत और अन्य राजनीतिक जटिलताओं को देखते हुए। जियो न्यूज ने पाकिस्तान पर इस महीने की शुरुआत में जारी अपनी स्टाफ रिपोर्ट में वाशिंगटन स्थित ऋणदाता के हवाले से कहा है कि फंड चुकाने की पाकिस्तान की क्षमता महत्वपूर्ण जोखिमों के अधीन है और नीति कार्यान्वयन और समय पर बाहरी वित्तपोषण पर गंभीर रूप से निर्भर है। असाधारण रूप से उच्च जोखिम - विशेष रूप से सुधारों को अपनाने में देरी, उच्च सार्वजनिक ऋण और सकल वित्तपोषण की जरूरतें, कम सकल भंडार और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) की शुद्ध एफएक्स व्युत्पन्न स्थिति, प्रवाह में गिरावट और सामाजिक-राजनीतिक कारक - नीति कार्यान्वयन को खतरे में डाल सकते हैं। और पुनर्भुगतान क्षमता और ऋण स्थिरता को नष्ट कर देता है ऐसा रिपोर्ट में कहा गया ।इसमें आगे कहा गया है कि पाकिस्तान की फंड चुकाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए बाहरी व्यवहार्यता बहाल करना महत्वपूर्ण है, और यह मजबूत नीति कार्यान्वयन पर निर्भर करता है, जिसमें बाहरी संपत्ति संचय और विनिमय दर लचीलापन शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि भू-राजनीतिक अस्थिरता जोखिम का एक अतिरिक्त स्रोत है, भले ही पिछली समीक्षा के बाद से वैश्विक वित्तीय स्थितियों को लेकर अनिश्चितता में कुछ हद तक गिरावट आई है।वैश्विक ऋणदाता ने कहा कि देश को अगले पांच वर्षों के दौरान 123 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल वित्तपोषण की आवश्यकता है, साथ ही कहा कि पाकिस्तान को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2025-26 में 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग करने की उम्मीद है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि संकटग्रस्त देश को 2026-27 में 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 2027-28 में 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2028-29 में 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उम्मीद है।मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, वैश्विक ऋणदाता की एक सहायता टीम देश की वित्तीय टीम के साथ अगले दीर्घकालिक ऋण कार्यक्रम के पहले चरण पर चर्चा करेगी।सूत्रों ने कहा कि अग्रिम दल बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंच चुका है जबकि आईएमएफ मिशन 16 मई को पहुंचेगा। टीम विभिन्न विभागों से डेटा प्राप्त करेगी और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ वित्तीय वर्ष 2025 (FY2025) के आगामी बजट पर चर्चा करेगी।सूत्रों ने यह भी बताया कि टीम 10 दिनों से अधिक समय तक पाकिस्तान में रहेगी।पाकिस्तान ने जलवायु वित्तपोषण के माध्यम से वृद्धि की संभावना के साथ ईईएफ के तहत तीन वर्षों के लिए 6 और 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अगले बेलआउट पैकेज की मांग की थी । आईएमएफ के एक बयान में पहले कहा गया था, "अब सुधारों में तेजी लाना कार्यक्रम के आकार से अधिक महत्वपूर्ण है, जो सुधार के पैकेज और भुगतान संतुलन की जरूरतों द्वारा निर्देशित होगा।"इस बीच, पाकिस्तान ने अपने बाहरी वित्तपोषण में 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारी अंतर को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में चीन जैसे प्रमुख सहयोगियों से लगभग 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लेने का फैसला किया है क्योंकि संघीय सरकार का लक्ष्य बजट लक्ष्यों को प्राप्त करना है। आईएमएफ टीम के देश में अपेक्षित आगमन से पहले।वित्त मंत्रालय के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, सऊदी अरब से 5 अरब अमेरिकी डॉलर, संयुक्त अरब अमीरात से 3 अरब अमेरिकी डॉलर और चीन से 4 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद ली जाएगी, साथ ही कहा गया है कि अगले वित्तीय वर्ष में चीन से और नए वित्तपोषण का अनुमान भी शामिल किया जाएगा। पर यह मिलेगा कि नहीं इस बात पर अब शंका जताई जा रही है । पाकिस्तान को नए ऋण कार्यक्रम के तहत आईएमएफ से 1 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक प्राप्त होना था जबकि विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से नए वित्तपोषण को भी अनुमानित बजट में शामिल किया गया था । ज्ञात हो कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और एक करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का यह अनुमान 1.8 प्रतिशत की सुस्त आर्थिक वृद्धि दर के साथ बढ़ती महंगाई पर आधारित है, जो चालू वित्त वर्ष में 26 प्रतिशत पर पहुंच गयी है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान तीन साल तक घाटे में रह सकता है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि करीब 9.8 करोड़ पाकिस्तानी पहले से ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। वही, गरीबी की दर लगभग 40 प्रतिशत पर बनी हुई है। गरीबी रेखा के ठीक ऊपर रह रहे लोगों के भी नीचे आने का जोखिम है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पाकिस्तान में महंगाई दर 30 फीसदी से ऊपर थी।

हाशिये पर जाती बहुजन समाज पार्टी

आर.के. सिन्हा

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटा दिया है। छह महीने पहले ही उन्होंने आकाश को धूम - धाम से अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। उन्होंने कहा कि आकाश तब तक उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं बन सकते , जब तक वे "पूरी तरह परिपक्व" नहीं हो जाते। आकाश आनंद बीते उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शुरुआती दो चरणों में बसपा के प्रचार अभियान का मुख्य चेहरा थे। उनके भाषणों में भाजपा और समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखे हमले किए गए थे। अप्रैल में सीतापुर में एक चुनावी रैली के दौरान कथित रूप से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। मायावती को लगता है कि ये भाषण पार्टी द्वारा निर्धारित नियमों और नीतियों से भटक गए थे। मायावती के इस तरह के अचानक फैसले पहले भी देखे गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इसका पार्टी और उनके दलित आंदोलन पर क्या असर होगा। बसपा के संस्थापक कांशी राम ने अपने परिवार को पार्टी से दूर रखा था और मायावती को उनके नेतृत्व कौशल के कारण ही अपना उत्तराधिकारी चुना था। इस रणनीति ने पार्टी को 2007 में उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सत्ता दिलाई, जहाँ दलित समाज आबादी का लगभग 21% हिस्सा हैं। हालांकि, मायावती बसपा को एक व्यापक बहुजन समाज की पार्टी के रूप में विकसित करने में विफल रहीं। पार्टी के कई संस्थापक नेता, जो ओबीसी, अल्पसंख्यक और दलित समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे, मायावती के नेतृत्व शैली से असंतुष्ट होकर पार्टी छोड़ गए। आज बसपा अपने पुराने अखिल भारतीय दलित संगठन के रूप में अपनी पहचान लगभग खो चुकी है, भले ही मायावती कहने को तो आज भी देश की सबसे बड़ी दलित नेता बनी हुई हैं। मायावती द्वारा बसपा के आंदोलनकारी चरित्र को नजरअंदाज करने और अपने परिवार के भीतर नेतृत्व को मजबूत करने के उनके फैसले ने पार्टी के विकास को नुकसान तो पहुँचाया ही है। दुर्भाग्य से, कई अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने भी यही रास्ता अपनाया है, जिनमें वे दल भी शामिल हैं जो वैचारिक रूप से शक्तिशाली आंदोलनों से उभरे थे। इसमें तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलनों से विकसित हुई डीएमके और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार की राष्ट्रीय जनता दल शामिल है, जो लोहियावादी समाजवादी परंपरा

और मंडल राजनीति की विरासत का दावा करती हैं । बसपा के मामले में, पार्टी के पतन को नए दलित नेताओं के उदय ने भी तेज किया है। पार्टी का वोट शेयर लगातार गिर रहा है। इस बात की संभावना कम ही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा उत्तर प्रदेश में कोई उल्लेखनीय परिणाम हासिल कर सकेंगी। अब उत्तर से पंजाब की ओर चलते हैं। बसपा की ताजा ताकत को जानने के लिए पंजाब के समीकरणों को जानना जानना जरूरी है, क्योंकि ; बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय कांशीराम जी पंजाब के रोपड़ शहर से ही थे। आप जब चंडीगढ़ से रोपड़ शहर में प्रवेश करते हैं तो आपको समूचे शहर की फिजाओं में लोकसभा चुनावों का रंग घुला हुआ मिलता है। सारा माहौल गुलजार है। आमतौर पर इधर बातचीत का मुख्य बिन्दू यही है कि राज्य की 13 लोकसभा सीटों में किस दल के हक के कितनी सीटें जाएंगी। पर यह एक दुर्भाग्य ही है कि बसपा दूर-दूर तक कहीं चर्चा में नहीं है। सभी को यह हैरान करता है। रोपड़ बसपा के संस्थापक कांशी राम का यह अपना शहर है। इधर ही उनका बचपन बीता,इधर के ही सरकारी कॉलेज से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। आप चाहें तो और हैरान हो सकते हैं कि उनके कॉलेज के आसपास भी बसपा का कोई झंडा तक दिखाई नहीं दिया। कुल मिलाकर यहां पर आकर चिराग तले अंधेरे वाली कहावत सच साबित होती दिखी। आखिरी पंजाब के चुनावी समर में भी बसपा या कांशीराम की कोई भारी-भरकम उपस्थिति रोपड़ या पंजाब में क्यों नजर नहीं आ रही? पंजाब के कुछेक समाज शास्त्रियों से बातचीत के बाद हमें अपने सवाल का जवाब मिला। इन सभी की राय थी कि चूंकि पंजाब में सिख धर्म और आर्य समाज के प्रभाव के चलते दलितों को उस तरह से सामाजिक स्तर पर प्रताडित नहीं होना पड़ा , जैसे अन्य राज्यों में उन्हें झेलना पड़ा। इन दोनों मज़बूत धार्मिक संस्थाओं ने जाति के कोढ़ पर हल्ला बोला। नतीजा यह हुआ कि पंजाब के समाज में दलितों का उत्पीड़न कम हुआ। इस पृष्ठभूमि की रोशनी में ही पंजाब का दलित अपने को बसपा से जोड़कर नहीं देखता। आपको पंजाब में जगह-जगह दलितों के गुरुद्वारे तो देखने को मिल जाएंगे। उनके बाहर गुरुमुखी और कइयों के बाहर हिन्दी में भी लिखा रहता 'मजहबी', 'रामगढ़िया' या 'संत रविदास' गुरुद्वारा। और तो और, चंडीगढ़ में भी आपको इस तरह के गुरुद्वारे मिल जाएंगे। यह अन्य गुरुद्वारे से भव्यता के स्तर पर कतई उन्नीस नहीं हैं। ये कहीं न कहीं उनकी आर्थिक सेहत को भी रेखांकित करते हैं। यानी कि पंजाब का दलित उस तरह से पिछड़ा,दबा-कुचला नहीं है, जिस तरह से वो देश के बाकी भागों में या कम से कम उत्तर भारत के अन्य सूबों में हैं। जाहिर है,इसलिए ही चुनावों में पंजाब में दलित बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में खड़े नजर नहीं आते। संभवतः इसलिए ही बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम पंजाब से संबंध रखने के बाद भी बसपा को अपने ही गृह प्रदेश में मजबूत आधार देने में कामयाब नहीं हुए। पंजाब में कुल 30 फीसद मतदाता दलित है, यानि उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा ! देश के किसी भी अन्य सूबे में इतने अधिक दलित वोटर कहीं नहीं हैं। देश से बाहर बड़ी संख्या में जाने के फलस्वरूप पंजाब के दलितों के हालात सुधर गए। जो बाहर गए, वे भारत में अपने परिवारों को अच्छी-खासी रकम भेजते रहे। पंजाब से बाहर रोटी-रोजी कमाने के लिए जाने वालों में दलित सिख सर्वाधिक रहे हैं। आपको अफ्रीका में भी दलितों के गुरुद्वारे मिल जाएंगे। एक दौर में पंजाब में कांग्रेस के पास ज्ञानी जैल सिंह और बूटा सिंह के रूप में दंबग दलित नेता थे, पर साल 1984 में पहले स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के कत्लेआम के बाद पंजाब में पार्टी कमजोर हुई। उसे उपर्युक्त दोनों दिग्गज दलित नेताओं के केन्द्र की राजनीति करने के कारण रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए भी कोई नया नेता सामने नहीं आया। जैल सिंह तो देश के राष्ट्रपति ही बन गए। बहरहाल, बसपा की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए काफी संख्या में उम्मीदवार खड़े हुए हैं। कुछ समय पहले तक अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में मंत्री रहे राजकुमार आनंद भी नॉर्थ –वेस्ट दिल्ली से बसपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि लगता नहीं कि बसपा कहीं भी अपना असर छोड़ेगी।

मेष राशि– आज का दिन बेहद खास होने वाला है। परिवार में किसी खास रिश्तेदार के आने से खुशी का माहौल बनेगा। दोस्तों और परिवार के साथ व्यस्त रहेंगे। कोई बड़ा काम निपटाने की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। आज कुछ नए काम भी अचानक सामने आ सकते हैं। आपको सोचे हुए कामों से फायदा हो सकता है। ऑटोमोबाइल के बिजनेस में अच्छी सेल से लाभ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

वृष राशि– आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आज राह चलते किसी अनजान व्यक्ति से बेवजह उलझने से बचें। इससे आपका ही समय बचेगा। अपनी स्थिति और योग्यता के हिसाब से ही काम करेंगे तो समाज में सम्मान मिलेगा। संयम रखने से रुकी योजनाएं सफल होंगी। किसी तरह की मानसिक उलझन से आज आपको छुटकारा मिलेगा।

मिथुन राशि– आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आपको माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आज खर्चों के मामले में ज्यादा दरियादिली ना रखें और ना ही दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करें। आज बच्चे अपने मन की बात आपसे शेयर कर सकते हैं। उचित मार्गदर्शन की जरूरत रहेगी, जिसमें आपका सहयोग कारगर साबित होगा।

कर्क राशि– आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज नकारात्मक विचारों से बचने की कोशिश करेंगे। आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। रोजगार के मामले में किसी से सलाह लेंगे। अपने स्वभाव को बैलेंस रखें आपके सभी काम बनेंगे। आज पुत्र पक्ष से सुख मिलेगा। बिजनेस में आपको कठिन मेहनत से अच्छा लाभ होगा। गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। छात्र अपने अधूरे काम पूरा कर लेंगे।

सिंह राशि– आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आज आप अपने कार्यों पर ज्यादा ध्यान देंगे। जहां तक हो सके, सकारात्मक और कॉन्फिडेंट रहें। आपके जरूरी कामकाज आज पूरे होंगे। रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज आस-पास के लोगों से कुछ नई बात सीखेंगे। आपको अपनी योजनाओं के प्रति गोपनीयता बनाये रखने की जरूरत है। मित्रों से मिलने उनके घर जा सकते हैं। आपकी दोस्ती और भी मजबूत होगी।

कन्या राशि–आज आपका दिन शानदार रहेगा। नौकरी पेशा वाले लोगों की अच्छी इनकम होगी। प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याओं के लिए भागदौड़ के उपरांत काम बन जाएगा। आज अपने विचारों को लेकर आप थोड़े जज्बाती भी हो सकते हैं। आज सगे सम्बन्धियों से अच्छे तालमेल बनेंगे।

तुला राशि–आज का दिन ठीक रहने वाला है। आज घर में रिश्तेदारों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा। आज हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करना और एकाग्र चित्त रहना आपको सफलता प्रदान करेगा। निवेश संबंधी महत्वपूर्ण योजनाएं भी सफल होंगी। दोस्तों के साथ बात कर के अच्छा समय बीतेगा। इस राशि के जो लोग मेडिकल स्टोर के व्यपार से जुड़े हैं आज उन्हें अचानक बड़ा ऑर्डर मिलेगा।

वृश्चिक राशि– आज आपका दिन जोश से भरा रहने वाला है। आज कार्यक्षेत्र में लोगों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आज इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। बच्चे माता-पिता के साथ मंदिर जाएंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आज किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी। आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं।

धनु राशि– आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज आपके खास काम मन मुताबिक तरीके से बनने वाले हैं, इसलिए मेहनत में कोई भी कमी न करें। आज रोचक और ज्ञानवर्धक किताबें पढऩे में भी कुछ समय व्यतीत करेंगे। आज कोई जरूरी कार्य पूरा होने से मानसिक सुकून और शांति रहेगी।

मकर राशि– आज दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। आज आप ऊर्जा से भरे रहेंगे जिससे आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। संचार से जुड़ी किसी नई तकनीक से फायदा जरुर मिलेगा। आस पास और साथ के लोगों में आपकी अच्छी इमेज बनेगी। आज आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रहने वाली है।

कुंभ राशि- आज आत्मविश्वास और उम्मीदों वाला दिन है। किसी भी स्थिति में घर के बुजुर्गों की सलाह अवश्य लें, आपको बढिय़ा सलाह मिलेगी। आज भावनाओं में आकर किसी से भी कोई वादा ना करें। आज आप फिजूलखर्ची से दूर रहे और उचित बजट बनाकर चलें। किसी नए काम की शुरुआत के लिए उचित समय का इंतजार करें। आज आपको कुछ नए अनुभव की प्राप्ति होगी।

मीन राशि– आज का दिन नई सौगात लेकर आया है। आज आपके मन में बहुत सी सकारात्मक भावनायें आयेंगी। लवमेट के लिए आज का दिन अनुकूल है। आज आप किसी के साथ बेवजह न उलझे और ईगो पर काबू रखें। आज अधिक सोचने विचारने से कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हाथ से भी निकल सकती है। आज सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। आज दांपत्य जीवन मधुरता से भरा रहेगा।

रोकनी होगी जंगल की आग

हिमालयी क्षेत्र पूरे देश के मौसम का नियामक है। उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा-जमुना जैसी अनेक सदानीरा नदियां देश की जीवनधारा को सींचती हैं। ग्लेशियरों वाले इलाके में जहां जल भंडार हैं, वहीं समृद्ध जैव विविधता भी। ऐसे में गंगा-जमुना के मायके के जंगलों से लगातार आग के समाचार परेशान करते हैं। मई के पहले सप्ताह में ही आग लगने की करीब साढ़े नौ सौ घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। जिसमें करीब बारह हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र को अग्निकांड से नुकसान हुआ । पांच लोगों के मरने की भी खबर है। यूं हर साल उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की खबरें आती हैं। यह सिलसिला मार्च के अंत से शुरू होकर मई तक चलता है। लेकिन इस बार यह संकट ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। कई जनपदों में दृश्यता में कमी आई है। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों व भौगोलिक जटिलताओं के चलते वनों का धधकना जारी है। काबू पाने के लिये वायुसेना व एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है। यह एक हकीकत है कि जंगलों के धधकने में मानवीय हस्तक्षेप कहीं न कहीं जरूर होता है। माना जंगलों में गिरने वाली पत्तियों व घास का समय रहते निस्तारण न होने से ज्वलनशीलता तो होती है, लेकिन आग इंसानी लापरवाही या साजिश से ही लगती है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि नवंबर 2023 से अब तक करीब पौने चार सौ वन अपराधों के मामले पंजीकृत हो चुके हैं। इसमें साठ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हो चुकी हैं। इस बात को उत्तराखंड का वन विभाग भी स्वीकार करता है कि 95 फीसदी अग्निकांड के मामलों में मानवीय दखल जिम्मेदार होता है। जिसमें लापरवाही के साथ-साथ इरादतन लगाई गई आग भी शामिल है। इस बार जहां आग लगाने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वहीं विभाग के लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ भी लापरवाही के चलते कार्रवाई की जा रही है। दरअसल, अग्निकांडों के बाद कार्रवाई फॉरेस्ट एक्ट व वन्य जीव संरक्षण कानूनों के तहत की जा रही है। इसके अलावा सार्वजनिक व निजी संपत्ति नुकसान क्षतिपूर्ति कानून के तहत भी कार्रवाई होगी। इस संकट को देखते हुए एनडीआरएफ व वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। वहीं आईआईटी रुड़की की मदद से कृत्रिम बारिश के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। निश्चित रूप से हर साल जलने वाले सैकड़ों हेक्टेयर वनों को आग से बचाने के लिये स्थायी उपायों की जरूरत महसूस की जा रही है।

भारत में पाकिस्तान के हिमायती !

महेश खरे

यह जुबान हिन्दुस्तानी है लेकिन बोल पाकिस्तानी हैं। ये और कोई नहीं जम्मू-कश्मीर के बड़े भारतीय चेहरे फारुख अब्दुल्ला हैं, जो मौका मिलते ही पाकिस्तान की हिमायत पर उतर आते हैं। अगर कोई कहे कि पीओके भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा तो इस पर फारुख को गुस्सा क्यों आना चाहिए? भारतीय राजनेता होने के नाते तो उनको कश्मीर मुद्दे पर भारत के साथ खड़े दिखना चाहिए। इसके उलट वे ऐसे बोल बोलते हैं कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखीं। उसके पास भी एटम बम है। जो कभी भी हम पर गिर सकता है।

पिछले वर्षों में फारुख ने कैसे कैसे बयान दिए हैं। पाठक भी जान लें- एक बार तो फारुख यह भी बोल गए कि भारत और पाकिस्तान बातचीत के जरिए विवादों का समाधान नहीं खोजेंगे तो कश्मीर का भी गाजा और फिलिस्तीन जैसा हाल होगा। द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार फारुख अब्दुल्ला 15 जनवरी 2018 को भी पीओके को लेकर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था -हम कब तक कहते रहेंगे कि पीओके हमारा है। पीओके पाकिस्तान का है और जम्मू- कश्मीर भारत का है। 70 साल से ज्यादा हो गए लेकिन पीओके नहीं मिला। इसी वर्ष 2 दिसंबर को भी फारुख ने ऐसा ही मिलता जुलता बयान दिया था।

दरअसल हाल ही में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने जब दोहराया कि भारत पीओके पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पाकिस्तानी लोग कश्मीर में विकास को देखने के बाद स्वयं भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे। इस बयान पर नेशनल कांफ्रेंस के इस नेता का आगबबूला होना भारतीयों की समझ के परे है।वैसे फारुख ने पाकिस्तान की हिमायत पहली बार की हो ऐसा नहीं है। जब-जब उन्हें मौका मिला है तब-तब उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर भारत को ही या तो खरी खोटी सुनाई है, नसीहतें दी हैं या दुश्मन देश का पक्ष 'बड़े भरोसे' के साथ रखा है। फारुख की जुबान पर भारत को नसीहत देने और पाकिस्तान का पक्ष लेने के कुछ नायाब उदाहरण याद दिलाना आवश्यक महसूस हो रहा है। फारुख के यह बयान न्यूज चैनलों और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में समय-समय पर प्रसारित और प्रकाशित हुए हैं।

पिछले वर्षों में फारुख ने कैसे कैसे बयान दिए हैं। पाठक भी जान लें- एक बार तो फारुख यह भी बोल गए कि भारत और पाकिस्तान बातचीत के जरिए विवादों का समाधान नहीं खोजेंगे तो कश्मीर का भी गाजा और फिलिस्तीन जैसा हाल होगा। द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार फारुख अब्दुल्ला 15 जनवरी 2018 को भी पीओके को लेकर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था -हम कब तक कहते रहेंगे कि पीओके हमारा है। पीओके पाकिस्तान का है और जम्मू- कश्मीर भारत का है। 70 साल से ज्यादा हो गए लेकिन पीओके नहीं मिला। इसी वर्ष 2 दिसंबर को भी फारुख ने ऐसा ही मिलता जुलता बयान दिया था। ऐसे नेताओं और बयानों पर भारतीयों को बड़ी कोफ्त होती है। जो खाते तो भारत का हैं और बजाते पाकिस्तान की हैं। यह जानते हुए भी कि पाकिस्तान ऐसा पड़ोसी मुल्क है जिसे भारत की प्रगति और शांति फूटी आंखों नहीं सुहाती। दो-दो युद्धों के लिए भारत को मजबूर कर चुका पाकिस्तान ही है जो सीमा पार में भारत विरोधी गतिविधियों को पनाह देता रहता है। आतंकियों की घुसपैठ किसके इशारे पर होती रही है। यह सारी दुनिया जानती है। मन में भारत के प्रति वैर पाले पाकिस्तान भुखमरी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आर्थिक दिवालियापन की परिस्थितियों को झेल रहा है। लेकिन भारत की खिलाफत करना नहीं छोड़ता।

जिस देश की आवाम विकास को लेकर भारत की तारीफों के पुल बांधती रही हो। भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की पक्षधर होती जा रही हो। उसी भारत के फारुख जैसे चंद नेता न जाने क्यों दुश्मन की हिमायत करने में जरा भी संकोच नहीं करते।

इंडिया गठबंधन में फारुख पाकिस्तान के अकेले हिमायती नहीं हैं। और भी हैं। उनमें से एक मणिशंकर अय्यर हैं जो अपनी वक्तव्य बहादुरी से ऐन चुनाव के समय खुद तो विवादों में फंसते ही हैं कांग्रेस की भी फजीहत कराते रहते हैं। याद होगा पिछले चुनावों के समय ही मणिशंकर ने मोदी को 'नीच' और चायवाला कह कर अपना गुस्सा जताया था। विरोधियों के विवादित बयानों का चुनावी लाभ उठाने में माहिर मोदी का कोई मुकाबला नहीं। मोदी ने मणिशंकर के बोलों को चुनाव में तबीयत से भुनाया। कांग्रेस तमाम सफाई देती रही। जैसे कमान से छूटा तीर कभी वापस नहीं जाता। इसी तरह जुबान से निकले बोल अपना असर छोड़कर ही दम लेते हैं। असर हुआ और कांग्रेस को चुनावी पराजय का मुंह देखना पड़ा।

कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर भी उन नेताओं में से हैं जो पाकिस्तान के मामले में फारुख अब्दुल्ला से सुर में सुर मिलाते रहे हैं। उनका एक पहले अप्रैल 2024 का एक पुराना कथित वीडियो चुनाव के समय वायरल हो रहा है। इसमें वे पाकिस्तान से बातचीत करने की सलाह देते हुए कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान को इज्जत देना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके पास भी परमाणु बम है। कोई सिरफिरा आया तो हम पर इसका इस्तेमाल कर सकता है। मोदी के धुर विरोधी मणिशंकर सवाल करते हैं कि उनकी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आखिर मोदी सरकार पाकिस्तान से क्या इसलिए बात नहीं करना चाहती क्योंकि वहां आतंकवाद है? जो देश भारत में आतंकवादियों को पनाह देते हुए भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो उसको सम्मान देने की सलाह देना कहां तक उचित है? पाकिस्तान मित्रता की भाषा समझता ही कहां है? कितने अवसरों पर भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन उसके नतीजे अनुकूल नहीं हुए।हालांकि, कांग्रेस नेता के बयान से किनारा करते हुए प्रियंका वाड्रा ने सवाल किया कि चुनाव के समय इस वीडियो के वायरल होने का अर्थ क्या है?

वीडियो नया हो या पुराना यह कांग्रेस की सोच को दशार्ता है। दुश्मन का डट कर मुकाबला करने की सलाह देने के बजाय केवल इसलिए बातचीत करने की सलाह देना कि उसके पास भी परमाणु बम है। कहां तक उचित है? आश्चर्यजनक यह है कि पाकिस्तान भारत की सामरिक क्षमता को जानता है। लेकिन परोक्षरूप से कमजोर पड़ोसी देश के आगे झुकने की सलाह देने वालों की दिमागी फितरत पर हंसा ही जा सकता है। हम 70 साल से यह देखते चले आ रहे हैं कि भारत के साथ शत्रुतापूर्ण रवैए के कारण पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना मान सम्मान ही खोया है। आत्मनिर्भरता की राह पर चलना तो दूर कटोरा लिए पाकिस्तानी हुक्मरान बड़े और सम्पन्न राष्ट्रों से मदद मांगने को मजबूर हैं। अमेरिका हो या ईरान किसी के भी आगे हाथ फैलाने से पाकिस्तान को गुरेज नहीं होता। पाकिस्तान के हिमायती नेता शायद पुलवामा के बाद बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को भूल गए हैं। लेकिन भारत के कड़े जवाब को पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता।

मोदी सरकार ने पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर कश्मीर राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। अनुच्छेद 370 हटाने, परिसीमन कराए जाने और शांति बहाली के सरकारी दावों के बाद जनता को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनावों के साथ कश्मीर के भी चुनाव कराए जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। इतना ही नहीं कश्मीर में होने जा रहे लोकसभा चुनावों से भी बाहर रह कर भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर की जनता के मन में उमड़ घुमड़ रहे अनेक सवालों को निरुत्तर छोड़ दिया है। पहले जम्मू और कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें थीं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 3 तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। लद्दाख के अलग होने के बाद अब जम्मू-कश्मीर में पांच लोकसभा सीटें बची हैं- बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू और उधमपुर। कश्मीर को लेकर भारत की नीतियां पाकिस्तान को नहीं सुहातीं। पाकिस्तान कश्मीर में अशांति फैलाने में मददगार ही साबित हुआ है। भारत के कदमों से घाटी का वातावरण शांति और सद्भाव की ओर बढ़ा है। ऐसे में भारत विरोध के पाकिस्तानी मंसूबों को फारुख अब्दुल्ला और मणिशंकर जैसे नेताओं के बयान से बढ़ावा ही मिलता है। सच यही है कि खुद बबार्दी के कगार पर खड़े पाकिस्तान की भारत के खिलाफ आंख उठाने की औकात ही नहीं है।

देश में भ्रष्टाचार का खंड बन गया है झारखंड

योगेन्द्र योगी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा था कि भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा लोकतंत्र को नष्ट करने का अभियान चला रही है।कांग्रेस यह भूल गई कि पिछले साल दिसंबर में भी झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स ने 350 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश बरामद किया था। इस पर साहू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि छापेमारी में जो कैश बरामद किया गया है, वो मेरी शराब की कंपनियों का है। शराब का कारोबार नकदी में ही होता है और इसका कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से 290 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश मिला था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साहू से जुड़े ओडिशा और झारखंड के उनके ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान विभाग को अलमारी में करोड़ों रुपये भरे हुए मिले। धीरज साहू के पास कितना कैश बरामद हुआ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगातार तीन दिन छापेमारी कर नोट गिनने पड़े।

गौर भाजपा राजनीतिक दलों के लिए देश में व्याप्त भ्रष्टाचार कोई चुनावी मुद्दा नहीं रह गया है। यही वजह है कि खासतौर से क्षेत्रीय दलों की सरकारों में बेशर्मी से लूटने की होड़ मची हुई है। झारखंड में एक मंत्री के निजी सहायक के नौकर के घर से मिले करीब 35 करोड़ रुपए मिलने पर किसी भी दल ने कठोर कार्रवाई की मांग तो दूर बल्कि इस भारी-भरकम भ्रष्टाचार के लिए अफसोस तक जाहिर नहीं किया। यह पहला मौका नहीं है जब इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की असलियत उजागर हुई हो। इससे पहले भी असीम सुर्खियों में रहे भ्रष्टाचार के मामलों में भी क्षेत्रीय दलों की सत्तारूढ़ सरकारो के काले कारनामे सामने आ चुके हैं।

भ्रष्टाचार के मामले सामने आने पर क्षेत्रीय दलों का प्रयास यही रहता रहा है कि इसे केंद्र की भाजपा सरकार की साजिश करार दिया जाए। कांग्रेस ने इन दलों के भ्रष्टाचार के मामलों में संरक्षक की भूमिका निभाई है। कारण स्पष्ट है यदि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के भ्रष्टाचार के मामले उठाती है तो उसे अपने गिरेबान में भी झाकना होगा। इससे ये दल एक-दूसरे के भ्रष्टाचार के मामलों में छिछालेदार करने लगेंगे। ऐसी हास्यास्पद स्थिति से बचने के लिए ये दल एक-दूसरे के भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं करते हैं। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मामलों में मौन साधे रखा है। यहां तक की कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार का जिक्र तक करना जरूरी नहीं समझा। कांग्रेस को अंदाजा था कि इसका जिक्र करते ही भाजपा गठबंधन खिल्ली उड़ाने से चूकेगा नहीं। यही वजह रही कि कांग्रेस घोषणा पत्र में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खात्मे को लेकर कोई वादा नहीं किया। आश्चर्य यह है कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू सहयोगी जहांगीर के यहां छापा मार कर प्रवर्तन निदेशालय ने 35 करोड़ रुपए बरामद किए। इस पर भी मंत्री आलम ने त्याग पत्र देना जरूरी नहीं समझा। झारखंड में सत्ता में शामिल कांग्रेस ने आलम के इस्तीफे की मांग तक नहीं की।

अलबत्ता कांग्रेस ने इससे अपना दामन बचाने की कोशिश जरूर की। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में आयोजित राहुल गांधी की सभा में मंच पर कांग्रेस कोटे से ग्रामीण विकास मंत्री बने आलमगीर आलम को जगह नहीं मिली। कांग्रेस ने आलमगीर को महज यह संदेश देकर औपचारिकता निभाई की पहले जांच से बरी होकर आओ। इससे पहले झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। सोरेन को जमानत नहीं मिल सकी है। पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन 6 अक्टूबर 2023 को नई हेमंत सोरेन को कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जैसा कि अक्सर होता है हर भ्रष्टाचारी ऐसे मामलों को फसाने की साजिश करार देता है, इसी तर्ज पर सोरेन ने भी आरोप से इनकार किया। कांग्रेस ने सोरेन की गिरफ्तारी की निंदा की और इसे संघवाद के लिए झटका बताया था।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा था कि भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा लोकतंत्र को नष्ट करने का अभियान चला रही है।कांग्रेस यह भूल गई कि पिछले साल दिसंबर में भी झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स ने 350 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश बरामद किया था। इस पर साहू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि छापेमारी में जो कैश बरामद किया गया है, वो मेरी शराब की कंपनियों का है। शराब का कारोबार नकदी में ही होता है और इसका कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से 290 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश मिला था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साहू से जुड़े ओडिशा और झारखंड के उनके ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान विभाग को अलमारी में करोड़ों रुपये भरे हुए मिले। धीरज साहू के पास कितना कैश बरामद हुआ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगातार तीन दिन छापेमारी कर नोट गिनने पड़े। आलम ये रहा है कि नोट गिनने के लिए लाई गईं मशीनों की क्षमता कम पड़ गई। नोट गिनने के लिए तीन दर्जन मशीनों को मंगाया गया था, जो कम पड़ गईं। पीएम मोदी ने ओडिशा की रैली में किया नकद बरामदगी का जिक्र चुनाव प्रचार के लिए ओडिशा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नकद बरामदगी का जिक्र भी किया। उन्होंने केंद्र द्वारा जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर विपक्ष के आरोप का जवाब देते हुए पूछा कि पड़ोसी राज्य झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं।

मोदी ने कहा कि अब आप ही बताइए, अगर मैं उनकी चोरी, उनकी कमाई, उनकी लूट बंद कर दूं, तो क्या वे मोदी को गाली देंगे या नहीं? गालियों के बावजूद, क्या मुझे आपका पैसा नहीं बचाना चाहिए। झारखंड और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ है। संयुक्त बिहार में ही झारखंड मे हुए चारा घोटाले से शुरू हुई थी और बड़े भ्रष्टाचार की कहानी आज भी बदस्तूर जारी है। चारा घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आया था। इस घोटाले में पशुओं के चारे की चोरी की गई। 950 करोड़ के इस घोटाले मे 53 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि कुल 170 आरोपी बने गए थे। इस मामले का खुलासा 1996 में हुआ था। इसके बाद मधु कोड़ा के मुख्यमंत्री काल मे शेल कंपनियों के जरिए काली कमाई को सफेद करने का मामला सामने आया। करीब 4 हजार करोड़ का ये घोटाले अपने आप में देशभर के बड़े घोटालों में से एक था। आज भी मामला अदालत में है। मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद जेल भी जाना पड़ा था। अलग झारखंड राज्य की मांग को अटल बिहारी वाजपेयी की तत्कालीन सरकार ने वर्ष 2000 में पूरा तो कर दिया था। लेकिन जिस मकसद से अलग राज्य की मांग हो रही थी, वह मकसद पीछे छूट गया। झारखंड में लूट का सिलसिला शुरू हो गया। बिहार से अलग झारखंड बनाने की मांग इसलिए हो रही थी कि इसका समुचित विकास अपने ही संसाधनों से सुचारू ढंग से हो पाएगा। इसकी झलक भी पहले बजट में दिखी थी। राज्य सरकार का शुरूआती बजट सरप्लस था। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद जिस विकास और खुशहाली का सपना लोगों ने देखा था, वह तो पूरा नहीं हुआ, उल्टे यहां लूट की संस्कृति दिन प्रतिदिन मजबूत होती गई। हाल के तीन साल में जिस तरह नौकरशाहों और नेताओं के घर से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम नोटों का जखीरा बरामद करती आ रही है, उससे तो झारखंड का अघोषित नाम लूटखंड हो गया है।

गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी तीन दक्षिणी राज्यों तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की भी जांच कर रही है। सभी नेताओं ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। क्षेत्रीय दल चाहे झारखंड का हो, दिल्ली, तमिलनाडू या फिर पश्चिमी बंगाल के, सब आकंठ तक भ्रष्टाचार के मामलों में डूबे हुए हैं। इन राज्यों के विपक्षी दलों के करीब एक दर्जन नेता जेलों में बंद हैं। इनमें से ज्यादातर की जमानत तक नहीं हो सकी है। इसी से विपक्षी दलों का यह आरोप कमजोर पड़ जाता है कि केंद्र में सत्तारुढ़ भाजपा जांच एजेंसियों को दुरुपयोग राजनीतिक रंजिश के कारण कर रही है। अभी तक किसी भी न्यायालय ने नेताओं के भ्रष्टाचार के भी मामले में यह निर्णय नहीं दिया कि केंद्रीय एजेंसियों ने दुर्भावनावश कार्रवाई की है। कांग्रेस इस मुद्दे पर मुंह इसलिए नहीं खोल सकती है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास और वर्तमान भी भ्रष्टाचार के आरोपों से रंगा हुआ है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

शिक्षा क्या है जो तब तक याद रहता है जब तक उसे अपने जीवन में लागू करते हैं नहीं तो वह सीखकर भुलाया गया एक पल है : बी एफ स्किनर

पाकिस्तान से डर या प्यार?

कांग्रेस का संकट खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। एक नेता के बयान से फैला रायता समेटा नहीं गया होता कि तब तक किसी और नेता का विवादित बयान आ जाता है। राहुल गांधी के सलाहकार माने जानेवाले सैम पित्रौदा ने एक के बाद एक ऐसे बयान दिए कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गईं। पहले विरासत कर का मामला उन्होंने उछाला। चूँकि राहुल गांधी लगातार सम्पत्ति के सर्वेक्षण एवं आबादी के अनुपात में देश के संसाधनों पर अधिकार की बात कर रहे हैं, इसलिए सैम पित्रौदा के बयान को इसी श्रृंखला का हिस्सा माना गया। हालांकि कांग्रेस ने पित्रौदा के विचार से किनारा करने का प्रयास किया। परंतु तब तक पित्रौदा ने भारतीय नागरिकों को चीनी, अफ्रीकी, अमेरिकी इत्यादि बता दिया। यानी रंग भेद एवं शारीरिक बनावट के आधार पर उनकी पहचान को किसी दूसरे देश से जोड़ने का कारनामा कर दिया। यह बयान इतना विवादित था कि कांग्रेस को सैम पित्रौदा का त्यागपत्र स्वीकार करना पड़ गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के एक नेता ने राम मंदिर के शुद्धिकरण करने की बात कहकर एक बार फिर राम मंदिर को लेकर कांग्रेस की मानसिकता को उजागर कर दिया। कांग्रेस की ओर से इन बयानों पर लीपापोती की जाती, उससे पहले ही मणिशंकर अय्यर ने ऐसा बयान दे दिया, जिसके कारण से भाजपा को कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का एक और सुअवसर मिल गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए और अपनी सैन्य ताकत नहीं बढ़ानी चाहिए क्योंकि इससे इस्लामाबाद नई दिल्ली के खिलाफ परमाणु हथियार तैनात करने के लिए परेशान हो सकता है। भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए अन्यथा उसे बुरा लग सकता है और वहाँ से कोई सिरफिरा भारत पर हमला कर सकता है। मणिशंकर अय्यर का यह बयान एक तरह से पाकिस्तान की जुबान है। जैसे कोई पाकिस्तानी नेता भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा हो। उल्लेखनीय है कि इस सप्ताह की शुरुआत में, कांग्रेस के सहयोगी विपक्षी गठबंधन की प्रमुख पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने तीखी टिप्पणी की थी कि अगर उकसाया गया तो पाकिस्तान परमाणु बम का सहारा ले सकता है। अय्यर ने भी यही कहा कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम हैं। हमारे पास भी हैं, लेकिन अगर कोई 'पागल' लाहौर पर बम गिराने का फैसला करता है, तो विकिरण को अमृतसर तक पहुंचने में 8 सेकंड नहीं लगेंगे। निःसंदेह, यह कांग्रेस का डर तो नहीं हो सकता अपितु उसके नेताओं का पाकिस्तान प्रेम अवश्य ही दिखता है। मणिशंकर अय्यर ऐसे नेता हैं, जिनका पाकिस्तान प्रेम अकसर जाहिर होता रहता है। हमेशा की तरह कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर के बयान से पल्ला झाड़ लिया है लेकिन प्रश्न यह है कि कांग्रेस इस प्रकार के नेताओं को अपने साथ रखती क्यों है? पाकिस्तान की जुबान बोलनेवाले नेताओं से कांग्रेस हमेशा के लिए पल्ला क्यों नहीं झाड़ लेती? यदि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलनेवाले नेताओं को पार्टी में बनाए रखेगी तब देश का आम नागरिक यही मानेगा कि कांग्रेस का पक्ष भी यही है। कांग्रेस को यदि जनता का विश्वास जीतना है, तब उसे मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं की हमेशा के लिए छुट्टी करनी होगी और इस प्रकार के विचारों की कड़ी निंदा करनी होगी।

कांग्रेस का संकट खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। एक नेता के बयान से फैला रायता समेटा नहीं गया होता कि तब तक किसी और नेता का विवादित बयान आ जाता है। राहुल गांधी के सलाहकार माने जानेवाले सैम पित्रौदा ने एक के बाद एक ऐसे बयान दिए कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गईं। पहले विरासत कर का मामला उन्होंने उछाला था।

हिन्दवी स्वराज्य स्थापना का 350 वां वर्ष

शिवाजी महाराज एवं उनकी शासन नीति

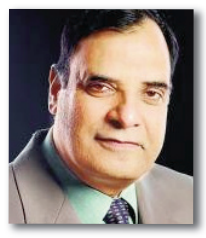

महाराज ने एक और क्रन्तिकारी कदम उठाया था। बँटाई अर्थात फसल के बँटवारे का ब्यौरा बनाया था तथा यह बनाने में अनाजी दत्तो प्रभुणीकर ने अपनी कुशलता का परिचय दिया था। यह लगान कितना लेना है इसकी एक नयी पद्धति का निर्धारण था। महाराज ने तय किया कि लगान की रकम व जमीन की श्रेणी का निर्धारण न अकेला किसान करेगा, न केवल प्रशासन करेगा। यह निर्धारण करने में गाँव के देशमुख, देशपांडे, गाँव के पाटील (पटेल /पटवारी) व गाँव के चार प्रतिष्ठित व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। यह सब करते समय जमीन कैसी है? फसल कितनी हो सकती है? कौनसी फसल ले सकते है? फसल रबी की होगी कि खरीप की? प्रत्यक्ष खेत देखकर, इन बिंदुओं का अध्ययन कर निर्णय करना होगा ऐसा नियम बनाया गया। इतना विवेक पूर्ण विचार होने के कारण किसी पर अन्याय नहीं होगा व राज्य को हानि नहीं पहुँचेगी यह देखा गया। किसान भी खुश हुए। अगर केवल शासन व किसान मिलकर यह कार्य करते तो शायद

रिश्वतखोरी को बल मिलता यह भी विचार महाराज ने किया था। इस बँटाई पद्धति से यह भी सिद्ध हुआ कि यह मराठों का राज्य है, उनकी कलाई में जितना बल है उतना ही विवेकपूर्ण विचारों का भी सामर्थ्य है।

इस निर्णय से किसान खुश हुए क्योंकि अधिक से अधिक फसल उगाकर वे अपने परिवार को समृद्ध करेंगे एवं स्वराज्य के खजाने में भी धनवृद्धि होगी। घर-परिवार को, बच्चों को, गाय-भैसों को पेटभर भोजन मिलने की निश्चिति हुई थी। महाराज आठ साल के होंगे तब दादोजी कोंडदेव ने सोने का फाल लगे हुए हल से जमीन जोती थी। तब दादोजी ने उस छोटे शिवबा को एक सीख दी थी कि अगर हम चाहते है किसान अधिक से अधिक फसल लेकर स्वराज्य के कोष में-खजाने में लगान के रूप में अपना योगदान दे तो उसके लिए भूमि के व किसान के मन की गहराई में उतरना होगा, किसान का भला किसमें है, उसका हित किसमें है यह देखना होगा। अब महाराज उसीको अपनी प्रगल्भ बुद्धि से देख रहे थे, चिंतन-मनन कर रहे थे क्योंकि स्वराज्य भी प्रजा का ही व प्रजा के लिए था। शाहियों के बार-बार हुए आक्रमण के कारण जनता त्रस्त हो गयी थी, हालत खस्ता थी क्योंकि शाही फौज ने सब नष्ट करने के साथ धन-संपत्ति भी लूट ली थी। पैसा देखने के लिए भी पास में नहीं था। महाराज ने लगान भरने के लिए एक और रास्ता ढूंढ निकाला जिससे किसानों के मन का बोझ हल्का हुआ। महाराज ने निर्देश दिया जिसके पास लगान नकद देने के लिए धन नहीं है, पैसा नहीं है वह लगान अनाज के, फसल के रूप में भी जमा कर सकता है। इससे किसान ओर खुश हुए। अनाज के रूप में प्राप्त लगान को व्यवस्थित रखने के लिए गोदाम भी बनाएँ गये। इससे एक ओर लाभ हुआ, अकाल पड़ने पर इस अनाज का उपयोग जनता के लिए भी हो सकेगा ऐसा दूरदर्शी विचार महाराज ने किया था। पूर्व में बहमानी सुल्तानों के समय ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी।

(संकलन)

बोध कथा

आस्था की दृष्टि

एक मिशनरी ने स्वामी रामकृष्ण से पूछा, 'वे माता काली के रोम-रोम में अनेक ब्रह्मांड होने की बात करते हैं और उस छोटी-सी मूर्ति को काली कहते हैं, यह कैसे?' इस पर परमहंस ने पूछा, 'सूरज दुनिया से कितना बड़ा है?' उन्होंने उत्तर दिया, 'नौ लाख गुना।' परमहंस ने फिर पूछा-'तब वह इतना छोटा कैसे दिखाई देता है?' मिशनरी ने कहा, 'नौ लाख गुना होने पर भी सूरज हमसे बहुत दूर है। इसलिए वह इतना छोटा दिखाई देता है।' परमहंस ने फिर पूछा, 'कितनी दूर?' उन्होंने बताया, 'नौ करोड़, तीस लाख मील।' परमहंस ने विनम्रता से जवाब दिया, 'ठीक इसी प्रकार आप मां काली से इतनी दूर हैं कि आपको वे छोटी दिखाई देती हैं। मैं उनकी गोद में हूं। इसलिए मुझे वे बड़ी लगती हैं। आप स्थूलदृष्टि से पत्थर देखते हैं, मैं आस्था की दृष्टि से शक्तिपुंज देखता हूं।'

कांग्रेस को भारत में रोजगार के मुद्दे पर भड़काने के बजाय सकारात्मक समाधान के रास्ते बताने चाहिए

राहुल प्रियंका दादी इंदिराजी की बातें भी याद करें

आलोक मेहता
आई टी वी नेटवर्क इंडिया न्यूज़ और आज समाज के सम्पादकीय निदेशक

रायबरेली अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल और प्रियंका गांधी इन दिनों अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम, काम और संबंधों को लेकर बहुत भावुक भाषण दे रहे हैं। वहीं देश के युवाओं की बेरोजगारी की समस्याओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं।

रायबरेली अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल और प्रियंका गांधी इन दिनों अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम, काम और संबंधों को लेकर बहुत भावुक भाषण दे रहे हैं। वहीं देश के युवाओं की बेरोजगारी की समस्याओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो चुनाव में 4 जून को विजयी होने का दावा करते हुए सभाओं में यह तक कह दिया कि 'उसी दिन सरकार 30 लाख लोगों को नौकरी देने का निर्णय करेगी और अगस्त से नौकरी दी जाने लगेगी।' यह वायदा एक हद तक हड़बड़ी में अव्यवहारिक और हास्यास्पद समझा जा रहा है, क्योंकि सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती और सरकारी भर्ती में घोटालों में देश के कई नेता जेल जा चुके और राहुल के नए साथी तेजस्वी लालू यादव परिवार पर रेलवे में भर्ती घोटाले की जांच चल रही है। यही नहीं राहुल गांधी युवाओं, महिलाओं को एक-एक लाख रूपये देने का वायदा भी कर रहे हैं।

इस तरह के भावुक, उत्तेजक और वायदों के भाषणों पर मुझे भी श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में दिए गए भाषणों और पत्रकारों से कही गई बातें ध्यान में आई। उस समय मैं संपादक नहीं राजनैतिक विशेष संवाददाता हुआ करता था। इसलिए अपने पास उपलब्ध रिकॉर्ड टटोला, ताकि राहुल प्रियंका गांधी या उनके काबिल सलाहकार उन बातों पर ध्यान दें या न दें, हमें गलत साबित नहीं कर सके। श्रीमती गांधी से 25 अप्रैल 1980 को एक इंटरव्यू के दौरान सवाल किया गया कि 'हर कोई बेरोजगारी की समस्या की चर्चा करता है। क्या यह इस देश की बुनियादी समस्या है?' इंदिराजी ने संक्षिप्त उत्तर दिया-'दुनिया के प्रत्येक देश में बेरोजगारी पाई जाती है।' तब सवाल हुआ -'जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलता, क्या बेरोजगार युवकों को नगद सहायता नहीं दी जा सकती?' श्रीमती इंदिरा गांधी ने उत्तर दिया- 'हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि हम इस तरह की सहायता दे सकें। जहां कहीं इस तरह की सहायता दी जाती है, उसका असर अच्छा नहीं होता।'

इसी तरह 27 सितम्बर 1980 को कोलकता के स्कॉटिश कॉलेज के स्थापना दिवस के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में युवाओं को समझाया- 'छात्रों को पहली

चिंता यह सताती है कि उन्हें पढ़ाई के बाद कोई काम मिलेगा या नहीं। यह स्वाभाविक है। लेकिन रोजी - रोजगार शिक्षा के अनेक लक्ष्यों में से एक है। केवल उन्हीं देशों में बेरोजगारी की अधिक परेशानी नहीं है जिनकी जनसंख्या काफी कम है। हम साधन सम्पन्न देशों के हजारों ऐसे युवाओं को देखते हैं जो मन में सूनापन लिए अपना देश त्याग कर अन्यत्र भटकते रहते हैं। उनके चेहरे पर परेशानी की रेखाएं बताती हैं कि जिस सम्पन्नता के लिए हमारे यहां के लोग प्रायः लालायित रहते हैं वह आध्यात्मिक दृष्टि से कितनी खोखली है।' इस दृष्टि से राहुल गांधी और प्रियंका अथवा उनकी कांग्रेस पार्टी के सलाहकारों को भारत में रोजगार के मुद्दे पर भड़काने के बजाय सकारात्मक समाधान के रास्ते बताने चाहिए। केवल निराशा पैदा करने वाले आंकड़ों और ब्रिटिश राज की तरह सरकारी नौकरियों के प्रलोभन के बजाय कौशल विकास और स्व रोजगार के नए रास्ते दिखाने की नई राष्ट्रीय नीतियों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सत्ता या प्रतिपक्ष में कोई भी हो, समाज में सही दिशा नहीं होने पर अराजकता का खतरा बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई शिक्षा नीति में डिग्री के साथ कौशल विकास पर जोर है, जिसका क्रियान्वयन हर राजनीतिक व्यवस्था और राज्य के लिए लाभकर होगा। राजनैतिक पूर्वाग्रह से हटकर दुनिया के विभिन्न देशों की आर्थिक एवं बेरोजगारी की स्थितियों पर ध्यान दिया जाए, तो भारत अपने सीमित संसाधनों के बावजूद सही दिशा में प्रगति कर रहा है। ताजे अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार ब्रिटेन में बेरोजगारी की दर 4 .2 प्रतिशत, अमेरिका में 4.47 प्रतिशत और भारत में 5.4 प्रतिशत है। बेरोजगारी का हल दुनिया में केवल सरकारी नौकरियों को बढ़ाने से नहीं निकला है। शिखा का विस्तार हुआ है, लेकिन केवल उच्च शिक्षा को सुगम बनाकर सामान्य बीए.एमए.की लाखों डिग्रीधारी खड़े करने से नौकरियां देना कठिन होता गया है। कुछ राजनेताओं ने अपने स्कूल कॉलेज आदि खोलकर या सत्ता में रहने पर फर्जी कॉलेज युनिवर्सिटी को मान्यता देकर पूरी शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्ट भी किया है। कांग्रेस के कुछ नेताओं या उनके करीबियों ने बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश में भर्ती के नाम पर करोड़ों कमाए। सबसे भ्रष्ट उदाहरण कांग्रेस के मुख्यमंत्री अजित जोगी के कार्यकाल का रहा है, जब उन्होंने छत्तीसगढ़ में करीब चालीस युनिवर्सिटी को मान्यता दे दी, जिनमें कुछ किसी बेसमेंट वाले पते से चल रही थी। हमने जब खोजी रिपोर्ट छापी, तब बाद में उन संस्थाओं की मान्यता अगली रमन सिंह सरकार ने रद्द की। दिग्विजय सिंह के राज में निजी सहायकों ने कॉलेज खोलकर सरकारी जमीन सहायता तो ली ही, छात्रों के प्रवेश में करोड़ों कमा लिए। दूसरी तरफ हाल के वर्षों में कौशल विकास केंद्रों से निकल रहे हजारों युवाओं को स्व रोजगार या छोटे बड़े उद्योगों में तत्काल काम के अवसर मिल रहे हैं। गांव से लेकर शहरों और महानगरों में संचार क्रांति से कमाई वाले व्यापार बढ़ने से टेक्निकल ज्ञान वाले युवा फ्री लांसिंग से हर महीने 50 हजार रूपये तक कमा रहे हैं। केवल आंकड़ों की बाजीगरी के बजाय असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार से नया विश्वास कायम हो रहा है। खादी ग्रामोद्योग में पिछले दस वर्षों के दौरान करोड़ों की बढ़ोतरी महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने का प्रमाण है। कभी युवा गांधी परिवार गांवों कस्बों में आत्म निर्भर हो रही सामान्य महिलाओं से मिलकर भी असलियत समझने का प्रयास करें। केवल झूठे प्रलोभन और जाति धर्म के आधार पर नौकरियों का भ्रमजाल फैलाने से कांग्रेस या सहयोगी दलों द्वारा शासित राज्यों में भी अशांति तथा अराजकता फैलेगी। मानव अधिकारों के नाम पर छत्तीसगढ़ या पूर्वोत्तर प्रदेशों में माओवादी और उग्रपंथियों को कांग्रेस के समर्थन का बहुत नुकसान लाखों आदिवासियों और देश ने भुगता है।

यह लेखक के निजी विचार है

केजरीवाल को जमानत

डा. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के पूर्व कुलपति

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में थे। वे इधर उधर सभी प्रकार के न्यायालयों में ज़मानत के लिए अर्ज़ी लगा रहे थे। जब जेल में दिल का दौरा पड़ने से मुख़्तार अंसारी की मौत हुई और उसके रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि जेल में उन्हें ज़हर दिया गया था, तो केजरीवाल ने भी कहना शुरु कर दिया था कि उन्हें भी जेल में ज़हर ही दिया जा रहा है। लेकिन उन्हें कचहरी से राहत नहीं मिली। उनके दो और साथी इसी शराब घोटाला मामले में साल भर से भी ज्यादा समय से जेल में हैं। लाख अर्ज़ियाँ लगाने के वाबजूद उन्हें ज़मानत नहीं मिली। केजरीवाल की इस मामले में संलिप्तता को लेकर अभी प्रवर्तन निदेशालय जाँच कर ही रहा था कि केजरीवाल ने देश की सबसे बडी कचहरी में यही अर्ज़ी लगा दी कि उनका तो शराब घोटाले वाले मामले से कोई सम्बध नहीं है। उनको बिना किसी कारण से पकड़ लिया गया है। इसलिए उनके खिलाफ की जा रही जाँच को बन्द करके उन्हें रिहा कर दिया जाए। बाक़ी उनके वकील इस मामले में ज्यादा तर्क यह भी दे रहे थे कि चुनाव का मौसम है और केजरीवाल दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री भी हैं, इसलिए और नहीं तो उनके मुवक्किल को चुनाव में प्रचार करने के लिए ही छोड़ दिया जाए। सबसे बडी कचहरी को उनके वकीलों का यह तर्क मज़ेदार लगा। इसलिए कचहरी ने स्वयं ही सुझाव दिया कि इसके लिए अंतरिम ज़मानत के लिए अर्ज़ी लगाओ तो देखते हैं। अब अर्ज़ी लगाने में भला कितनी देर लगती। तब अर्ज़ी पर बहस शुरु हुई। दोनों ओर से वकील कचहरी में डट गए। केजरीवाल के वकीलों का तो तर्क वही था कि 'लोगों के चुने हुए मुख्यमंत्री' जेल में हैं और चुनाव का मौसम है। केजरीवाल जेल से बाहर न निकाले गए तो देश में लोकतंत्र और संविधान दोनों ख़तरे में पड जायेंगे। यहाँ तक कहा गया कि केजरीवाल को तो पकड़ा ही इसलिए गया है ताकि वे प्रचार न कर सकें। बाक़ी शराब घोटाला तो बहाना है। इतना ही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय की हिमाक़त तो देखें कि केजरीवाल को तब पकड़ा गया जब देश में आदर्श चुनाव संहिता लागू हो चुकी थी। वैसे ये तर्क सुन कर देश का आम आदमी तो सिर पीट रहा था। अभी तक तो यही माना जा सकता था कि चुनाव संहिता के दिनों में सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर सकती, जिस से मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। लेकिन अब यह भी कहा जा रहा था चुनाव संहिता के दिनों में किसी तथाकथित अपराधी को भी गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। बस एक ही रट थी कि देश में लोकतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा केजरीवाल के बाहर आने से ही हो सकती है।

सरकारी वकील यह सब सुन सुन कर दाँतों तले उँगलियाँ चबा रहे होंगे। सरकारी वकील गा कहना था कि केस सुनते समय और न्याय करते समय तथाकथित अपराधियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस प्रकार तो जेल में बन्द हर विचाराधीन व्यक्ति को कोई न काम लगा ही रहेगा। उदाहरण के लिए किसान कहेगा, हजूर बिठाई गा समय आ गया है।

महीना भर में चला जाएगा। इसलिए दस दिन के लिए ज़मानत दे दें, गेहूँ बीज कर वापिस आ जाऊँगा। जितना जरुरी चुनाव में प्रचार करना है, शायद उससे भी ज्यादा जरुरी खेत में गेहूँ बोना है। वैसे भी राजनीतिज्ञों के तो मज़े लग जाँएगे। चुनाव तो पाँच साल चला ही रहता है। जैसे केजरीवाल साल भर से ईडी को कह ही रहे थे, सअपने समन सम्भाल कर रखो, मुझे पाँच राज्यों के चुनाव में प्रचार करना है। चुनाव निकल गया तो ईडी ने फिर समन भेजने शुरू कर दिए तो केजरीवाल ने फिर झिड़क दिया कि आपको शराब घोटाला की पड़ी है, इधर राज्य सभा के चुनाव सिर पर मँडरा रहे हैं। ईडी फिर हाथ मलती रही। ईडी ने कहा भी कि भाई, आपको अपराधी कौन कह रहा है, आप आ कर जाँच में शामिल हो जाएँ, ताकि पता तो चले कि शराब घोटाला का मामला कैसे हुआ। लेकिन केजरीवाल तो पैरों पर पानी नहीं पड़ने दे रहे थे। कभी कहने लगे सवाल लिख कर भेज दो, सिफ़र देख लेंगे। कभी कहने लगे वर्चुअल पूछ लो। ईडी परेशान कि यदि हर व्यक्ति ईडी को ही बताने लगे कि जाँच कैसे करनी है तब तो किसी केस की जाँच हो ही नहीं सकती। केजरीवाल की इसी ड्रामेबाज़ी के चलते लोक सभा के चुनाव आ गए। तब ईडी को लगा कि कोई न कोई चुनाव तो होते रहेंगे और केजरीवाल उसी की आड लेकर जाँच का सामना करने से बचते रहेंगे। पानी सिर के ऊपर तक ही आ गया था। तब ईडी ने केजरीवाल को एक और समन भेजा और इस बार उसने और रास्ता निकाला कि इस बात का इंतज़ार न किया जाए कि वे जाँच में शामिल होने के लिए आते हैं या नहीं। इसलिए उनके घर जाकर ही पूछताछ कर ली जाए। जब ईडी के अधिकारी उनके घर पूछताछ करने पहुँचे तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईडी अधिकारियों कोघर के अन्दर जाने से रोकने की कोशिश भी की। लेकिन अन्ततः पिछले कई महीनों के संघर्ष के बाद केजरीवाल ईडी के सामने थे। लेकिन कहा जाता है ज्यादा प्रश्नों के 'उत्तर याद नहीं' वाला सूत्र ही प्रयोग में किया गया। कुछ टैलीफोन भी 'पता नहीं कहाँ रख दिए' वाले सूत्र से टाल दिए गए। जाहिर है ऐसी स्थिति में ईडी के पास उन्हें गिरफ्तार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। वे 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिए गए। तब एक से दूसरी अदालत में ज़मानत की अर्ज़ियाँ चलीं। लेकिन मामला गम्भीर था, इसलिए जेल से बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। तब अन्त में यह तर्क चला कर देख लिया गया कि हजूर मैं कोई साधारण क़ैदी नहीं हूँ। मैं तो राजनीतिज्ञ हूँ। मुझे तो चुनाव प्रचार बगैरह भी करना है। इसलिए मुझे रिहा कर दिया जाए।

लगता है कचहरी को यह तर्क ठीक लगा। उन्होंने कहा भी शराब घोटाले का मामला तो अगस्त 2022 से चल रहा है। अब केजरीवाल को गिरफ्तार भी तो इतने समय बाद मार्च 2024 में किया गया था। वैसे भी वे कोई आदतन अपराधी तो हैं नहीं। इसलिए कुछ दिन बाहर रह जाने से कोई पहाड तो नहीं टूट पड़ेगा। हम उन्हें कोई पक्की ज़मानत दो दे नहीं रहे। दो जून को उन्हें खुद चल कर वापिस तिहाड़ जेल जाना ही है। ख़ैर हुजूर की बात को कौन टाल सकता है। लेकिन जैसा ईडी के वकील ने कहा कि इससे विचाराधीन क़ैदियों के दो वर्ग मान लिए गए हैं। पहला वर्ग राजनीतिज्ञ क़ैदियों का और दूसरा सामान्य क़ैदियों का। ज़मानत चाहे वह पक्की हो चाहे अंतरिम, उसके लिए मानक भी अलग अलग ही मान लिए गए हैं। जैसा भारत में स्थिति बनती जा रही है, राजनीतिज्ञ क़ैदियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वैसे भी राजनीतिज्ञ बनने के लिए कोई परीक्षा तो पास नहीं करनी पड़ती। किसी प्रकार के चुनाव में, चाहे वह पंचायत का हो, नगरपालिका का हो, विधान सभा का हो, विधान परिषद का हो, लोक सभा का हो या राज्य सभा का हो, में केवल चुनाव लडने के लिए काग़ज़ भर कर स्वयं को प्रत्याशी घोषित करना होगा।

समय-बोध

हाशिये पर जाती बहुजन समाज पार्टी

आर.के. सिन्हा

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटा दिया है। छह महीने पहले ही उन्होंने आकाश को धूमधाम से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उन्होंने कहा कि आकाश तब तक उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं बन सकते, जब तक वे पूरी तरह परिपक्व नहीं हो जाते। आकाश आनंद बीते उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शुरुआती दो चरणों में बसपा के प्रचार अभियान का मुख्य चेहरा थे। उनके भाषणों में भाजपा और समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखे हमले किए गए थे। अप्रैल में सीतापुर में एक चुनावी रैली के दौरान कथित रूप से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया

था। मायावती को लगता है कि ये भाषण पार्टी द्वारा निर्धारित नियमों और नीतियों से भटक गए थे।

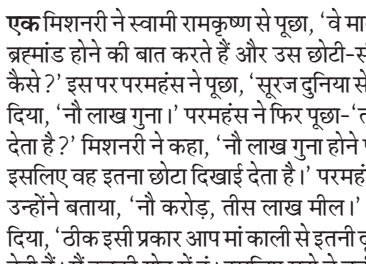

मायावती के इस तरह के अचानक फैसले पहले भी देखे गए हैं लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इसका पार्टी और उनके दलित आंदोलन पर क्या असर होगा। बसपा के संस्थापक कांशीराम ने अपने परिवार को पार्टी से दूर रखा था और मायावती को उनके नेतृत्व कौशल के कारण ही अपना उत्तराधिकारी चुना था। इस रणनीति ने पार्टी को 2007 में उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सत्ता दिलाई, जहाँ दलित समाज आबादी का लगभग 21 फीसदी हिस्सा हैं।

हालांकि, मायावती बसपा को एक व्यापक बहुजन समाज की पार्टी के रूप में विकसित करने में विफल रहीं। पार्टी के कई संस्थापक नेता, जो ओबीसी, अल्पसंख्यक और दलित समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे, मायावती के नेतृत्व शैली से असंतुष्ट होकर पार्टी छोड़ गए। आज बसपा अपने पुराने अखिल भारतीय दलित संगठन के रूप में अपनी पहचान लगभग खो चुकी है, भले ही मायावती कहने को तो आज भी देश की सबसे बड़ी दलित नेता बनी हुई हैं।

मायावती द्वारा बसपा के आंदोलनकारी चरित्र को नजरअंदाज करने और अपने परिवार के भीतर नेतृत्व को मजबूत करने के उनके फैसले ने पार्टी के विकास को नुकसान तो पहुँचाया ही है। दुर्भाग्य से, कई अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने भी यही रास्ता अपनाया है, जिनमें वे दल भी शामिल हैं जो वैचारिक रूप से शक्तिशाली आंदोलनों से उभरे थे। बसपा के मामले में पार्टी के पतन को नए दलित नेताओं के उदय ने भी तेज किया है। पार्टी का वोट शेयर लगातार गिर रहा है।

राजशेखर ने सृष्टि को दिखाई दृष्टि

हेमेन्द्र क्षीरसागर
पत्रकार, लेखक व स्तंभकार

दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा हो तो दुनिया का कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। इसमें कोई आतिशोय्क्ति नहीं है। बस जिस दिन ठान लेंगे, समझो मंजिल हासिल कर ली। बाकी रहेगी तो बस तारीख। ऐसे कई उदाहरण और जज्बे हमारे सामने हैं। जिनको दुनिया सलाम करती है। विपदा में समाधान ढूंढ़ना कोई ऐसी कर्मवीरों से सीखें। मिसाल के तौर पर अक्षरशः शब्द! 'हैदराबाद में मेरा कोचिंग सेंटर घर से बहुत दूर था और मुझे सुबह छह बजे से पहले बस पकड़नी होती थी। आज मैं उन सभी हाथों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे सहारे के लिए आगे बढ़े, जिन्होंने मुझे सड़क पार करने में मदद की। मेरी सफलता में उन सबका हाथ है।' - चाटर्ड एकाउंटेंट जे. राजशेखर रेड्डी।

हालिया, आंध्र प्रदेश के रहने वाले जे. राजशेखर रेड्डी भारत के ऐसे पहले सीए हैं, जो बिलकुल भी देख नहीं सकते। राजशेखर जन्म से दृष्टिहीन नहीं थे, सिर में हुए एक ट्यूमर से ऑप्टिकल नर्व डैमेज के कारण 11 वर्ष की आयु में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। गुंटूर में रहने वाले राजशेखर उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं ' जब मैं कुछ भी देखने के काबिल नहीं रहा तो मुझे लगा कि 'अब मेरे जीवन का अंत हो गया है। मैंने कभी आत्महत्या की बात तो नहीं सोची लेकिन मेरा जीवन निराशा में डूब गया था।

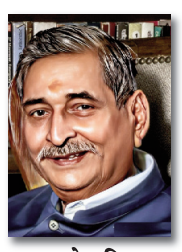

निश्चित ही राजशेखर के अद्भुत समर्पण ने जीवन की नई राह दिखाई है। इनके परिश्रम से यह सिद्ध हो गया दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। राजशेखर का सबक उन लोगों के लिए खास मायने रखता है जो सब कुछ होने के बावजूद बहाने बाजी में अपनी किस्मत को दोष देते फिरते हैं। याद रहे! किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है कायरों का नहीं।

प्रसंग, मैं एक साल तक घर में किसी पत्थर की तरह पड़ा रहा। मेरे माता-पिता मुझे देख कर रोते थे और कहते थे कि काश वे मेरे लिए कुछ कर सकते।' यही आंसू राजशेखर के लिए प्रेरणास्त्रोत बन गए। इसके बाद हैदराबाद का देवनार फाउंडेशन, जो देश में दृष्टिहीन बच्चों का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल था, राजशेखर का नया घर बन गया। देवनार फाउंडेशन के संस्थापक और आंखों के मशहूर डॉक्टर पद्मश्री साईं बाबा गौड़ कहते हैं, 'जब राजशेखर रेड्डी हमारे पास आया था तो 11 साल का बच्चा था। लेकिन उसकी योग्यता, कड़ी मेहनत और संकल्प को देखकर हर कोई प्रभावित था।'

स्तुत्य, दसवीं कक्षा के बाद जब राजशेखर ने एक चार्टर्ड एकाउंटेंट बनने की इच्छा जताई तो सभी को यह असंभव लगा लेकिन परिवार और करीबियों ने उनका समर्थन किया। उन्होंने ऑडियो बुक्स की मदद से अपनी तैयारी की। राजशेखर का कहना है, 'मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि दृष्टिहीन लोग न केवल शिक्षा में सफल हो सकते हैं, बल्कि काम के मैदान में भी वह दूसरों से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।' नतीजा देखिए आज राजशेखर ने चार्टर्ड एकाउंटेंट जैसी कठिनतम परीक्षा पास कर सृष्टि को दृष्टि दिखाई।

निश्चित ही राजशेखर के अद्भुत समर्पण ने जीवन की नई राह दिखाई है। इनके परिश्रम से यह सिद्ध हो गया दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। राजशेखर का सबक उन लोगों के लिए खास मायने रखता है जो सब कुछ होने के बावजूद बहाने बाजी में अपनी किस्मत को दोष देते फिरते हैं। याद रहे! किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है कायरों का नहीं। आईए राजशेखर के प्रेरक कर्मयोग से सीख लेकर अपने कर्तव्य पथ पर ईमानदारी से आगे बढ़े। तो हम देखेंगे सफलता भी हमारे कदम चूमेगी। प्रणाम और साभार! कथित कथन जे. राजशेखर रेड्डी, सीए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • सोमवार • 13 मई • 2024
www.rashtriyasahara.com

अवधारणा बदलते केजरी

अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते ही ताल ठोकने लगे हैं। वे भाजपा नेता एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संभावनाओं पर संशय पैदा कर रहे हैं। उनकी तर्ज पर गारंटीमय हो रहे हैं। कल रविवार को उन्होंने लोक-लुभावनी 10 गारंटी दीं, वे भाजपा के लिए-खुद उनके लिए भी-तलवार की तेज धार होने वाली हैं। इनमें अन्यों की तरह ही कुछ अतिवाद हैं। जैसे चीन से जमीन लेना, दो करोड़ रोजगार देना और हर घर को बिजली एवं गरीबों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा। पर यह कांग्रेस के घोषणापत्र के साथ मिलकर भाजपा का घेराव बनाती है। चुनाव प्रचार के जिस एकल ध्येय से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी, उसमें वे धार दे रहे हैं। मोदी को उन्हीं की बोली-बानी और कार्यशैली में जवाब दे रहे हैं। तो क्या इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया था ताकि वे गुजरात में विकल्प का अर्थ न बन सकें? वस्तुतः ऐसा है नहीं। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी गिरफ्तारी को वैध माना है। आबकारी मामले के मेरिट पर भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है। उनको दो जून को समर्पण का आदेश दिया है। जब यह सब है ही तो फिर अंतरिम जमानत क्यों? कोर्ट का कहना है कि वे आदतन अपराधी नहीं, चुने सीएम हैं, चुनाव पांच साल में आता है। प्रचार करने देने में कोई हर्ज नहीं है। फिर झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन पर इसी नजरिए से विचार क्यों नहीं हुआ जबकि चुनाव उनकी भी पार्टी लड़ रही है? न्यायालय का यह 'सेलेक्टिव एप्रोच' आम जनमानस को पच नहीं रहा है। इसलिए भी कि ईडी की इस ठोस दलील की उपेक्षा की गई है कि तब हरेक विचाराधीन राजनीतिक कैदी को चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर करना होगा। इससे जमानत का नया आधार बनेगा। इससे समानता के सिद्धांत का विभाजन होगा। केजरीवाल की अंतरिम रिहाई इसलिए अटपटी लग रही है। अब इसका राजनीतिक-न्यायिक संदेश जो भी हो, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर हैं। वे इंडिया गठबंधन के मजबूत और विजयी होने की अवधारणा बनाने में राहुल गांधी की आक्रामकता से मिलकर अपना योगदान दे रहे हैं। तीन चरणों के चुनावों में मतों की गिरावट में भाजपा की अंदरूनी लड़ाई और मोदी के भाषणों में उठाए मुद्दों के आधार पर जो परिदृश्य बन रहा है, वह सत्ता-प्रतिष्ठानों के तमाम अंगों पर पड़ने वाले दबावों को जाहिर करता है। जनता के संदर्भ में एक नए आकलन पर विचार शुरू होने का संकेत देता है। विपक्ष के लिए यह सांत्वना है। पक्ष-विपक्ष के आशावाद पर अंतिम मुहर परिणाम ही होगा।

खतरे में प्रजनन दर

अमेरिका की प्रजनन दर में 2023 के दौरान 2% की गिरावट दर्ज की गयी है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की ताजा रपट के अनुसार आस्ट्रेलिया में भी समान पैटर्न नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि कोविड-19 महामारी के चरम के वक्त प्रजजन दर में अस्थाई वृद्धि देखी गयी थी। जिसे छोड़ कर अमेरिकी प्रजनन दर लगातार गिर रही है। इससे कम प्रजनन दर के मामले में जापान, दक्षिण कोरिया व इटली हैं। अमेरिका व आस्ट्रेलिया में इस वक्त प्रजनन दर 1.6 है। जबकि दक्षिण कोरिया में 0.68 रह गयी है। इन देशों में जितने बच्चे जन्म रहे हैं, उससे ज्यादा मौतें हो रही हैं। असल सवाल महिलाओं के कम बच्चे पैदा करने पर जा अटकता है। यूं भी आस्ट्रेलियाई महिलाएं दुनिया में सबसे शिक्षित हैं। पढ़ाई को काफी वक्त देने के बाद वे करियर बनाने में जुट जाती हैं। बच्चे पालना महंगा तथा समय लेने वाली जिम्मेदारी है। महिलाएं ही नहीं पुरुष भी स्थाई नौकरी व आर्थिक सुरक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। अमीर देश ही नहीं, दुनिया भर के 204 देशों और क्षेत्रों में से 155 यानी 76% में 2050 तक प्रजनन दर जनसंख्या प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुंच जाएगी। जनसंख्या को स्थिर बनाये रखने के लिए प्रति महिला 2.1 प्रजनन दर की आवश्यकता है। चूंकि अपने यहां इस वक्त उर्वर यानी 18-35 की उम्र वालों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक तकरीबन साठ करोड़ बतायी जा रही है। विश्लेषकों का अनुमान है कि जनसंख्या 2064 में लगभ 9.7 अरब पहुंच सकती है। मगर 2100 में यह सिकुड़ कर 8.8 अरब पर थम सकती है। प्रजनन दर में आने वाली गिरावट के लिए अकेले महिलाओं को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह सच है कि बच्चों के लालन-पालन में लगने वाले समय, ऊर्जा व धन को लेकर मानदंड बलदते जा रहे हैं। दूसरे देर से युवावस्था की ढलाने में हो रही शादियां व प्रजनन क्षमता में होने वाली गिरावट/दिक्कतों की अनदेखी नहीं की जा सकती। बदलती जीवन-चर्या, आर्थिक दबाव, करियर की बढ़ती मांगे, प्रतिस्पर्धा आदि ने युवाओं का जेहनी सुकून छीना है। बच्चों की देखभाल की उचित व्यवस्था का अभाव भी युवाओं को परिवार बढ़ाने से विमुख करता है। यह जटिल समस्या नहीं है, इसे लाइफ स्टाइल से जोड़ कर देखा जाना चाहिए और इसे सुधारने के प्रति सभी को आगे बढ़ना चाहिए।

परिधि/ राजीव मंडल

लापरवाही का वही ढर्रा

कहते हैं आस्था में कष्ट नहीं देखा जाता। वैसे भी हमारे देश में ज्यादातर धार्मिक यात्राएं बेहद कष्टप्रद होती हैं। उत्तराखंड में शुक्रवार को पवित्र यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन को कष्ट सहने के बावजूद पहुंच रहे हैं। अभी तक की खबर है कि दो श्रद्धालुओं की यात्रा के दौरान मौत हो चुकी है। इसके अलावा, यात्रा के मार्ग पर उन बातों का ख्याल नहीं रखा गया है, जिससे दर्शनार्थियों को सुकून मिल सके।

फिलवक्त जो दृश्य और जानकारियां सामने आ रही हैं, उससे वहां की प्रशासनिक लापरवाही का साफ पता चलता है। कहीं खाने की चीजें महंगे दाम में मिल रही हैं, तो कहीं पानी की घोर किल्लत है। यहां दो रोटी और अचार के लिए 500 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। वहीं गंगोत्री धाम में होटल खाली हैं क्योंकि यहां पानी की घोर कमी है। स्वाभाविक है, प्रशासन ने इन सब बातों को नजरअंदाज किया है। ज्ञात है कि देश के कोने-कोने से आस्थावान लोग बेहद कष्टदायक होने के बावजूद यहां की यात्रा के लिए मानसिक तौर पर खुद को तैयार करते हैं। कई महीने पहले से यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन और अन्य उपक्रम की तैयारी करने में मशगूल हो जाते हैं। जाहिर है, सरकार और प्रशासनिक तंत्र को इस बात का ख्याल रखना ही चाहिए कि जो भी श्रद्धालु यहां पहुंचें, उन्हें तकलीफ न हो। मगर हो इसके ठीक उलट रहा है। रास्ते भी इतने संकरे हैं कि अनहोनी की आशंका बराबर बनी रहती है।

इतने वर्षों बाद भी यहां के हालात बेहतर क्यों नहीं हो पा रहे हैं। करोड़ों रुपये खर्चने के बावजूद श्रद्धालुगण उन्हीं दुश्वारियों से दो-चार होते हैं, जैसा वर्षों पहले करते थे। घंटों यात्री रास्तों में ही फंसे रहने को मजबूर हो रहे हैं। कइयों को तो गाड़ी में ही रात गुजारनी पड़ी। यह हाल तब है जब अभी बदरीनाथ की तरफ श्रद्धालुओं की संख्या का पता नहीं चला है। रविवार को बदरीनाथ के कपाट खुलने के बाद ही वहां की सुविधाओं और दिक्कतों का पता चल सकेगा। बहरहाल, यात्रियों की भारी और अनियंत्रित भीड़, ट्रैफिक का अस्त-व्यस्त होना और खाने-पीने से लेकर बाकी सुविधाओं में दिक्कतों से कुल मिलाकर पर्यटन और राज्य सरकार की कमाई पर ही असर पड़ेगा। हां, राज्य सरकार की बदनामी होगी सो अलग।

संजीदगी से सोचना होगा

बुजुर्ग आबादी

डॉ. सुरजीत सिंह गांधी

हाल में आई एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट भारत सहित एशियाई देशों में होने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को ही रेखांकित नहीं करती, बल्कि बुजुर्गों की बढ़ती संख्या की चुनौतियों के प्रति भी सजग करती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित एशियाई देशों में बुजुर्गों की संख्या और अनुपात में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। भारत में आर्थिक-सामाजिक प्रगति से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होने से जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष से अधिक हो गई है। वर्तमान में भारत में बुजुर्गों की आबादी 10 प्रतिशत से अधिक है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के अनुसार, 2050 तक बुजुर्गों की संख्या कुल संख्या का 19.5 प्रतिशत तक होने का अनुमान है। रिपोर्ट यह भी उल्लेख करती है कि 2031-40 के दौरान भारत में उम्रदराज आबादी से आर्थिक विकास पर बहुत कम प्रभाव होगा क्योंकि इस दशक में भी युवा आबादी अधिक ही रहेगी। लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया 2021 की रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि बुजुर्ग आबादी का एक बड़ा हिस्सा पुरानी बीमारियों, कार्यात्मक सीमाओं, अवसादग्रस्त लक्षणों और कम जीवन संतुष्टि से पीड़ित है।

आयु बढ़ने के साथ बुजुर्गों की दैनिक गतिविधि देखभाल की जरूरतें भी बढ़ने लगती हैं। औद्योगीकरण एवं शहरीकरण बढ़ने से परिवारों का आकार छोटा होता जा रहा है, जिससे बुजुर्गों की देखभाल और भी मुश्किल होती जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल के अनुसार, 2017 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 100,000 जनसंख्या पर 43 चिकित्सक थे, जबकि शहरी क्षेत्रों में 118 चिकित्सक। ऐसे में भारत में वृद्धों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच चुनौती है। तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी के लिए व्यापक दीर्घकालिक देखभाल रणनीतियां डिजाइन करने की आवश्यकता है जिसमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा है। भारत में अभी तक स्वास्थ्य बीमा लगभग 20 प्रतिशत आबादी को ही कवर करता है। स्वास्थ्य बीमा कंपनियां अपने उत्पाद मुख्य रूप से उच्च आय समूहों के लिए डिजाइन करती हैं। मध्य आय वर्ग के अधिकांश लोगों के पास बीमा सुविधा नहीं है। शहरी और ग्रामीण आबादी में भी काफी भिन्नता है। भारत में बुजुर्गों की पहुंच स्वास्थ्य बीमा तक कम होने का प्रमुख कारण यह सुविधाजनक होने की बजाय पेचीदा चुनौती है। पॉलिसियों में कम कवरेज, उच्च प्रीमियम और लंबी प्रतीक्षा अवधि जैसी अनेक बाधाओं एवं जेब पर पड़ने वाले भारी बोझ के कारण अधिकांश बुजुर्ग स्वास्थ्य बीमा को बीच में ही छोड़ देते हैं। हाल में इस दिशा में सार्थक पहल करते हुए बीमा नियामक-

आईआरडीएआई-ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने वालों के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा को हटा दिया है, जिससे न केवल बीमा क्षेत्र के बाजार का विस्तार होगा, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल खर्चों से पर्याप्त सुरक्षा भी मिलेगी। यद्यपि सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं आयुष्मान भारत जैसी योजना से निम्न आय वर्ग को कैशलेस स्वास्थ्य सेवा से स्वास्थ्य कवरेज में सुधार हुआ है।

इसके बावजूद बुजुर्ग आबादी का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य बीमा से वंचित है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए विचार इस बात पर होना चाहिए कि अधिक समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को किस प्रकार विकसित किया जाए कि सीनियर सिटीजन को अर्थव्यवस्था के लिए अधिक उत्पादक बनाने की नई शुरुआत की जा सके। एडीबी के मुख्य अर्थशास्त्री अल्बर्ट पार्क का मानना है कि वृद्धों से अतिरिक्त उत्पादकता के रूप में प्राप्त कर सकल घरेलू उत्पाद को औसतन 0.9 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। नीति आयोग के अनुसार स्वस्थ और शिक्षित वृद्ध लोगों को अधिक उत्पादक बनाने, उनकी अप्रयुक्त कार्य क्षमता से प्राप्त होने वाला लाभांश या अतिरिक्त उत्पादकता से अर्थव्यवस्थाओं के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 1.5 प्रतिशत के बराबर वृद्धि की जा सकती है। भारत में लगभग एक तिहाई बुजुर्ग ही काम कर रहे हैं। सरकार की ओर से उचित हस्तक्षेप द्वारा बुजुर्गों को विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए एक मंच प्रदान कर अर्थव्यवस्था में इनके योगदान को बढ़ाया जा सकता है। भविष्य की इस चुनौती के लिए व्यापक, एकीकृत नीति बनानी होगी।

भारत में सामुदायिक सहभागिता परियोजनाएं शुरू करने की आवश्यकता है और सामाजिक भागीदारी में डिजिटल और भौतिक, दोनों बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है। बुजुर्गों का सशक्तिकरण मौजूदा कानूनी सुरक्षा उपायों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता और मौजूदा कल्याण और रखरखाव अधिनियम को मजबूत करने जैसे कानूनी सुधार सुनिश्चित करने से भी स्थिति को सुखदायी बनाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021-2030 को स्वस्थ उम्र बढ़ने का दशक घोषित किया गया है। वृद्ध लोगों, उनके परिवारों और जिस समुदाय में वे रहते हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में मिलकर काम करना होगा। जिससे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके जिससे उन्हें भोजन, आश्रय, चिकित्सा देखभाल और यहां तक कि मनोरंजन के अवसर जैसी विभिन्न बुनियादी सुविधाएं मिल सकें।

विभिन्न शहरों में समाजसेवियों को पहल करते हुए एक वरिष्ठ नागरिक डिजिटल मंच बनाया जाना चाहिए जिससें बुजुर्ग लोग अपनी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को साझा कर सकें और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें जिनका वे दिन-प्रतिदिन सामना करते हैं। अब चिकित्सा और सामाजिक आयामों के अलावा वरिष्ठ देखभाल के विशेष आयामों के बारे में सोचना शुरू करने का समय आ गया है। यही समय है जब उम्र बढ़ने को गरिमा से प्रेरित, सुरक्षित और उत्पादक बनाने पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, भलाई और देखभाल पर अधिक जोर देने की जरूरत है।

आयु बढ़ने के साथ बुजुर्गों की दैनिक गतिविधि की देखभाल की जरूरतें भी बढ़ने लगती हैं। औद्योगीकरण एवं शहरीकरण बढ़ने से परिवारों का आकार छोटा होता जा रहा है, जिससे बुजुर्गों की देखभाल मुश्किल होती जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल के अनुसार, 2017 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 100,000 जनसंख्या पर 43 चिकित्सक थे, जबकि शहरी क्षेत्रों में 118 चिकित्सक। तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी के लिए रणनीतियां बनाने की जरूरत है

पार्किंसंस डिजीज के प्रति जागरूकता जरूरी

- पार्किंसंस डिजीज बुजुर्गों को होने वाली आम न्यूरोलॉजिकल समस्या है। यह बढ़ती उम्र में होने वाली समस्या है, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में बच्चे और किशोर भी इसके शिकार हो जाते हैं
- पार्किंसंस के शिकार लोगों में हाथों का हिलना, मांसपेशियों में जकड़न, चलने-फिरने में परेशानी और संतुलन बनाने में मुश्किल जैसे लक्षण दिखते हैं
- महिलाओं की तुलना में पुरुषों में इसकी आशंका ज्यादा रहती है। अगर दवा से लाभ न हो तो कुछ मरीजों में सर्जरी की सलाह भी दी जाती है

(मीडिया इन्पुट्स)

भारत को लेकर मैं आशावादी हूं क्योंकि किसानों से लेकर कामगारों से लेकर कॉरपोरेट दिग्गजों यहां तक कि सरकार में काम कर रहे अफसरशाहों तक का एक बड़ा विचारशील हिस्सा आज महसूस कर रहा है कि भारत में परिवर्तन की दरकार है।

कौशिक बसु, अर्थशास्त्री
@kaushikcbasu

पर्यावरण संरक्षण प्रो. किरण कुमारी

नवाचार से सुधरेंगे हालात

प्राचीन समय से ही मानव समुदाय ने प्रकृति के महत्त्व को समझा है। प्रकृति हमारे जीवन का मूलभूत आधार है। हमें आहार, जल, वायु और अन्य सामग्री प्रदान करती है जो जीवन के लिए आवश्यक है। मानव पर पर्यावरण के प्रभावों और उसकी और प्रकृति के बीच की जो क्रियाएं हैं, वे मानव को प्रभावित करती हैं। जिस प्रकार मनुष्य प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, पुनः दोनों मिलकर अपने-अपने कार्यों का संपादन करते हैं। इसलिए प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण हमारे लिए ही नहीं, बल्कि समस्त जीवों के लिए आवश्यक है।

हम सभी जानते हैं कि प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रकृति के सभी तत्वों का संतुलन आवश्यक है। यदि पारिस्थितिकी तंत्र का किसी भी एक तत्त्व का विनाश होता है तो इससे संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। वर्तमान समय में मानव जाति के समक्ष पीने योग्य पानी की उपलब्धता, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और भूमि संरक्षण की समस्या भयावह रूप धारण करती जा रही है। अनुमान है कि 2050 तक लवणीय मृदा में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। आज का वैज्ञानिक युग का मनुष्य चांद और मंगल ग्रह पर निवास करने की बात कर अरबों रुपया केवल अंतरराष्ट्रीय कोषों से खर्च कर रहा है, जब की यह गहन चिंतन, मंथन और विचार करने योग्य बात है कि स्वयं हमने ही इस हरी-भरी पृथ्वी के सुंदर कल्याणकारी स्वरूप को विकृत बना डाला है, इसके जिम्मेदार हम ही हैं। आवश्यकता है, स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र और संपूर्ण भूमंडल पर मानव जाति के आर्थिक क्रियाकलाप के प्रभावों को नियंत्रित करने की और वैश्विक तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चुनौतियों को स्वीकार कर मनुष्य को अपनी जीवनशैली के बारे में पुनर्विचार कर सुधारने की। प्रकृति, पर्यावरण, और भूसंरक्षण सामाजिक और आर्थिक विकास के महत्त्वपूर्ण पहलुओं में शुमार हैं। इनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए संवेदनशीलता बढ़ रही है, अतः इन्हें शिक्षा प्रणाली के माध्यम से बच्चों और युवाओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा घोषित, राष्ट्रीय शिक्षा

नीति-2020 के कार्यान्वियन से, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी, समर्पित और सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए इसमें शिक्षा के समावेशीकरण, उत्तम तकनीकीयुक्त व गुणवत्तायुक्त शिक्षा और पर्यावरणीय शिक्षा को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में पर्यावरण संरक्षण के लिए कई पाठ्यक्रम और उपायों की बात की गई है। नई शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा को समावेशीकरण के लिए प्रोत्साहित किया है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सिखाया जाएगा और माध्यमिक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के बारे में गहरी जागरूकता प्राप्त कराई जाएगी। एनईपी ने गुरुकुल प्रणाली को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है, जिसमें छात्रों को प्रकृति के साथ निकटता बनाने का अवसर मिलेगा। इसके माध्यम से वे प्राकृतिक परिवेश में रहकर पर्यावरण के महत्त्व को समझेंगे। उसकी रक्षा के लिए सक्रिय योगदान करेंगे। एनईपी ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी पर्यावरण अध्ययन को महत्त्व दिया गया है। छात्रों को पर्यावरणीय विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा ताकि वे पर्यावरण संरक्षण नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकें।

एनईपी में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में विस्तृत अध्ययन कराने का प्रस्ताव है। इसमें छात्रों को प्रकृति के साथ संबंधित विषयों में गहरी समझ और जागरूकता प्रदान करने के लिए विशेष पाठ्यक्रम समिल्लित किए गए हैं। एनईपी में विभिन्न समुदायों के साथ सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है, जिसमें स्थानीय समुदायों, स्थानीय प्रशासन और संगठनों के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए योजनाएं विकसित की जा सकती हैं और शिक्षा प्रणाली में पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है। यह नीति न केवल छात्रों को अपने पर्यावरण के प्रति सचेत बनाने में मदद करेगी, बल्कि भविष्य के लिए भारतीय समाज को एक साथ और स्थायी पर्यावरण की दिशा में अग्रसर करने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान करेगी। आवश्यकता है, हमें साझेदारी, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने की। वन्य जीवों का अनुरक्षण, वनस्पति का संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन से ही हम स्वस्थ और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह हम न केवल अपने वर्तमान के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की रक्षा कर हम आत्मनिर्भर भारत, उन्नत भारत और विकसित भारत की कल्पना को साकार कर सकते हैं।

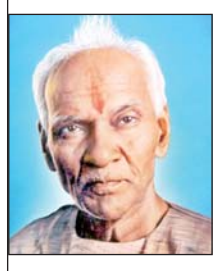

प्रतिकूलताएं श्रीराम शर्मा आचार्य

दुनिया में जितने धर्म, संप्रदाय, देवता और भगवानों के प्रकार हैं, उन्हें कुछ दिन मौन हो जाना चाहिए और एक नई उपासना पद्धति का प्रचलन करना चाहिए जिसमें केवल 'मां' की ही पूजा हो, मां को ही भेंट चढ़ाई जाए? मां बच्चे को दूध ही नहीं पिलाती, पहले वह उसका रस, रक्त और हाड़-मांस से निर्माण भी करती है, पीछे उसके विकास, उसकी सुख-समृद्धि और समुनति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। उसकी एक ही कामना रहती है कि मेरे सब बच्चे परस्पर प्रेमपूर्वक रहें, मित्रता का आचरण करें, न्यायपूर्वक सम्पत्तियों का उपभोग करें, परस्पर ईर्ष्या-द्वेष का कारण न बनें। चिर शान्ति, विश्व-मैत्री और 'सर्वे भवन्ति सुखिनः' वह आदर्श है, जिनके कारण मां सब देवताओं से बड़ी है। मां के आंचल में ही भविष्य पलता है। मां से मिले संस्कारों के बल पर ही व्यक्ति जीवन पर्यंत तमाम चुनौतियों का सामना करता रहा है, उसे कहीं से भी इस कमजोरी का अहसास नहीं होने पाता कि किस कदर मां ने उसे सशक्त कर दिया है। जब भी पोषण की बात आती है, तो सहसा मां की मूर्त आंखों के सामने घूम जाती है। प्रकृति के संरक्षण और प्राकृतिक उपहारों को सहेजने की बात होती है, तो सहसा मां का अक्स आंखों में उतर आता है। हमारी धरती ही हमारी माता है यह मानकर उसकी उपासना करें। अहंकारियों ने, दुष्ट-दुराचारियों स्वार्थी और इन्द्रिय लोलुप जनों ने मातृ-भू को कितना कलंकित किया है, इस पर भावनापूर्वक विचार करते समय आंखें भर आती हैं। हमने अप्रत्यक्ष देवताओं की तो पूजा की पर प्रत्यक्ष देवी धरती माता के भजन का कभी ध्यान ही नहीं आया। आया होता तो आज हम अधिकार के प्रश्न पर रक्त न बहाते, स्वार्थ के लिए दूसरे भाई का खून न करते, तिजोरियां भरने के लिए मिलावट न करते, मिथ्या सम्मान के लिए अहंकार का प्रदर्शन न करते। संसार भर के प्राणी उसकी सन्तान-हमारे भाई हैं। यदि हमने मां की उपासना की होती तो हक कदापि छल-कपट, ईर्ष्या-द्वेष दम्भ, हिंसा, पाशविकता, युद्ध को प्रश्रय न देते। स्वर्ग और है भी क्या, जहां ये बुराइयां न हों वहीं तो स्वर्ग है। मां की उपासना से स्वर्गीय आनंद की अनुभूति इसीलिए यहीं प्रत्यक्ष रूप से अभी मिलती है। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ दिन और सब उपासना पद्धति बंद कर केवल 'मां' की मातृ-भूमि की उपासना करनी चाहिए।

रीडर्स मेल

चिंता की बात

अभी हाल ही में जनसंख्या पर आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 43.15 प्रतिशत की दर से मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है, जबकि हिन्दू की जनसंख्या में 7.82 प्रतिशत की गिरावट सामने आई है यानी आनुपातिक दृष्टि से भारत में हिन्दुओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है। चिंता यह नहीं है हिन्दू कम क्यों होते जा रहे हैं, बल्कि चिंता इस बात की है कि मुसलमानों की जनसंख्या में यह वृद्धि कहीं घुसपैठ के कारण तो नहीं है। अगर यह सत्य है तो और भी गंभीर चिंता का विषय है। इसी घुसपैठ के चलते भारत के नौ राज्यों में आज हिन्दू अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ गया है। इसके कारण देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है क्योंकि संसाधन सीमित होने के बाद भी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश की राजनीतिक-सामाजिक संस्थाओं को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जनसंख्या का यह आनुपातिक असंतुलन क्यों पैदा हो रहा है। इसके निहितार्थ क्या हैं? अगर इस पर अभी विचार नहीं किया गया तो आने वाला समय बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है।

सुरेश हिन्दुस्थानी, ग्वालियर, मप्र

केजरीवाल की कुंठा

अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं, जो हमेशा गलत वजहों से खबरों में बने रहते हैं। उनकी टिप्पणियां प्रायः बेतुकी और असंगत होती हैं। उनकी ये बातें उनकी कुंठा को ही व्यक्त करती हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उनको सशर्त जमानत देते हुए उन्हें सचिवालय और मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाने का आदेश दिया है। जेल से छूटते ही उन्होंने भाजपा पर हमला बोला और कहा कि मोदी अगली बार जीतकर आएंगे तो योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। कांग्रेस और आप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह कांग्रेस आजादी के बाद से भ्रष्टाचार की वैतरणी पार कर रही है वैसे ही केजरीवाल सहित कई नेता जेल में हैं। एक मुख्यमंत्री की ऐसी बयानबाजी अच्छी बात नहीं है। केजरीवाल दरअसल भाजपा के भीतर जो छिटपुट मनमुटाव है, उसे सार्वजनिक कर फायदा उठाने की जुगत में हैं।

कांतिलाल मांडोत, सूरत, गुजरात

मुफ्त का झुनझुना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रेबड़ी कल्चर पर विपक्षी सरकारों को कोसते हैं। अब दिल्ली की लोक सभा सीटों की बात करें। यहां बीजेपी ने कहा है कि वह दिल्ली में रहने वाले सीनियर सिटीजन को रेल बस किराये में रियायत जारी रखेगी। उत्तर प्रदेश में और लोगों की तरह वरिष्ठ नागरिकों को भी यात्रा का पूरा किराया चुकाना होता है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। वहां सभी उम्र की महिलाओं को बस किराये में रियायत मिलती है। प्रश्न बस रेल या बस किराए में रियायत का है। यदि बीजेपी सरकार दे रही है तो यह सुविधा सभी बीजेपी शासित राज्यों में मिले। राजस्थान, दिल्ली के लोगों को ही ये सुविधाएं क्यों मिलें। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ही मुफ्त रेबड़ी बांट कर चर्चा में रहती है और लगातार बहुमत से जीतती है। अब बीजेपी दिल्ली की लोक सभा सीटों के लिए रियायत का झुनझुना लोगों को दे रही है। क्या वह दिल्ली में अपने विरोधी केजरीवाल से डर गई है जो खुद रेबड़ी कल्चर का विरोध करते हैं, खुद उसका हिस्सा बने हैं। दरअसल, मुफ्त की चीजों पर पहले तो सभी दलों ने आम आदमी पार्टी की आलोचना की, मगर बाद में भाजपा भी उसी ढर्रे पर चलती दिख रही है।

दिलीप कुमार गुप्ता, बरेली

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 269
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **जिया कादरी** द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। **समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र*** ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, **फैक्स** - 23352370, **दूरभाष - नोएडा प्रेस** 0120-2444755, 2444756 **फैक्स** - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

पीओकेमें बगावत

पाकिस्तानके अवैध कब्जेवाले कश्मीर (पीओके) में बगावतकी स्थिति उत्पन्न हो गयी है। वहांकी सरकार और सेना इसपर काबू पानेमें पूरी तरहसे विफल है। पूरा माहौल अशान्तिपूर्ण हो गया है। विभिन्न स्थानोंपर विरोध और प्रदर्शनका सिलसिला प्रारम्भ हो गया है। शनिवारको झड़पोंके दौरान एक पुलिस अधिकारीकी मौत हो गयी और सौसे अधिक लोग घायल हो गये हैं। भीषण महंगी, भारी कर और बिजलीकी कमीके खिलाफ शुरू हुआ जन-आन्दोलन अब बगावतकी ओर अग्रसर हो गया है। इसने पीओकेमें अधिकारों और आजादीके लिए आन्दोलनका रूप ले लिया है। प्रदर्शनकारी न केवल आजादीके लिए नारे लगा रहे हैं, बल्कि भारतसे गुहार भी कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद और अन्य जिलोंमें पुलिस और सुरक्षा एजेंसियोंके साथ लोगोंकी झड़पें हुईं। जम्मू-कश्मीर संयुक्त अवामी पार्टी एक्शन कमेटी इस विरोध प्रदर्शनका नेतृत्व कर रही हैं, जिसमें व्यापारी सबसे आगे हैं। शुक्रवारको हड़तालका आह्वान करनेके बाद अबतक ऐक्शन कमेटीके दर्जनों नेताओं और सदस्योंको गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रदर्शनकारियोंके साथ पुलिस बर्बरता कर रही है। बर्बरताके खिलाफ पीओके विशेष रूपसे मुजफ्फराबादमें पूरी तरह शटडाउन और चक्का जाम, हड़तालकी तैयारी हो गयी है, जिससे स्थिति और गम्भीर हो जायगी। आजादीकी मांग कर रहे स्थानीय लोगोंके वीडियो वायरल हो गये हैं। सभी लोगोंसे बाहर सड़कपर आने और अपने अधिकारोंके लिए आवाज उठानेकी अपील की जा रही है। इसका जनतापर पूरा असर पड़ा है। ऐक्शन कमेटीने इसी तरहका अगस्त २०२३ में भी विरोध प्रदर्शन किया था लेकिन इस बार यह और गम्भीर हो गया है। पीओकेके मीरपुर जिलेमें कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्कूली छात्रोंपर आंसू गैसके गोले दागे गये। वहां मानवाधिकारोंका उल्लंघन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्रकी मानवाधिकार संस्थासे तत्काल हस्तक्षेपकी मांग की गयी है। पाकिस्तानकी आर्थिक स्थिति बदसे बदतर हो गयी है। जीवनयापनके लिए आवश्यक वस्तुएं काफी महंगी हो गयी हैं। देशका विदेशी मुद्रा भण्डार आठ बिलियन डालर है, जिससे लगभग डेढ़ माहतकका सामान आयात किया जा सकता है। स्थिति इतनी बेकाबू हो गयी है कि लोग गिलगित और बाल्टिस्तानकी आजादीकी मांग कर रहे हैं। जनता सुरक्षाबलोंको दौड़ाकर मार रही है। वस्तुत: पीओके भारतका ही अभिन्न हिस्सा है और अब वहांके लोग भारतमें उसके विलयकी मांग कर रहे हैं। परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकरने पांच मईको ओडिशाके कटकमें कहा था कि स्थिति बहुत ही खेदजनक है। जो हालात हैं उसे देखते हुए अब पीआकेपर पूरा कब्जा भारतका होना चाहिए क्योंकि यह भाग भारतका ही रहा है। वहांकी जनता भी यही चाहती है।

हृदयविदारक घटना

घरेलू कलहका दुष्परिणाम कितना हृदयविदारक और दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, इसे उत्तर प्रदेशके सीतापुर जिलेमें एक ही परिवारके छह लोगोंकी मौतके परिप्रेक्ष्यमें देखा जा सकता है। दिल दहला देनेवाली यह घटना रामपुर मथुरा क्षेत्रके पाल्हीपुर गांवमें घटी, जहां नशेमें धुत एक युवकने शनिवार तड़के करीब चार बजे पत्नीसे झगड़ेके बाद मां, पत्नी और तीन बच्चोंकी हत्या कर दी और खुदको भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सूत्रोंके अनुसार युवक नशेका आदी था। परिवारवाले उसे नशामुक्ति केन्द्र ले जाना चाहते थे, इसी बातको लेकर शुक्रवार रात विवाद हुआ था और उसके कुछ घण्टे बाद ही युवकने इस सनसनीखेज घटनाको अंजाम दिया जो अत्यन्त दुखद और मर्माहत करनेवाली है। हालांकि युवकका परिवार पूरे गांवमें सबसे सम्पन्न है। दो भाइयोंके बीच करीब २६० बीघा खेती थी जिसे वही सम्भालता था। वह एक प्रगतिशील किसान होनेके साथ ही सफल कारोबारी भी था जिसका कारोबार लखनऊतक फैला था और लखनऊमें एक शानदार अपार्टमेण्ट भी है। उसकी पत्नी भी लखनऊमें एक इंश्योरेंस कम्पनीमें सेवारत थी और अपने बच्चोंके साथ अपार्टमेण्टमें रहती थी। वह शुक्रवारको ही बच्चोंको लेकर गांव आयी थी। इतनी सम्पन्न और भरापूरा परिवार होनेके बाद इस तरहकी रोंगटे खड़ा कर देनेवाली वारदात हैरान करनेवाली है। इसकी पारदर्शितासे जांच होनी चाहिए। पुलिस जो घटना कारण बता रही है वह सन्देहास्पद है। गांववाले भी पुलिसकी थ्योरीसे सन्तुष्ट नहीं हैं। युवकके सालेने भी पुलिसके बयानको सरासर गलत बताया है। उसका आरोप है कि यह मामला प्रापर्टीका विवाद है। वैसे सचाई चाहे जो भी हो यह तो जांचका विषय है लेकिन इस तरहकी घटना विचलित करनेवाली है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिससे सचाई लोगोंके सामने आ सके।

लोक संवाद

तनावमुक्त हों शिक्षक

महोदय,-शिक्षक सुखी हो तो पढ़ाईका स्तर बहुत अधिक सुधर सकता है। यदि शिक्षकका अधिक समय तनाव, आपसी मतभेदों और इधर-उधरकी बातोंमें व्यर्थ होता है तो इसका सबसे अधिक असर बच्चोंकी पढ़ाईपर पड़ेगा। अंग्रेजीका एक शब्द है बर्नआऊट। इसका अर्थ है बहुत अधिक कामके कारण अवसाद, चिड़चिड़ापन और हमेशा थकानका अनुभव होना। गौरतलब है कि देशमें शिक्षणके पेशेमें भी बर्नआऊटकी गम्भीर समस्या होने लग गयी है, परन्तु इसपर शायद ही कोई गम्भीरतासे ध्यान दे रहा हो। शिक्षक तनाव महसूस करते हैं, उन्हें शारीरिक और मानसिक थकानका अनुभव होता है तो वे अकसर अपने कामकाजको लेकर उदासीन हो जाते हैं। नौकरीमें आनन्द नहीं बचता, परन्तु नौकरी करना मजबूरी भी है। स्कूलोंमें शिक्षकोंकी संख्या अकसर आवश्यकतासे कम होती है। जब कुछ शिक्षक गैर-हाजिर हों तो समस्या और बढ़ जाती है। बाकी शिक्षकोंको अनुपस्थित शिक्षकोंकी कक्षाएं लेनी पड़ती हैं, जिसका अर्थ है अतिरिक्त जिम्मेदारी और दोहरा तनाव। अकसर स्कूलोंमें शिक्षकोंको प्रशासनिक काम भी सौंप दिये जाते हैं। जब शिक्षकोंको पर्याप्त वेतन नहीं मिलता है या पर्याप्त लाभ नहीं मिलता तो यह उन्हें बहुत थका हुआ और निराश कर सकता है। यह शिक्षणके लिए उनकी ऊर्जा और प्रेरणाको छीन लेता है। ऐसी भी व्यवस्था हो कि कामके बाद शिक्षक पूरी तरहसे अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवनपर ध्यान दे सकें। स्कूलकी बुनियादी सुविधाओंपर ध्यान देना जरूरी है। शहरोंमें कई स्कूल बहुमंजिला होते हैं। ऐसेमें शिक्षकको बार-बार ऊपर-नीचे जाना पड़ सकता है। अधिक उम्रके शिक्षकोंको ज्यादा कक्षाएं निचली मंजिलपर ही मिलें, समय सारिणी बनानेवालेको इसका ख्याल रखना चाहिए। सकारात्मक स्कूली संस्कृति छात्र और शिक्षक दोनोंके लिए कितनी लाभकारी होगी, यह आसानीसे समझा जा सकता है। शिक्षकोंके लिए जरूरी है कि उनके रोजमर्राके जीवनमें ऐसा समय भी हो जब उन्हें स्कूल, छात्रों और कामके बारेमें बिल्कुल सोचना न पड़े। यह जिम्मेदारी खुद उनकी है कि ऐसा समय वे खुदकी और परिवारकी देखभालमें बितायें, क्योंकि परिवारके सदस्योंके बीच समय बितानेसे कामके तनावको कम किया जा सकता है। सही संगी-साथियों और बेहतर माहौल तैयार करके भी इससे बचा जा सकता है। **-डा.मोहन लाल शर्मा, वाया ईमेल।**

कांग्रेसपर आरक्षणमें फेरबदलका सच

मुस्लिम आरक्षण चुनावमें बड़ा मुद्दा बन गया है। भाजपा कांग्रेसपर आरोप लगा रही है कि वह अनुसूचित जाति-जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गके आरक्षण हटाकर मुसलमानको देना चाहती है। कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष कह रहा है कि मोदी देशमें हिंदू-मुस्लिमके नामपर चुनावमें ध्रुवीकरण चाहते हैं जो सरेआम सांप्रदायिककरण है।

❒ **अवधेश कुमार**

यदि चुनावमें किसी संप्रदायपर हमला किया जाय या उसके विरुद्ध दूसरे संप्रदायको भड़काया जाय तो यह साम्प्रदायिकताकी श्रेणीमें आयगा और इसके लिए चुनाव कानून ही नहीं सामान्य कानूनोंमें भी मुकदमा चलाने तथा सजा देनेका प्रावधान है । प्रश्न है कि क्या प्रधान मंत्रीने जो आरोप लगाया उसे चुनावको साम्प्रदायिक रंग देनेका षड्यंत्र मान लिया जाय या उसके पीछे तथ्य भी हैं। कांग्रेसके नेता और प्रवक्ता प्रधान मंत्रीपर हमले कर रहे हैं किन्तु यह कहनेको तैयार नहीं है कि वह मजहबके आधारपर मुसलमानोंको आरक्षण देनेके पक्षमें नहीं है। कांग्रेस यह भी स्पष्ट नहीं करती कि वह धर्मके आधारपर आरक्षण के विरुद्ध है। कांग्रेस अपने घोषणा-पत्रमें आरक्षणकी सीमा बढ़ानेका वचन देते हुए यह सुनिश्चित करनेकी घोषणा करती है कि अल्पसंख्यकोंको शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सार्वजनिक रोजगार, सार्वजनिक कार्य अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियोंमें बिना किसी भेदभावके अवसरोंका उचित हिस्सा मिले तो इसलिए मंशापर प्रश्न उठता है क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि है। कांग्रेस सरकारोंने पहले भी मुसलमानोंको आरक्षण देनेकी पहल की है। चूंकि धर्मके आधारपर आरक्षण मान्य नहीं था, इसलिए अन्य पिछड़े वर्गके आरक्षणमें से ही कर्नाटकमें मुसलमानोंको चार प्रतिशत आरक्षण दिया गया। केन्द्रमें यूपीए सरकारके कार्यकालके दौरान आंध्रप्रदेशकी कांग्रेस सरकारने मुसलमानोंको आरक्षण देनेका कानून बना दिया। यह विषय सुप्रीम कोर्टतक गया और कांग्रेसके सभी नामी वकीलोंने इसमें पैरवी की। आज भी अनुसूचित जनजातिसे धर्म परिवर्तन कर मुसलमान या ईसाई बननेवालोंको आरक्षणका लाभ मिलता है। वे अल्पसंख्यक होनेका भी लाभ पाते हैं और अनुसूचित जनजातिका भी।

पिछड़े वर्गका हक मारकर ही कांग्रेस या इण्डी गठबंधनके अन्य दल मुसलमानोंको आरक्षण दे सकते हैं। जब २०१२ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावके दौरान सलमान खुर्शीदने मुसलमानोंके लिए आरक्षणकी घोषणा की और उसके विरुद्ध न्यायालयमें मामला गया तो कांग्रेसकी ओरसे पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवीने बाहर आकर बयान दिया कि खुर्शीद साहबने जो कहा है वह कांग्रेसकी मंशा है। पश्चिम बंगालमें १७९ जातियां अन्य पिछड़े वर्गमें शामिल हैं जिनमें ११८ मुस्लिम है और हिंदू सिर्फ ६१। ममता बनर्जीने ७१ जातियां शामिल की, जिनमें ६५ मुस्लिम थे।

कांग्रेस यह तो कह रही है कि इसमें मुस्लिम शब्द कहीं नहीं है परन्तु अल्पसंख्यकका अर्थ क्या है। यूपीए सरकारके दौरान मुसलमानोंको आरक्षण कांग्रेसकी नीतिमें शामिल हुआ। मनमोहन सरकारने सत्तामें आनेके बाद सच्चर समिति गठित की, जिसने अपनी रिपोर्टमें मुसलमानोंकी स्थितिकी भयावह तस्वीर पेश किया और उनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरणके नामपर अनेक अनुशंसाएं की। इनमें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानोंमें आरक्षण भी शामिल था। सच्चर समितिकी अनुशंसाओंके आलोकमें न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र समितिका गठन हुआ जिसने पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति जनजातिसे धर्म परिवर्तन करनेके बावजूद मुसलमानोंको आरक्षण देते रहनेकी सिफारिश की। यही नहीं उसने पिछड़ा वर्गके २७ प्रतिशतोंके आरक्षणमेंसे मुसलमानको देनेकी सिफारिश की। ३० नवंबर २००६ को सच्चर समितिकी सिफारिशें सरकारको प्राप्त हुई और तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहने ९ दिसंबर २००६ को राष्ट्रीय विकास परिषदकी बैठकके भाषणमें कहा कि मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचेमें निवेशके साथ ही एससी/एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चोंका उत्थान है। हमें ऐसी नयी योजनाएं बनानी होंगी, जिनसे अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमोंको विकासमें समान भागीदारी मिल सके। देशके संसाधनोंपर उनका पहला हक होना चाहिए।

कांग्रेस पार्टीकी धारणा यही थी कि मुस्लिम मत खिसकनेके कारण ही विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगालमें हाशियेपर गयी और उसकी जगह सपा, बसपा, राष्ट्रीय जनता दल और तृणमूल कांग्रेसने ले लिया। कांग्रेसको फिरसे अपना स्थान बनाना है तो उसे स्वयंको मुस्लिमपरस्त दिखाना होगा। इस कारण उस दौरान मुसलमानोंके लिए सरकारकी नीतियोंमें जबरदस्त ढांचा तैयार हुआ। अल्पसंख्यक आयोगको संवैधानिक दर्जा देनेसे लेकर अल्पसंख्यक मंत्रालयका गठन हुआ। तत्कालीन गुजरातके मुख्य मंत्री नरेंद्र मोदीके विरुद्ध अभियान इसी कड़ीका अंग था, जिसमें तीस्ता शीतलवाडको हर तरहसे मदद दी गयी। २०१४ लोकसभा चुनावके लिए आचार संहिता लागू होनेसे ठीक एक दिन पहले मनमोहन सरकारने ५ मार्च, २०१४ को दिल्लीकी १२३ प्रमुख संपत्तियोंको दिल्ली वक्फ बोर्डके हवाले कर दिया। दिल्ली वक्फ बोर्डने २७ फरवरी, २०१४ को राष्ट्रीय राजधानीमें इन प्रमुख संपत्तियोंपर दावा किया था। अनेक उदाहरण मिलेंगे जिनसे साबित होगा कि मनमोहन सरकार ऐसी मुस्लिम संस्थाओं, संघटनों और व्यक्तियोंके पूरी तरह प्रभावमें था। यह आदेश सरकारने उचित मुआवजेका अधिकार और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापनमें पारदर्शिता अधिनियम, २०१३ के तहत मिली शक्तियोंका प्रयोग करते हुए किया तो क्या यह संशोधित अधिनियम ऐसे ही कार्योंको ध्यानमें रखते हुए पारित हुआ था। नरेंद्र मोदी सरकारके आनेके बाद इन सम्पत्तियोंको मुक्त कराया गया और उसके लिए भी न्यायालयमें संघर्ष करना पड़ा। उस समय कांग्रेसकी राज्य सरकारोंके कदमोंकी छानबीन की जाय तो पता चलेगा कि अनेक राज्योंमें इस तरहके निर्णय हुए जिनका कोई वैधानिक आधार नहीं था। जिस तरह तेलंगाना एवं कर्नाटकमें उसे मुस्लिम समुदायका वोट मिला उससे उसको लगता है कि ऐसी नीतियोंपर आगे बढ़नेसे उसका खोया जनाधार वापस आ सकता है। इसलिए राहुल गांधी और उनके नेतृत्वमें पूरी कांग्रेस यह साबित करनेमें लगी है कि मुसलमानके हितोंके प्रति वह पूरी तरह समर्पित है या उसके लिए किसी सीमातक जाने को तैयार है।

ध्यान रखिये पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातिको आरक्षण पहलेसे प्राप्त है, नरेन्द्र मोदी सरकारने आर्थिक रूपसे कमजोर वर्गोंके लिए दस प्रतिशत आरक्षणका प्रावधान कर दिया है। इसमें आर्थिक रूपसे कमजोर मुसलमान भी शामिल हैं तो आप आरक्षणकी सीमाको बढ़ाना किसके लिए चाहते हैं। अपने भाषणों और वक्तव्योंमें राहुल गांधी सहित ज्यादातर नेता अनुसूचित जाति-जनजाति एवं पिछड़े वर्गके साथ ही अल्पसंख्यकों और मुसलमानोंके उत्थानकी बात करते हैं। आखिर अनुसूचित जाति-जनजाति जाति और पिछड़े वर्गके साथ मुसलमानको क्लब कैसे किया जा सकता है। मुसलमानोंने देशमें लम्बे समयतक शासन किया और इस कारण वे विशेषाधिकार वर्गमें आते हैं। मुस्लिम नवाबों और जमींदारोंकी बड़ी संख्या पूरे देशमें रही है। उनकी शक्ति इतनी थी कि उन्होंने जबरन देशका विभाजन भी करवा दिया। मुसलमानोंका आर्थिक-सामाजिक-विकास हो इससे किसीको दो राय हो नहीं सकता। मोदी सरकारमें ही सरकारी नौकरियोंमें उनकी संख्या २०१४ के मुकाबले दोगुनीसे ज्यादा हुई है। किन्तु हमारे यहां जाति व्यवस्थामें हाशियेपर रहे समूहोंके कारण आरक्षणका प्रावधान संविधानमें लाया गया। इसमें धर्मके आधारपर आरक्षणकी कोई व्यवस्था न थी और न हो सकती है। ऐसी अवस्थामें निश्चित रूपसे अन्य पिछड़े वर्गका हक मारकर ही कांग्रेस या इण्डी गठबंधनके अन्य दल उन्हें आरक्षण दे सकते हैं। जब २०१२ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावके दौरान सलमान खुर्शीदने मुसलमानोंके लिए आरक्षणकी घोषणा की और उसके विरुद्ध न्यायालयमें मामला गया तो कांग्रेसकी ओरसे पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवीने बाहर आकर बयान दिया कि खुर्शीद साहबने जो कहा है वह कांग्रेसकी मंशा है। पश्चिम बंगालसे इसके संदर्भमें एक डरानेवाला आंकड़ा आया है। इस समय वहां १७९ जातियां अन्य पिछड़े वर्गमें शामिल हैं जिनमें ११८ मुस्लिम है और हिंदू सिर्फ ६१। मोदी सरकारने जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगको संवैधानिक दर्जा दिया तो उसने राज्योंको भी पिछड़े वर्गकी सूचीमें जातियोंको शामिल करनेका अधिकार दिया। ममता बनर्जीने ७१ जातियां शामिल की, जिनमें ६५ मुस्लिम थे। जब पिछड़ा वर्ग आयोगने इसका कारण पूछा तो बताया गया कि पिछड़े हिंदुओंने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण कर लिया। जब यह पूछा गया कि कहां-कहां ऐसा हुआ इसकी जानकारी दीजिए तो उत्तर आया कि इसकी जानकारी नहीं है। सरकारोंने ऐसे नियम और ढांचे बना दिया जिनसे राजस्थान, बंगाल, कर्नाटक सहित कई राज्योंमें पिछड़े वर्गके आरक्षणका ज्यादातर लाभ मुस्लिम समुदायको मिल रहा है। इसके बाद क्या किसी संदेहकी गुंजाइश रह जाती है।

पित्रोदाके माध्यमसे पश्चिमकी साजिश

ओवरसीज कांग्रेसके अध्यक्ष, राहुल गांधीके राजनीतिक गुरू सैम पित्रोदाने भारतके लोगोंके प्रति कांग्रेसकी सोचको अति महत्वपूर्ण साक्षात्कारमें प्रकट किया। उन्होंने देशके समाजशास्त्रको विस्फोटक ढंगसे परिभाषित किया है।

❒ **कुलदीप चंद अग्निहोत्री**

कांग्रेसके वरिष्ठ नेता और सोनिया परिवारके अंतरंग मित्रोंमें शुमार सैम पित्रोदा अमेरिकामें रहते हैं। अमेरिकामें अधिकांश गोरे इंग्लैंडसे ही गये हैं। इसलिए सैमको लगता होगा कि यदि भारतमें अरब, अफ्रीकी, चीनी जैसे लोगोंपर ही अध्ययन खत्म कर दिया तो अमेरिका क्या कहेगा। सैमको अमेरिकाका कर्ज भी चुकाना था। इसलिए उन्होंने उत्तरी भारतको गोरोंके खातेमें जोड़ दिया। लेकिन जहांतक दक्षिण भारतीयोंका सवाल है, उनको सैम पित्रोदाने अफ्रीकियोंके साथ उनके रंगके आधारपर ही जोड़ा होगा, क्योंकि दोनोंका रंग काला है। दूसरी कोई समानता तो उनकी आपसमें मिलती नहीं। लेकिन क्या केवल रंगको आधार बनाकर कांग्रेसके बुद्धिजीवी उनको अफ्रीकी कहना शुरू कर देंग। बाबा साहिब अंबेडकरने कहा था कि हिन्दुस्तानमें और अनेक कारणोंसे समाजमें भेद-व्यवहार हो सकता है, लेकिन रंग कभी भी भेदभावका आधार नहीं रहा। पश्चिममें इसके विपरीत है। वहां भेदका आधार ही रंग भेद है। वहांका समाज रंगभेदपर आधारित है। कांग्रेस और उसके गुरू सैम पित्रोदा भी भारतको पश्चिमकी समाजशास्त्रीय दृष्टिसे समझनेकी कोशिश करते हैं, इसलिए उनके अध्ययनमें दक्षिण भारत अफ्रीका बन जाता है। जाहिर है सोनिया गांधीको सैम पित्रोदाके इस अध्ययनमें कुछ अनुचित नहीं लगता होगा, क्योंकि वे भी भारतको पश्चिमके चश्मेसे ही देखती हैं। पश्चिमके देश और सांस्कृतिक लिहाजसे उनके प्रतिनिधि देश उत्तरी अमेरिका भारतपर दोहरा आक्रमण करते हैं। वे भारतको सांस्कृतिक लिहाजसे तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि भारत उनके कलैश ऑफ सिविलाईजेशनके थीसिसमें किसी प्रकार भी फिट नहीं बैठता। भारत दुनियामें सबसे पुरानी जीवन्त सभ्यता और संस्कृतिवाला देश है। यूरोप दो हजार साल पुरानी संस्कृतिका वाहक है। ब्रिटिश, पुर्तगाल और फ्रांसीसी शासन कालमें भारतमें भी प्रयोग किया गया कि भारतीय अपनी मूल संस्कृति, स्वभाव और प्रकृतिको छोड़कर पश्चिमी मान्यताओंमें स्वयंको ढाल लें। इन यूरोपीय शासकोंने जब भारत छोड़ा तब उन्हें इस बातकी तसल्ली थी कि जिन भारतीय शासकोंके हाथमें वे शासन छोड़कर जा रहे हैं वे भी इसी नीतिको जारी रखेंगे। अबतक सभी कुछ उनकी योजनाके अनुसार ही चल रहा था। भारतमें कांग्रेसी शासनने अंग्रेजोंकी उसी नीतिको जारी रखा।

यही कारण था भारतीयोंके लिए पश्चिम एक मानक बना रहा। लेकिन पिछले एक दशकसे भारतीयोंने सत्ता भाजपाको सौंप दी। भाजपाने एक बार फिरसे भारतीय स्वभाव और प्रकृतिके साथ जुड़ना शुरू किया, तब पश्चिमी देशों और वहांके थिंक टैंकोंको लगा कि यदि भाजपा ज्यादा देर सत्तामें रही तो उनकी चार सौ सालकी मेहनत बेकार हो जायगी। इतना ही नहीं, यदि भारतमें सोनिया परिवार पराजित हो गया तो यूरोपकी इस सांस्कृतिक नीतिको क्रियान्वित कौन करेगा। लेकिन सोनिया परिवार कैसे जीते, इसके लिए वही यूरोपीय टोटके अपनाये जा रहे हैं जो निश्चय ही भारतीय जमीनपर बेकार सिद्ध होंगे। सैम पित्रोदाका यह टोटका उसी प्रकारका है। इसमें ताकत हो न हो, लेकिन यह भारतको बदनाम करता है, उसे अपमानित भी करता है। सैमने अपने इस टोटकेमें कुछ और बातें भी कही हैं। उसका कहना है कि भाजपा राम मंदिर और रामनवमीके माध्यमसे देशको चुनौती दे रही है। सैमके इस कथनका अभिप्राय तो यही हुआ कि राम और राम नवमी भारतके लिए विदेशी हैं जिनके माध्यमसे भारतको चुनौती दी जा रही है। सैम पित्रोदासे पूछा जा सकता है कि यदि राम भारतके लिए विदेशी हैं और वे भारतको चुनौती दे रहे हैं तो भारतमें देसी कौन है। बाबर, औरंगजेब या लार्ड माऊंटबेटन। दरअसल सोनिया कांग्रेसकी जड़ें भारतकी मिट्टीमें न होकर उस विदेशी मिट्टीमें हैं जिसे भारतमें राम भी भारतको चुनौती देते लगते हैं। सोनिया कांग्रेसके ही एक नेताने कहा था कि गोवामें तो भारतका संविधान थोपा गया था। यानी भारतके इस हिस्सेमें तो पुर्तगालका संविधान ही उचित था। इससे स्पष्ट हो रहा है कि सोनिया कांग्रेसकी परतें धीरे-धीरे उतर रही हैं। लेकिन सैम पित्रोदा द्वारा भारतपर किये गये इस आक्रमणको आईसोलेशनमें नहीं देखा जा सकता। यह लम्बी श्रृंखलाकी केवल एक कड़ी है। इस श्रृंखलाका मूल सिरा अमेरिकाके हाथमें है। सैम पित्रोदा भारतके सामाजिक ताने-बानेपर चोट कर रहे हैं तो अमेरिका कनाडाके साथ मिलकर भारतकी प्रकृतिको विश्वमें खंडित करनेका प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं, उत्तरी अमेरिकाके ये देश भारतको खंडित करनेकी प्रक्रियामें उलझे हुए हैं। अमेरिका और कनाडाने गैंगवारमें मारे गये निज्जरकी हत्या और पन्नूको मारनेके प्रयासकी एक घटना परिचालित कर, इन दोनों घटनाओंको भारतके मत्थे मढ़नेका प्रयास किया है। समयके चुनावपर ध्यान देना जरूरी है। जिस दिन कनाडा निज्जरकी हत्याको लेकर भारतकी तथाकथित संलिप्तताको लेकर कोई बयान देता है, उसके दूसरे या तीसरे दिन अमेरिका भी गुरपतवन्त सिंह पन्नूकी तथाकथित हत्याके प्रयासमें भारतकी संलिप्तताको लेकर जरूर कोई न कोई बयान देता है।

मकसद इतना ही है कि दोनोंके बयानका सामूहिक प्रभाव विश्व जनमानसपर पड़े। अमेरिका भारतका एक रोग स्टेटकी तरहका इमेज स्थापित करना चाहता है और सैम पित्रोदा उसकी सामाजिक संरचनाको तार-तार करनेके प्रयासमें लगा हुआ है। कांग्रेसका ही एक दूसरा वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी, जो पंजाबमें मुख्य मंत्री भी रह चुका है, कुलगाममें पाकिस्तानी आतंकवादी हमलेमें हुए शहीद सैनिकका उपहास उड़ाता है। यूरोपकी ईसाई मिशनरियां पिछले लम्बे अरसेसे मांग कर रही थीं कि भारत सरकार अपनी जनगणना नीतिमें परिवर्तन करे। वह जनगणना जातिके आधारपर करे। इसका इन मिशनरियोंको एक लाभ है। भारतकी सामूहिक पहचानको धुंधला किया जा सकता है। अब सोनिया परिवारके प्रमुख सदस्य राहुल गांधीने सार्वजनिक रूपसे घोषणा की है कि यदि कांग्रेस सत्तामें आयी तो वह जनगणनाके समय सरना कोड स्थापित करेगी। कांग्रेसकी रणनीतिको समझनेके लिए केवल सैम पित्रोदाको समझना ही काफी नहीं है, कनाडा और अमेरिकाके व्यवहारको समझना होगा। सभी मिलकर भारतकी घेराबन्दी कर रहे हैं और उनकी साजिशोंको सफल बनानेके लिए भारतमें भी बहुत मिल ही जाते हैं। बाबा साहिब अंबेडकरने संविधान सभाके अपने अंतिम भाषणमें इसी खतरेकी ओर संकेत किया था। सैम पित्रोदा सीमाओंको लांघकर बयान दे रहे हैं और भारतकी छविको धूमिल करनेका प्रयास कर रहे हैं।

आत्मबोध

आध्यात्मिक जीवन

❒ **सिद्धगुरु प्रमोदजी**

पृथ्वी गोल है, यानी इसका कोई आरम्भ और कोई अंत नहीं है। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि पृथ्वीका गोला बनानेके लिए हम जहांसे शुरू करते हैं, उसका अंत भी वहीं होगा। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते-लिखते हैं, पढ़ाई पूरी होनेपर कामपर जाना शुरू करते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं और हमारी उम्र बढ़नेके साथ हमारे बच्चोंके साथ भी यही क्रम चलता है। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करते हुए हम एक तरहसे गोल.गोल घूमते हैं, यह है अपनी ही धुरीपर घूमना। जैसे पृथ्वी अपनी धुरीपर घूमती है, वैसे ही हम भी जब अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करते हैं तो हम अपनी धुरीपर घूम रहे होते हैं। लेकिन जब हमारे बच्चे सैटल हो जाते हैं और उनकी शादी भी हो जाती है तो हमारा वह चक्कर भी पूरा हो जाता है जिसकी तुलना हम पृथ्वीके सूर्यके चारों तरफ चक्कर लगानेसे कर सकते हैं। वह जीवनका एक चक्र है, जो पूरा हो गया। अपनी धुरीपर घूमते रहना तो तब भी जारी रहता ही है, क्योंकि हम परिवारकी जिम्मेदारियोंसे मुक्त नहीं हो पाते। बच्चोंके बाद नाती-पोते हमारे नये खिलौने बन जाते हैं और हम उन्हें सहेजने-संवारनेमें जुट जाते हैं। लेकिन सूर्यके चारों तरफके पृथ्वीके चक्करकी तुलनावाले अपने चक्करके बाद हम मानो ठहर जाते हैं और सूर्यके चारों ओरका हमारा अगला चक्कर लगता ही नहीं। यहां फिर सवाल यह है कि हमारे अपने जीवनमें हमारे लिए सूर्यके चक्करका क्या मतलब है और इसका महत्व क्या है। जब एक बार हमारे अपने बच्चे सैटल हो गये और शादी करके अपने-अपने परिवारमें रम गये तो हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियोंका एक चरण पूरा हो गया। इस दौरान हमारी उम्र बढ़ी, हमारा अनुभव बढ़ा, हमने कई नये पाठ सीखे, अब दौर है कि हम अपना ज्ञान दुनियामें बांटें। जब हम परिवारके लिए कुछ करते हैं तो हम अपनी धुरीपर घूम रहे हैं और जब हम समाजके लिए कुछ करते हैं तो हम मानो सूर्यके चारों ओर चक्कर लगानेवाला काम कर रहे हैं। पृथ्वी गोल है, यानी हमें इसी गोलेमें घूमते रहना है, परिवारका भी ध्यान रखना है और समाजको भी कुछ देना है। पृथ्वी एक तरफ २३.५ डिग्री झुकी हुई है, यानी हमें भी झुककर, विनम्र होकर सेवा करते हुए चलना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सच्चे इनसान बन जाते हैं। यही आध्यात्मिकता है। अपने आसपासके लोगोंके प्रति सहृदय होना होगा, उनकी भावनाओंको समझना और उनका आदर करना होगा। अध्यात्मकी यह पहली सीढ़ी है।

भारतीय लोकतंत्रकी शक्ति है मतदान

❒ **आर.के.सिन्हा**

भारतके कई राज्योंमें तापमान ४२ डिग्री सेल्सियससे भी ऊपर हो गया है। इसके साथ ही लू भी चल रही है। इतने कठोर मौसममें चुनाव प्रचार करना और फिर मतदान करनेके लिए मतदान केन्द्रोंके बाहर लम्बी लाइन लगाकर खड़ा होना सामान्य बात तो नहीं मानी जा सकती है। इसलिए प्रचार भी सुबह या शामको ही संभव हो पाता है। दोपहरके समय तो मात्र रणनीति ही बनायी जा सकती है। परन्तु इतने खराब मौसममें भी देशके लाखों-करोड़ों मतदाता घरोंसे निकलकर वोट तो दे ही रहे हैं। यह हमारे मजबूत लोकतंत्रके लिए शुभ संकेत भी है। आखिर देशके जनमानसको पता है कि उनके वोटसे ही देशकी तकदीर लिखी जायगी। बेहतर होगा कि मतदाता सुबह जल्दी ही अपने मताधिकारका प्रयोग करके घर वापस आ जायें। उन्हें मतदान केन्द्रोंमें जाते वक्त अपने साथ पानीकी बोतलें करोड़ रख लेनी चाहिएं। मुह-सिर ढकनेके लिए एक गमछा भी सही रहेगा। इस साल भारत रिकॉर्डतोड़ गर्मीसे रूबरू है। पिछले महीने, देशमें भीषण गर्मीके कारण कमसे कम नौ लोगोंकी मौत हो गयी थी। चुनाव प्रचारके दौरान केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी पश्चिमी राज्य महाराष्ट्रमें एक चुनावी रैलीको संबोधित करते हुए बेहोश हो गये थे, बादमें उन्होंने बताया कि भीड़भरे स्थान और उच्च तापमानके कारण उन्हें असहज महसूस हुआ था। इससे कुछ दिन पहले, पूर्वी शहर कोलकातामें, जहां तापमान ४३ सेल्सियससे ऊपर चला गया था, एक खबरिया चैनलकी एंकर मौसम अपडेट प्रस्तुत करते समय बेहोश हो गयी थी। बादमें उसने बताया कि स्टूडियोका कूलिंग सिस्टम खराब हो जानेके कारण बहुत गर्मी हो जानेके कारण ऐसा हुआ! चुनाव अधिकारी मतदान केन्द्रोंपर पेयजलकी आपूर्ति करके और मतदानका समय बढ़ाकर इससे निबटनेके लिए कदम तो उठा रहे हैं।

२०१९ के चुनावकी तुलनामें, १९ अप्रैल और २६ अप्रैलको हुए मतदानके पहले दो चरणोंमें मतदाता मतदानमें कमसे कम तीन प्रतिशतकी गिरावट देखी गयी। चुनाव आयोगको अगले चुनावोंके पूर्व एक बार यह विचार करना होगा कि आम चुनावोंकी तिथियोंको अप्रैल-मईकी जगह फरवरी-मार्चमें किया जा सकता है क्या। इससे पूरे देशमें सुविधा होगी। कुछ पर्वतीय राज्योंमें बर्फ जमा रहनेके कारण दिक्कत तो हो सकती है, परन्तु उन क्षेत्रोंमें एक महीने बाद चुनाव और उसके बाद चुनाव परिणामोंकी घोषणा तो की ही जा सकती है। यह तो सोचना ही होगा कि क्या देशमें फरवरी और मार्चके ठंडे महीनोंके बीच लोकसभा चुनाव करानेके बारेमें विचार नहीं किया जा सकता है। इसके चलते अधिक लोगोंको वोट देनेके लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। गर्मीमें लम्बे समयतक रहनेसे थकान, चक्कर आना और बेहोशी हो सकती है। इसलिए, उम्मीदवारों, पार्टी कार्यकर्ताओं मतदाताओंको बहुत संभल कर चलना होगा। उन लोगोंको भी अपनी सेहतका ध्यान देना होगा जो विभिन्न राजनीतिक दलोंकी सभाओंमें नेताओंको सुननेके लिए जाते हैं। डाक्टरोंका कहना है कि हृदय रोग या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियोंवाले मरीजोंको भी गर्मीमें अतिरिक्त रूपसे सतर्क रहनेकी जरूरत है। मतदाताओंका कहना है कि वे गर्मीको लेकर आशंकित हैं लेकिन सावधानी बरतेंगे। दिल्ली और हरियाणाकी क्रमश: सात और दस सीटोंके लिए मतदान आगामी २५ मईको होना है। आशंका है कि २५ मईको दिल्ली-हरियाणामें पारा ४२ सेल्सियसके आसपास होगा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम समेत एनसीआरके इलाकोंमें बीते कुछ दिनोंसे आसमानसे आग बरस रही है। दिनमें तापमान ४० पार कर जा रहा है और ऐसेमें लोगोंका गर्मीसे जीना मुहाल हो गया है। आनेवाले दिनोंमें दिल्ली-एनसीआरमें गर्मीका कहर अभी और देखनेको मिलेगा। तो बहुत साफ कि जब दिल्ली और हरियाणाके मतदाता अपने मतदान केन्द्रमें जायंगे तो उन्हें बेहद गर्म मौसममें घरसे निकलना होगा। इसलिए यदि वे सुबह ११ बजेतक मतदान कर लें तो बेहतर होगा। उसके बाद गर्मीका असर भयावह होने लगेगा। बताया जा रहा है कि आनेवालेमें दिल्लीके कुछ इलाकोंमें ४३ डिग्रीतक तापमान पहुंचनेकी उम्मीद है। इतनी भीषण गर्मीमें वोट देनेके लिए घरसे निकलनेसे पहले बुजुर्गोंको अपना ख्याल रखना ही होगा। इस बीच, पुणे महाराष्ट्रके सबसे गर्म क्षेत्रोंमेंसे एक है, जहां १३ और २० मईको दो और चरणोंमें मतदान होना है। पिछले एक हफ्तेसे पुणेमें ३१ सेल्सियस और ४२ सेल्सियसके बीच तापमान चल रहा है और मौसम विभागका कहना है कि आनेवाले दिनोंमें इसके जारी रहनेकी सम्भावना है। गर्मीके प्रकोपका असर हर तरफ है। इस मौसममें यदि सावधानी न बरती जाय तो हीटस्ट्रोक हो सकता है या डिहाइड्रेशन हो सकता है। हरियाणाके पड़ोसी राज्य पंजाबकी १३ लोकसभा सीटोंके लिए मतदान १ जूनको होना है। पंजाब आजकल ही गर्मीसे झुलस रहा। माना जा रहा है कि राज्यमें मतदानवाले दिन तापमान ४३ डिग्री सेल्सियसके करीब पहुंचेगा। आजकल लुधियाना एवं फाजिल्का सबसे गर्म चल रहे हैं। यहांका अधिकतम तापमान सबसे अधिक ४२.८ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्यसे तीन डिग्री सेल्सियस अधिक था। कहना न होगा कि इतनी तेज गर्मीमें मतदान करनेके लिए घरसे निकलना कठिन तो है।

दक्षिणी राज्य तेलंगानामें १३ मईको चौथे चरणमें मतदान करनेवाला है। वहां भी चिलचिलाती गर्मीको जनता झेल रही है। इस तापमानमें वोट डालनेके लिए बाहर आना मुश्किल है। बुजुर्गोंको मतदान केन्द्रोंतक ले जाना चुनौतीपूर्ण होनेवाला है। इस साल पहली बार, देशमें चुनावोंकी देखरेख करनेवाले चुनाव आयोगने ८५ वर्षसे अधिक उम्रके लोगों और विकलांग लोगोंको अपने घरोंसे वोट डालनेकी अनुमति दी है। आयोगने मार्चमें चुनावोंपर गर्मीके प्रभावको कम करनेके लिए दिशा-निर्देश भी जारी किये। इसके साथ ही मतदान केन्द्रोंपर पेयजल और ओरल हाइड्रेशन सॉल्ट उपलब्ध कराने, मेडिकल किट तैयार रखने और देरीको रोकनेके लिए पर्याप्त मतदान कर्मचारी रखनेके निर्देश दिये गये हैं। फिलहाल आम भारतीयका यही कहना है कि गर्मी हमें वोट देनेसे नहीं रोक सकती। यही जज्बा भारत और भारत लोकतंत्रकी ताकत है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

पाक के भेदभावपूर्ण रुख से चढ़ा पीओके का पारा

हर क्रिया की उसकी विपरीत दिशा में समान प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के गति के इस तीसरे सिद्धांत की जीती-जागती तस्वीरें इन दिनों पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नजर आ रही हैं। बिजली और आटे की बढ़ती कीमतों को लेकर पीओके के लोग पाकिस्तान के साथ अपनी संघीय सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं।

पाकिस्तान के सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों के मुजफ्फराबाद मार्च को दबाने की जितनी कोशिश कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन उतना ही उग्र हो रहा है। पीओके की अवामी एक्शन कमेटी के मार्च और धरने के आह्वान के बाद बेकाबू होते हालात 1955 के अवज्ञा आंदोलन की यादें ताजा कर रहे हैं, जब पीओके के लोगों और पाकिस्तानी फौज में सीधा टकराव हुआ था। अब फिर पीओके के लोगों के उबलते गुस्से ने पाकिस्तानी हुकूमत के माथे पर बल बढ़ा दिए हैं। दरअसल, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के कब्जे के बाद से ही पीओके लगातार उपेक्षा झेल रहा है। उसकी समस्याओं और विकास पर ध्यान देने की बजाय पाकिस्तान का जोर वहां आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप खोलने पर ज्यादा रहा। पीओके के प्राकृतिक संसाधनों का पाकिस्तान खुलकर दोहन करता रहा, जबकि वहां के लोग ईंधन, बिजली और जरूरी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझते रहे। पीओके के लोगों ने मई 2023 में बिजली की ऊंची दरों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, जो एक साल बाद अब उग्र रूप ले चुका है। आंदोलन से काफी पहले पीओके के लोगों का भारत के प्रति झुकाव समय-समय पर मुखर होता रहा है।

पिछले साल पीओके और गिलगित के लोगों ने पाकिस्तान की भेदभाव वाली नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने इलाकों को भारत के लद्दाख के साथ मिलाने की मांग उठाई थी। तब प्रदर्शन के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वहां के लोग 'आर-पार जोड़ दो, करगिल को खोल दो' जैसे नारे लगाते नजर आए थे। पीओके के लोग चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) का भी विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि गलियारे की आड़ में उनकी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जाएगा और भारत के जवाबी हमले उन्हें झेलने पड़ेंगे। पीओके में विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरह भारतीय तिरंगा लहराया जा रहा है और भारत में विलय के स्वर उठ रहे हैं, उससे भविष्य में इस विवादित क्षेत्र पर निर्णायक पटकथा लिखे जाने के आसार नजर आ रहे हैं। भारत को पीओके के घटनाक्रम पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, ताकि इससे हमारे सुरक्षा हितों पर प्रतिकूल असर न पड़े।

बिहार : 17 साल बाद जेल से छूटे अशोक महतो ने पत्नी को चुनाव मैदान में उतारकर मुकाबले को बनाया रोचक

मुंगेर में सजा बाहुबलियों का अखाड़ा, लड़ाई को अगड़ा बनाम पिछड़ा रंग देने की कोशिश

मुंगेर से
नवनीत मिश्र

चिराग पासवान के साथ जनसंपर्क करते जदयू प्रत्याशी ललन सिंह।

पत्नी अनिता के साथ चुनाव प्रचार करते अशोक महतो।

बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम ने जब मुंगेर में राजधानी शिफ्ट की थी तो गंगा तीरे भव्य किले का भी निर्माण कराया था। समय के साथ नवाब की सल्तनत तो चली गई, लेकिन उनका किला 2024 के लोकसभा चुनाव में बाहुबलियों के सियासी वर्चस्व की रोचक लड़ाई का गवाह बन रहा है। मुंगेर के सियासी किले को जीतने के लिए यहां बाहुबलियों का अखाड़ा सजा हुआ है। साहेब, बीवी और गैंगस्टर जैसी कहानी फिजाओं में तैर रही है। बेगूसराय से एनएच 31 पर सवा घंटे की दूरी तय कर मैं मुंगेर पहुंचा तो दूसरी सीटों की तुलना में यहां चुनावी रंग कुछ ज्यादा ही चटख दिखा। यहां विपक्ष ने अगड़ा बनाम पिछड़ा रंग देने की कोशिश की है तो एनडीए डैमेज कंट्रोल के लिए दलित से लेकर अति पिछड़ा जातियों की नेताओं की यहां सभाएं कराने में जुटा है। यहां 17 साल बाद जेल से छूटे कई नरसंहार और नवादा जेल ब्रेक कांड के आरोपी रहे गैंगस्टर अशोक महतो की पत्नी अनीता चुनाव मैदान में हैं। उनके सामने नीतीश कुमार के चाणक्य कहे जाने वाले जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह हैं। यह वही अशोक महतो हैं, जिन पर नेटफ्लिक्स पर पर 'खाकी-द बिहार चैप्टर' सीरीज बन चुकी है। अशोक महतो और जदयू प्रत्याशी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का समर्थन कर रहे अनंत सिंह जैसे बाहुबलियों को कोई खौफ का पर्याय बताता है तो कोई अमीरों से लेकर गरीबों को देने वाला रॉबिनहुड।

एनडीए कर रहा डैमेज कंट्रोल

मुंगेर में विपक्ष ने लड़ाई को अगड़ा बनाम पिछड़ा रंग देने की कोशिश की है। राजद से चुनाव लड़ रहीं अशोक महतो की पत्नी अनीता जहां पिछड़ा वर्ग की कुर्मी हैं तो जदयू के प्रत्याशी ललन सिंह भूमिहार हैं और उनका समर्थन कर रहे बाहुबली अनंत सिंह भी भूमिहार हैं। दूसरी तरफ राजद समर्थक पिछड़ी जातियों के बीच घूम-घूमकर कह रहे हैं कि अशोक महतो ने भूमिहारों और अगड़ी जातियों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसके कारण जेल जाना पड़ा। अगड़ा बनाम पिछड़ा रंग देने की कोशिश से चिंतित एनडीए यहां एलजेपी मुखिया चिराग पासवान से लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी डैमेज कंट्रोल के लिए एक्टिव हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी मुंगेर में रैली कर चुके हैं।

दुश्मन बन गए दोस्त

इस चुनाव ने ललन सिंह और बाहुबली अनंत सिंह को सियासी दुश्मन से दोस्त बना दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह की कांग्रेस उम्मीदवार पत्नी को ललन सिंह ने 1.67 लाख वोटों के अंतर से हराया था। लेकिन, आज अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी घूम-घूमकर ललन सिंह के लिए ही वोट मांग रहे हैं। यहां हर व्यक्ति की जुबान पर चर्चा है कि बाहुबली अशोक महतो के मुकाबले के लिए दूसरे बाहुबली अनंत सिंह की पैरोल पर रिहाई कराई गई है। 2020 में अनंत सिंह मोकामा से चौथी बार विधायक बने थे, लेकिन घर से एके-47 और कारतूस मिलने के मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा और 10 साल की सजा होने पर विधायकी चली गई। जिसके बाद अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी के टिकट पर 2022 के उपचुनाव में विधायक बनीं। हालांकि, नीतीश कुमार के एनडीए में फिर से आने पर अनंत सिंह की पत्नी भी राजद छोड़ नीतीश के साथ आ गई थीं।

जनता की राय

मुंगेर से दो किमी दूर चंडी स्थान मंदिर पर मौजूद मिले सुकेश कुमार कहते हैं कि स्थानीय सांसद ललन सिंह के प्रति जनता में काफी नाराजगी हैं। कोविड में वे कहीं जनता की मदद करते नही दिखे, लेकिन मोदी के नाम पर बेड़ा पार हो जाएगा। रेखा देवी कहती हैं कि अशोक महतो के अपराध के बारे में बहुत कुछ लोग चुनाव में बोल रहे हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति की पत्नी को वोट नहीं करेंगी।

भरत कुमार कहते हैं कि मुंगेर में पत्थर उद्योग बंद होने के कारण गरीब मजदूर पलायन कर रहे हैं। पेशे से अधिवक्ता सुधांशु कुमार कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास तो हुआ है, लेकिन निर्माण पूरा नहीं हुआ। मोकामा के रेफरल अस्पताल को ट्रामा सेंटर बनाने की मांग अब तक नहीं पूरी हुई। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि देश का चुनाव है तो मोदी को देखकर लोग वोट करेंगे। जमालपुर के पाटम क्षेत्र के कुछ किसानों ने कहा कि उचित संरक्षण न मिलने से पान की खेती घाटे का सौदा साबित हो हो रही है।

पटना रोड शो पीएम मोदी की राह करेगा आसान!

प्रियरंजन भारती

बिहार की राजधानी पटना में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ। पीएम मोदी 14 मई को अपने संसदीय क्षेत्र काशी यानी वाराणसी जाकर एनडीए उम्मीदवार के रूप में विधिवत नामांकन करेंगे। माना जाता है कि चुनावी रोड शो चुनाव के नतीजों पर सीधे असर दिखाता है।

प्रधानमंत्री का पटना में रोड शो ऐतिहासिक रहा। वैशाली में रैली चुनाव भी सकारात्मक दिशा देने वाली हो सकती है। इसके आसपास के क्षेत्रों पर भी सकारात्मक असर पड़ने के आसार हैं। अभी 26 सीटों पर चुनाव बाकी हैं। मोदी के रोड शो से 13 मई के मतदान वाले बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, उजियारपुर और मुंगेर के चुनावी माहौल पर भी पड़ेगा। बेगूसराय में गिरिराज सिंह, मुंगेर में ललन सिंह, उजियारपुर में नित्यानंद राय तथा समस्तीपुर में लोजपा की सांसें अटकी हुई हैं। प्रधानमंत्री 13 मई को चिराग पासवान की सीट हाजीपुर समेत मुजफ्फरपुर और सारण की चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगे। सारण में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजीव प्रताप रूडी तथा मुजफ्फरपुर में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस से उम्मीदवार बने निवर्तमान सांसद अजय निषाद ने चुनावी संघर्ष को एनडीए के लिए बेहद आसान नहीं रहने दिया है।

प्रधानमंत्री की ये रैलियां और पटना रोड शो इस बात का भी परीक्षण हैं कि मोदी मैजिक वाकई वोट ट्रांसफर की ताकत अब भी उतना ही रखता है या नहीं?

तेलंगाना में तीनों दलों की साख दांव पर

बीआरएस के खिसकते जनाधार पर भाजपा और कांग्रेस की नजर

जी.किशन रेड्डी

के. चन्द्रशेखर राव

रेवंत रेड्डी

हैदराबाद से
राजीव मिश्रा

तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से एक हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी और भाजपा के बीच मुकाबला है। इस लोकसभा क्षेत्र की डेमोग्राफी ओवैसी को फिर एक बार मजबूत उम्मीदवार बनाती है। शेष 16 सीटों पर कांग्रेस, भाजपा और बीआरएस के लिए संभावनाएं हैं। बीआरएस का दावा है कि वह इनमें से 8 से 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। लेकिन, पार्टी के ही नेता दबी जुबान से स्वीकार करते हैं कि संभावनाएं सिर्फ एक या दो सीटों पर हैं। हालांकि, बीआरएस कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही हैं लेकिन, सिकंदराबाद, चेवल्ला और महबूबाबाद को छोड़कर अधिकांश सीटों पर उसे वोट काटने के तौर पर देखा जा रहा है।

बीआरएस के खिसकते जनाधार का फायदा कांग्रेस और भाजपा दोनों उठाना चाहते हैं। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा प्रवक्ता रुद्रमा रानी कहती हैं कि पिछले चुनाव में राज्य की जनता बीआरएस के खिलाफ मतदान करना चाहती थी लेकिन, कांग्रेस को चुना। अब कांग्रेस ने भी जो वादे किए उसे पूरे नहीं किए हैं। जनता कांग्रेस से भी नाराज है। भाजपा ने गांव-गांव तक अपना नेटवर्क विकसित किया है। लोग पीएम मोदी और भाजपा पर विश्वास जता रहे हैं। इसका फायदा लोकसभा चुनाव के बाद अगले विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा।

बीआरएस के लिए बड़ी चुनौती उससे दूर होते अल्पसंख्यक मतदाता भी हैं। राज्य में करीब 13 फीसदी मुस्लिम मतदाता हैं और जहां कांटे की टक्कर होती है वहां कांग्रेस को इसका लाभ मिलता है। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भाटी विक्रमार्क ने पत्रिका के साथ चर्चा में कहा कि उनका मुकाबला बीआरएस और भाजपा, दोनों से है। इस चुनाव में जनता कांग्रेस सरकार की पिछले 5-6 माह की उपलब्धियों पर मुहर लगाएगी।

इस लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए खोने और पाने को बहुत कुछ है। अगर पार्टी मौजूदा 4 में से एक भी सीट हारती है तो उसे झटके के तौर पर माना जाएगा। चुनाव में बेहतर प्रदर्शन से भाजपा मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी।

'नेताजी के तारे-सितारे'

झांकी जमेगी, प्रतिद्वंद्वी की सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाएगी

लोकसभा चुनाव के रण में कई नेता ताल ठोक रहे हैं। इनमें ऐसे भी नेता भी हैं, जिन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। वे बागी होकर मैदान में हैं। चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। नेता शुभ-अशुभ का ध्यान रख कदम उठा रहे हैं तो जानिए आज नेताजी के तारे-सितारे क्या कह रहे हैं।

-अज़हर हाशमी

मेष- आज गोचर में आपकी राशि में चंद्रमा चौथा यानी कर्क का है, जो बहुत अशुभ है। प्रतिद्वंद्वी आज आपको प्रचार में धूल चटा सकता है।

वृषभ- आज आपकी राशि में गोचर में चंद्रमा तीसरा है, जो अनुकूल है। प्रचार रूपी 'कुश्ती' में प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ देंगे। वाह! क्या बात है।

मिथुन- आज आपकी राशि में गोचर में चन्द्रमा दूसरा है जो शुभ है। आज प्रचार में आपकी झांकी जम जाएगी, जिससे प्रतिद्वंद्वी की सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाएगी।

कर्क- आपकी राशि में तो चन्द्रमा गोचर में अपने ही घर यानी कर्क राशि में है जो शुभ है। आज प्रतिद्वंद्वी 'सेर' तो आप 'सवासेर' रहेंगे। बधाई!

सिंह- आपकी राशि में गोचर में बारहवां चन्द्रमा अशुभ है। आज आप गड्ढे में गिर सकते हैं। फूंक-फूंक कर कदम रखें। बला टल जाएगी।

कन्या- आज तो आपकी राशि में गोचर में चंद्रमा ग्यारहवां है। यानी लाभ ही लाभ। आज प्रचार में आपके शानदार प्रभाव का 'चक्का' चलेगा।

तुला- आज गोचर में आपकी राशि में चन्द्रमा दसवां है, जो शुभ है। आज आप प्रचार में प्रतिद्वंद्वी को अपने ठोस तर्कों से आइना दिखा देंगे।

वृश्चिक- आज राशि में गोचर में नौवां चन्द्रमा आपके अनुकूल है। प्रचार में प्रतिद्वंद्वी नौ बार पांव छुएगा। लेकिन आप फूलकर कुप्पा मत हो जाना।

धनु- आज आपकी राशि में गोचर में आठवां चंद्रमा आपके लिए अशुभ है। अशुभता दूर करने के लिए आठ बार प्रतिद्वंद्वी के नाम का पाठ करें।

मकर- आज आपकी राशि में गोचर में सातवां चन्द्रमा अनुकूल है। आज प्रचार में आप ही आप छाए रहेंगे। मुबारक हो!

कुंभ- आज आपकी राशि में गोचर में छठां चंद्रमा आपके लिए अशुभ है। आज प्रचार में आपकी 'किरकिरी' हो सकती है। चमचों को काबू में रखें।

मीन- आज आपकी राशि में गोचर में पांचवां चंद्रमा अनुकूल है। आप प्रचार में अपने प्रतिद्वंद्वी को पस्त कर देंगे और स्वयं मस्त रहेंगे।

अगला राशिफल गुरुवार के अंक में

महाराष्ट्र : मुंबई में कोई दुविधा में तो कोई कर चुका फैसला

'आम' के लिए पेट का तो 'खास' के लिए अर्थव्यवस्था और देश का सवाल

मुंबई से
दौलतसिंह चौहान

देश की आर्थिक राजधानी मायानगरी मुंबई के मतदाताओं का बड़ा हिस्सा लोकसभा चुनाव के लिए 20 मई को होने वाले मतदान से पहले दुविधा में है। वह अब भी कोई स्पष्ट फैसला नहीं कर पा रहा है। जहां एक तरफ बड़े उद्योगपति, व्यापारी, कारोबारी, प्रोफेशनल्स और बहुत अच्छा वेतन पाने वाले नौकरीपेशा पुरुष एवं महिला मतदाता कुलांचे मार रही अर्थव्यवस्था पर किसी तरह का ब्रेक नहीं लग जाए और इससे उनका निजी आर्थिक नुकसान न हो जाए, इस चिंता में पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा के पीछे मजबूती से लामबंद और मुखर हैं, उनमें कोई दुविधा नहीं है। वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी, महंगाई और रोजमर्रा की महानगरीय समस्याओं की मार से त्रस्त मध्यम, निम्न मध्यम और निम्न वर्ग का आम आदमी बदलाव के मानस के बावजूद भाजपा के आक्रामक प्रचार और कमजोर विपक्ष के चलते भ्रमित सा है। इस वर्ग का कहना है कि राम से पेट नहीं भरता पेट भरने के लिए तो काम बहुत जरूरी है।

नफा और नुकसान

2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव भाजपा और शिवसेना ने एनडीए के पार्टनर के रूप में साथ मिल कर लड़े थे। पहले जहां पूरी शिवसेना भाजपा के साथ और पूरी एनसीपी कांग्रेस के साथ थी। अब शिवसेना और एनसीपी का एक-एक टुकड़ा भाजपा यानी महायुति के साथ और एक-एक टुकड़ा कांग्रेस के यानी महाविकास अघाड़ी के साथ है। गणित लगाएं तो हिसाब बराबर रहा, लेकिन धरातल पर गणित काम करती नहीं दिख रही। कुछ मतदाताओं का मानना है कि यह तोड़फोड़ भाजपा की ओर से की गई है। इस पर मतदाता कैसे रिएक्ट करेगा, बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तो सभाओं में यह कहना शुरू कर दिया है कि शिवसेना शिंदे को दिए जाने वाला हर वोट पीएम मोदी को जाएगा। शिवसेना और एनसीपी के सामने चुनौती केवल चुनाव जीतने की ही नहीं है, अपने आपको असली साबित करने की भी है। इधर मतदाताओं को यह भी स्पष्टता से पता नहीं चल पा रहा है कि कौनसा नेता अब किस धड़े में है। चुनाव आयोग ने शिवसेना के शिंदे गुट को असली मानते हुए 'धनुष-बाण' का चुनाव चिह्न दिया है, वहीं शरद पवार की एनसीपी तोड़ कर अलग हुए अजित पवार को 'घड़ी' का चुनाव चिह्न दे दिया। शिवसेना उद्धव ठाकरे को 'मशाल' और एनसीपी शरद पवार गुट को 'तुरही बजाता व्यक्ति' चुनाव चिह्न मिला है। पुराने चिह्न वाले दोनों गुटों को फायदे की बात कही जा रही है। सहानुभूति की आस लगाए उद्धव ठाकरे अपनी आन-बान के लिए पुरजोर लड़ाई लड़ रहे हैं, शरद पवार को लेकर मतदाताओं से यह भी सुना गया कि उनकी दोनों हाथों में लड्डू रखने की रणनीति है।

मतदाताओं की मुश्किल

महाराष्ट्र की जिन 13 लोकसभा सीटों पर 20 मई को वोट पड़ेंगे, उनमें महामुंबई की सभी छह सीटें -मुंबई उत्तर, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई दक्षिण मध्य और मुंबई दक्षिण तथा दो उपनगरीय सीटें ठाणे और कल्याण भी शामिल हैं। इन 8 में से 5 सीटों पर शिवसेना के शिंदे और उद्धव गुट में सीधी फाइट हो रही है। असली नकली शिवसेना का असल फैसला मुंबई महानगर में होने वाला है। मतदाताओं का असमंजस केवल मुद्दों के स्तर पर हो, ऐसा नहीं है। उनके सामने एक और बड़ा संकट इस बार शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) चेहरे और चिह्न बदल जाने का है। ये दोनों दल न केवल टूटे बल्कि टूटा हुआ एक-एक धड़ा पाला बदल विरोधी पक्ष की गोद में जा बैठा। कौन नेता किस शिवसेना में है या कौन नेता किस एनसीपी में है, इसको लेकर मतदाताा कन्फ्यूज हो जाता है।

अपनी-अपनी राय

टैक्सी चालक अखिलेश से सफर के दौरान चर्चा छेड़ी तो बोला , रास्ते सुधर गए तो हमारा काम आसान हो गया, लेकिन टोल और ट्रैफिक नियम उल्लंघन का फाइन बेतहाशा बढ़ा दिया गया। विपक्ष के नेता आपस में झगड़ते रहते हैं। सरकार आ गई तो पहली लड़ाई तो पीएम कौन बनेगा, इसी सवाल पर हो जाएगी। मलाड की एक बहुमंजिला इमारत में रहने वाले सीए नैनराजा ने कहा कि बड़ा मुद्दा देश है, अगर सरकार बदली तो अर्थव्यवस्था, बाजार और दुनिया में देश की छवि का क्या होगा? नैनराजा के पड़ोसी सोसायटी के अध्यक्ष जुगल पारीक ने कहा कि यह बात सही है कि कई दिक्कतें आम जनता को हो रही हैं, लेकिन फिलहाल देश के सामने और कोई विकल्प नहीं है। अपार्टमेंट के गार्डन में गपशप कर रही महिलाओं के समूह से सवाल किया तो वे मोदी-मोदी बोलने लगीं।

आखिर क्यों करते हैं मतदान से किनारा

डॉ. ईश मुंजाल
मेम्बर, सीडब्ल्यूसी , आइएमए
@patrika.com

मतदान के प्रति बरसों से जगाई जा रही अलख अब तक कोई खास रंग नहीं दिखा पाई है। 13 मई को लोकसभा चुनाव के मतदान का चौथा चरण है। शुरुआती तीन चरण में मतदाताओं का रुख उत्साहजनक नहीं रहा। मतलब साफ है कि मतदान में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, कई इलाकों में तो पहले से भी काफी कम मतदान हुआ है। इस लोकसभा चुनाव में 96.86 करोड़ मतदाता हैं। औसत मतदान के हिसाब से भी देखें तो करीब तीस से पैंतीस फीसदी वोटर्स तो हर चुनाव में ही नदारद रहते हैं। लोगों को वोट देने का अधिकार तो मिला, लेकिन एक बड़ा तबका अब भी इसका महत्त्व नहीं समझ पाया।

मतदान के प्रति लोगों की उदासीनता को दूर करने के साथ लोकतंत्र की सुरक्षा में चुनाव के महत्त्व के बारे में जागरूकता पैदा करने की कवायद भी बरसों से चली आ रही है। स्वयंसेवी संस्थाएं ही नहीं , सरकारें भी मतदाता को वोट देने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसके बाद भी कहीं कोई बेहतर उम्मीद नजर नहीं आती। गांवों में महिलाओं का बड़ा वर्ग आज भी पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच रहा। पढ़ी-लिखी पीढ़ी में से भी कई वोट देने को जरूरी नहीं समझ रहे। मेरे वोट नहीं देने से क्या हो जाएगा, यही मानसिकता करीब एक तिहाई वोटर को अपने वोट के अधिकार से दूर कर रही है। मतदाता को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए चुनाव आयोग और ऑल इण्डिया रेडियो की तरफ से अभियान चलाया गया। करीब 23 भाषा में इसके 52 एपिसोड प्रसारित किए गए पर उससे भी मतदाताओं पर खास असर नहीं हुआ।

कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगाने का अभियान चलाया गया था। सरकारी स्तर पर भी यह काम युद्धस्तर पर किया गया। लोगों को हर स्तर पर प्रेरि किया गया। इसके अच्छे परिणाम आए। मतदान के लिए भी ऐसी ही मुहिम चलाने की आवश्यकता है। चुनाव में एक तिहाई से अधिक जनता भाग नहीं ले रही। हम यह भी मानते हैं कि शत प्रतिशत मतदान संभव नहीं हो पाएगा पर सहभागिता इतनी तो बढ़े कि लोकतंत्र भी गर्व करे। आखिर लोग मतदान से किनारा कौन क्यों कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब तो तलाशना ही होगा।

आज का सवाल

क्षतिग्रस्त सड़कों को समय रहते ठीक क्यों नहीं किया जाता?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

सही व्यक्ति को मिले टिकट

राजनीति में सुधार के लिए राजनीतिक दलों को स्वच्छ छवि के व्यक्ति को ही टिकट देना चाहिए। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट देने से बचना चाहिए।

-अजीतसिंह सिसोदिया, खारा, बीकानेर

दलबदल पर अंकुश जरूरी

राजनीति अब सेवा का नहीं, मेवा बटोरने का साधन बन गई है। सुधार के लिए राजनीति का अपराधीकरण रोकना होगा। दलबदल पर अंकुश लगाना जरूरी है।

-संध्या रामकृष्ण, इंदौर, मप्र

जरूरी है जागरूकता

चुनावों में जनभागीदारी होनी आवश्यक है। जनता का जागरूक होना जरूरी है। गलत प्रत्याशी को टिकट देने पर उसका खुलकर विरोध किया जाना चाहिए।

-कैलाश कुमार, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़

जनता की जिम्मेदारी

राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहिए। जनता को भी ऐसे लोगों को नहीं चुनना चाहिए, चाहे वे किसी भी दल के हों।

-अरविंदर सिंह, कोटपुतली

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, ' राजनीति में सुधार कैसे हो सकता है?' पाठकों की प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।

इसे स्कैन करें

rb.gy/zegwoc

नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। सोमवार, 13 मई 2024

मोदी हैं शीर्ष नेता

अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 'BJP के PM का सवाल' उठाकर उस नैरेटिव को पलटने की कोशिश की, जो विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. को लगातार रक्षात्मक मुद्रा में बनाए हुए था।

मोदी के मुकाबले कौन | BJP पिछले एक दशक से हर चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ती आई है। उसकी यह रणनीति कामयाब भी रही है। इसके बरक्स वह विपक्ष से यह सवाल करती आई है कि मोदी के मुकाबले कौन? इस लोकसभा चुनाव में भी BJP ने अपनी चुनावी रणनीति के केंद्र में इसी सवाल को रखा कि विपक्षी गठबंधन की ओर से पीएम प्रत्याशी आखिर कौन है?

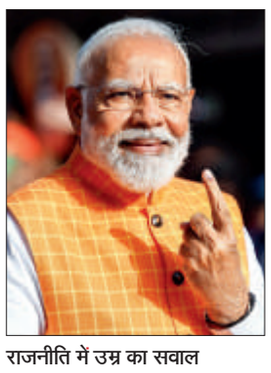

राजनीति में उम्र का सवाल

75 वर्ष का फेर | विपक्षी खेमे की अनिश्चितता के मुकाबले NDA की सुनिश्चितता नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे के रूप में स्पष्ट थी। लेकिन BJP ने यह कायदा बनाया था कि 75 वर्ष से अधिक उम्र का होने पर पार्टी के नेता सक्रिय राजनीति छोड़ देंगे। विपक्ष ने इसी आधार पर यह सवाल किया है कि अगले साल मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे तो क्या उनकी जगह कोई और नेता लाया जाएगा? और अगर ऐसा है तो फिर बड़ा सवाल यह उठता है कि BJP की तरफ से PM पद का असली प्रत्याशी किसे माना जाए?

सवाल गारंटी का | सवाल महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि BJP घोषणापत्र में इस बार किए जा रहे वादों को पार्टी 'मोदी की गारंटी' के रूप में पेश कर रही है। BJP ने भी सवाल की गंभीरता को समझा। तत्काल पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह जैसे शीर्ष नेता सामने आए और स्पष्ट शब्दों में बताया कि पार्टी के चुनाव जीतने की स्थिति में न केवल नरेंद्र मोदी फिर PM बनेंगे बल्कि वह अपना कार्यकाल भी पूरा करेंगे।

उम्र की कसौटी | वैसे राजनीति में उम्र कोई सीमा नहीं मानी जाती है। इस बात का श्रेय BJP और खासकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देना पड़ेगा कि वह अपनी पार्टी के जरिए भारतीय राजनीति में रिटायरमेंट का चलन लेकर आए। 2014 के बाद BJP के कई प्रभावशाली नेता इस नए चलन के मुताबिक रिटायरमेंट की राह पर बढ़ते देखे गए। इसे पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की मजबूती का संकेत भी माना गया।

बहस में मोड़ | ऐसे में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जारी रखने की पार्टी की घोषणा चाहे-अनचाहे बहस को इस सवाल की ओर ले जाएगी कि क्या पार्टी नरेंद्र मोदी को इस नियम का अपवाद मान चुकी है? अगर हां तो क्या यह पार्टी के अंदर लोकतंत्र के कमजोर होने का सूचक है? अच्छी बात यह है कि अब लोकसभा चुनाव के दौरान इन सवालों पर वोटरों की राय भी दर्ज हो जाएगी।

चक्र-व्यू
सांपों की सीमा

राहुल पाण्डेय

तीन-चार दिन पहले सुपी के एक स्कूल में सांप निकला। सुपी नैनीताल से आगे और मुक्तेश्वर से पहले पड़ने वाला एक गांव है। यहां सेब, नाशपाती, आड़ू, अखरोट वगैरह बहुतायत में होते हैं। सुपी में ही पहली बार मैंने काफल का पेड़ देखा था, वरना तब तक सिर्फ महिमा सुनी थी। खैर, सुपी में जब सांप निकला, संयोग से मित्रवर गोपाल भाई मौके पर मौजूद थे। गोपाल भाई सुपी के अगले गांव लोध में रहते हैं, फलों की खेती करते हैं और जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए गढ़वाल से कुमायूं तक एक किए रहते हैं। सांप जहरीला था। जहर का भय लोगों के चेहरों पर चढ़ा था। गोपाल भाई संभलकर सांप की ओर गए, उसकी पूंछ पकड़ी और सांप को उठा लिया। सांप बार-बार उनकी ओर मुंह मार रहा था, मगर उसे नहीं पता था कि वह एक अनुभवी सांप पकड़ने वाले के हाथ में है। सांप को हाथ में पकड़े-पकड़े ही गोपाल भाई बच्चों को बताने लगे कि यह बेहद सुंदर जीव होता है। जितना हम इससे डरते हैं, उससे ज्यादा यह हमसे डरता है। जिस तरह से सांप को देखकर हम लोग भागते हैं, उसी तरह से सांप भी हमें देखकर सर्र से निकल लेता है।

सांप वाकई सुंदर था। काला तो था, मगर पूरा काला नहीं। बीच-बीच में हलकी सी पीली चकत्ती, जैसे दूर किसी काली चट्टान पर पीली लिली खिली हो। जब सांप शांत हो गया तो गोपाल भाई ने स्कूल के पीछे वाली खाई में उसे धीमे से सरका दिया। संयोग से उसी दिन मेरे एक और मित्र फेलिक्स भाई ने एक वाइपर की तस्वीर शाया की। फेलिक्स भाई डार्विन के पड़पोते हैं और गुजरात से लंदन आना-जाना करते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि डार्विन का एक पोता हमारे, यानी भारत के हिस्से में भी आया है। फेलिक्स भाई के वाइपर में भी वैसी ही लिली के फूल खिले थे, जैसे सुपी के सांप में। बस उनका वाइपर यूरोपियन था और गोपाल भाई वाला सांप विशुद्ध इंडियन। फेलिक्स भाई से मैं पूछना चाहता था कि क्या यूरोपियन सांप खुद को यूरोपियन मानते हैं, मगर उससे पहले गोपाल भाई ने ही ज्ञान दे दिया। सांप छोड़ने के बाद बताने लगे कि सांपों की कोई सीमा नहीं होती है। ताज्जुब नहीं कि कश्मीर में ढेरों पाकिस्तानी सांप हों और कराची के बिलों में भारतीय सांप रेंग रहे हों। सांपों को नहीं पता कि सीमा होती क्या है। सीमाएं तो इंसानों ने बनाई हैं, सांपों ने नहीं। शायद इसीलिए सांप किसी भी सीमा से कहीं ज्यादा सुंदर होते हैं। मुझे लगता है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुतों को भी यही लगता है कि सीमाएं संसार की सबसे असुंदर चीजें हैं। इंसान ने जबसे इसे बनाया है, तभी से सारी समस्याएं शुरू हुई हैं।

एकदा
पत्तलों में जीवन

20वीं सदी के शुरुआत की बात है। रमण महर्षि के आश्रम के पास एक व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। आश्रम के सदस्यों ने उसे देख लिया और वे उस व्यक्ति को महर्षि के पास ले गए। पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि वह एक टीचर है और पास के गांव का रहने वाला है। पारिवारिक कलह से वह इतना अधिक परेशान हो गया है कि उसके जीवन में निराशा भर गई है। अपनी बातें बताकर वह महर्षि को प्रणाम कर जमीन पर बैठ गया। आत्महत्या करने का विचार मन में कैसे आया? पूछने पर उसने खुलकर सारी बाताईं। महर्षि ने उसे थोड़ी देर बैठने का इशारा किया। उस समय

महर्षि आश्रमवासियों के भोजन के लिए बड़ी जतन से पत्तलें बना रहे थे। वह व्यक्ति बड़े गौर से महर्षि को देख रहा था। पत्तलें बनाने में महर्षि की तल्लीनता और लगन देखकर वह सोच रहा था, पत्तलें स्थायी नहीं हैं। थोड़ी देर में इनकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी, फिर इतना जतन क्यों? अब उस टीचर ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, 'भगवन, आप इन पत्तलों को इतनी मेहनत से बना रहे हैं। मगर जब लोग भोजन कर लेंगे तो ये कूड़े में फेंक दी जाएंगी।' महर्षि मुस्कुराते हुए धीरे से बोले- आप ठीक कहते हैं। किसी वस्तु की उपयोगिता खत्म हो जाने पर उसे फेंक दिया जाता है। लेकिन गलत तो तब कहा जाएगा, जब उसका इस्तेमाल किए बगैर ही कोई उसे फेंक दे। आप तो सुविज्ञ हैं। मनुष्य का जीवन अनमोल है। इसे यूं ही नहीं खोना चाहिए, हर स्थिति में संघर्ष करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब शायद आप समझ गए होगें? महर्षि के शब्दों से अध्यापक की समस्या का समाधान हो गया। वह महर्षि के चरणों में नतमस्तक हो गया और जीवन जीने की नई आशा लेकर अपने घर को लौट गया।

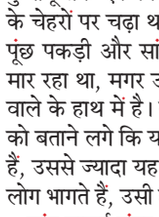

संकलन : **रमेश जैन**

राज्य में BJP की रणनीतिक नाकामियों की वजह से विपक्षी दलों में एका हो गया है
क्या पश्चिम बंगाल को समझ नहीं पाई BJP

शिखा मुखर्जी

BJP के लिए पश्चिम बंगाल अहम है। पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की कुल 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। केंद्र में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए उस प्रदर्शन को दोहराना महत्वपूर्ण है। लेकिन, राज्य में पार्टी का अभियान लड़खड़ाता रहा है। इतना कि सात में से तीन चरणों के चुनाव के बाद उसके लिए खुद को संभाले रखना मुश्किल हो चला है।

CAA की विफलता | जब मूल मुद्दा राज्य में लोगों के प्रति केंद्र का व्यवहार हो, तो एक गलत कदम से ही बेचैन मतदाता राजनीतिक सीमा को पार कर सकता है। ऐसा लगता है कि CAA ने यही किया है। जल्दबाजी में इसका नोटिफिकेशन जारी कर इसे BJP का मास्टरस्ट्रोक बताया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद इससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका असर राज्य में 20 सीटों के नतीजों पर पड़ सकता है।

Redistribution का खेल | BJP का चुनावी अभियान '2047 तक विकसित भारत' से अचानक मुड़कर बहुसंख्यक उन्माद पर पहुंच गया। आरोप लगाया गया कि सभी विपक्षी दलों का एक छिपा हुआ अजेंडा है। BJP ने इस बात को उछाला कि कथित रूप से सभी विरोधी दलों ने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का वादा किया है। कहा गया कि इसमें संपत्ति का redistribution, दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण रद्द करना और इसे मुसलमानों को देना शामिल है।

BJP की गलती | इस हमले ने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और CPM की अगुआई वाले लेफ्ट को साथ ला दिया। BJP के लिहाज से यह अच्छा नहीं है। इन हमलों ने विपक्ष के उन दलों को दोस्त बना दिया, जो पहले दुश्मन थे। अब वे एक आम मकसद से एकजुट हो गए हैं। मकसद है बंगाल में BJP को रोकना।

बंगाल का चुनावी हाल
- CAA से BJP को सही रेस्पॉन्स नहीं
- तुष्टीकरण का आरोप असरदार नहीं
- TMC, कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ

विपक्ष एकजुट | खासतौर पर, तीसरे चरण की वोटिंग के बाद, जैसे-जैसे बाकी इलाकों में मतदान की तैयारी हो रही है, एक महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इस बदलाव का नतीजा तो समय के साथ ही पता चलेगा, लेकिन यह पहले से ही साफ है कि BJP ने बाकी दलों को एकजुट कर दिया है। 2024 में उनके लिए अब प्रमुख दुश्मन BJP ही है।

बाहरी का ठप्पा | 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में बाकी दलों की TMC से टक्कर थी। लेकिन, पिछले इलेक्शन की सारी उलझन और दुविधा खत्म हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस अब प्रतिद्वंद्वी हैं, दुश्मन नहीं। कांग्रेस, CPM, TMC अब एक ही खेमे में हैं। सीएम ममता बनर्जी और लेफ्ट ने BJP को 'बाहरी' का तमगा दे रखा है। यही बाहरी सभी के निशाने पर है।

AFP

कूच बिहार के दिनहाटा जिले में पहले चरण की वोटिंग के दौरान मतदाता

हिंदुत्व कार्ड फेल | ऐसा लगता है कि BJP के रणनीतिकारों ने 2021 विधानसभा चुनाव के परिणामों का ठीक से अध्ययन नहीं किया। 294 विधानसभा सीटों में से 77 पर जीत का संदेश यह था कि संघ परिवार का हिंदुत्व कार्ड बंगाल में काम नहीं करता और CAA नियमों के अलावा बाकी मुद्दों पर गौर करें। अनियमितताओं को लेकर केंद्र ने राज्य का भुगतान रोक रखा है। केंद्रीय एजेंसियों के छापे भी मुद्दा हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप से भी BJP और सत्ताधारी TMC के बीच गरमागरम बहस हो रही है। कुल मिलाकर, राजनीतिक रूप से अनुभवी बंगाली मतदाताओं के पास पिछली प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के पर्याप्त कारण हैं।

मोदी लहर का असर | पीछे मुड़कर देखें तो 2019 के चुनाव परिणाम ने राज्य में BJP को एक छोटी पार्टी से प्रमुख विपक्षी दल में बदल दिया। उस चुनाव में CPM का खाता भी नहीं खुला था, जबकि कांग्रेस ने अपने गढ़ बहरामपुर और मालदा दक्षिण को बचा लिया था। यह तब हुआ था, जब पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी। बंगाल में भी वोटरों को यकीन हो गया था कि एक नई मजबूत ताकत का उदय हुआ है। CPM से बड़ी संख्या में वोट BJP में ट्रांसफर हो गए। 2014 में लेफ्ट का वोट शेयर 29.9% था, जो गिरकर 7.5% हो गया। इसके उलट 2014 में 17% पर रहने वाली BJP बढ़कर 40% पर पहुंच गई।

लेफ्ट की उम्मीद | इस बार CPM को भरोसा है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में वोटर उसके पाले में लौट रहे हैं। पार्टी के राज्य प्रमुख और पोलित ब्यूरो सदस्य मोहम्मद सलीम मुर्शिदाबाद सीट से खड़े हैं। उन्होंने तीन चीजों पर दांव खेला है। पहला दांव है, कांग्रेस से CPM में वोटों का ट्रांसफर। दूसरा है, TMC और BJP के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाना। तीसरा है, BJP के पक्ष में किसी लहर का अभाव।

स्मार्ट रणनीति | I.N.D.I.A. के पास पीएम पद के लिए कोई चेहरा नहीं है, कोई साझा घोषणापत्र भी नहीं। लेकिन, यह एक स्मार्ट रणनीति साबित हो सकती है। लक्ष्य सिर्फ एक है, BJP के खिलाफ वोटों को एकजुट करना और वोटरों के लिए विकल्प को आसान बनाना। अगर विपक्ष थोड़ा भी BJP को हिला पाता है, तो यह एक बड़ी सफलता होगी। बंगाल में एक जीत और वोट शेयर में उछाल इस बात की पुष्टि होगी कि लेफ्ट फिर से खड़ा हो रहा है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

चुप करके सुनेंगे, तभी तो ठीक से बहस करेंगे

गधे ने एक बार आसमान की तरफ सिर उठाकर देखा तो लाल-लाल बादलों ने उसमें डर पैदा कर दिया। फिर उसने कभी ऊपर नजरें नहीं कीं। इस लिहाज से वह सही कह रहा था कि आसमान लाल रंग का होता है। लेकिन, घोड़ा इस बात पर अड़ा था कि आसमान नीला है। दोनों में से कोई हार मानने को तैयार न था। आखिर में बहस पहुंची राजा शेर के दरबार में। शेर ने फैसला गधे के हक में सुनाया और घोड़े को कोड़ों की सजा मिली। जब घोड़े ने अपना पक्ष रखना चाहा, तो शेर ने कहा कि तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन गधे से बहस क्यों की?

आम बहस में यह खतरा रहता है कि कोई एक पक्ष हार जाए, कोई हार कर भी जीत जाए और किसी को सजा भुगतनी पड़ जाए। लेकिन, बहस अगर राजनीतिक हो, तो ये सारे खतरे करीब-करीब लुप्त हो जाते हैं। तब न पूरी तरह कोई सही होता है और न पूरी तरह गलत। बहस इस पर होती है कि कौन ज्यादा सही है। चूंकि मौसम चुनावों का है, तो ऐसे में राजनीतिक बहस और भी मौजूं हो जाती है।

सियासी बहस जब तक तर्क-वितर्क पर चलती रहे, कुतर्क में न फंसे, तब तक इससे बढ़िया टाइमपास कोई नहीं। इसमें वक्त भी कटता है और आनंद भी आता है। सामान्य तौर पर बहस को जोड़ लिया जाता है अनुशासन से। बच्चा जब मां-बाप से, जूनियर जब सीनियर से नाइत्तफाकी जाहिर करने की कोशिश करता है, तो उसे यही ताकीद मिलती है, बहस नहीं। लेकिन, राजनीतिक बहस इस दायरे से बाहर आती है। इसकी सबसे बड़ी USP ही है, दूसरों की बात से असहमति।

AI Image

जीवन आनंद

ये बहसें होती हैं बैठकों में और इन बैठकों का कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता। ट्रेन, बस, चाय-पान की गुमटी, घर या ऑफिस- कहीं भी दो या उससे ज्यादा लोग राजनीतिक बहस शुरू कर सकते हैं। ऐसी दो-चार बैठकी के बाद ही आपको लगने लगेगा कि आपके तर्क ज्यादा परिपक्व हो रहे हैं, आपको अपनी बात पर डटे रहने के लिए ज्यादा ठोस वजह मिलने लगी है और नए-नए विचार आ रहे हैं।

बात से बात जोड़ना और बात से अपने मतलब की बात निकालना सिखाती है राजनीतिक बहस। जब तक एक पक्ष हार न माने, तब तक इसका अंत नहीं हो सकता और ऐसा अपवाद स्वरूप होता है जब कोई हार माने। तो सियासत पर छिड़ी एक बहस सैकड़ों मील लंबा रास्ता भी पार करा देती है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप किसी भी बहस का किसी भी समय हिस्सा बन सकते हैं, किसी भी पक्ष के साथ हो सकते हैं और किसी भी समय उस बहस से बाहर निकल सकते हैं।

राजनीतिक बहस धैर्य धरना सिखाती है। दूसरों को दम साधकर सुने बिना अच्छा बहसबाज नहीं बना जा सकता। विपक्ष के एक-एक तर्क पर गौर करना, उसकी काट तैयार करना और फिर उसे एक के बाद एक, संभलने का मौका दिए बिना तीर की तरह चलाना- यह सब राजनीतिक बहस में ही संभव है। इस दौरान खुशी के छोटे-छोटे मौके भी मिलते हैं, छोटी-छोटी जीत के रूप में। लेकिन, एक सीख भी छिपी है इस जीत में कि यह जीत हमेशा नहीं रहेगी, बिल्कुल हार की तरह। आप जब अपने पर मुग्ध हो रहे होंगे, तभी सामने वाला जवाब तलाश कर आपके तर्क को ढेर कर सकता है। तो राजनीतिक बहस ज्यादा सचेत बनाती है। पर इसकी सबसे जरूरी शर्त यह है कि बहस के दौरान उस सीमा को न लांघें जिससे कड़वाहट पैदा होने लगे। अगर चाहते हैं कि बैठकी यूं ही चलती रहे, बात होती रहे, तो जीत-हार का ख्याल दिल से निकाल कर बस बहस करते जाइए।

शेयर करें अपने अनुभव

जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, हमें बताएं **nbtreader@timesgroup.com** पर, और सब्जेक्ट में लिखें- **'जीवन आनंद'**

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

प्रतिभा सिर्फ अपने काम आए तो तारीफ नहीं होती

प्रणव पण्ड्या

समय की मांग के हिसाब से इन दिनों लोगों पर दो तरह के दबाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक, अनचाही चीजों से जूझना और दूसरा, नए जमाने में सृजन कैसे हो, इसे जानना और इसमें काबिल बनना। क्षेत्र चाहे निजी हो, या सार्वजनिक ये दोनों चीजें करना काफी कठिन होता है। फिर जहां देश, समाज या दुनिया का सवाल हो, जाहिर है कि वहां तो मुश्किलें और भी बड़ी होंगी। विकास किसी का भी करना हो, उसके लिए उसी हिसाब से काबिलियत भी चाहिए और कर्मनिष्ठा भी। बिना इसके ढेरों समस्याएं और मुश्किलें आए दिन बनी रहती हैं। जो इन दिक्कतों से जूझ सकता है और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने के साधन जुटा सकता है, उसी को प्रतिभावान कहते हैं।

मनुष्यों का एक वर्ग होता है जो साधनों और मार्गदर्शन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यहां तक कि अपनी स्वतंत्र चेतना के बलबूते वो जीने लायक साधन भी नहीं जुटा पाता। इस तरह के मनुष्यों का उत्थान हो या पतन, उसका कारण हमेशा कोई दूसरा ही होता है। दूसरा वर्ग वह है जो समझदार होते हुए भी मतलबीपन से घिरा रहता है। योग्यता होने पर भी वह अपना लोभ, मोह और अहंकार को पूरा करने में लगा रहता है। तीसरा वर्ग प्रतिभाशालियों का है। ऐसे लोग कई व्यवस्थाएं बनाते हैं, बड़ी योजनाएं प्लान करते हैं, फिर उन्हें चलाते भी हैं। जो लोग आगे बढ़ने वाले होते हैं, जीतने वाले होते हैं, उनमें ऐसी ही मौलिक सूझ-बूझ होती है।

सबसे ऊंची श्रेणी महापुरुषों की है, जिन्हें भावना के चलते हम देवमानव भी कहते हैं। वे अपनी प्रतिभा का उपयोग आत्म परिष्कार से लेकर लोकमंगल तक के बेहतरीन कामों में करते हैं। समाज के उत्थान और मौजूदा मुश्किलों को हल करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। किसी देश की सच्ची संपदा ऐसे ही लोग ठीक से समझ पाते हैं। बड़े कामों को पूरा करने में बड़ी ताकत लगती है।

दलदल में फंसे हाथी को उससे ताकतवर हाथी ही बाहर निकाल सकता है। पटरी से उतरे इंजन को उससे बलवान क्रेन वापस पटरी पर लाती है। ऐसे ही समाज और संसार की बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए विशिष्ट और वरिष्ठ प्रतिभावानों की जरूरत पड़ती है। प्रतिभाशाली व्यक्ति सबकी मुश्किलें सुलझाने में कामयाब होते हैं। इसी से इन्हें देवदूत तक कहा जाने लगता है। आड़े समय में ऐसे ही प्रतिभाएं चाहिए होती हैं। ऐसे मनस्वी, तेजस्वी और ओजस्वी ऐसे कर्मयोग की साधना करते हैं, जो मौका पड़ने पर अपने प्रामाणिक व्यक्तित्व से कर्म करें और ऊर्जा का स्रोत बनें।

वर्तमान समय विश्व इतिहास में अद्भुत और अभूतपूर्व स्तर का है। इसमें एक ओर महाविनाश का प्रलयंकारी तूफान अपनी तेजी बता रहा है, तो दूसरी ओर सतयुगी नवनिर्माण की उमंगें भी उछल रही हैं। विनाश और विकास एक-दूसरे के विपरीत हैं, फिर भी उनके साथ एक ही समय में अपनी-अपनी दिशा में चल पाना मुमकिन है। इन दिनों अगर एक ओर आकाश में अंधेरा घना है तो दूसरी ओर सूरज अपनी लाली फैलाता भी दिखाई देता है। इन दोनों के समन्वय को देखते हुए ही यह समय युगसंधि का समय माना गया है।

विचार विंडो
क्या अमेरिकी लोकतंत्र खतरे में है?

मृत्युंजय राय

अमेरिका खुद को दुनिया में लोकतंत्र का अगुआ और संरक्षक मानता रहा है। अतीत में वह कई देशों के अंदरूनी मामलों में लोकतंत्र की दुहाई देकर दखल भी देता रहा है। लेकिन अब खुद अमेरिका में ही लोकतंत्र के बचे रहने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। **Rebellion** नाम की किताब में Robert Kagan ने इस विषय का गहन विश्लेषण किया है। वह चेतावनी देते हैं कि 2024 का चुनाव शायद अमेरिका का आखिरी 'फ्री इलेक्शन' हो सकता है।

Robert Kagan का यह दावा हैरान करता है और अजीब भी लगता है। लेकिन उन्होंने अपने दावे के हक में दलीलें भी दी हैं। वह लिखते हैं कि अगर डॉनल्ड ट्रंप नवंबर में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव में हार जाते हैं तो वह अपनी हार मानने से इनकार कर सकते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के लीडर ट्रंप की जब 2020 में जो बाइडन के हाथों हार हुई थी तो उन्होंने उस चुनाव के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया था। वह आज तक यही कहते हैं कि उन्हें उस चुनाव में धोखे से हराया गया।

Robert Kagan का कहना है कि 2024 के चुनाव में अगर ट्रंप को हार मिली तो वह अपने करोड़ों समर्थकों से इसके नतीजों का नामंजूर करने का आह्वान कर सकते हैं। Robert का दावा है कि इसके बाद जिन राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी का शासन है, वे संघीय सरकार की वैधता को अस्वीकार कर सकते हैं, जो एक तरह से अमेरिका से अलग होना ही माना जाएगा। वह लिखते हैं कि ऐसा होने पर 'यूनाइटेड स्टेट्स' असल में यूनाइटेड यानी एकजुट नहीं रह जाएगा, जिसके अमेरिका और समूची दुनिया के लिए गंभीर परिणाम होंगे।

Rebellion में वह उन बातों का विश्लेषण करते हैं, जिससे अमेरिका इस मुकाम पर आ खड़ा हुआ है। Robert Kagan इस बात की ओर ध्यान दिलाते हैं कि अमेरिका में संघीय सरकारों और liberalism के विरोध का लंबा इतिहास रहा है। आज जो अमेरिका दिखता है, एक तरह से उसके निर्माण में इन बातों की भूमिका रही है। वहीं, ट्रंप एक ऐसा राजनेता साबित हुए हैं, जो इस असंतोष को भुनाने में कामयाब रहे हैं।

किताब का नाम उन्होंने **Rebellion** क्यों रखा? इस सवाल के जवाब में Robert Kagan बताते हैं कि ट्रंप अमेरिका में जिस राजनीति की अगुआई करते हैं, वह उस अमेरिका के खिलाफ है, जिसकी कल्पना इसके संस्थापकों ने की थी। ये नेता लोकतंत्र के हिमायती थे। वे उदारवाद के समर्थक थे। ट्रंप उस सोच के विरोधी हैं। वह अपने समर्थकों को उस उदारवाद के खिलाफ भड़काते हैं। Robert Kagan अपने रीडर्स से यह अपील करते हैं कि वे राजनीतिक संघर्ष में शामिल हों और लोकतंत्र-उदारवाद की रक्षा के लिए आगे आएं। वैसे, उनका यह भी कहना है कि अमेरिका के इतिहास में उदारवाद पर हमला कोई पहली बार नहीं हो रहा, ना ही इसे आखिरी हमला माना जाना चाहिए।

अमेरिका के लोकतंत्र की ताकत उसके संस्थान रहे हैं। इसी वजह से पहले भी जब उदारवाद पर हमला हुआ, तो वहां के संस्थानों ने उसे बचाने में अहम भूमिका निभाई। वैश्विक मंचों के जरिये भी अमेरिका ने दुनिया में लोकतंत्र को बढ़ावा देने की पहल की, जिसके लिए उसे दुनिया में एक वर्ग की ओर से आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। इसमें दो राय नहीं है कि अमेरिका में अंदर से ही लोकतांत्रिक और उदारवादी मूल्यों को चुनौती मिल रही है। लेकिन यह उम्मीद भी है कि जिन वजहों से उसका स्वरूप संरक्षित रहा है, वही factors आगे भी वहां लोकतंत्र और उदारवाद की रक्षा करेंगे।

आधी दुनिया
हालात से दो-दो हाथ

प्रणव प्रियदर्शी

आज की तारीख में नेहा कार फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, इंडिया में स्क्रम मास्टर और चैप्टर लीड की भूमिका में हैं। लेकिन जब वह स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाली महज एक लड़की थीं, तब भी उनकी आंखों में सपने थे। वह घर-परिवार के दायरे के बाहर अपने अच्छे काम से नाम और पहचान बनाना चाहती थीं। जीवन के उतार-चढ़ाव भरे सफर में यही सपने उन्हें आगे बढ़ने की ऊर्जा देते रहे। बचपन में मिला उनका पारिवारिक माहौल कितना संकीर्ण था, इसका अंदाजा इस बात से मिलता है कि घर में लड़कियों को प्रायः बालकनी में भी निकलने की इजाजत नहीं होती थी। घर की लड़की किसी और शहर में जॉब करे, यह सोचना भी आसान नहीं था। मगर नेहा उसी माहौल में धीरे-धीरे अपने और अपने सपनों के लिए स्पेस बनाती और एक-एक कदम आगे बढ़ती रहीं।

नेहा कार

BITS पिलानी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करते हुए उन्हें विप्रो में प्लेसमेंट मिल गई। कुछ साल विप्रो में गुजारने के बाद वह बतौर लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स में आ गईं। नौ साल काम करने के बाद नेहा ने अपनी जुड़वां बेटियों की देखभाल के लिए जॉब से इस्तीफा दिया। मगर नियति ने कुछ और सोच रखा था। उसी दिन उनका एक्सीडेंट हुआ और सर्जरी करानी पड़ा। दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने में आठ महीने लग गए। सर्जरी से ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि उनकी दुनिया घर-परिवार की चारदीवारी तक सिमटती जा रही है। उन्हें एहसास हुआ कि वह बिल्कुल अपनी मां की तरह सोचने लगी हैं, वैसे ही बहानों से खुद को तसल्ली देने लगी हैं। यह उन्हें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। फिर शुरू हुई हालात को अपने मुताबिक मोड़ने की मशक्कत। मुश्किलें कम नहीं थीं, लेकिन चाहे नई टेक्नॉलजी में खुद को पारंगत करने की बात हो या नाइट शिफ्ट और शहर से बाहर ट्रैवेल की चुनौती स्वीकारने की, नेहा कहीं पीछे नहीं हटीं। नतीजा है फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, इंडिया में उनकी यह शानदार दूसरी पारी।

रीडर्स मेल
www.edit.nbt.in

याद ही न रहे मोबाइल

6 मई को 'जीवन आनंद' कॉलम में लेख 'मोबाइल स्विच ऑफ करने से ऑन होंगी खुशियां' पढ़ने को मिला। आज के जमाने में हर व्यक्ति के दिमाग में यही रहता है कि यदि मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई महत्वपूर्ण सूचना छूट जाए। कोई इमरजेंसी हो तो जानकारी न मिले। खासकर तब जब किसी का परिजन बाहर रहता है, या बॉस का कोई आदेश आने वाला हो। बेहतर तो यही होगा कि स्विच ऑन रखें, पर मोबाइल से ध्यान हटा लें। जरूरत न हो तो मोबाइल को भूल जाएं।

सरिता ओचानी, राजेंद्र नगर

कहीं काम न बिगड़े

मोबाइल फोन आज बहुत जरूरी साधन बन गया है। पर 'मोबाइल स्विच ऑफ करने से ऑन होंगी खुशियां' में लेखक ने उस ओर हमारा ध्यान दिलाया है कि मोबाइल में उलझे रहना ठीक नहीं है। काम के सिलसिले में मोबाइल फोन जरूरी है तो छोड़ नहीं सकते। बात करने के लिए तो यह चाहिए ही। पर हम टहलने निकलते हैं, फिर भी मोबाइल से चिपके रहते हैं। जरूरी न हो तब भी, मोबाइल स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रहना ठीक नहीं है। इस कारण हम एक-दूसरे से कटते जा रहे हैं।

प्रतिभा गोयल, ईमेल से

जीवन को साकार बनाएं

जीवन के कड़वे अनुभव हमें ऐसे जकड़े रहते हैं कि उनके बीच आनंद महसूस करना कठिन हो जाता है। लेकिन जीवन के उन्हीं पलों में कहीं न कहीं खुशियां छिपी होती हैं। हमारा काम है, खुशियां देने वाले कुछ पलों को समेटकर उसे महसूस करें। यही सकारात्मक सोच है। इस बात की समझ से संबंधित लेख 'जीवन आनंद' कॉलम में पढ़ने को मिलते हैं। जीवन के खट्टे-मीठे अनुभव ही जीवन को साकार बनाते हैं। तनाव है तो विश्राम भी जरूरी है। अक्सर ऐसे लेख पढ़कर मुझे विश्राम का अनुभव मिलता है। फिर आगे बढ़ने का हौसला और रास्ता दोनों मिलता हैं।

जितेन माखीजा, ईमेल से

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

चीन के नए राजदूत ने कहा, समाधान पर रहेगा फोकस - खबर - नई पहचान बढ़ाने वाले अक्सर बात करने का बहाना ढूंढते हैं!

परविंदर भाटी

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

भारत की परमाणु शक्ति

भारत ने भारत में जितने भी परमाणु विस्फोट किए हैं उनका सबब यही रहा है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। भारत का अमेरिका के साथ हुआ 2008 का परमाणु समझौता भी इसी बात का प्रमाण है कि परमाणु ऊर्जा केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही उपयोगी होनी चाहिए। भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण को अब 26 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं जब 1998 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने राजस्थान के पोखरण में दूसरा परमाणु विस्फोट किया था परंतु इस विस्फोट के तुरंत बाद ही पड़ोसी पाकिस्तान ने भी परमाणु विस्फोट करके स्वयं को परमाणु शक्ति घोषित कर दिया था। हालांकि उसकी परमाणु शक्ति को दुनिया ने मान्यता प्रदान नहीं की और उसके परमाणु शक्ति बनने को अवैध दर्ज ही दिया जबकि भारत के साथ ऐसी स्थिति नहीं थी पूरी दुनिया ने भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति से संपन्न देश माना। पूरी दुनिया जानती है कि भारत की अभी तक की सबसे अधिक शक्तिशाली प्रधानमंत्री माने जाने वाली स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1974 में पोखरण में ही पहला विस्फोट करके पूरी दुनिया को बता दिया था कि भारत में परमाणु शक्ति बनने की पूरी क्षमता है परंतु वह अपनी इस ताकत से पूरे विश्व में शांति स्थापित करने की ही कामना करता है।

श्रीमती गांधी ने इससे पहले 1971 में ही बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान को बीच से चीर कर दो टुकड़ों में बांट दिया था और पूरी दुनिया को संदेश दिया था कि मानवता के विरुद्ध जहां भी अपराध होगा खासतौर से भारत के पड़ोस में तो भारत उसे स्वीकार नहीं करेगा। 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाने वाले बांग्लादेश में आज के पाकिस्तान की फौज ने जो बर्बरता और अत्याचार किया था तथा बंगाली मुसलमानों पर जो जुल्म उठाया था उससे पूरी दुनिया दहल गई थी। इंदिरा जी ने तब बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए मानवता के आधार पर भारत की सेवाएं देना स्वीकार किया था और इस देश के लाखों शरणार्थियों को भारत में पनाह दी थी। इसके बाद ही 1974 में भारत ने परमाणु विस्फोट किया और खासतौर पर अमेरिका को बताया कि वह अपनी परमाणु शक्ति से दुनिया के किसी भी देश और खासतौर पर भारत को डरा नहीं सकता है। वह शीत युद्ध का दौर था और इंदिरा जी ने उस समय सोवियत संघ से रक्षा संधि करके भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए थे। इसके बाद 2008 के आते-आते परिस्थितियां इस प्रकार बदलीं कि स्वयं अमेरिका को ही भारत के साथ परमाणु समझौता करने की पहल करनी पड़ी और इसके लिए उसने अपने संविधान में संशोधन भी किया।

> **श्रीमती गांधी ने इससे पहले 1971 में ही बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान को बीच से चीर कर दो टुकड़ों में बांट दिया था और पूरी दुनिया को संदेश दिया था कि मानवता के विरुद्ध जहां भी अपराध होगा खासतौर से भारत के पड़ोस में तो भारत उसे स्वीकार नहीं करेगा। 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाने वाले बांग्लादेश में आज के पाकिस्तान की फौज ने जो बर्बरता और अत्याचार किया था तथा बंगाली मुसलमानों पर जो जुल्म उठाया था उससे पूरी दुनिया दहल गई थी। इंदिरा जी ने तब बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए मानवता के आधार पर भारत की सेवाएं देना स्वीकार किया था और इस देश के लाखों शरणार्थियों को भारत में पनाह दी थी।**

दुनिया के पांच अधिकृत परमाणु संपन्न देशों के साथ भारत इस परमाणु क्लब का छठा देश बना हालांकि अभी इसे परमाणु ईंधन सप्लाई करने वाले देशों के समूह का सदस्य नहीं बनाया गया है। इसके लिए भारत की कोशिश जारी है। आज सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास जो अवैध परमाणु शक्ति है उससे क्या भारत को डरना चाहिए? हमें पता है कि पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति क्या है। वहां सेना के हाथ में परमाणु बम की डोर है और पाकिस्तानी फौज भारत के प्रति इसके जन्म से ही जैसा रवैया अपनाती रही है उसे देखकर कहा जा सकता है कि यह भारत के साथ विरोध को अपने और पाकिस्तान के वजूद की वजह मानती है। अत: अन्तर्राष्ट्रीय जगत में आज पाकिस्तान की जो स्थिति है वह एक आतंकवाद की खेती करने वाले देश की है । दुनिया के लगभग सभी बड़े मुल्क यह बात स्वीकार कर चुके हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों की सैरगाह बन चुका है। निश्चित रूप से यह डर सही है कि पाकिस्तान अपने परमाणु बमों का प्रयोग डराने के लिए करने की बात करता रहता है परंतु क्या उसके ऐसा कहने से पूरी दुनिया के देश सचेत नहीं होते।

भारत में यह राय बहुमत की राय मानी जा सकती है कि पाकिस्तान एक नाजायज मुल्क है। इसका उदय मजहब की बुनियाद पर जिन्ना के जिन तर्कों के आधार पर हुआ वे तर्क स्वयं ही तब निराधार साबित हो गए जब 1971 में मुस्लिम बहुल पूर्वी पाकिस्तान ही बांग्लादेश के रूप में दुनिया के मानचित्र पर उभरा। मगर भारत की तुलना जब हम गलती से पाकिस्तान से कर बैठते हैं तो अपनी ही नादानी का इजहार करते हैं। दोनों देशों की कोई तुलना नहीं है। पाकिस्तान द्वारा परमाणु शक्ति अर्जित किए जाने से पूरी दुनिया भी चिंतित है और ऐसी कोशिश जारी है कि पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों को अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी में रखा जाए। जहां तक भारत का सवाल है तो यह अब अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु क्लब का सम्मानित सदस्य है। अमेरिका के साथ परमाणु समझौता होने के बाद ही यह तय हो गया था। इसके बाद ही भारत अमेरिका संबंधों में नया आयाम आया है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

साफ-सुथरी सरकार की दरकार है...

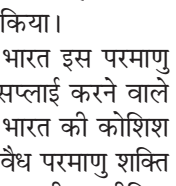

भ्रष्ट तंत्र ने बड़ी तीव्र गति से पकड़ ली रफ्तार है,
प्रतिभाशाली युवा इस दुर्घटना में बेरहमी से हुआ शिकार है,
चपरासी, क्लर्क, शिक्षक भर्ती सभी विभागों में भ्रष्टाचार-
की संक्रमणीय बीमारी से मची हाहाकार है,
इस रोग से मुक्ति के लिए जनता कर रही ईमानदार,
साफ सुथरी सरकार की दरकार है...!!

गीता पाढा

बच्चों का बढ़ता स्क्रीन टाइम है 89% मदर्स की चिंता

नई दिल्ली, (आईएएनएस): बच्चों के स्क्रीन टाइम (मोबाइल, टेलीविजन, टैब, लैपटॉप आदि देखने की अवधि) को लेकर 89 प्रतिशत भारतीय मां चिंता करती हैं। रविवार को जारी एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। बाजार अनुसंधान कंपनी टेकआर्क द्वारा मदर्स डे पर जारी इस रिपोर्ट के लिए 600 ऐसी कामकाजी मांओं के बीच सर्वेक्षण कराया गया जिनका कम से कम एक बच्चा तीसरी से 10वीं कक्षा में पढ़ता हो।

इसमें महिलाओं से डिजिटल इकोसिस्टम में उनकी चिंताओं, चुनौतियों, रुचि और पसंदों के बारे में पूछा गया था।

रिपोर्ट में कहा गया है, मांओं का मानना है कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और उनके मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मांओं की सबसे बड़ी चिंताओं में निजता (81 प्रतिशत), अनुचित कंटेंट (72 प्रतिशत), टीनएज इंफ्लुएंसर (45 प्रतिशत) और डीप फेक (26 प्रतिशत) सबसे ऊपर हैं। उनका मानना है भविष्य में डीप फेक और जेन एआई अभिभावकों के लिए और बड़ी चिंता बनेगी।

चुनावों का मौसम और उदासीन बुद्धिजीवी

डा. चन्द्र त्रिखा
chandertrikha@gmail.com

चुनावों का मौसम आते ही चुनावी राजनीति से जुड़ी अनेक भूली-बिसरी यादें ज़ेहन में तैरने लगती हैं। इन यादों में युवाओं की उदासीनता, लेखन जगत से जुड़ी शख्सियतों का लगभग पूरी तरह हाशिए पर सरक जाना, भाषा के स्तर में गिरावट, मीडिया का बहरूपियापन आदि पर ध्यान अटकना स्वाभाविक है। बुद्धिजीवी वर्ग या कला-संस्कृति एवं साहित्य से जुड़े लोगों ने अधिकांशत: चुनावी-राजनीति से दूरी बनाए रखी है। वैसे भी उन्हें कभी वोट-बैंक आकर्षित करने वाला चुम्बक नहीं माना गया।

दक्षिण भारत व मध्य भारत में शुरुआती दौर में बुद्धिजीवियों ने कुछ भूमिका निभाई लेकिन उनकी लीक पर चलने में उनके अपनों ने भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। उड़ीसा में दो बार ऐसा हुआ। पहली बार नंदिनी सत्पथी ने वहां की सियासत में विशिष्ट पहचान बनाई, यद्यपि वह स्वयं और उनके पति तथागत की मूल पहचान लेखन के क्षेत्र से ही थी। दूसरी बार बीजू पटनायक के आकस्मिक निधन के पश्चात उनकी तीन संतानों में किसी एक को उत्तराधिकारी बनाने पर विचार हुआ। तब सबसे पहले बीजू के बड़े बेटे श्री प्रेम पटनायक का नाम उभरा। मगर वह किनारा कर गए। शेष दो में छोटे बेटे नवीन पटनायक और उनकी लेखिका बहन गीता मेहता का नाम चर्चा में चला। लेकिन गीता मेहता उन दिनों अमेरिका में थीं। उन्हें बुकर-पुरस्कार भी मिला था। वैसे भी उन्हें राजनीति या सत्ता के गलियारे से कोई जुड़ाव नहीं था। सबसे छोटे नवीन पटनायक 1970 के दशक में दक्षिणी दिल्ली में अपने यारों-दोस्तों की महफिलों में छाए हुए थे।

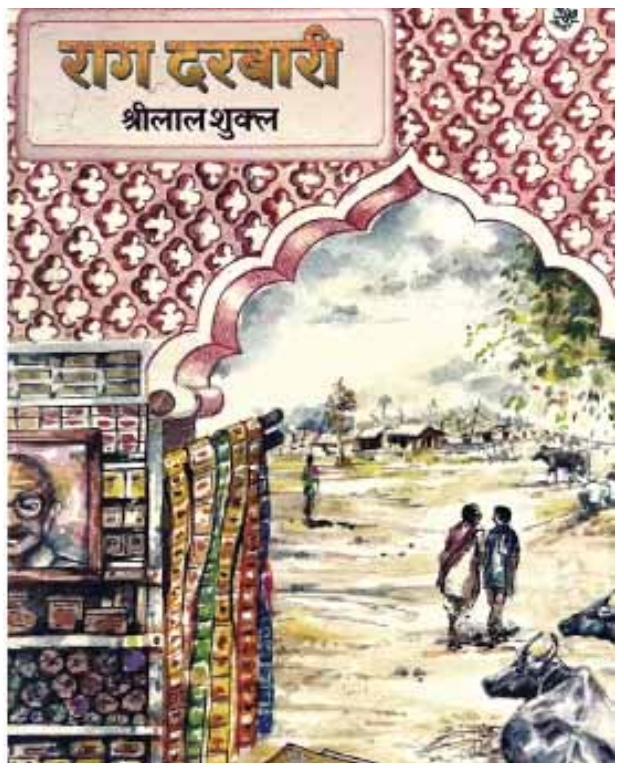

उन्होंने कुछ वर्षों तक दिल्ली के ओबेराय होटल में अपना बुटीक भी चलाया। वहां पर अक्सर तीन काफी टेबल उनके नाम पर 'बुक' रहती थीं। इसी नाम से उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी 'श्री काफी टेबल्स'। उनके सहपाठियों में संजय गांधी भी शामिल थे। उन दिनों 'जींस-टी शर्ट' ही पहनते थे नवीन और जब सत्ता के गलियारे में धकेले गए तो पहचान ही बदल गई। अब कुर्ता-पायजामा ही उनकी पहचान बन चुकी है। नवीन की कुछ विशिष्ट बातें भी हैं, जिन्हें लेकर कई बार पार्टी में भी संकट खड़ा हो जाता है। लेकिन उनका एक ही उत्तर होता है, 'मैं कोरे दिखावे या नाटकीयता में कोई दिलचस्पी नहीं रखता।

पार्टी में अक्सर उन्हें आग्रह किया जाता है कि उड़िया भाषा में लिखने-पढ़ने का अभ्यास कर लें। वह अक्सर जनसभाओं में भी ठीक से उड़िया भी नहीं बोल पाते थे। यह बात अलग है कि वह उड़िया की संस्कृति और वहां के साहित्य के बारे में अंग्रेजी में समुचित संवाद कर लेते हैं। यदि इस बार भी वह विधानसभा चुनावों में जीत गए तो देश में सर्वाधिक लम्बे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का उनका कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा। वैसे इस समय इस सूची में सिक्किम के पवन कुमार चेमलिंग शिखर पर हैं।

नवीन अब 78 वर्ष के होने वाले हैं। उनके उत्तराधिकारी के बारे में भी चर्चा है। स्वयं अब तक कुंवारे ही हैं। राजनैतिक उत्तराधिकारी के रूप में अब वहां के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पांडियन का नाम चर्चा में चलता है। नवीन पटनायक की एक विशेषता यह भी है कि वह 'मीडिया केंद्रित' राजनीति पसंद नहीं करते। बहुत कम बोलते हैं और भाषा की गरिमा पर उनका ज्यादा ध्यान रहता है। वह न तो बड़बोले हैं, न ही बयानबाज़ी का कोई शौक है। ओडिशा में वैसे बुद्धिजीवी, लेखक सदा सक्रिय रहे हैं। कर्नाटक आदि में तो परंपरा यह भी रही है कि मुख्यमंत्री समय-समय पर प्रतिष्ठित लेखकों के घर भी जाते रहे हैं।

तमिलनाडु, केरल में भी बुद्धिजीवियों के लिए राजनीति के गलियारे खुले रहे हैं। इसके विपरीति उत्तर भारत में, विशेष रूप से उत्तरप्रदेश में डॉ. सम्पूर्णानंद, पीडी टंडन व प्रयाग-बनारस की कुछेक विभूतियों के बाद माहौल में बाहुबलियों की चर्चा ज़्यादा होने लगी थी। मध्यप्रदेश में भी शुक्ला बंधुओं से पहले द्वारिका प्रसाद मिश्र व कुछ अन्य साहित्य और लेखन दोनों में चर्चा का केंद्र बने। मिश्रा जी ने तो एक महाकाव्य भी लिख डाला था।

अपने समय का बहुचर्चित उपन्यास रागदरबारी और एक पत्रकार चाणक्य सेन द्वारा लिखे गए उपन्यास 'मुख्यमंत्री' में भी बुद्धिजीवियों व राजनीति के गलियारे की सांझी चर्चा होती रही। वैसे भी वहां मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के समय में बाल कवि बैरागी व अशोक वाजपेई सरीखे साहित्यकारों की सक्रियता, साहित्य व राजनीति की सांझी इबारत लिखी जाती रही। मगर अब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली आदि में यह सांझी इबारत कमोबेश पूरी तरह गायब है। लेखकों व कलाकारों आदि को यहां प्रथम पंक्ति में रखे जाने की परंपराएं स्थापित हो ही नहीं पाईं लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस जुगलबंदी के बिना एक सभ्य व विकसित समाज की परिकल्पना हो ही नहीं सकती।

बढ़ते नौकरी घोटालों से कैसे बचा जा सकता है ?

मेलबर्न, (द कन्वरसेशन): डिजिटल युग में, नौकरी बाजार तेजी से एक भूलभुलैया जैसा बनता जा रहा है - जिसमें मांग बहुत ज्यादा है और मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल। ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, नवंबर 2023 और फरवरी 2024 के बीच नौकरी की रिक्तियों की संख्या में 6.1 प्रतिशत की गिरावट आई है। नौकरी के विज्ञापन पर प्रत्येक क्लिक या तो अद्भुत अवसरों के द्वार खोल सकता है या नौकरी चाहने वालों को पूरी तरह से स्थापित साइबर जाल में फंसा सकता है।

नवीनतम वार्षिक टारगेटिंग स्कैम रिपोर्ट से पता चलता है कि आस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा रिपोर्ट किए गए घोटाला नुक्सान में 13.1 प्रतिशत की उत्साहजनक गिरावट आई है - जो 2023 में घटकर 2.74 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हो गई है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। घोटालेबाज लगातार अपनी तकनीकों को परिष्कृत कर रहे हैं और अपनी पहुंच का विस्तार कर रहे हैं। विशेष रूप से चिंताजनक नौकरी घोटालों की मात्रा है (जिन्हें रोजगार या भर्ती घोटाले के रूप में भी जाना जाता है)। ये घोटाले 2023 में शीर्ष दस घोटाला श्रेणियों में से एक थे, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय घाटे में नाटकीय रूप से 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

नौकरी घोटाले वास्तव में कैसे काम करते हैं? और नौकरी चाहने वाले वैध नौकरी प्रस्तावों और भ्रामक योजनाओं के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं? नौकरी घोटालेबाज नकली नौकरियों का वादा करके लोगों को आकर्षित करते हैं, जिनमें कम प्रयास की आवश्यकता होती है लेकिन वे पर्याप्त वित्तीय लाभ या ''निश्चित'' आय का वादा करते हैं, या शायद किसी ऐसी वास्तविक कंपनी में ''बेहतरीन नौकरी'' का भी वादा करते हैं, जिसका नुमांइदा होने का वह दावा करते हैं। सभी मामलों में अंतिम लक्ष्य पीड़ित से पैसे या व्यक्तिगत विवरण निकालना है।

रोज़गार घोटालों के कई रूप हो सकते हैं लेकिन कई स्पष्ट संकेत भी हैं। घोटालेबाज गैर-मौजूद नौकरियों का विज्ञापन करने के लिए सोशल मीडिया, अनचाहे ईमेल, एन्क्रिप्टेड चैट एप्लिकेशन (जैसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम), फोन कॉल या यहां तक कि वैध रोजगार वेबसाइटों का उपयोग करते हैं। नौकरी घोटालेबाज वास्तविक संगठनों से भर्ती करने वालों का भी रूप धारण कर सकते हैं, जिनमें उच्च-स्तरीय अधिकारी भी शामिल हैं या यहां तक कि ऐसी नौकरियों के लिए साक्षात्कार आयोजित करने वाले प्रबंधकों को नियुक्त करना भी शामिल है जो अस्तित्व में ही नहीं हैं। इनमें से कुछ नौकरियों के लिए, घोटालेबाज रोजगार सुरक्षित करने, ऑनबोर्डिंग के लिए भुगतान करने, या नौकरी चाहने वाले को कुछ (गैर-मौजूद) उत्पादों को खरीदने के लिए कुछ प्रकार के अग्रिम शुल्क की मांग करेगा। जैसे ही शुल्क का भुगतान किया जाएगा, घोटालेबाज तुरंत गायब हो जाएगा।

कभी-कभी, नौकरी घोटालेबाज उच्च कमीशन का वादा करते हैं। यदि व्यक्ति अपने स्वयं के बैंक खाते का उपयोग मौजूदा धन को एक ऑफशोर खाते, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज या उपहार कार्ड में स्थानांतरित करने के लिए करता है। यह संभवत: मनी लॉन्ड्रिंग है। नौकरी घोटाले के प्रकार के आधार पर फर्जी आवेदन और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया का संचालन करने वाले साइबर अपराधी आपके पासपोर्ट नंबर, ड्राइवर का लाइसेंस और अन्य क्रेडेंशियल्स

जैसी संवेदनशील जानकारी तक भी पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको पहचान की चोरी का उच्च जोखिम रहता है। स्कैमर्स अपने पीड़ितों को उनके ऑनलाइन व्यवहार, वित्तीय स्थिति, जरूरतों और यहां तक कि कुछ प्रकार के अनुनय के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर लक्षित करते हैं।

ऑस्ट्रेलिया में रहने की बढ़ती लागत नौकरी घोटालों के लिए उपजाऊ जमीन तैयार कर रही है। जिन लोगों को रोज़गार की सख्त ज़रूरत है, जो बहुत लंबे समय से बेरोजगार हैं और जो अंशकालिक (आमतौर पर दूरस्थ) नौकरियों के माध्यम से अतिरिक्त आय की तलाश कर रहे हैं, उन सभी को इन नौकरी घोटालों का शिकार बनने का उच्च जोखिम है।

ये व्यक्ति आर्थिक ज़रूरतों से प्रेरित होते हैं और जोखिम को आसानी से नज़रअंदाज़ कर देंगे या पहचान नहीं पाएंगे। कठिन नौकरी बाजारों में मूल्यवान कार्य अनुभव की तलाश कर रहे विश्वविद्यालय के छात्र और हाल ही में स्नातक भी तेजी से नौकरी घोटालों का निशाना बन रहे हैं। अप्रवासी विशेष रूप से नौकरी घोटालों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, मुख्यत: क्योंकि वे वैध रोजगार प्रक्रियाओं, मानक भर्ती प्रथाओं और ऑस्ट्रेलियाई रोजगार अधिकारों से शायद परिचित नहीं होते हैं।

चरम मामलों में रोजगार घोटालों का परिणाम अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी भी हो सकता है, जैसा कि पिछले साल कंबोडिया में हुई एक घटना से पता चला है, जिसमें पीड़ितों को परिसरों में बंद कर दिया गया, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए और उन्हें दूसरों को धोखा देने के लिए प्रशिक्षित किया गया। बंधक बनाने वाले उन्हें फिरौती मिलने पर ही रिहा करते हैं।

व्यापक जानकारी और योग्यताओं की सूची की तलाश करके नौकरी लिस्टिंग का आलोचनात्मक मूल्यांकन और जांच करें। नौकरी की पेशकश की वैधता को सत्यापित करने के लिए विश्वसनीय पेशेवरों से सलाह लें। उच्च रिटर्न वाले अनचाहे रोजगार के अवसरों की पेशकश करने वाले गैर-कॉर्पोरेट ईमेल, टेक्स्ट या अन्य संदेशों का जवाब न दें। हमेशा प्रस्ताव की वैधता की पुष्टि करके गहन शोध करें। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट देखें, विश्वसनीय समीक्षाएं पढ़ें, कॉल करें या हो सके तो वहां जाएं। आवेदन या ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान पासपोर्ट विवरण, ड्राइवर का लाइसेंस, मेडिकेयर नंबर, या वित्तीय जानकारी (बैंक खाता नंबर या पेआईडी) सहित महत्वपूर्ण जानकारी देने से बचें। नियुक्ति की शर्त के रूप में अग्रिम भुगतान न करें और प्रशिक्षण, उपकरण या सॉफ्टवेयर के लिए शुल्क का भुगतान न करें। कमीशन के लिए किसी अन्य की ओर से अपने स्वयं के बैंक खाते के माध्यम से धनराशि प्राप्त करने या स्थानांतरित करने के लिए कभी भी सहमत न हों। कुल मिलाकर सतर्क रहें। यदि आप किसी भी नौकरी घोटाले में फंसते हैं तो स्कैमवॉच वेबसाइट पर उनकी रिपोर्ट जरूर करें।

कौन हैं संजीव खन्ना जो अगले सीजेआई बनेंगे ?

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने 10 मई को आबकारी नीति से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत दे दी। इस फैसले के बाद जस्टिस खन्ना को गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया। जस्टिस खन्ना की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के बाद दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। ऐसे में सीजेआई चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट के बाद वह अगले चीफ जस्टिस बनने की कतार में सबसे आगे हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ का कार्यकाल नवंबर 2024 को पूरा हो रहा है, जिसके बाद जस्टिस खन्ना 10 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक सीजेआई के रूप में काम करेंगे।

जस्टिस संजीव खन्ना करीब पांच साल पहले जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बने थे। वह जस्टिस हंसराज खन्ना के संबंधी हैं, जिन्होंने आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ था और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। 1983 में उन्होंने दिल्ली की जिला अदालत में प्रैक्टिस शुरू की और फिर दिल्ली हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में वकालत की। उन्होंने संवैधानिक कानून, डायरेक्ट टैक्स, मध्यस्थता और कमर्शियल मामलों, कंपनी लॉ, भूमि कानून, पर्यावरण और प्रदूषण कानून एवं चिकित्सीय लापरवाही से जुड़े केस में वकालत की है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद जस्टिस खन्ना की डिटेल्स के मुताबिक, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एडीशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और कई आपराधिक मामलों में कोर्ट की तरफ से न्याय मित्र के रूप में बहस की थी। टैक्सेशन के मामलों में उनकी काफी महारत हासिल मानी जाती है और उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में 7 साल तक काम किया।

बतौर जज क्या-क्या दिए फैसले

अप्रैल 2024 में जस्टिस खन्ना ने वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में डाले गए वोटों के क्रॉस-वेरिफिकेशन से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने अपने फैसले में ईवीएम की पवित्रता और देश के चुनाव आयोग पर भरोसे को लेकर विस्तार से लिखा है।

मार्च में जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए रोक लगाना सही नहीं है। हालांकि अदालत ने जल्दबाजी में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए भी सरकार की आलोचना की। जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने मार्च 2023 में शराब नीति मामले में बीआरएस नेता और तेलंगाना एमएलसी के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कविता से ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन करने और सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आने को कहा था।

लोकसभा चुनाव के दौरान हर बार शेयर बाजार में होती है उथल-पुथल

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): लोकसभा चुनाव और शेयर बाजार का आपस में गहरा नाता है। जैसे ही चुनावों का ऐलान होता है तो बाजार में इसे लेकर प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, जिसके कारण उतार-चढ़ाव आता है। इस साल भी कुछ ऐसा ही है। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव 7 अप्रैल से 12 मई के बीच नौ चरणों में संपन्न हुआ था और इसके नतीजे 16 मई को आए थे।

चुनाव शुरू होने से पहले बाजार में बड़ा उछाल देखा गया था। निफ्टी 10 फरवरी को 6,041 अंक पर था, जो 7 अप्रैल तक 6,776 अंक पर पहुंच गया। इस दौरान सेंसेक्स 20,414 अंक से बढ़कर 22,628 अंक पर पहुंच गया। अगले तीन सप्ताह में 7 अप्रैल से 28 अप्रैल तक निफ्टी ने 200 अंक और सेंसेक्स ने 500 अंक के सीमित दायरे में रहा।

बाजार में 28 अप्रैल से लेकर 19 मई तक एक बार फिर बड़ी तेजी देखी गई। निफ्टी 7,367 अंक पर पहुंच गया। इस दौरान सेंसेक्स भी 24,693 अंक तक पहुंच गया।

लोकसभा चुनाव 2019 सात चरणों में संपन्न हुआ था। पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल को हुई थी जबकि सातवें चरण की वोटिंग 19 मई को हुई थी। 23 मई को इसके नतीजे घोषित हुए थे। चुनाव शुरू होने से पहले बाजार में बड़ी तेजी देखी गई। निफ्टी 18 फरवरी के 10,738 अंक से बढ़कर 15 अप्रैल को 11,752 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स भी इसी अवधि में 35,820 अंक से बढ़कर 39,140 अंक पर पहुंच गया।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

CMYK

एआई की दुनिया

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नित नई होती दुनिया पर सबकी नजर स्वाभाविक और सुखद है। इंटरनेट पर अब लोगों के लिए केवल सर्च इंजन नहीं, बल्कि एआई से लैस बेहतर सर्च इंजन की उपलब्धता सुनिश्चित होने वाली है। इंटरनेट की दुनिया में यह सबसे बड़ी खबर है कि ओपनएआई एक नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित सर्च इंजन की घोषणा के लिए तैयार है। यह घोषणा किसी भी समय हो सकती है और इसके साथ ही गूगल की बादशाहत को भी चुनौती मिलने लगेगी। अभी गूगल का सर्च इंजन हर कंप्यूटर और हरेक स्मार्टफोन में मौजूद है, पर जब ओपनएआई का कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला सर्च इंजन सक्रिय हो जाएगा, तो स्थितियां बदलेंगी। वैसे पर्प्लेक्सिटी नामक एक सर्च इंजन भी लगातार विकसित हो रहा है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस है, लेकिन ओपनएआई का सर्च इंजन विशेष होगा। यह गौर करने की बात है कि ओपनएआई ने बड़ी संख्या में गूगल के विशेषज्ञ प्रोग्रामरों को अपने यहां बहाल किया है, जिससे यह संभावना बढ़ी है कि ओपनएआई दुनिया के सामने कुछ बहुत खास पेश करने वाला है।

माइक्रोसॉफ्ट समर्थित ओपनएआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अभी सबसे आगे है। चैटजीपीटी भी ओपनएआई का अब तक का सफलतम उत्पाद है। अब नए सर्च इंजन के आने से ओपनएआई के चैटजीपीटी की क्षमताओं में वृद्धि की उम्मीद है, जिससे यह वेब से वास्तविक समय में या तत्काल जानकारी प्राप्त कर सकेगा और अपनी प्रतिक्रियाओं में अनेक उद्धरण शामिल कर सकेगा। यह अक्सर कहा जा रहा है कि चैटजीपीटी काफी मशीनी या एकरूपता वाले पाठ पेश कर रहा है, जबकि बाजार में ज्यादा विविधता वाले ऐसे पाठों की जरूरत है, जो मशीनी नहीं, बल्कि ज्यादा मानवीय लगें। एक ही तरह के बनावटी, घिसे-पिटे जवाबों या पाठों की शिकायतें बार-बार आ रही हैं। गूगल ही नहीं, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट की भी कोशिश है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में त्रुटिहीन या कम त्रुटियों वाले उत्पाद पेश करे। हालांकि, ऐसा नहीं है कि पहली बार ओपनएआई का जुड़ाव किसी सर्च इंजन से होने जा रहा है। इसके पहले ओपनएआई ने माइक्रोसॉफ्ट के ही सर्च इंजन बिंज के साथ मिलकर काम किया है, जिसका लाभ चुनिंदा या प्रीमियम उपयोगकर्ताओं को ही मिला है।

ओपनएआई एक नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित सर्च इंजन की घोषणा के लिए तैयार है और इसके साथ ही गूगल की बादशाहत को चुनौती मिलने लगेगी।

इंटरनेट की दुनिया में लोगों को नए सर्च इंजन का इंतजार तो है, पर ओपनएआई के ही एक शोधकर्ता द्वारा बनाए गए पर्प्लेक्सिटी की भी लोकप्रियता बढ़ी है और इस कंपनी का बाजार भाव एक अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। बहरहाल, अभी जो एआई सक्षम सर्च इंजन उपलब्ध हैं, उनकी सेवाएं पाठ और छवि तक ही सीमित हैं, इसलिए बाजार में एक ऐसे सर्च इंजन की जरूरत है, जो व्यापक रूप से किसी भी खोज को ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से आसान बनाए। गूगल पर सर्च की अभी जो विविध सुविधाएं हैं, वैसा ही अगर ओपनएआई ने पेश किया, तो एक नई क्रांति आ जाएगी। हालांकि, गूगल भी शांत नहीं है, आने वाले दिनों में गूगल के सर्च इंजन में ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समावेश हो जाए, तो दुनिया में इंटरनेट सेवा एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाएगी। लोग तो मानो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इंतजार में बैठे हैं। मिसाल के लिए, चैटजीपीटी की शुरुआत साल 2022 के अंत में हुई थी और अब तक उसके दस करोड़ मासिक उपयोक्ता हो चुके हैं। कुछ दिन और सब्र कीजिए, इंटरनेट की दुनिया में एक नई क्रांति के कदमों की आहट महसूस होने लगी है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 13 मई, 1949

राष्ट्रीयता की जीत

विधान परिषद् की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति ने केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा सभाओं में अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देने के बारे में जो निर्णय किया है, उसे हम वास्तव में राष्ट्रीयता की जीत कह सकते हैं। इससे स्वाधीनता और पराधीनता का अन्तर भी आसानी से समझ में आ जाता है। अंग्रेजी राज्य के जमाने में अल्पसंख्यकों की समस्या इतनी जटिल जान पड़ती थी कि उसका हल प्रायः असंभव नजर आता था। विदेशी शासनकर्ताओं ने अल्पसंख्यकों के भय और सन्देहों को खूब उकसाया और विभिन्न जातियों में एक-दूसरे के प्रति इतना अविश्वास पैदा कर दिया कि प्रत्येक अल्पसंख्यक जाति अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग से पकाने लगी और उनकी ओर से धर्म और जाति के नाम पर ऐसी अजीब मांगें पेश की जाने लगीं कि जिनको देखकर हैरानी और परेशानी होती थी। यदि उन मांगों को पूरा किया जाता, तो इस देश में वास्तविक लोकतन्त्र की स्थापना असंभव होता। यह स्थिति पैदा करने में विदेशी राज्यकर्ताओं का अपना विशेष स्वार्थ निहित था। वे इस देश में अपना वर्चस्व स्थायी बनाना चाहते थे और यह तभी संभव था जबकि इस देश के लोग जाति और धर्म के नाम पर विभाजित और विभक्त रहें।... देश का विभाजन उसी दुर्नीति का परिणाम था।

किन्तु जब से भारत स्वतन्त्र हुआ है, अल्पसंख्यकों की समस्या सरल से सरलतर होती गई है। परिस्थितियों में बड़ी तेजी से अन्तर पड़ता जा रहा है। अल्पसंख्यकों में यह विश्वास घर करता जा रहा है कि गैर-मजहबी राष्ट्रीयता के आधार पर खड़ी सरकार अल्पसंख्यकों के प्रति कोई अन्याय नहीं होने दे सकती। विधान परिषद् की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति ने अल्पसंख्यकों के बारे में सन् १९४७ में एक निर्णय किया था। यह राष्ट्रीयता और साम्प्रदायिकता के बीच एक समझौता ही था। उसके अनुसार केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा सभाओं में अल्पसंख्यकों के लिए स्थान सुनिश्चित कर दिये गये थे और उन्हें स्वतन्त्रता दी गई थी कि वे चाहें तो सामान्य स्थानों पर भी उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं... किन्तु इसी अर्से में लोकमत में और स्वयं अल्पसंख्यकों की राय में इतना परिवर्तन हो गया कि अल्पसंख्यक सलाहकार समिति ने अल्पसंख्यकों के लिए स्थान सुरक्षित करने की रियायत को रद्द करने का निर्णय किया है।

डिजिटल लेन-देन पर न लगे दाग

यहां स्कैन करें

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

रिजर्व बैंक की पिछली सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल फ्रॉड के 6,659 मामले सामने आए, जिनमें करीब 276 करोड़ रुपये की ठगी हुई।

तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा... कबीर दास ने जब यह कहा, तो इसका अर्थ बहुत गूढ़ था। मगर सामान्य भाषा में इसका अर्थ आसान है- सावधान न रहेंगे, तो कोई आपकी गठरी या जेब साफ कर सकता है। आज चूंकि आप अमूमन अपना माल-मत्ता मोबाइल फोन में ही लेकर चलते हैं, इसलिए चोरों के लिए भी आसान हो गया है कि बिना हाथ लगाए, यानी कैशलेस अंदाज में ही वे इसे साफ कर डालें। 'सावधानी हटी, दुर्घटना घटी' वाली कहावत अब सड़क पर ही नहीं, डिजिटल दुनिया में भी चरितार्थ हो रही है। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि डिजिटल लेन-देन खतरनाक है या इससे किनारा कर लेना चाहिए। मगर इतना साफ है कि लेन-देन जितना आसान होता जा रहा है, अपने पैसे और उससे जुड़ी जानकारी की हिफाजत उतनी ही जरूरी और मुश्किल होती जा रही है।

समझने में आसानी होगी यह जानकर कि डिजिटल लेन-देन की दुनिया में जालसाजी का आलम क्या है? ट्रांसयूनियन एक इंफॉर्मेशन और इनसाइट कंपनी है। वह दुनिया भर में डिजिटल और बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के जरिये होने वाले लेन-देन को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी आंकड़े जुटाती है। दुनिया भर में लेन-देन के कारोबार में जालसाजी पर उसकी ताजा रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में जितना डिजिटल लेन-देन हुआ, उनमें से करीब पांच प्रतिशत पर जालसाजी का शक है। लेन-देन के संदिग्ध मामलों की गिनती इस साल पिछले वर्ष के मुकाबले 14 फीसदी बढ़ी है। जालसाजी की रफ्तार कितनी तेज है, इसका नमूना यह है कि 2019 से 2023 के बीच जहां कुल डिजिटल लेन-देन का काम 90 फीसदी बढ़ा, वहीं जालसाजी वाले या इसकी आशंका वाले लेन-देन में 105 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

आपके क्रेडिट कार्ड का ब्योरा चुराकर या उसकी कॉपी बनाकर ठगी करने के किस्से अब भी बंद नहीं हुए हैं। इसी तरह, किसी न किसी बहाने से फोन पर आपका ब्योरा चुराने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। हाल तो यह है कि अगर अपने शहर से बाहर अचानक आपका फोन खो जाए और आप किसी दूसरे नंबर से अपने दोस्तों-परिचितों से मदद मांगने की कोशिश करें, तो ज्यादातर मामलों में उन्हें पहले शक होता है कि कोई जालसाज खेल तो नहीं कर रहा? आपके फेसबुक अकाउंट या वाट्सएप को हैक करके या उसका क्लोन बनाकर आपके नाम पर लोगों से पैसे मांगने वाली ठगी का कारोबार भी जोरों पर है।

भारत डिजिटल लेन-देन के मामले में दुनिया में अगली कतार में खड़े देशों में शामिल है। यूपीआई से लेन-देन की शुरुआत 2016 में हो गई थी, लेकिन खासकर नोटबंदी और कोरोना के बाद इसमें जबर्दस्त तेजी आई है। 2023 में भारत में यूपीआई के जरिये होने वाले लेन-देन की गिनती 117.6 अरब थी। यहां कुल मिलाकर 182 लाख करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ। इसी साल जनवरी से दिसंबर के बीच यूपीआई के इस्तेमाल में 49 प्रतिशत का उछाल देखा गया और तेजी का यह सिलसिला थमा नहीं है। अनुमान है कि जल्द ही हर महीने 20 लाख करोड़ रुपये का लेन-देन इस रास्ते होने लगेगा। इसमें क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग या दूसरे चैनलों से होने वाला ऑनलाइन लेन-देन शामिल नहीं है। ऐसे में, डिजिटल चोरी या जालसाजी की आशंका भी बढ़ती जा रही है।

रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल फ्रॉड के 6,659 मामले सामने आए, जिनमें 276 करोड़ रुपये की ठगी हुई। जबकि, उससे पिछले साल 3,596 मामलों में 155 करोड़ रुपये की जालसाजी की खबर मिली थी। ध्यान रहे कि ये वही मामले हैं, जिनकी शिकायत रिजर्व बैंक तक पहुंची है। बहुत से लोग रकम गंवाने के बाद भी उसकी शिकायत करने की जहमत नहीं उठाते हैं। कई मामलों में तो लोगों को ठगी की जानकारी भी नहीं हो पाती।

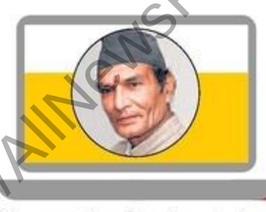

मगर जब ऐसी जालसाजी किसी कंपनी के साथ होती है, तो उसे वह ठगी की रकम से कहीं ज्यादा महंगी पड़ती है। डिजिटल जालसाजी रोकने के कारोबार की दिग्गज कंपनी लेक्सिसनेक्सिस रिस्क सॉल्यूशंस ने 'ट्रू कॉस्ट ऑफ फ्रॉड' नाम की रिपोर्ट निकाली है, जिसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र की तमाम कंपनियों का सर्वे करके यह हिसाब जोड़ा गया है कि जालसाजी जितनी रकम की होती है, उसके मुकाबले कंपनियों को इससे कितने की चोट पड़ती है? इसके मुताबिक, अगर कहीं एक रुपये की जालसाजी होती है, तो उसके ऊपर होने वाला कुल खर्च करीब चार गुना हो जाता है। इसमें डूबी हुई रकम के अलावा उसकी भरपायी के लिए होने वाली मेहनत, कानूनी कार्रवाई, कंपनी की साख का नुकसान और इसके साथ जुड़े छोटे-बड़े खर्च शामिल होते हैं।

आज ठगी के एक से एक नायाब तरीके सामने आ रहे हैं। ई-मेल या वाट्सएप पर लिंक भेजकर फिशिंग। कोई इनाम जीतने का लालच देकर ठगना। आपका बिजली कनेक्शन कट जाएगा, आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार पुलिस थाने में है, आपका कोई पार्सल विदेश से आकर कस्टम में अटका है आदि धमकी देकर किसी तरह क्रेडिट कार्ड का ब्योरा हासिल करना। फोन पर बातों में उलझाकर ओटीपी हासिल करना- ये सब तो पहले से चल रहे थे, लेकिन अब ऑनलाइन गेम के नाम पर, शेयर बाजार में किसी बड़े एक्सपर्ट का चेहरा लगाकर उससे मुलाकात या उसकी सलाह के नाम पर, बड़े-बड़े व्यापारियों की तस्वीरों के साथ कोई खास कोर्स चलाने के नाम पर भी ठगी के नए जाल बिछाए जा रहे हैं। आगे और भी नए तरीके सामने आते जाएंगे।

आखिर इनसे बचें कैसे? यह चिंता सरकार को भी है, इसीलिए हाल में वित्त मंत्रालय ने देश की फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ इस मसले पर चर्चा की और ऐसी जालसाजी पर लगाम कसने की तैयारी शुरू कर दी है। बैंकों और लेन-देन के काम में लगी कंपनियों ने भी ऐसे इंतजाम किए हैं, ताकि आपकी इच्छा के बिना आपके खाते या कार्ड से पैसा निकालना संभव न हो। हालांकि, जब कहीं 'डाटा ब्रीच' की खबर आती है, तो सावधानी और बढ़ाने की जरूरत बढ़ जाती है। लिहाजा, सबसे जरूरी यही है कि अपने क्रेडिट कार्ड या बैंक खाते से जुड़ी हरेक जानकारी बेहद गोपनीय रखी जाए और जरा भी शक होने पर उसकी रिपोर्ट बैंक या पुलिस को की जाए। वहीं, सरकार को भी बाकी सब चीजों के साथ इतना इंतजाम जरूर करना चाहिए कि पूरे बाजार में हर दुकान जिस अंधाधुंध अंदाज में ग्राहकों के मोबाइल फोन नंबर व अन्य जानकारी जमा करने में लगी है, उस पर कम से कम लगाम लगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

उत्तराखंड के जलते जंगल और कृत्रिम बारिश की आस

यहां स्कैन करें

वीरेंद्र कुमार पैन्यूली | पर्यावरण वैज्ञानिक व सामाजिक कार्यकर्ता

उत्तराखंड के जंगलों के सुलगने का सिलसिला जारी है। दावानल इतना भयावह है कि सेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अब आग मुख्य राजमार्गों व सहायक मार्गों, खेतों, आवासों और गांवों को जोड़ने वाले पैदल मार्गों तक आ-जा रही है। पिछले पांच वर्षों में सबसे सूखा गुजरा अप्रैल माह ही था। फिर, चारधाम यात्रा भी शुरू हो गई है, जिसमें अभी ही 15 लाख से ज्यादा यात्रियों का पंजीकरण हो चुका है। पारंपरिक ग्रीष्मकालीन फायर सीजन अभी 40-50 दिन और चलेगा, जिसके बाद ही मानसून राज्य में पहुंचेगा। मगर जाड़ों में मौसमी बदलाव से वनाग्नि का चक्र फिर से शुरू हो जाएगा, जिसकी तस्दीक सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड के उप-महाधिवक्ता जतिंदर कुमार सेठी के इस उद्धरण से भी होती है कि नवंबर, 2023 से अब तक तक 398 बार जंगल सुलगे हैं। इसी सुनवाई के दौरान में यह भी बताया गया कि राज्य सरकार क्लाउड सीडिंग, यानी कृत्रिम बारिश से वनाग्नि को काबू करने का विचार कर रही है, जिस पर अदालत ने कहा कि जंगल की आग बुझाने के लिए केवल कृत्रिम बारिश या बरसात पर भरोसा न किया जाए। यह बिल्कुल सही सीख थी कि हम बरसात के इंतजार में ही नहीं बैठे रह सकते हैं। वनाग्नि को रोकने के उपाय जल्द ही करने होंगे।

उत्तराखंड की वनाग्नि को देखते हुए कृत्रिम बारिश का सुझाव उचित नहीं था। शीर्ष अदालत की सीख सही है कि हम इसे रोकने के उपाय करें।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया था कि उत्तराखंड की भयावह वनाग्नि की स्थिति पर वह तत्काल सुनवाई करे। 8 मई को उसी सुनवाई के दौरान कृत्रिम बारिश पर टिप्पणी आई, जिस पर राज्य सरकार को गंभीरता से अमल करना चाहिए। बताया जाता है कि जंगल में आग लगाने के अपराध में 350 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें 62 आरोपियों को नामजद किया गया है, किंतु 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका सुनी जा रही थी, उस दिन भी उत्तराखंड में आग लगने की 15 बड़ी घटनाएं घटीं! इस दावानल से वन्य जीव अभयारण्य, संरक्षित दुर्लभ वानस्पतिक प्रजातियां, ग्लेशियर आदि सभी संकट में हैं। धुएं के कारण यहां दृश्यता कम हो गई है, जिसके कारण हवाई सेवाएं भी स्थगित की जा रही हैं। होटल की बुकिंग भी रद्द की जा रही हैं, यानी राज्य को पर्यावरणीय ही नहीं, आर्थिक नुकसान भी हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि क्लाउड सीडिंग से बारिश ही नहीं कराई जाती, हिमपात भी कराया जा सकता है। विश्व में पहली बार 1946 में न्यूयॉर्क में कृत्रिम बारिश कराई गई थी। इसका जनक भी एक अमेरिकी रसायन वैज्ञानिक और मौसम वैज्ञानिक था। आज कई देश इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें चीन सबसे आगे है। ऑस्ट्रेलिया में भी इसका खासा उपयोग किया जाता है। इससे संघर्ष-काल में शत्रु क्षेत्रों में बाढ़ और सूखे की स्थितियां पैदा की जा सकती हैं। अपने देश में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में इसका उपयोग हुआ है। जलाशयों में पानी की कमी होने पर, जल भंडारण की संभावनाओं को बढ़ाने, स्मॉग-वायु प्रदूषण से निपटने और लैंडफिल्स की आग को रोकने के लिए इसके इस्तेमाल पर विचार होता रहा है। 2009 में तानसा झील में पानी की कमी से निपटने के लिए महाराष्ट्र ने इसी तकनीक का उपयोग किया था। माना जाता है कि क्लाउड सीडिंग का खर्च अब करीब एक लाख रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर तक आ सकता है। आईआईटी, कानपुर के वैज्ञानिकों की इस पर विशेषज्ञता हासिल है।

जंगलों की आग अक्सर जन-सतर्कता और बरसात से ही रोकी जाती रही है। मगर दिक्कत यह है कि सरकारी अकर्मण्यता, पौधारोपण में अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, आपराधिक तत्वों की जंगलों में उपस्थिति आदि कमियों को दूर करने की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके कारण दावानल की भयावहता साल-दर-साल बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले राजीव दत्त यह भी बताते हैं कि उत्तराखंड सरकार को वनाग्नि पर दिशा-निर्देश देने की मांग करने वाली कई याचिकाएं वर्षों से शीर्ष अदालत में लंबित हैं। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि वह सारी याचिकाओं को सुनेगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। अब नई तारीख 15 मई है, जिस दिन शीर्ष अदालत इस मामले को सुनेगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मनसा वाचा कर्मणा

मेरा पनीर किसने लिया

किसी कंपनी में प्रबंधक कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो वे आपस में बैठकें करते हैं और एक नतीजे पर पहुंचते हैं। फिर मुट्ठी भर व्यवस्थापकों को लेकर यह योजना समझाई जाती है, लेकिन जमीन पर काम करने वाले लोग अलग होते हैं। उनको समझाया नहीं जाता कि यह बदलाव किसलिए लाना है, इसलिए वे अंदर से विरोध करते हैं और फिर कई बार योजनाएं असफल हो जाती हैं। बदलाव का फैसला ऊपर किया जाता है। उन्होंने उस पर गहरे सोच-विचार किया होता है, नए को अपनाने के लिए वह एक मंथन से गुजरे होंगे, बहुत से सवाल उठे होंगे, जिसके जवाब उन्होंने खोजे होंगे। मगर निचले स्तर तक यह बात एक आदेश की तरह पहुंचती है।

जैसे, एक अखबार के मालिक अपने दैनिक में ओशो के लेख छपवाना चाहते थे। सो उन्होंने एक लेखक से कहा कि आप अमुक उप-संपादक को लेख भेजना शुरू करें, वह छापेंगे। कुछ समय तक लेख छपा और बाद में बंद हो गया। लेखक बार-बार संपादकीय विभाग में पूछते कि बात क्या है? लेकिन सही जवाब नहीं मिलता। आखिरकार उन्होंने तंग आकर लिखना बंद कर दिया। बात यह थी कि वह पन्ना जिस उप-संपादक के पास था, वह ओशो को पसंद नहीं करता, पर मालिक से यह कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी, सो वह मालिक को 'हां' कहता और पीछे लेखक से बदला ले लेता। यह चूहे वाली मानसिकता हुई। मालिक ने अपने तईं तो फैसला ले लिया, लेकिन संपादकीय विभाग से चर्चा करके नीचे के कर्मियों को नहीं समझाया। उप-संपादक के लिए वह पन्ना उसकी मिल्कियत थी, वह उससे छिन गई।

इसे ह्यूमन इंजीनियरिंग, यानी मन की अभियांत्रिकी कहते हैं। इसे देखते हुए अमेरिकी लेखक स्पेंसर जॉन्सन ने एक किताब लिखी है, *हू मूव्ड माई चीज* अर्थात, मेरा पनीर किसने हटाया? यह किताब बदलाव के विषय में है, जिसमें दो चूहों के प्रतीक को लेकर दिखाया गया है कि साधारण आदमी के मन में परिवर्तन का कितना विरोध होता है और उससे बचने के लिए वे कैसी-कैसी राजनीति खेलते हैं।

अधिकारी संवेदनशील हो, तो वह देख लेगा कि लोगों की अपने काम से पकड़ हो जाती है और उसे छोड़ना उनको असुरक्षित लगता है। इस असुरक्षा के भाव से ही परिवर्तन का विरोध होता है।

वस्तुतः काम दो तल पर होता है- एक शरीर के स्तर पर और दूसरा, मन के तल पर। अधिकारी संवेदनशील हो, तो वह देख लेगा कि लोगों की अपने काम से पकड़ हो जाती है और उसे छोड़ना उनको असुरक्षित लगता है। इस असुरक्षा के भाव से ही परिवर्तन का विरोध होता है। जैसे मशीन का छोटे से छोटा पुर्जा भी बेहद महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही छोटे से छोटे कामदार को अपने साथ लेना जरूरी होता है। उन्हें यह भरोसा होना चाहिए कि यह बदलाव उनके हित में है, उनके खिलाफ नहीं। तभी पूरे संस्थान का काम सुचारू रूप से चलेगा!

अमृत साधना

द्रौपदी मुर्मु | राष्ट्रपति, भारत

शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो विद्यार्थियों को शिक्षित करने के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनाए, उनके चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करे। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में अपनी संस्कृति, परंपरा और सभ्यता के प्रति जागरूकता लाना भी है।

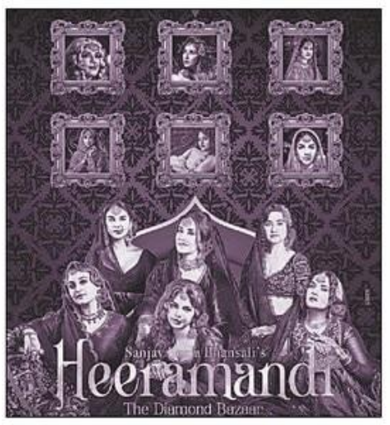

कहानियों और किरदारों का कोलाज हीरामंडी

हीरामंडी एक ऐसी सीरीज है, जो उस चकाचौंध में आपसे एक ही चीज मांगती है और वह है धैर्य। अगर आप अधीर होकर, मन में पूर्वाग्रह लेकर बैठेंगे देखने, फिर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। *हीरामंडी* में कई किरदार हैं और हर किरदार की एक कहानी है। इसको देखकर मुझे जो सबसे पहली बात समझ आई, वह यह कि चाहे तवायफों का जीवन हो या किसी अन्य पेशे से जुड़ा जीवन, सबकी अपनी दुश्वारियां हैं और सबकी अपनी चुनौतियां हैं।

हीरामंडी में मल्लिका जान (मनीषा कोइराला) ने रेहाना आपा (सोनाक्षी सिन्हा) का कत्ल कर दिया, क्योंकि रेहाना ही उस शाही महल की साहेब थी। कत्ल क्यों किया, कैसे किया, इसे सीरीज देखकर समझा जाना चाहिए। इस कत्ल के बाद मल्लिका जान ही बन गई साहेब और पूरी कहानी के केंद्र में कमोबेश वही रही। बावजूद इसके कहानी में केवल एक ही नायिका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके समानांतर कई कहानी चल रही है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम व उस आंदोलन में तवायफों की भूमिका को भी रेखांकित करने का प्रयास ठीक-ठाक किया गया है। कई कहानी, हर कहानी में कई किरदार, हर किरदार का अपना अलग चल रहा जीवन, प्रेम, नफरत, राजनीति, सत्ता की लड़ाई, सब कुछ है *हीरामंडी* में। कहानी के भीतर कहानी, किरदार के भीतर कई किरदार और यह सब आपसे मांगता है केवल और केवल धैर्य।

हालांकि, एक-दो नहीं, बल्कि कई तरह की कमियां हैं इसमें। पहली, किरदार निभाने के लिए चुने गए कलाकार। कुछ चुनाव अच्छे हैं, तो कुछ औसत। भाषा को लेकर भी बहुत झोल है इसमें। 1930 के दशक में उर्दू खालिस रही होगी और जब उर्दू लाहौर की हो, तो क्या ही कहना। फिर, कोठों को संजय लीला भंसाली ने महल बना दिया है, हालांकि पहले एपिसोड को छोड़ दें, तो बाकी में कोठों की भव्यता में कमी लाई गई है। पुरुष किरदारों का अभिनय भी मुझे प्रभावी नहीं लगा। संभव है, स्त्री-केंद्रित सीरीज और विषय है, तो जान-बूझकर पुरुषों को 'फेडेड' रखा गया हो, कुछेक अपवाद हैं। रही बात सेट की, तो 'लार्जर दैन लाइफ' संजय लीला भंसाली का मोटो और यूएसपी, दोनों है। अपने किरदारों को भव्य दिखा देने में भी कौशल तो लगता ही है। हां, विषय का रिसर्च अच्छा है। बहरहाल, *हीरामंडी* देखते हुए मुझे *चमकीला* का एक डायलॉग बार-बार याद आ रहा था कि जब अशांति, हताशा और निराशा अपने चरम पर हो, तो लोगों में मनोरंजन की भूख और बढ़ने लगती है। *हीरामंडी* को उसके विषय के कारण एक बार जरूर देखा जाना चाहिए।

रोहिणी कुमारी, शिक्षाविद्

अनुलोम-विलोम

हीरामंडी

भव्य सेट के अलावा कुछ खास नहीं इसमें

भंसाली साहब तो सेट और कॉस्ट्यूम्स दिखाने के लिए फिल्म बनाते हैं। कहानी बाद में ढूंढ़ी जाती है कि इस सेट पर कौन सी कहानी फिट बैठेगी? इस बार वेब सीरीज बना दी है। इतिहास से उन्हें ज्यादा सरोकार रहता नहीं है। भव्यता दिखाने के लिए ऐतिहासिक पात्र उठा लेते हैं, फिर अपनी मर्जी चलाते हैं। फिल्म इतिहास नहीं होती, यह मान लिया, मगर इतना भी कचरा नहीं किया जाता है फिल्म के नाम पर। जैसे, मस्तानी और काशी बाई को नचाना। उपन्यास उठाते हैं, तो उसमें पारो और चंद्रमुखी को नचा देते हैं। एक दर्शक के रूप में अखर तो जाता ही है।

ऐसा ही *हीरामंडी* देखते हुए महसूस हुआ। इतने करोड़ खर्च कर दिए सिर्फ भव्यता दिखाने में। तवायफों के ऊपर हमारे यहां इतनी सारी फिल्में बनी हैं। एक से बढ़कर एक। क्लासिक से लेकर मसाला तक, कि उनसे *हीरामंडी* की तुलना होनी ही है। हर दूसरे सीन में किसी न किसी फिल्म की झलक है इसमें। गीत तक उसी तरह फिल्माए गए हैं, *नजरिया की मारी* तो पूरा *पाकीजा* से उठा लिया। भले ही यह प्रसिद्ध ठुमरी हो, पर वही क्यों रखनी है डायरेक्टर साहब? एक नृत्य *जब प्यार किया तो डरना क्या* की तरह फिल्मा दिया गया। *पाकीजा* फिल्म में मीना कुमारी अपने प्रेमी राजकुमार की शादी पर मुजरा करती हैं, लहूलुहान होने तक। अंत में उनकी खाला आकर राजकुमार के चचा जान बने अशोक कुमार से सवाल करती हैं और राज खोलती हैं कि यह तुम्हारी बेटी है। हुबहू वही दृश्य रच दिया। रिचा चड्ढा का मुजरा, अध्ययन सुमन की शादी और अंत में मनीषा का खुलासा। कोई नया दृश्य नहीं लिखा जा सकता था क्या इस प्रेम और बेवफाई को दर्शाने के लिए? मुझे तो आखिरी एपिसोड बनावटी ज्यादा लगा। जैसे हारे को हरिनाम। माने अब कुछ न बचा, तो चलो क्रांति कर लें। सिर्फ बिब्बो जान का किरदार सही लगता है, जो शुरू से अंग्रेजों के विरुद्ध बगावती सुर रखती है। *हम देखेंगे* की नकल भी साफ दिखती है। रही बात अभिनय पक्ष की, तो जैसे इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। जो जितना निभा जाए, ठीक है।

हीरामंडी की कहानी कितने उम्दा रूप में दिखा सकते थे, अगर सिर्फ भव्यता पर फोकस न करते। कुछ काम कहानी, किरदारों और अभिनय पर भी किया होता, तो बेहतर होता। छोटे बजट में फिर भी अच्छी कोशिश की जा रही है अच्छी कहानियां कहने की, वह भी नए ढंग से, पर बड़े निर्माता-निर्देशक आज भी सिर्फ भव्यता और पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। फिल्म-निर्माता भव्यता के बजाय लेखकों पर पैसा खर्च करें, तो कुछ बेहतर फिल्में सामने आ सकती हैं।

निष्ठा, शिक्षाविद्

• बेस्ट सेलर से सबक | रोक्सी नफूसी

पॉजिटिव वाइब्स को अपनी ओर खींचना

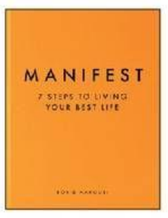

क्या यह सम्भव है कि आप अपने विचारों की शक्ति के जरिए ही अपने सपनों का जीवन रच सकें? अपनी बेस्टसेलर किताब 'मैनिफेस्ट' में रोक्सी नफूसी बताती हैं कि वास्तव में ऐसा हर कोई कर सकता है। कैसे? इसका विस्तारपूर्वक जवाब ही यह किताब है।

लॉ ऑफ अट्रैक्शन

बहुत-से लोग मैनिफेस्टिंग को केवल इतना ही समझते हैं कि जो हम कहना चाहते हैं उसे व्यक्त करें। लेकिन प्रभावी मैनिफेस्टेशन के लिए आपको अपने माइंडसेट यानी अपने विचारों, व्यवहार और भावनाओं को बुनियादी रूप से बदलने की आवश्यकता होती है। वास्तव में मैनिफेस्टिंग एक प्रैक्टिस है, जिसकी आजमाइश हर कोई कर सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ही यह आधारित होती है, जिसका मतलब है कि हम दुनिया में जिस तरह की एनर्जी को प्रस्तुत करते हैं, वह उसी प्रकार की एनर्जी को अपनी ओर खींचती है। सकारात्मक मानसिकता सकारात्मक व्यक्तियों को अट्रैक्ट करेगी, जो अपने लक्ष्यों को पाने में हमारी सहायता करेंगे।

यकीन रखने के मायने

भरोसा होने का मतलब है इस बात में यकीन रखना कि जीवन में जो कुछ भी होता है, वह उसी तरह से होना नियत है और यह सब आपको एक उच्च प्रयोजन की ओर ले जाने के लिए है। मंजिल का रास्ता सीधा-सरल और सहज-सुगम नहीं होता।

सकारात्मकता का प्रबंधन

लोकप्रिय संस्कृति और आध्यात्मिक दुनिया में मैनिफेस्ट शब्द का जो मतलब निकाला जाता रहा है, उससे भिन्न अर्थ इस किताब में प्रकट हुआ है। वो यह है कि आप पॉजिटिव बिलीफ से उन चीजों को अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं। और ऐसा आप मन बनाकर कर सकते हैं, आकस्मिक रूप से नहीं। आप सकारात्मकता का प्रबंधन कर सकते हैं।

अपने बारे में पॉजिटिव

नकारात्मकता से बचने के लिए कुछ तकनीकें कारगर साबित हो सकती हैं। इन्हीं में से एक है पॉजिटिव-अफर्मेशन, जिसकी मदद से आप नकारात्मक विचारों के उभरते ही सकारात्मक बातों को दोहराकर खुद को प्रोत्साहित करते हैं। या आप अपने को कमतर बताने वाली इनर-वॉइस को सुनकर उनसे विपरीत अपने बारे में सकारात्मक अफर्मेशन निर्मित कर सकते हैं।

स्पष्ट और ब्योरेवार इमेज

मैनिफेस्टिंग का पहला सिद्धांत यह है कि हम अपने दिमाग में उस चीज की एक स्पष्ट और ब्योरेवार इमेज बनाएं, जिसे हम चाहते हैं। विजुअलाइजिंग का यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा दिमाग मानसिक-छवियों को सच मानकर ही उन पर प्रतिक्रिया करता है। एक बार आपका दिमाग यह करने लगे तो फिर आप पॉजिटिव इमोशंस को अनुभव कर सकते हैं।

सेल्फ-लव और कृतज्ञता

सेल्फ-लव का प्रदर्शन करना और कृतज्ञता से भरा होना एक पॉजिटिव माइंडसेट के बुनियादी गुण हैं। इससे आपके पास सकारात्मक वाइब्स निर्मित हो जाती हैं, जो बदले में और सकारात्मक वाइब्स को आपकी ओर खींचती हैं। इससे आप अपने निगेटिव विचारों को भी पीछे धकेल सकते हैं, जो आपके पॉजिटिव-मैनिफेस्टेशन की राह का रोड़ा बन रहे हों।

• अनंत ऊर्जा | ज्ञानवत्सल स्वामी, प्रेरक वक्ता और विचारक

काम निपटाना नहीं, पूर्ण करना सीखें

हम जिस भी क्षेत्र या पेशे में हो, हमें जो काम और जिम्मेदारी मिली है, अगर उसे उत्साह-आनंद के साथ लगन से पूरा करें तो जीवन यात्रा का आनंदमयी होना तय है। जिस व्यक्ति के लिए उसका काम ही उसकी दुनिया बन जाता है उस व्यक्ति को ठहराव-बदलाव की जरूरत ही महसूस नहीं होती। काम ही उसका आराम-आनंद बन जाता है।

जीवन भर हमें कुछ न कुछ करना ही होता है। बावजूद इसके कई मौके या काम ऐसे होते हैं, जो इच्छा न होने पर भी करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए विद्यार्थी को पढ़ना और परीक्षा देना। कामकाजी व्यक्ति को वरिष्ठ या मालिक की कड़वी और अप्रिय बातों से जूझना। फोन पर किसी व्यक्ति से बात करना पसंद न आने पर भी उसे झेलना, क्योंकि रिश्ते निभाना है। आदि-आदि। उपरोक्त सूची व ऐसे ही प्रसंगों के वक्त एक भाव जरूर ही मन में उभरता है कि 'यह जल्दी निपटे तो ठीक रहे।' हमारा ध्यान अप्रिय काम को जैसे-तैसे पूरा करने पर होता है न कि इसकी गुणवत्ता पर। बस, हाथ आए-सिर पर पड़े काम को पूरा करने का ही भाव बचा होता है।

हां, यह भी सच है कि हम जीवन में सभी काम और क्रियाओं से समान न्याय नहीं कर पाते। लेकिन जिन कार्यों का हमारे जीवन पर दीर्घकालिक और गहनतम प्रभाव पड़ने वाला होता है, उन कार्यों को लेकर भी हमारा मनोभाव उथला-जल्दबाजी से पूरा करने वाला नजर आता है। जैसे विद्यार्थी के पास अध्ययन-परीक्षा का कोई विकल्प नहीं है- उसे चरणबद्ध रूप से बार-बार इस प्रक्रिया से गुजरना ही है। ऐसे में जिस विद्यार्थी की नजर हर साल गर्मियों की छुट्टियों पर रहती हो तो समझिए कि ज्ञानार्जन के मार्ग में उसका पराभव से सामना होना सहज है। कीमती समय देने के बावजूद उसे अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति को जब अपना कामकाज उबाऊ लगने लगे तब यही स्थिति पेश आती है। दशकों तक नौकरी करने के बावजूद जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में खुद को प्रासंगिक और दक्ष विशेषज्ञ के रूप में स्थापित नहीं कर पाता तो यही नौबत आती है। इसकी वजह है कि उसका रवैया हर काम को पूरा करने वाला रहा होता है। इसके उलट यदि महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति नजरिया बदल लें तो हमारी जिंदगी नए आकार लेने लगती है।

माइकल एंजेलो नामक महान शिल्पकार-चित्रकार हुए हैं। मौजूदा युग में भी उनकी रचनाएं प्रेरक नजीर हैं। सदियों के बाद भी यह सवाल अनुत्तरित है कि क्या विश्व को अब माइकल एंजेलो सरीखा व्यक्तित्व मिलेगा? उनके बारे में कहा जाता है कि वह शिला पर शिल्प उकेरने के काम में इतने तल्लीन हो जाते थे कि समय-काल का बोध तक भूल जाते थे। शिला के रजकण से नासिका अवरूद्ध होने व इसके चलते सांस लेने में दिक्कत होने पर एहसास होता था कि अरे, अब मुझे विराम लेना होगा। छैनी-हथौड़ी से आकार ले रही शिला पर अंतिम वार करते हुए बोलते थे- हे! शिल्प अब तो बोलिए। इतनी तन्मयता वाले काम का परिणाम-'मास्टरपीस' के रूप में मिलने पर आश्चर्य क्यों होगा।

हम जिस भी क्षेत्र-पेशे में हो, हमें जो काम-जिम्मेदारी मिली है उसे उत्साह-आनंद के साथ लगन से पूरा करें तो जीवन यात्रा का आनंदमयी होना तय है। जिस व्यक्ति के लिए उसका काम ही उसकी दुनिया बन जाता है उस व्यक्ति को ठहराव-बदलाव की जरूरत ही महसूस नहीं होती। काम ही उसका आराम-आनंद बन जाता है।

हम जो काम करते हैं, उसमें समय देना ही होता है। तो क्यों ना दिल लगाकर काम करें। हर काम में मेहनत करनी ही है तो क्यों न इसे सीख-जानकारी पाने के भाव से करें।

ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज जो भी कार्य करते थे, उसमें डूब जाते थे। कोई भी स्थिति-परिस्थिति उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी। कच्छ-भूकंप के बाद राहत-बचाव कार्य हो अथवा गगनचुंबी पावन मंदिर निर्माण प्रोजेक्ट्स अथवा देश-विदेश में उत्सव अथवा किसी बच्चे को मार्गदर्शन देना...वह कोई भी काम सिर्फ उसे करने के लिए नहीं करते थे। हर कार्य-क्रिया का उद्देश्य उनके मन में स्पष्ट रहता था। इसलिए आनंद-उत्साह से हर कार्य को यथेष्ठ श्रेष्ठता देते थे। अति व्यस्ततम कार्यक्रम के बीच भी वह किसी भी कार्य की गुणवत्ता के साथ तनिक भी समाधान नहीं करते थे। यही मूलमंत्र है कि प्रमुख स्वामी महाराज के प्रकल्प आज भी समाज-संसार के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं।

संक्षेप में कहें तो हम जो काम करते हैं, उसमें समय देना ही होता है। जब समय देना ही है तो क्यों ना दिल लगाकर काम करें, तब परिणाम बदल जाएगा। हर काम में मेहनत करनी ही है तो क्यों न इसे सीख-जानकारी पाने के भाव से करें। इतना ही करें तो परिश्रम भरी राह आनंद की राह बनकर आपके लिए समृद्धि-संतोष का संसार खोल देगी। हां, आर्थिक लाभ होगा वह तो ब्याज में।

• देश-दुनिया की सकारात्मक परंपराएं

आर्मीनिया : यहां की लेटर आर्ट इस देश की पहचान बनी

• **अगर** आप आर्मीनिया जाएं तो बड़ी-बड़ी मूर्तियों में वहां की वर्णमाला के 39 अक्षर उकेरे हुए नजर आएंगे। अक्षरों-शब्दों को सजावट के साथ लिखा जाता है और इसे विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। यहां की लेटर आर्ट को यूनेस्को ने भी मान्यता दी है।

• इतिहासकारों के मुताबिक 405 ईस्वी में भाषा के जानकार मेसरोप मैशटॉश ने आर्मीनियाई वर्णमाला ईजाद की। उन्होंने 36 (बाद में 39) अक्षरों वाली एक लेखन प्रणाली तैयार की, जो बाएं से दाएं और क्षैतिज रूप से पढ़ी जाती थी।

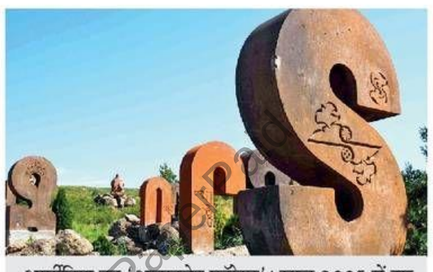

आर्मीनिया का 'अल्फाबेट फॉरेस्ट'। साल 2005 में इस वर्णमाला स्मारक का उद्घाटन हुआ था।

• आर्मीनियाई वर्णमाला न सिर्फ इतिहास, विज्ञान और वहां की क्रिप्टोग्राफी का आधार बनी, बल्कि आज इसका इस्तेमाल हैंडीक्राफ्ट में भी किया जाता है। खासतौर पर लोककला में इनका विशेष रूप से इस्तेमाल होता है।

• आर्मीनिया के लगभग सारे शैक्षणिक संस्थानों में लेटर आर्ट सिखाई जाती है। इससे जुड़ा सारा साहित्य पढ़ना और जानना भी सबके लिए जरूरी है। आर्मीनिया में चित्रकार, मूर्तिकार, बुनकर, आभूषण निर्माता आदि अपनी कृतियों में इन लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं।

• प्रेरक पत्र

प्रेम ही प्रकाश है और प्रेम ही गुरुत्वाकर्षण भी

अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह प्रसिद्ध पत्र अपनी पुत्री को लिखा था।

प्रिय लीजरेल,

जब मैंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था तो बहुत कम लोग उसे समझ पाए थे। लेकिन एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति ऐसी भी है, जिसका अभी तक विज्ञान कोई भी औपचारिक स्पष्टीकरण नहीं ढूंढ पाया है। यह शक्ति हम सभी के भीतर है और यह हम सभी को निरंतर नियंत्रित करती है।

यह सार्वभौमिक शक्ति प्रेम है। जब वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के एकीकृत सिद्धांत की खोज की तो वे सबसे शक्तिशाली अदृश्य शक्ति को भूल गए। जबकि प्यार ही प्रकाश है और प्यार ही गुरुत्वाकर्षण भी है। यह इन अर्थों में एक महान शक्ति है कि यह हमारे पास मौजूद सर्वश्रेष्ठ को कई गुना बढ़ा देता है, और मानवता को अंधे स्वार्थ में नष्ट नहीं होने देता।

प्रेम प्रकट होता है और प्रकट होना चाहता भी है। यह शक्ति जीवन को अर्थ देती है। यह वह परिवर्तन है, जिसे हमने बहुत लंबे समय तक नजरअंदाज कर दिया है, शायद इसलिए कि हम प्यार से डरते हैं। क्योंकि यह ब्रह्मांड में मौजूद एकमात्र ऐसी ऊर्जा है, जिसे मनुष्य ने अपनी इच्छानुसार चलाना नहीं सीखा है।

ब्रह्मांड की अन्य ताकतों पर नियंत्रण पाने में विफलता के बाद, हमारे लिए यह जरूरी हो गया है कि हम खुद को दूसरी तरह की ऊर्जा से पोषित करें... अगर हम जीवन में अर्थ ढूंढना चाहते हैं, अगर हम दुनिया को बचाना चाहते हैं, तो प्यार ही एकमात्र उत्तर है। हर व्यक्ति के भीतर प्रेम का एक छोटा लेकिन शक्तिशाली जनरेटर है, जिसकी ऊर्जा अभिव्यक्त होने की प्रतीक्षा कर रही है।

जब हम इस ऊर्जा को देना और प्राप्त करना सीख जाते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि प्रेम हर चीज से परे जाने में सक्षम है, क्योंकि वह जीवन का सार है।

-तुम्हारा पिता, अल्बर्ट!

© The New York Times

दैनिक भास्कर

अब आप NYT के सभी आर्टिकल DB एप पर हर सोमवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

बिजनेस

सेमीकंडक्टर और सोलर पैनल जैसी चीजों को भारी इंपोर्ट टैक्स के दायरे में लाया जाएगा

एलन रेपेपोर्ट, जिम टैंकरस्ले

चीन की सस्ती इलेक्ट्रिक कारों से अमेरिकी इंडस्ट्री को नुकसान; इसलिए बाइडेन 100% टैक्स लगा सकते हैं

अमेरिकी सरकार अब एक बार फिर चीन के बढ़ते व्यापार के खिलाफ शिंकजा कस रही है। दरअसल अमेरिका क्लीन एनर्जी प्रोड्क्टस की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को चीनी प्रोडक्ट से नुकसान को लेकर चिंतित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन ने ग्लोबल बाजारों में सस्ते सोलर पैनलों, बैटरियों, इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य प्रोडक्ट का अंबार लगा दिया है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिकी ऑटो इंडस्ट्री को बचाने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर इस सप्ताह 100 फीसदी तक नए टैक्स लगा सकते हैं। सेमीकंडक्टर सहित कुछ अन्य चीनी वस्तुओं पर भी अतिरिक्त इंपोर्ट टैक्स लगाए जाएंगे।

चीनी प्रोडक्ट्स पर नए टैरिफ का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। इससे पहले भी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2018 में चीन के करीब 25 लाख करोड़ रुपए के आयात पर टैक्स लगाए थे। हालांकि, ट्रम्प के अधिकतर टैक्स लागू रहेंगे लेकिन बाइडेन अब नए क्षेत्रों में टैक्स लगाएंगे। राष्ट्रपति ने 2022 में इनफ्लेशन रिडक्शन एक्ट के तहत जिन क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब्सिडी दी है, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए सरकार कदम उठाएगी। फिलहाल अमेरिका में चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर इस समय 25 प्रतिशत टैरिफ लगता है। बाइडेन सरकार इन्हें 100 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है ताकि चीनी ईवी खरीदना मुश्किल हो जाए।

बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद चीन पर टैरिफ का मामला व्हाइट हाउस में बहस का विषय रहा है। इस मुद्दे पर आर्थिक और राजनीतिक सलाहकारों के बीच अक्सर टकराव होता रहा है। लेकिन इस साल चीन ने इलेक्ट्रिक वाहनों, लीथियम बैटरी और सोलर पैनल का प्रोडक्शन बहुत अधिक बढ़ा दिया। बाइडेन सरकार अमेरिका में इन सभी प्रोडक्ट का उत्पादन बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर तक इन्वेस्ट कर रही है। बीजिंग के पैंतरे ने दोनों देशों के बीच ट्रेड युद्ध फिर से भड़का दिया है। लिहाजा बाइडेन को अधिक कड़े व्यापार प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है, यदि वे इस साल फिर राष्ट्रपति चुने गए तो चीनी इंपोर्ट पर 60 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है, मैक्सिको में चीनी कंपनियों द्वारा बनाई गई कारों पर 100 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा।

चुनाव को ध्यान में रखकर बाइडेन चीन पर दबाव बढ़ाएंगे

बाइडेन पहले ही चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर चिंता जता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इंटरनेट से कनेक्टेड चीनी कारों और ट्रकों से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है क्योंकि उनके ऑपरेटिंग सिस्टम चीन को संवेदनशील जानकारी भेज सकते हैं। राष्ट्रपति ने इन वाहनों को अमेरिका आने से रोकने के लिए साल की शुरुआत में कदम उठाए हैं। बाइडेन चीन पर दबाव बढ़ाकर नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रम्प से मुकाबले से पहले अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग की हिफाजत का इरादा जाहिर करना चाहते हैं।

जानबूझकर कम कीमत पर हैवी मैटल्स की बिक्री

• बाइडेन ने पिछले माह कहा था, वे चीन से आयातित स्टील और एल्यूमीनियम प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाने के पक्ष में हैं।

• बाइडेन का आरोप है कि चीन बाजार पर कब्जा करने के लिए दुनियाभर में जानबूझकर कम मूल्यों पर हैवी मैटल्स बेच रहा है।

• अमेरिकी सोलर इंडस्ट्री भी सस्ते सोलर पैनल की अमेरिका में बाढ़ रोकने के लिए चीन से इंपोर्ट पर नए कर लगाने की मांग कर रही है।

• चीन ने अमेरिका पर नए टैरिफ लगाने की संभावना की आलोचना की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार थी, तब से ही टैक्स के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कारोबार प्रभावित हुआ है। इसका संबंधों पर और असर पड़ेगा।

© The New York Times

साइकोलॉजी

खुद से बात करिए, इससे मन को खुशी के साथ प्रेरणा भी मिलेगी

जांसी डन

क्या अधेड़ आयु (मिडिल एज्ड) के लोग दिन भर खुद से बात करते हैं, क्या यह कोई समस्या है? मिशिगन यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर एथन क्रॉस ने बताया कि यह आम है। वैसे, मिड लाइफ में स्वयं से बात करने पर बहुत अधिक गहराई से अध्ययन नहीं हुए हैं। जब लोग मन ही मन बात करते हैं तो उसे आंतरिक संवाद कहते हैं। वे जोर से बोलते हैं तो उसे प्राइवेट स्पीच या स्वयं से बाहरी बातचीत कहते हैं। डरहम यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के प्रोफेसर चार्ल्स फर्नीहॉफ कहते हैं, बचपन की शुरुआत में प्राइवेट स्पीच सबसे अधिक होती है। लेकिन, जिंदगी का आधा सफर पूरा होने पर कई लोग फिर से यह आदत अपना लेते हैं। आयु बढ़ने के साथ लोग सामाजिक दबाव की परवाह नहीं करते हैं।

डॉ. फर्नीहॉफ का कहना है, खुद से बातचीत से बेचैनी खत्म हो सकती है। प्रेरणा और उत्साह बढ़ता है और खाली कमरे में मित्र की मौजूदगी महसूस कर सकते हैं। डॉ. क्रॉस बताते हैं, जोर से बोलने से मौखिक याददाश्त (वर्बल वर्किंग मेमोरी) मजबूत होती है। हाथ में शॉपिंग लिस्ट रखने और विभिन्न कामों, कार्यक्रमों को लंबे समय तक याद रखने में सहायता मिलती है। रिसर्च के अनुसार अगर ग्रॉसरी स्टोर में आप कुछ खोज रहे होते हैं तो उस चीज का नाम तेज आवाज में बोलने से उसे खोजना आसान बनता है।

निगेटिव बातचीत से नुकसान

डॉ. क्रॉस कहते हैं, कई बार एकतरफा बातचीत व्यक्ति की मानसिक सेहत के बारे में सवाल उठा सकती है। यह उस वक्त तकलीफदेह है, जब दूसरों को परेशानी होने लगती है। सिएटल यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिस्ट रेचेल गोल्डस्मिथ तुरो कहती हैं, लगातार निगेटिव बातचीत हानिकारक हो सकती है। हमेशा अपनी आलोचना से बेचैनी जैसी स्थिति बढ़ सकती है। सब कुछ बदतर हो जाता है।

© The New York Times

एपल : दस साल का सबसे अहम प्रोजेक्ट चैटबॉट सिरी को एआई में दक्ष बनाएगा

टेक्नोलॉजी

चैटबॉट प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला करने के लिए एपल की नई रणनीति

ट्रिप मिकले, ब्रायन चेन, केड मेट्ज

एपल ने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की होड़ में शामिल होने के लिए नई रणनीति बनाई है। यह पिछले दस साल में कंपनी का सबसे अहम प्रोजेक्ट होगा। इसके तहत वॉइस असिस्टेंट सिरी को चैटबॉट का मुकाबला करने के लिए जेनरेटिव एआई से लैस किया जाएगा। 10 जून को अपनी सालाना डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में सिरी का बेहतर वर्जन जारी होगा। यह अधिक बातचीत करेगा और तेजी से काम करेगा। सिरी में एक नया जनरेटिव एआई सिस्टम होगा जो उसे एक बार में एक सवाल का जवाब देने की बजाय चैट करने की क्षमता देगा।

एपल ने एआई पर फोकस बढ़ाया है। अब नए सिरी की क्षमता को सहारा देने के लिए इस वर्ष आईफोन की मेमोरी बढ़ाएगा। कंपनी ने गूगल, कोहियर और ओपन एआई सहित कई कंपनियों के चैटबॉट्स को चलाने वाले एआई मॉडल की लाइसेंसिंग पर चर्चा भी की है।

एआई टेक्नोलॉजी से एपल के 2 लाख करोड़ रुपए के व्यापार पर संकट

एपल को चिंता है कि उसे नई एआई टेक्नोलॉजी के कारण ग्लोबल स्मार्ट फोन मार्केट से खतरा है। यह टेक्नोलॉजी आईफोन के आईओएस सॉफ्टवेयर को हटाकर प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम बन सकती है। यह एजेंट नामक एआई एप्स का ईको सिस्टम बना सकती है। इससे एपल स्टोर का दो लाख करोड़ रुपए का सालाना कारोबार खतरे में पड़ सकता है। एपल ने जेनरेटिव एआई को अपनाने के लिए 80 हजार करोड़ रुपए के सेल्फ ड्राइविंग कार प्रोजेक्ट को ताक पर रख दिया है। एपल को आशंका है यदि उसने नई टेक्नोलॉजी नहीं अपनाई तो आईफोन अन्य टेक्नोलॉजी की तुलना में पीछे रह जाएगा।

© The New York Times

डोनाल्ड ट्रम्प ने दो बार छूट लेकर अमेरिकी बैंकों से 835 करोड़ रुपए का टैक्स बचाया

फाइनेंस

शिकागो के 92 मंजिला ट्रम्प टॉवर में नुकसान बताकर फायदा लिया

रस ब्युटनेर, पॉल कीफ

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शिकागो में अपनी बहुमंजिला इमारत के लिए अकाउंटिंग में हेराफेरी कर नाजायज तरीके से टैक्स रियायत हासिल की है। आंतरिक रेवेन्यू सर्विस (आईआरएस) की जांच में ये खुलासा हुआ है। टैक्स छूट हासिल करने के दावे पर एक साल से चल रहे ऑडिट मामले में हारने पर ट्रम्प को 835 करोड़ रु. से अधिक टैक्स चुकाना पड़ेगा। 92 मंजिला ट्रम्प टॉवर शिकागो में है। यह ट्रम्प का अंतिम बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था। हालांकि, लागत बढ़ने और मंदी के कारण टॉवर को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। लेकिन, ट्रम्प ने जब अपने नुकसान से टैक्स बेनीफिट हासिल करना चाहा तो आईआरएस की दलील थी कि वे हद से बाहर चले गए हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स और प्रोपब्लिका मीडिया की छानबीन के अनुसार ट्रम्प ने पहला राइट ऑफ 2008 के टैक्स रिटर्न में बताया। कारोबार में हुए खर्च को दर्शाकर टैक्स राइट ऑफ हासिल करते हैं। उन्होंने दावा किया कि अनुमान से बहुत कम बिक्री और आय की वजह से कोण्डो-होटल टॉवर में उनके निवेश का कोई मूल्य नहीं रहा। प्रोजेक्ट पर कर्ज का अर्थ है कि उन्हें कभी मुनाफा नहीं होगा। ट्रम्प ने वर्ष के लिए 5,438 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया था।

2010 में ट्रम्प और उनके टैक्स सलाहकारों ने शिकागो प्रोजेक्ट से और फायदा उठाने की कोशिश की। इस जोड़तोड़ की ओर आईआरएस का ध्यान गया। उन्होंने पहले टॉवर की ओनर कंपनी को नई पार्टनरशिप में बदल दिया। वे दोनों कंपनियों के मालिक थे। उसके बाद उन्होंने अगले दशक में 1400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त घाटा दिखा दिया। ट्रम्प जब राष्ट्रपति थे तब आईआरएस ने जांच शुरू करने से पहले मामले की कानूनी समीक्षा की थी। आईआरएस की जांच से सामने आया है कि ट्रम्प को 835 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स, ब्याज और जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।

घाटे के ट्रम्प टॉवर में 100 अपार्टमेंट भी नहीं बिके

ट्रम्प ने 6,400 करोड़ रुपए का कर्ज दो बैंक से लिया था। होटल के 100 से अधिक अपार्टमेंट कभी नहीं बिके। सभी यूनिटों की बिक्री से केवल छह हजार करोड़ रुपए मिले। यह ट्रम्प की लागत (7200 करोड़ रु.) से कम था। लगभग 70 हजार वर्गफुट रिटेल स्पेस खाली रहा। ट्रम्प ने 2011 से 2020 के बीच 1,400 करोड़ रुपए का घाटा दर्शाया।

© The New York Times

कल्पमेधा

गुरु की निष्ठा और ग्रंथ की निष्ठा जब अभिमान, आवेश और उन्माद का रूप ले लेती है, तो उसमें से आक्रामक संप्रदायवाद पैदा होता है।

– दादा धर्माधिकारी

आरोपों का अखाड़ा

महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में एक बार फिर इंसाफ की उम्मीद जगी है। दिल्ली की एक अदालत ने कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूतों के आधार पर आरोप तय कर दिए हैं। छह में से पांच महिला पहलवानों के आरोपों को सही माना है। इस तरह अब बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले वर्ष जनवरी में महिला पहलवान बृजभूषण शरण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गई थीं। मगर तब पुलिस मामले को टालती रही। जब सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, तब मुकदमा दर्ज किया गया। फिर भी जांच को लेकर टालमटोल का रवैया बना रहा। अदालत ने फिर फटकार लगाई, तो जांच शुरू हुई। पिछले वर्ष जून में दिल्ली पुलिस ने पंद्रह सौ पन्नों का आरोपपत्र दायर किया। उसमें महिला पहलवानों की तरफ से लगाए गए ज्यादातर आरोप सही पाए गए थे। पुलिस ने बृजभूषण शरण के खिलाफ यौन उत्पीड़न, पीछा करने, धमकाने और महिला गरिमा को आहत करने के लिए मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी। हालांकि उस पर पहली ही सुनवाई में अदालत ने मामले को एमपी-एमएलए अदालत में भेज दिया था।

इस मामले में सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया, जिससे जाहिर हो कि वह महिला पहलवानों के पक्ष में है। पिछले वर्ष केंद्रीय खेलमंत्री ने महिला पहलवानों को न्याय दिलाने का भरोसा देते हुए एक जांच समिति गठित कर दी थी। मगर वह समिति चुप्पी साध कर बैठ गई। इससे नाराज पहलवान दुबारा धरने पर बैठ गईं। फिर उन्हें तरह-तरह से आंदोलन वापस लेने को विवश किया जाता रहा। जब आंदोलन कुछ उग्र होता दिखा तो पुलिस ने दमन का रास्ता अख्तियार किया और पहलवानों को धरना स्थल से उखाड़ फेंका था। उसके बाद महिला पहलवानों का हौसला जैसे पस्त पड़ गया। उन्होंने अपने पदक गंगा में बहाने की कोशिश की, फिर उन्हें प्रधानमंत्री निवास के बाहर रख आए। फिर भी बृजभूषण शरण सिंह पर कोई शिकंजा कसता नजर नहीं आया। वे बेखौफ घूमते रहे। विचित्र है कि जिन धाराओं में उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया, उनके तहत अगर कोई सामान्य नागरिक होता, तो उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया होता। मगर बृजभूषण शरण न केवल बाहर घूमते रहे, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी भी करते रहे। आखिरी वक्त तक लोकसभा चुनाव का टिकट हासिल करने की दौड़ में शामिल थे। हालांकि पार्टी ने उनकी जगह उनके बेटे को प्रत्याशी बना दिया।

जिन महिला खिलाड़ियों ने बृजभूषण के खिलाफ आवाज उठाई थी, वे अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता हैं। वे अच्छी तरह जानती थीं कि उनके इस कदम का उन्हें क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कुश्ती महासंघ को साफ-सुथरा बनाने के लिए एक तरह से अपना पूरा खेल जीवन दांव पर लगा दिया। मगर उन्हें इंसाफ दिलाने के बजाय सारा सरकारी तंत्र आरोपी के पक्ष में खड़ा नजर आया। जांच में जानबूझ कर देर की गई। अब अदालत के ताजा रुख से फिर उम्मीद बनी है कि इंसाफ हो सकता है। जब यौन उत्पीड़न के खिलाफ ऐसे नामचीन खिलाड़ियों की गुहार पर सुनवाई की प्रक्रिया में इतनी देर लग सकती है, जिनके साथ पूरे देश की भावना जुड़ी हुई है, तो सामान्य महिलाओं की दबंग लोगों के खिलाफ शिकायतों का निपटारा भला कहां तक और किस रूप में हो पाता होगा, समझना मुश्किल नहीं है।

बुजुर्गों की सेहत

अगर बुजुर्गों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा किन्हीं वजहों से अपना इलाज नहीं करा पाता, तो यह समाज और व्यवस्था की एक बड़ी नाकामी है। गौरतलब है कि एक गैरसरकारी संगठन के अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है कि शहरी इलाकों के लगभग पचास फीसद बुजुर्ग आर्थिक मुश्किलों और कई अन्य तरह की चुनौतियों के चलते जरूरत के वक्त चिकित्सकों के पास नहीं जा पाते हैं। ग्रामीण इलाकों में यह समस्या ज्यादा व्यापक है। वहां बुजुर्ग आबादी के बासठ फीसद से ज्यादा के सामने आर्थिक और अन्य बाधाएं खड़ी हैं, जिनके चलते उन्हें बीमारी में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर साठ वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति को सेवानिवृत्ति की वजह से आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जबकि इसी उम्र में उन्हें सेहत संबंधी देखभाल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हों तो उनका जीवन कुछ आसान हो सकता है। मगर कई बार पारिवारिक उपेक्षा के शिकार बुजुर्गों को सरकार की ओर से भी सामाजिक सुरक्षा के रूप में कोई विशेष सुविधा नहीं मिल पाती है। वहीं देश के कई इलाकों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और आर्थिक स्थिति से जुड़ी समस्याएं जगजाहिर रही हैं।

यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि आज वृद्धावस्था में पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा के अभाव में दैनिक खर्च और स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च में भारी उछाल आया है। इसके अलावा, स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में ज्यादा उम्र वालों के लिए अब तक जो शर्तें रही हैं, वे स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच को मुश्किल बनाती हैं। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि किसी वृद्ध व्यक्ति के बीमार पड़ने पर उचित इलाज न मिल पाने से उसकी जान चली गई। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आमतौर पर हर बुजुर्ग अपने बाद की उस पीढ़ी को बेहतर जीवन देने के लिए अपनी जिंदगी झोंक देता है, जो अपने परिवार साथ-साथ समाज और देश के लिए एक उपयोगी संसाधन बनता है। सवाल है कि बुजुर्गों की अपनी संतानें और सत्ता-तंत्र उसके स्वास्थ्य और संतोषजनक जीवन के लिए उचित व्यवस्था करने के प्रति उदासीन क्यों रहता है।

कचरा निपटान की बढ़ती चुनौतियां

इस समय दुनिया में प्रतिवर्ष 201 करोड़ टन से ज्यादा ठोस कचरा पैदा हो रहा है। अनुमान है कि वर्ष 2050 तक ठोस कचरे का कुल उत्पादन बढ़कर 340 करोड़ टन तक पहुंच सकता है, जो दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन सकता है।

अमित बैजनाथ गर्ग

भारत दुनिया में कचरा पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश है, जहां हर साल करीब तीस करोड़ टन से भी ज्यादा ठोस कचरा पैदा हो रहा है, लेकिन हम इसका साठ फीसद ही निस्तारित कर पाते हैं। बाकी यह इधर-उधर पड़ा रह कर पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। यह कचरा जल, वायु और भूतल प्रदूषण का कारण बन रहा है। देश में 75 फीसद से ज्यादा कचरा खुले में डाल दिया जाता है। विश्व बैंक की रपट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा कचरा उत्पन्न होता है। इस मामले में दिल्ली ने मुंबई, बंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों को काफी पीछे छोड़ दिया है। इन शहरों में इलेक्ट्रानिक, प्लास्टिक जैसे कचरे को अलग-अलग करने और सही ढंग से पुनर्चक्रित करने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इन शहरों के कचरा भराव भर चुके हैं।

इस समय दुनिया में प्रतिवर्ष 201 करोड़ टन से ज्यादा ठोस कचरा पैदा हो रहा है। अनुमान है कि वर्ष 2050 तक ठोस कचरे का कुल उत्पादन बढ़कर 340 करोड़ टन तक पहुंच सकता है, जो दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन सकता है। हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञों की राय है कि अगर ठोस कचरे का सही तरीके से निस्तारण हो तो यह एक नए विकसित उद्योग की जगह ले सकता और रोजगार उपलब्ध कराने का एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है।

वर्ष 2009 में भारत के शहर प्रतिदिन अस्सी हजार मीट्रिक टन कचरे का उत्पादन कर रहे थे। अनुमान है कि 2047 तक भारत एक वर्ष में 26 करोड़ टन कचरे का उत्पादन करेगा, जिसका निपटान करने के लिए करीब चौदह हजार वर्ग मीटर भराव क्षेत्र की आवश्यकता होगी। यह क्षेत्र हैदराबाद, मुंबई और चेन्नई के संयुक्त क्षेत्रफल के बराबर होगा। वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नगर निगमों द्वारा निजी ठेकेदारों को जो ठेके दिए जाते हैं, उनमें ठेका लेने वालों को ज्यादा से ज्यादा कचरा लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठेके में शुल्क का भुगतान कचरा ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही के अनुसार मिलता है। जितना ज्यादा कचरा लाएंगे, उतना ज्यादा शुल्क मिलेगा। भूमि की लागत और इसकी उपलब्धता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

कई देशों में कचरे के निपटान के लिए पूर्व व्यवस्था को बदला गया है। स्वीडन और अमेरिका में भराव क्षेत्र में कचरा फेंकने के लिए भारी प्रवेश शुल्क वसूला जाता है। 2013 में स्वीडन में कचरा फेंकने के लिए औसतन 212 डालर प्रति टन वसूला जाता था, जबकि इसकी तुलना में अमेरिका में 150 डालर प्रति टन वसूला जाता था। गौरतलब है कि भारत में शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग साफ-सफाई के आधार पर दी जाती है। रैंकिंग में कई वर्ष से इंदौर देश का सबसे साफ शहर बना हुआ है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ठोस कचरे के उचित निपटान में विफलता प्रदूषण बढ़ाती है। इससे कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, वेक्टर-जनित बीमारियों का प्रकोप, हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, भूजल का प्रदूषण, परिवहन के दौरान ध्वनि और सूक्ष्म

धूल। बढ़ती आबादी, शहरीकरण और बढ़ती प्रौद्योगिकी ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के कुछ कारण हैं। ठोस अपशिष्ट से जुड़ी इन समस्याओं से निपटने के लिए ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण सबसे अच्छा तरीका है। वहीं कचरे को सूखे और गीले कचरे के रूप में अलग करना, घर-घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करना और छंटाई के बाद इसे प्रसंस्करण के लिए भेजना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं।

> ठोस अपशिष्ट प्रबंधन चर्चा में इसलिए भी है कि लगभग सभी देश बढ़ते कचरे के कुशलतापूर्वक निपटान की चुनौती का सामना कर रहे हैं। असल में ठोस अपशिष्ट के निपटान की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। सरकारों की ओर से संचालित कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कूड़े-करकट से अधिकतम मात्रा में उपयोगी संसाधन प्राप्त करना और ऊर्जा का उत्पादन करना है, ताकि कम से कम मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों को भराव क्षेत्र में फेंकना पड़े। भराव में फेंके जाने वाले कूड़े का भारी खमियाजा भुगतना पड़ रहा है।

कचरे पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 2016 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली लागू की थी। इसके मुताबिक भराव क्षेत्र का इस्तेमाल केवल ऐसे कचरे के लिए किया जाएगा, जिसका दुबारा उपयोग न किया जा सके, जैविक रूप से नष्ट होने योग्य न हो, जो ज्वलनशील न हो तथा रासायनिक प्रतिक्रिया न करता हो। नियमावली में यह भी कहा गया है कि भराव क्षेत्र से कचरा समाप्त करने के लिए कचरे के पुनः उपयोग या उसे नवीकृत करने के प्रयास किए जाएंगे। यह भराव क्षेत्र की आवश्यकता पर जोर देने की पुरानी नीति को हटाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। भराव क्षेत्र के इस्तेमाल को न्यूनतम करने के लिए भराव क्षेत्र कर लगाएं, अपशिष्ट कचरे के निपटान के लिए साफ-सुथरे भराव क्षेत्र बनाए जाएं, ताकि प्रदूषण कम हो। नवनिर्मित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का लक्ष्य कचरा मुक्त भराव क्षेत्र सुनिश्चित करना होना चाहिए।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन चर्चा में इसलिए भी है कि लगभग सभी देश बढ़ते कचरे के कुशलतापूर्वक निपटान की चुनौती का सामना कर रहे हैं। असल में ठोस अपशिष्ट के निपटान की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। सरकारों की ओर से संचालित कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कूड़े-करकट से अधिकतम मात्रा में उपयोगी संसाधन प्राप्त करना और ऊर्जा का उत्पादन करना है, ताकि कम से कम मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों को भराव क्षेत्र में फेंकना पड़े। भराव में फेंके जाने वाले कूड़े का भारी खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक तो इसके लिए काफी जमीन की आवश्यकता होती है, जो लगातार कम होती जा रही है और दूसरा, कूड़ा वायु, मिट्टी और जल-प्रदूषण का संभावित कारण भी है।

कचरे के पुनर्चक्रण के मामले में जर्मनी सबसे बेहतर काम कर रहा है, जो अपने 56 फीसद कचरे का पुनर्चक्रण करता है। इसके बाद आस्ट्रिया 53 फीसद, दक्षिण कोरिया 53 फीसद, वेल्स 52 फीसद और स्विट्जरलैंड 49 फीसद पुनर्चक्रित करता है। इस मामले में स्वीडन, नार्वे और सिंगापुर भी अच्छा काम कर रहे हैं। भारत में भी पुनर्चक्रण धीरे-धीरे एक उद्योग का रूप ले रहा है। अहमदाबाद और त्रिवेंद्रम अपने यहां के कुल कचरे का बड़ा भाग पुनर्चक्रित कर रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र को एक स्थायी उद्योग का रूप देने के लिए बेहतर तकनीकी और आर्थिक मदद की आवश्यकता है।

एक अनुमान के अनुसार, भवन निर्माण क्षेत्र में भारी कचरा पैदा होता है। पुराने भवन को तोड़ने के बाद निकलने वाली सामग्री बड़ी समस्या बन गई है। हालांकि आज कंपनियां इस कचरे के 75 फीसद से ज्यादा को रिसाइकिल कर रही हैं। इस कचरे से ईंटें, प्लास्टिक और कई अन्य ठोस पदार्थ बनाए जा रहे हैं। प्लास्टिक कचरा एक बड़ी समस्या है। इस कचरे का कम से कम उत्पादन ही दुनिया को कचरे से मुक्ति दिलाने में मदद कर सकता है। इस संदर्भ में विशेषज्ञ चार 'आर' का सिद्धांत अपनाने की बात करते हैं। इसमें पहले 'आर' का अर्थ 'रिफ्यूज' यानी प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग न करना, दूसरे 'आर' का अर्थ 'रिड्यूस' यानी प्लास्टिक पदार्थों का कम से कम उपयोग करना, तीसरे का अर्थ 'रीयूज' यानी नए के बजाय पुराने प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग करना और अंत में 'रिसाइकिल' यानी पुराने प्लास्टिक पदार्थों का पुनर्चक्रण कर दुबारा उपयोग करना है। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर हम कचरे की समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

पहचान का संकट

पूजा खिल्लन

सच्ची शिक्षा, कला और ज्ञान मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं। ये हमें एक-दूसरे के निकट ले जाते हैं। हमारी संस्कृति का मूल भी यही है- एक-दूसरे तक पहुंचना। मगर आज हम एक-दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। दरअसल, जहां हमें पहुंचना था, वहां हमसे पहले बाजार पहुंच रहा है। बाजार हमारे घर तक आ पहुंचा है और हम निरुपाय, ठगे से चुपचाप यह तमाशा देख रहे हैं। बाजार ने मनुष्य की पहचान खरीदार के रूप में की है। इसने मनुष्य की परिभाषा ही बदलकर रख दी है। कल तक मनुष्य की पहचान उसके संस्कार और गुण देखकर की जाती थी, आज उसका धन देखकर की जाती है। बाजार इस सोच से चलता है कि जिसकी जेब में पैसा है वह मनुष्य है, बाकी सब गौण हैं। हमारी संस्कृति कहती है 'वसुधैव कुटुम्बकम', यानी विश्व एक परिवार है और हम चाहे किसी भी जाति, धर्म या व्यवसाय के हों, इसके सदस्य हैं। वहीं बाजार और तकनीक का कहना है कि संसार एक 'ग्लोबल विलेज' है, मगर व्यवसाय की दृष्टि से। हम घर बैठे कहीं से भी एक-दूसरे से संपर्क साध सकते हैं और वह भी मिनटों में। सवाल यह भी है कि इतने संपर्क और साधनों में मनुष्य अपने संबंधों और नातों में अकेला क्यों होता जा रहा है?

पिछले दिनों एक खबर आई थी कि एक महिला ने अपनी इमारत की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी। उसका मानसिक इलाज चल रहा था, पति विदेश में रहता था। इस तरह की दूरी जो हम संबंधों में महसूस कर रहे हैं, पहले नहीं थी। लोग थोड़े से भी संतुष्ट थे और जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ बना रहता था या किसी भी विपत्ति और संकट में मनुष्य अकेला और असहाय नहीं था। आज यह सीख मिल रही है कि ऊंचे-ऊंचे लक्ष्यों को साधें, बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में ऊंचे वेतन पर काम करें। लेकिन इससे जो तनाव युवाओं के जीवन में पैदा हो रहा है वह आज की सबसे बड़ी चुनौती है। काम के दबाव के चलते हमारे बच्चे मशीन में तब्दील हो चुके हैं। वे अपने सोचने-समझने की शक्ति खो रहे हैं और अंत में इतना एकाकी महसूस करने लगते हैं कि कई बार आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है। कुछ समय पहले एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में ऊंचे वेतन पर काम कर रहे युवक ने मरणोपरांत छोड़े गए अपने नोट में लिखा कि वह संबंधों में नितांत अकेला महसूस कर रहा था। क्या उसके द्वारा कमाई गई करोड़ों की दौलत उसका जीवन बचा पाई?

दरअसल, जीवन जीने के लिए करोड़ों की संपत्ति नहीं, बल्कि रिश्तों में आपसी सद्भाव, प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के प्रति सम्मान और अपनी परेशानी और दुख को साझा करने के लिए रिश्तों में उचित जगह का होना, ये सारी चीजें ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं। आज हमारे पास जानने वाले की संख्या बहुत है, पर हमें पहचानने वाला अपना कोई नहीं। इस मायावी और कृत्रिम दुनिया को देखकर यही बिम्ब उभरता है कि जैसे एक समुद्र है, जिसमें पानी ही पानी है, मगर उसे प्यास नहीं बुझाई जा सकती।

गलत तरीकों से और प्रकृति का दोहन करके कमाई गई दौलत हमें विनाश की ओर धकेल रही है। जिस समय आजादी प्राप्त करने का बड़ा और ऊंचा लक्ष्य हमारे सामने था, उस समय भी गांधीजी ने शस्त्र नहीं उठाया। अहिंसा और मार्ग की शुद्धता पर बल दिया। चूंकि वे चाहते थे आजादी हमें हमारी शर्तों पर मिले। मगर आज जिसे हम आजादी मानकर धन-दौलत की प्रदर्शन प्रियता पर बल दे रहे है, वह हमें अपने आप से दूर कर रहा है। शक्ति, बल, धन के आडंबर में फंसकर हम अपनी सरलता और सहजता का सौदा कर रहे हैं। जबकि इस देश की सच्ची पहचान इसकी आत्मा की पहचान में निहित है जो इस देश के किसानों, छोटे-छोटे व्यवसाय चलाने वाले कुशल कारीगरों और महापुरुषों द्वारा निर्मित की गई है। फिर भी हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें अपनी पीढ़ी को क्या देना है, उससे क्या बनाने की हमें अपेक्षा है।

सवाल है कि क्या हम इस देश को ऐसे धन्ना सेठ देना चाहते हैं जो हमारा ही धन हमें भीख की तरह लौटाएं और हम सब कुछ छोड़ उनके गुणगान में लिप्त रहें या फिर गांधी, गोखले भगत सिंह जैसे आदर्श, जिन्होंने चिंतन के बल पर इस देश के चरित्र को बनाने में अपना योगदान दिया। हमारे यहां 'अन्य' या 'दूसरा' कोई नहीं, सब अपने हैं। हमें पृथ्वी के लिए आंसुओं को सहेजना है। उसके लिए जगह बचानी है। जबकि हमें बिना गमगीन हुए कृत्रिम तौर पर 'हैप्पी' रहने का पाठ सिखाया जा रहा है और हम अपने बच्चों से यह कह रहे हैं कि कठोर बनो, क्योंकि हंसने वाले के साथ सब हंसते हैं, रोने वाले के साथ कोई नहीं रोता। ऐसा कहते वक्त हम कबीर को बिसार देते हैं, जो कहते हैं- 'सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए।' जो संवेदनशील होगा, वह सोचेगा। जो सोचेगा, उसे आज के संसार पर रोना आएगा। उसकी दशा पर रोना आएगा। पर हम कृत्रिम सुख का लबादा ओढ़कर सुखी होने का ढोंग करना चाहते हैं, जो हमें हमारी पीढ़ी से दूर कर रहा है और हम उसके वास्तविक दुख को नहीं पहचान रहे हैं।

दुनिया मेरे आगे

> जीवन जीने के लिए करोड़ों की संपत्ति नहीं, बल्कि रिश्तों में आपसी सद्भाव, प्रेम, विश्वास और एक-दूसरे के प्रति सम्मान और अपनी परेशानी और दुख को साझा करने के लिए रिश्तों में उचित जगह का होना, ये सारी चीजें ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं। आज हमारे पास जानने वालों की संख्या बहुत है, पर हमें पहचानने वाला अपना कोई नहीं।

समय की महिमा

समय को इस सृष्टि की सबसे अनुपम और बलवती वस्तु माना गया है। जब समय यानी वक्त बदलता है तो इंसान को राजा से रंक और रंक से राजा बना देता है। इसके कहर से बड़े-बड़े राजा-महाराजा तक घबराते हैं। कहा जाता है कि समय एक अच्छा चिकित्सक भी है। यह बड़े से बड़े घाव को भरने में सक्षम है। समय सभी चीजों और स्थितियों को नियंत्रित करता है। समय कुछ भी बदल सकता है, पर किसी के लिए कभी रुकता नहीं है। कहते हैं, 'आदमी अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उसका समय अच्छा और बुरा होता है।' जब समय अच्छा चल रहा होता है तो सब काम अपने आप अच्छे हो जाते है, लेकिन खराब समय शुरू होने के बाद बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। समय को एक अच्छा अध्यापक भी माना गया है। स्कूल में हमें सीखने के बाद परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन समय हमारी पहले परीक्षा लेता है और फिर सिखाता है। यानी समय महाबली है और वह 'उचित-अनुचित' की पूरी खबर रखता तथा समय आने पर 'काल के कठघरे' में सब को खड़ा कर देता है। अज्ञानी लोग काल की इस चाल को समझते नहीं हैं। जिस दिन समझने लगेंगे, उस दिन से कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे।

– शिबन कृष्ण रैणा, अलवर

भ्रष्टाचार का सिरा

लंबे समय से देश में काले धन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय जांच एजंसियां लगातार सक्रिय हैं। मगर तमाम कोशिशों और कवायदों के बाद भी इस समस्या से पार पाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ अभियान चलाते हुए वर्तमान सरकार को लगभग दस बरस का समय बीत चुका है, फिर भी इस मामले में कोई उल्लेखनीय प्रगति दिखाई नहीं देती। आखिर क्या वजह है कि हर छोटे से अंतराल के बाद जब किसी संदिग्ध नेता, अधिकारी या व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी की जाती है तो वहां से अथाह नगदी और कालाधन बरामद किया जाता है। सख्त कदम और कठोर कार्रवाई सिर्फ कहने के लिए है। हर पांच वर्ष में नई सरकार का गठन होता है। लोक-लुभावन दावे और वादे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ केवल एक सुनहरा सपना भर होता है।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

बदलती शर्तें

आस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में पढ़ाई का सपना लेकर जा रहे भारतीय विद्यार्थियों के साथ कुछ विदेशी सरकारों के सख्त मानदंड अपनाने से विद्यार्थी के समक्ष बड़ी मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। 'शिक्षा की राह' (संपादकीय, 8 मई) में उचित विश्लेषण किया गया है। यह समझना मुश्किल नहीं है कि आस्ट्रेलिया ने किन कारणों से वार्षिक प्रवासन की संख्या घटकर आधी कर दी। ऐसे बड़े बदलावों से अच्छी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को दाखिला मिलने और नौकरी करने में भी मुश्किलें हो रही है। आस्ट्रेलिया और कनाडा आदि देशों से अच्छा वातावरण, सुविधा और प्रवेश प्रक्रिया आदि में भारतीय सरकार क्यों सुधार नहीं करती? भारतीय छात्र इस तरह विदेश की ओर कब तक टकटकी लगाए बैठे रहेंगे? सरकार को इस फैसले के संदर्भ में कूटनयिक स्तर पर भी कुछ प्रयास करने चाहिए, ताकि भारत से उच्च शिक्षा के लिए कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि देशों में जाने वाले विद्यार्थियों के सामने ज्यादा मुश्किल न हो।

– बीएल शर्मा 'अकिंचन', उज्जैन

पहाड़ में यातायात

गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। अब बहुत से दूसरे राज्यों और विदेश से लोग हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू-मनाली और अन्य क्षेत्रों का रुख करेंगे और इन ठंडी वादियों का लुत्फ लेंगे, लेकिन इन क्षेत्रों में पर्यटकों को यातायात समस्या से भी जूझना पड़ता है। इस बार तो लोकसभा चुनाव का भी समय है, इसके लिए चुनावी रैलियां भी होंगी। इस कारण यातायात समस्या ओर भी विकराल हो सकती है। हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर वाहनों की भीड़ सड़क हादसों के साथ समस्या को विकराल करती जा रही है। प्रदेश के बहुत से पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल ऐसे भी हैं, जो इक्कीसवीं सदी में भी सरकारों के यहां तक रेल लाइनों के विस्तार के प्रति उदासीन रवैए के कारण रेलवे सुविधा से वंचित हैं, जिस कारण पर्यटक और श्रद्धालु सड़क मार्ग से ही आते हैं।

– राजेश कुमार चौहान, जलंधर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

नई दिल्ली

www.readwhere.com

हरियाणा में संकट
समाधान की प्रतीक्षा

हरियाणा में राजनीतिक संकट जारी है और इसके समाधान की प्रतीक्षा है। हरियाणा के राजनीतिक क्षेत्रों में उठापटक की हालिया घटनाओं ने एक बार फिर गठबंधन राजनीति की समस्यायें उजागर कर दी हैं। राज्य की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाने वाली जननायक जनता पार्टी-जेजेपी ने कांग्रेस के साथ जाने का निर्णय किया है। उसने हरियाणा विधानसभा में भाजपा-नीत सरकार के बहुमत परीक्षण की मांग की है। इसके पहले तीन निर्दलीय विधायकों ने सत्तारूढ़ गठबंधन से समर्थन वापस ले लिया था, इससे 90 विधायकों वाले सदन में 44 विधायकों के साथ सरकार अल्पमत में आ गई थी। कांग्रेस नवीनतम घटनाक्रम से प्रसन्न है और इसे वह अपने पक्ष में एक अवसर की तरह देख रही है। वह भाजपा सरकार पर दबाव डाल रही है। लेकिन इस राजनीतिक उठापटक के पीछे जेजेपी अपने आंतरिक असंतोष से परेशान है। खबरें हैं कि उसके तीन विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री एम.एल. खट्टर से गोपनीय मुलाकात की है। इससे संभावित पालाबदल की आशंका पैदा हो गई है। जेजेपी में वर्तमान असंतोष के पीछे विधायकों के हितों और आकांक्षाओं का टकराव है जो अक्सर गठबंधन राजनीति में सामने आता है। पिछले विधानसभा चुनाव में 'त्रिशंकु' जनादेश से जेजेपी एक प्रमुख पक्ष के रूप में उभरी थी। लेकिन उसके लिए अपनी कतारों में एकजुटता और गठबंधन साझीदारों की मांगों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं था। अतीत पर नजर डालने से पता लगेगा कि हरियाणा में ही 'आया राम गया राम' संस्कृति का विकास हुआ था जो अब भी जारी है। इस आंतरिक टकराव का असर न केवल हरियाणा की तात्कालिक राजनीति पर पड़ेगा, बल्कि इसके राज्य के भविष्य पर भी दूरगामी प्रभाव होंगे।

गठबंधन में परिवर्तन तथा संबंध बदलने की स्थिति में केवल सत्ता प्राप्ति की इच्छा ही स्थाई होती है। इससे प्रतियोगिता में एक कदम आगे रहना मजबूरी हो जाता है। 90 सदस्यों के सदन में किसी राजनीतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त करने और सरकार बनाने के लिए 46 विधायकों का समर्थन चाहिए। तीन निर्दलीयों की समर्थन वापसी के बाद भाजपा के पास सरकार में बने रहने के लिए दो विधायकों की कमी हो गई है। भाजपा के पास अब 40 विधायक हैं तथा उसे हरियाणा लोकहित पार्टी के एक विधायक व कम से कम तीन निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जबकि पहले उसे 6 निर्दलीयों का समर्थन प्राप्त था। इस प्रकार सदन में उसकी कुल संख्या 44 रह गई है। भाजपा के लिए दुहरा संकट है क्योंकि यह सब लोकसभा चुनाव के पहले हो रहा है जब हरियाणा की 10 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 35 प्रतिशत मतों के साथ राज्य की 7 सीटों पर विजय मिली थी। 2019 में 58 प्रतिशत वोटों के साथ भाजपा राज्य की सभी दस सीटें जीतने में सफल हुई थी। हालांकि, वर्तमान समय में उसके लिए यह स्थिति बनाए रखना कठिन हो सकता है। जननायक जनता पार्टी-जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने भाजपा की नायब सिंह सैनी सरकार पर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए दबाव डाला है। उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष विश्वास मत परीक्षण की अनुमति दे देंगे। ऐसे में यदि जेजेपी में विभाजन हो जाता है तो भाजपा को अपनी सरकार बनाए रखने में सफलता मिल जाएगी। हालांकि, अभी विश्वास मत व उसके भावी परिणामों की प्रतीक्षा करनी होगी, पर इतना तो निश्चित है कि हरियाणा में राजनीतिक उठापटक और पालाबदल का दौर तेज होने वाला है।

उन्नत कृषि से खाद्य सुरक्षा

भारतीय कृषि का भविष्य परंपरा और खोज में समन्वय पर आधारित है। उन्नत कृषि 1.7 बिलियन लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।

पराग आचार्य
(लेखक, कृषि वैज्ञानिक हैं)

भारत की जनसंख्या 2050 तक लगभग 1.7 बिलियन होने की आशा है। ऐसे में भारतीय कृषि के लिए खासकर जलवायु परिवर्तन में जारी बदलावों को देखते हुए इतनी बड़ी जनसंख्या की खाद्य मांगें पूरी करना एक बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ ही इस क्षेत्र के समक्ष बुढ़ाते किसानों की भी समस्या है। युवा पीढ़ी लगातार परिवार की परंपरागत खेती से दूरी बना रही है। वह कृषि के बजाय अन्य ज्यादा आकर्षक और कम श्रम ववाले कॅरियर विकल्प अपना रही है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों, जैसे 'प्रिसीज़न फार्मिंग' या सटीक खेती तथा 'डिजिटल स्मार्ट एग्रीकल्चर' का महत्व बढ़ता जा रहा है। यह टिकाऊ खाद्यान्न उत्पादन तथा भारतीय कृषि से भावी समृद्धि के लिए आवश्यक है। हाल ही में एक संसदीय समिति ने कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने की पैरवी की है।

यह खासकर छोटे व सीमान्त किसानों के लिए जरूरी है। इसमें छोटे रोबोटों तथा कृत्रिम बुद्धि-एआई के समन्वय से टुकड़ों-टुकड़ों में बंटे खेतों के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का सामना करने की संभावना है। इसके साथ ही समिति ने 'नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चर रोबोटिक्स एंड आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस' स्थापना की संस्तुति की है ताकि भारत का घरेलू व अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर कृषि विकास में अग्रणी स्थान सुनिश्चित किया जा सके। 23 अगस्त, 2022 को कृषि मशीनीकरण के संबंध में कृषि शोध एवं शिक्षा विभाग के सचिव ने खुलासा किया कि भारत में मशीनीकरण का स्तर 47 प्रतिशत है। इस प्रकार वह 59.5 प्रतिशत मशीनीकरण वाले चीन, 75 प्रतिशत मशीनीकरण वाले ब्राजील तथा 95 प्रतिशत मशीनीकरण वाले अमेरिका से पीछे है। भारत में भी विभिन्न क्षेत्रों में मशीनीकरण के स्तर में व्यापक भिन्नता है।

उत्तरी राज्यों में यह स्तर 70-80 प्रतिशत है जिसका कारण उपजाऊ जमीन, श्रमिकों की कमी तथा राज्य का समर्थन है। इसके उलट दक्षिणी व पूर्वी राज्यों में जमीन के टुकड़ों में बंटे होने के कारण यह 35-45 प्रतिशत है। पूर्वोत्तर राज्य दुर्गम इलाकों, उपकरणों की लागत तथा सामाजिक-आर्थिक कारणों का सामना कर रहे हैं।

निश्चित रूप से कृषि का लगातार विकास हुआ है और यह परंपरागत व श्रम-बहुल माडल के बजाय अब संवेदनशील, तकनीक-संचालित व्यवस्था में बदल रही है। इसमें कृषि शोध एवं शिक्षा विभाग-डेयर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-आईसीएआर तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों-केवीके का महत्वपूर्ण योगदान है। अधिक पैदावार, लागत प्रभावी, रोग व कीटनाशक प्रतिरोधी तथा जलवायु-प्रतिरोधी किस्मों के विकास तथा तकनीकी प्रगति से फसलों, बागवानी, पशुपालन व मत्स्यपालन क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुआ है। आईसीएआर द्वारा विकसित वैज्ञानिक तकनीकों ने उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन इस प्रगति को स्वीकार करते हुए भी यह मानना जरूरी है कि प्रगति की गति हमारे बदलते समय के अनुकूल होनी चाहिए।

ऐतिहासिक रूप से लोग काम करने के लिए आसान, तेज व ज्यादा बेहतर तरीके खोजते रहे हैं। इस खोज ने एक तकनीकी क्रांति को जन्म दिया जिसने सदियों पुराने कृषि व्यवहारों को अद्यतन तकनीकों, जैसे 'इंटरनेट आफ थिंग्स'-आईओटी से जोड़ दिया है जिसे एजी-आईओटी कहा जाता है। इससे कृषि में व्यापक परिवर्तन आया है और फसलें उगाने, उनके प्रबंधन तथा खाद्य संरक्षण के तरीके पूरी तरह बदल गए हैं। इन समाधानों का संबंध केवल क्षमता से न होकर किसानों के सशक्तीकरण से भी है ताकि वे अपने दैनिक कार्यों में क्षमता, उत्पादकता व सटीकता पर ज्यादा समय दे सकें। इसका अर्थ एक प्रकार का 'सुपर स्मार्ट असिस्टेंट' प्राप्त करना है जो भूमि, पशुओं, फसलों और खेतों की देखभाल कर सके तथा सभी कामों के लिए मनुष्यों की जरूरत न पड़े। लोग इसे सटीक खेती, स्मार्ट खेती या डिजिटल खेती कहते हैं। यह कृषि में बड़ा कदम है क्योंकि यह निर्णय लेने में डेटा का प्रयोग करता है तथा सभी चीजों को ज्यादा सक्षम एवं उत्पादक बना देता है। एजी-आईओटी के माध्यम से पौधों व पशुओं की नब्ज पहचानी जा सकती है। किसान इससे पूरे समय अपनी मृदा पर नजर रख सकते हैं, सिंचाई व्यवस्थाओं पर दूर से नियंत्रण कर सकते हैं तथा दूर से ही अपने पशुओं के स्वास्थ्य पर नजर रख सकते हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि फसलों से कितना उत्पादन होगा। इस प्रकार एजी-आईओटी फसल प्रबंधन, कीट एवं रोग नियंत्रण, खाद्यान्नों के भंडारण, मवेशियों की देखभाल, रोगों पर निगरानी, डेरी गतिविधियों, सप्लाई श्रृंखला लाजिस्टिक्स तथा इससे आगे अन्य चीजों पर नियंत्रण रखा जा सकता है।

ड्रोन तकनीक के विकास ने फसलों के आंकलन और निगरानी में असीम संभावनायें खोली हैं। ऐसी ही एक उल्लेखनीय पहल 'नमो ड्रोन दीदी' है जिने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। एक महत्वपूर्ण संकेत देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा नई दिल्ली की पहल पर व्यक्तिगत रूप से पूरे देश में 10 स्थानों पर 1000 नमो ड्रोन दीदियों को 1000 से अधिक ड्रोन दिए हैं। इन ड्रोनों के माध्यम से फसलों पर नजर रखने तथा उर्वरक छिड़कने व बीज बोने में सहायता मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'ड्रोन दीदी' योजना 2023-24 की घोषणा से सरकार की तकनीक प्रयोग तथा समाज की बेहतरी के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट होती है। भारत सरकार ने 2020-21 और 2021-22 में राज्यों को 1756.3 करोड़ तथा 2422.7 करोड़ रुपयों का आबंटन अद्यतन कृषि तकनीकों के प्रयोग के लिए दिए हैं जिनमें ड्रोन, कृत्रिम बुद्धि, ब्लाकचेन, रिमोट सेंसिंग तथा जीआईएस शामिल हैं। इसी कालखंड में आईसीएआर को आरएंडडी के लिए 7302.50 करोड़ तथा 7908.18 करोड़ रुपये आबंटित किए गए इससे स्पष्ट होता है कि सरकार कृषि आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। 'रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन'-आरएफआईडी जैसी तकनीकी प्रगति तथा 'नेशनल लाइवस्टाक आइडेंटीफिकेशन स्कीम'-एनएलआईएस व 'इन्फार्मेशन नेटवर्क फार एनीमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ'-आईएनएपीएच जैसी योजनाओं के माध्यम से सटीक पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्विफ्ट एलेक्ट्रानिक स्कैनिंग तथा डेटा इंटीग्रेशन के माध्यम से किसान प्रभावी रूप से गायों के स्वास्थ्य, उत्पादकता व रिकार्ड पर नजर रख सकते हैं। इसे पशुपालन उद्योग में सटीकता और क्षमता संवर्धन होता है। इसी प्रकार मत्स्यपालन उद्योग में एक्वाकनेक्ट व श्रिंपबाक्स जैसी तकनीकें श्रिंप फार्मिंग में क्रांति ला रही है। इससे श्रिंप व मत्स्यपालन को छोटे व मझोले किसानों तक पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ ही तुलनात्मक रूप से ठंडे क्षेत्रों और चारों ओर भूमि से घिरे क्षेत्रों में इनकी उत्पादकता बढ़ाने में पानी के न्यूनतम प्रयोग तथा एंटीबायोटिक के न्यूनतम उपयोग की संभावनायें सामने आई हैं।

भारत में वर्ड इकोनोमिक फोरम के एआई फार एग्रीकल्चर इनोवेशन पहल से खेती में एआई के प्रयोग से क्राति आ रही है। बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने तेलंगाना के खम्माम जिले में 'सागू बागू' पायलट परियोजना शुरू की है। इस परियोजना से 7000 किसानों को लाभ हुआ है, मिर्च उत्पादन में 21 प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा कीटनाशक उपयोग में 9 प्रतिशत व उर्वरक प्रयोग में 5 प्रतिशत कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप किसानों की आय दूनी हुई है और एक फसल में उनको प्रति एकड़ 66,000 रुपये की आय हुई है। कुल मिला कर भारत में 175 फार्मों पर 175 एआई हस्तक्षेपों से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-आईसीएआर के अनुसार फसलों की उत्पादकता में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस प्रकार भारतीय कृषि का भविष्य परंपरा और खोजों के सम्मिश्रण पर निर्भर है। बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधनों को देखते हुए सटीक खेती 1.7 बिलियन लोगों को लगातार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। कृषि मशीनीकरण के लाभ हमारे देश के हर कोने तक पहुंचने चाहिए ताकि कृषि क्षेत्र में विभाजक रेखाओं को समाप्त कर समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके।

ऐसे में डिजिटल डिवाइड से प्रभावित छोटे किसानों पर खास ध्यान देना जरूरी है। भारतीय कृषि का भविष्य तकनीक केन्द्रित कृषि परिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर है जिसमें किसानों का सशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा भावी पीढ़ियों की खाद्य सुरक्षा समाहित है।

एक सफल व्यक्ति की विशेषताएं

"हमें ब्रह्मांड से ऐसे अवसर प्रदान करने के लिए कहने के लिए साहस और विनम्रता की आवश्यकता है, हम अपनी सभी सीमाओं को पीछे छोड़ दें।"

रवि वलूरी
(लेखक, रेलवे से जुड़े हैं)

हमारा एक हिस्सा ऐसा है जो हमें तब तक संतुष्ट नहीं होने देता जब तक हम वह सब नहीं बन जाते जो हम बनने में सक्षम हैं। जीवन हमारी पिछली उपलब्धियों और उपलब्धियों पर आराम करने और अपने आराम क्षेत्र में रहने के बारे में नहीं है। यह सामान्य से असाधारण बनने का साहसिक कार्य है। किसी की वर्तमान स्थिति अच्छी हो सकती है, लेकिन यदि कोई बड़ा अवसर सामने आता है, तो उसे विस्तार के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको भागना है या अपनी ईमानदारी का उल्लंघन करना है।

के वल उपयोग और स्ट्रेचिंग से ही मांसपेशियां मजबूत और लचीली रहती हैं और हमारा दिमाग भी ऐसा ही करता है। चुनौती ब्रह्मांड का मार्ग है और हमें रास्ता दिखाती है कि हम उतना ही बड़ा रूप और आकार धारण करते हैं। हमें उस अवसर की पहचान करने के लिए अपने सपनों और अपनी इच्छाओं को आशीर्वाद देना चाहिए जो छुपे हुए हैं क्योंकि कोने में कई संभावनाएं उत्पन्न होंगी। हमें ब्रह्मांड से ऐसे अवसर प्रदान करने के लिए कहने के लिए साहस और विनम्रता की आवश्यकता है, हम अपनी सभी सीमाओं को पीछे छोड़ दें और ब्रह्मांड द्वारा निर्धारित शानदार और विशाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ें।

सफल लोग अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं जो उन्हें अज्ञात क्षेत्रों में प्रवेश करने का अधिकार देता है। इससे उनके प्राण/चि का स्तर, ध्यान की अवधि और कार्य की प्रकृति बढ़ती है, जिससे व्यक्तित्व में एक नया आयाम जुड़ता है। सफल लोग कभी भी अपने दृष्टिकोण में सीधे-सीधे नहीं रहते और जोखिम लेने में आनंद लेते हैं। के वल जोखिम लेने वाले ही गेम-चेंजर बनते हैं।

राहुल बजाज के बेटे राजीव और संजीव ने स्कूटर बनाने के लिए सेवामुक्त हो चुके आईएनएस विक्रांत के स्क्रैप को बचाने का एक आकर्षक विचार शुरू किया। यह एक नवोन्मेषी विचार था, जिसमें स्क्रैप का नये तरीके से उपयोग किया गया। जबकि अभ्यास का मूल उद्देश्य लाभ उत्पन्न करना हो सकता है, अप्राप्य विचार दुस्साहसी है। इसलिए, सफल उद्यमी कभी भी किसी विचार को खत्म नहीं करते। एक सरल विचार मौलिक खोज के लिए एक मंच हो सकता है। एक अद्भुत विचार लुभावनी और आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक और विस्मयकारी है। जब विचार अंकुरित होता है तो कुछ अद्भुत घटित होता है। बड़ा सोचें और उन लोगों की न सुनें जो आपसे कहते हैं कि यह नहीं किया जा सकता। टिम फेरिस लिखते हैं, छोटा सोचने के लिए जीवन बहुत छोटा है। ब्रह्माण्ड हमारे गहनतम विचारों को सुनता है। यदि विचार सकारात्मक है, तो हमें सकारात्मक परिणाम मिलते हैं।

जीवन का मुख्य सिद्धांत यह सुनिश्चित करना है कि हम के वल सकारात्मक विचार ही प्राप्त करें और प्रसारित करें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम हमेशा प्रभावशाली लोगों से घिरे रहें। जिम्मेदारी निभाते रहें और सुनिश्चित करें कि हमारे पास हां करने वाला मन है। सफल उद्यम यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका कार्यबल टीमों में काम करते समय सद्भाव और तालमेल के साथ प्रदर्शन करे।

ब्रह्मांड आकर्षण के नियम, प्रचुरता के नियम, कृतज्ञता के नियम और सर्पिल प्रभाव के नियम में विश्वास करता है। यह सब उस चीज़ में परिवर्तित हो जाता है जिसे डैरेन हार्डी यौगिक प्रभाव कहते हैं। इसके बाद, हमें हमेशा धन्य महसूस करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि एक श्रेष्ठ शक्ति हमारे प्रयासों में हमारा मार्गदर्शन कर रही है। एक श्रेष्ठ बुद्धि है जो हमेशा हमारे लिए अद्भुत अवसर पैदा कर रही है और इन्हें विनम्रता के साथ पकड़ना चाहिए।

एक विजयी व्यक्ति अपने विश्वास को इस विचार पर टिका देता है कि ईश्वर हर चीज का ख्याल रखेगा और वह के वल उस श्रेष्ठ शक्ति पर विश्वास रखता है। सफल लोग इन सिद्धांतों पर काम करते हैं जहां फुटबॉल एक परवलय की तरह घूमती है और नेट में प्रवेश करती है और हम स्तब्ध रह जाते हैं और खड़े होकर तालियां बजाते हैं। यही चमत्कार किया गया है। इसे सर्वशक्तिमान की शक्ति या ब्रह्मांड की वास्तुकला कहना चुनें। लेकिन यह सकारात्मक सोच और सफल होने की शक्ति के आधार पर काम करता है।

आप की बात

बेतुके बयान

अभिव्यक्ति की आजादी का इससे अधिक मखौल और क्या हो सकता है कि इस समय बेतुके बयान देने की होड़ मची है। सैम पित्रोदा के रंगभेदी दृष्टिकोण वाले बयान से कांग्रेस ने उनके इस्तीफे से छुट्टी पाई ही थी कि उसके वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान प्रेम जागृत हो गया। उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान नाभिकीय आयुध संपन्न देश है, इसलिए उसका सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस के एक नेता ने तो अयोध्या में राम मंदिर के शुद्धीकरण की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनने पर मंदिर का शुद्धीकरण कराया जाएगा। इंडिया गठबंधन में शामिल सपा के विद्वान प्रोफेसर राम गोपाल ने तो राम मंदिर को बेकार तथा उसके नक्शे को खराब बता डाला। राम मंदिर के बारे में ऐसे बेतुके बयानों का कोई औचित्य नहीं है। देश में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों, वैज्ञानिकों व भू-वैज्ञानिकों के साथ ही वास्तुविदों ने प्राचीन भारतीय मंदिरों का विस्तृत अध्ययन कर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया है। इसके निर्माण के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा में सभी भारतीय परंपराओं व शास्त्रोक्त पद्धतियों का पूरा ध्यान रखा गया है। इन बेतुके बयानों से विपक्ष देश की नजरों में अपनी ही छवि खराब कर रहा है जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा।

– **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

भ्रूण का लिंग परीक्षण

भ्रूण का लिंग परीक्षण लंबे समय से चिकित्सा क्षेत्र में अनैतिकता तथा समाज में व्याप्त महिला-विरोधी दृष्टिकोण का प्रतीक रहा है। अब डॉक्टर की चूक पर उनको दंड से बचाने के लिए भ्रूण के लिंग परीक्षण मामलों में छूट देने की मांग की जा रही है। यह सरासर गलत है। अभी ऐसे परीक्षण करने वाले डॉक्टरको 3 वर्ष की कठोर सजा का नियम है, लेकिन इसके बावजूद पैसा फेंक कर लोग देश में या विदेश में जाकर भ्रूण परीक्षण करवा कर कन्या भ्रूण होने पर उसका अबॉर्शन भी करवा रहे हैं। ऐसी हालात में भ्रूण परीक्षण कानून में छूट देने के बारे में सोचा भी नहीं जाना चाहिए। भ्रूण का लिंग परीक्षण तथा कन्या भ्रूण की हत्या देश में लंबे समय से व्याप्त महिला-विरोधी प्रवृत्ति का नतीजा है। हालांकि, अब पढ़े-लिखे शहरी मध्यवर्ग में महिला-विरोधी प्रवृत्ति में भारी कमी आई है, पर यह सामंती सोच वाले कुछ ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों में अब भी जारी है। जन्म लेने के बाद भी कुछ लोग कन्याओं को दूसरे दर्जे का व लड़कों से हीन मानते हैं। इस कारण उनको सताने के प्रयास होते हैं तथा खाने पीने से लेकर पढ़ाई-लिखाई तक दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। ऐसी सोच बदलने की जरूरत है, उम्मीद है कि समय के साथ बदलेगी भी।

– **सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

जनसंख्या असंतुलन

देश में उपलब्ध प्राकृतिक और अन्य संसाधनों व सुविधाओं के मद्देनजर आबादी का बेलगाम बढ़ना ही चिंतनीय है। किंतु धार्मिक आधार पर अधिक बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति देश की जनसंख्या संरचना और इस कारण देश की सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक संरचना के लिए खतरा बन सकती है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में गत 65 वर्षों में हिंदू आबादी 7.82 प्रतिशत घटी, जबकि मुस्लिम आबादी 43.15 प्रतिशत बढ़ी है। यही स्थिति पड़ोसी देश नेपाल में है जबकि 38 मुस्लिम बहुसंख्यक देश में मुसलमानों की संख्या लगभग 70 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है। मुस्लिम देशों में रहने वाले दूसरे धर्मानुयाइयों की संख्या में 22 प्रतिशत से अधिक कमी आई। इस तरह का बढ़ता जनसंख्या असंतुलन अनेक देशों में समस्याओं का कारण बन रहा है। भारत में ऐसे असंतुलन से बचने के लिए समान नागरिक संहिता तथा व्यापक रूप से स्वीकार्य जनसंख्या नीति की जरूरत है। इसके साथ ही सभी धर्मों में छोटे परिवारों को प्रोत्साहन देने के आर्थिक कदमों के साथ ही यह चेतना पैदा करने की भी जरूरत है कि बच्चों का पालन-पोषण अंततः उसके माता-पिता की जिम्मेदारी है।

– **बीएल शर्मा,** उज्जैन

हड़ताल के सबक

टाटा के अधिग्रहण के बावजूद एयर इंडिया में विमानन सेवा प्रबंधन की कमी है। चालक दल के सदस्यों के अचानक सामूहिक रूप से छुट्टी लेने और इसके चलते कई हवाई सेवाओं के निरस्त करने का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ा। हो सकता है किसी का इंटरव्यू रहा हो, किसी को मेडिकल इलाज की जरूरत रही हो या अन्य भी कारण हो सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या टाटा समूह का मैनेजमेंट इतना सुस्त पड़ गया और अदूरदर्शी हो गया है कि वह पुराने अनुभवों से सबक नहीं ले पाया। टाटा समूह द्वारा एयर इंडिया का अधिग्रहण करने और बड़ी संख्या में आधुनिकतम विमान खरीदने के आदेश से जनता में बहुत उम्मीदें जगी थीं। लेकिन इस हड़ताल से उनको धक्का लगा है। हालांकि, टाटा समूह ने तुलनात्मक रूप से स्थिति पर जल्दी नियंत्रण पाने में अपनी क्षमता प्रदर्शित की, लेकिन भविष्य में प्रबंधन को इस हड़ताल से समुचित सबक लेने होंगे। भारत सरकार को भी विमानन सेवाओं में कर्मचारियों के वेतन व भत्ते के बारे में सलाह देनी चाहिए। विमानन जैसी सेवाओं में हड़ताल की परिस्थिति नहीं बननी चाहिए।

– **भगवानदास छारिया,** इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 74

मायने रखता है प्रवास

कई भारतीय नागरिक अन्य देशों, खासकर खाड़ी और विकासशील देशों में जाते हैं। आंतरिक प्रवास यानी देश के भीतर लोगों का एक स्थान से दूसरे पर जाना और देश से दूसरे देशों में जाना अक्सर आजीविका के बेहतर अवसरों के लिए होता है। परंतु कई बार ऐसा हताशा में भी होता है। वर्ष 2020 में करीब 1.8 करोड़ भारतीय अपने जन्म के देश से बाहर रह रहे थे। सबसे अधिक प्रवासी भारतीय संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब में रहते हैं। इंटरनैशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की ताजा रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि भारत से संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब को होने वाला प्रवास दो देशों के बीच होने वाले प्रवास गलियारों में शीर्ष 10 में शामिल है। दिलचस्प है कि बांग्लादेश से भारत को होने वाला प्रवास भी इस सूची में शामिल है। भारत से बाहर जाने वाले लोगों की तादाद न केवल दुनिया में सबसे अधिक है बल्कि इसमें लैंगिक झुकाव भी नजर आता है। भारत से दूसरे देशों में जाने वाले प्रवासियों में पुरुषों की तादाद करीब 65 फीसदी है। इससे संकेत मिलता है कि पुरुष काम की तलाश में बाहर जाते हैं जबकि महिलाएं देश में ही रह जाती हैं।

वृहद आर्थिक दृष्टि से देखें तो प्रवास विदेश से स्वदेश धन भेजने का बहुत बड़ा जरिया है। रिपोर्ट में यह रेखांकित किया गया है कि 2022 में भारत विदेश से धन पाने वाला सबसे बड़ा देश रहा। उसे 111 अरब डॉलर से अधिक राशि मिली। इस धनप्रेषण में भारत का दबदबा लगातार बढ़ रहा है और वह कई वर्षों से शीर्ष पर बना हुआ है। देश के चालू खाते का घाटा कम करने में भी इसकी अहम भूमिका रही है। 2023-24 की तीसरी तिमाही में यह सकल घरेलू उत्पाद के 1.2 फीसदी के स्तर पर था। चूंकि भारत ऊर्जा का बड़ा आयातक है इसलिए वाणिज्यिक घाटे का स्तर भी अधिक है। अतिरिक्त खर्च करने योग्य आय का जरिया होने के कारण यह धन प्रेषण घरेलू खपत व्यय में इजाफा करता है और घरेलू मांग को मजबूत करता है। बहरहाल, दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाले धन पर बहुत अधिक निर्भरता भी चिंता का विषय है। कई बार यह कहा जाता है कि इससे प्राप्तकर्ता देश में निर्भरता की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। इससे उत्पादकता कम होगी और आर्थिक वृद्धि में धीमापन आएगा। इससे अर्थव्यवस्था की स्थिति संवेदनशील हो सकती है और कई कारणों से अगर धन प्रेषण अचानक प्रभावित होता है तो मुश्किल हालात बन सकते हैं। खुशकिस्मती से रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े बताते हैं कि अन्य देशों की तुलना में भारत की निर्भरता सीमित है। ताजिकिस्तान इस सूची में शीर्ष पर है और 2022 में उसका धनप्रेषण-जीडीपी अनुपात 51 फीसदी रहा। इसके विपरीत उसी वर्ष भारत में यह केवल 3.3 फीसदी रहा। श्रम आधिक्य वाला देश होने के नाते भारत को प्रवासी आबादी से बहुत मदद मिलती है। इन प्रवासियों का बड़ा हिस्सा कम वेतन वाले कामों मसलन विनिर्माण, सुरक्षा, घरेलू काम और खुदरा क्षेत्र में काम करता है जबकि अन्य उच्च वेतन वाले कौशल संपन्न पेशों में हैं। भारत जैसे विकासशील और बड़े देश में कुछ लोगों का बेहतर अवसरों की तलाश में विकसित देशों में चले जाना सामान्य बात है। परंतु कम कौशल वाले लोगों का बाहर जाना यही बताता है कि देश में उत्पादक रोजगार अवसर तैयार करने की आवश्यकता है। बहरहाल, बड़े पैमाने पर ऐसे अवसर तैयार करना लंबे समय से नीतिगत चुनौती बना हुआ है। ऐसे में निकट भविष्य में प्रवासन का यह रुझान बने रहने की उम्मीद है। इस संदर्भ में जहां हाल के वर्षों में प्रगति हुई है, वहीं भारत को विदेशों में रहने वाले भारतीयों की दिक्कतें दूर करने के लिए भी अपनी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें भेदभाव, शोषण, स्वदेश वापस भेजने आदि के मामलों से निपटना तथा बाहर रहने वाले भारतीयों की पूरी जानकारी रखना शामिल है। फिलहाल जो हालात हैं, वैश्विक श्रम की गतिशीलता भारत की आर्थिक कूटनीति की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसे ऐसी दुनिया में भारत के हितों की रक्षा करनी चाहिए जहां संरक्षणवाद तेजी से बढ़ रहा है।

अजय मोहंती

चमकीला, कनाडा और भविष्य के खतरे

अमर सिंह चमकीला की हत्या के कुछ सप्ताह पहले भी पंजाब में हर दूसरे दिन हत्याएं हो रही थीं, वह पूरा दौर आतंकी घटनाओं और हत्याओं का दौर था।

आम चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच भला किसी को एक ओटीटी फिल्म के बारे में क्यों बात करनी चाहिए? भले ही वह समालोचकों द्वारा सराही जा रही इम्तियाज अली की फिल्म अमर सिंह चमकीला (नेटफ्लिक्स पर प्रसारित) ही क्यों न हो?

फिल्म का कथानक 1988 के पंजाब का है जहां उस समय आतंकवादियों का दबदबा था। फिल्म की कहानी 8 मार्च, 1988 को अमर सिंह चमकीला की गोली मारकर हत्या किए जाने के साथ ही समाप्त होती है। चमकीला पंजाब के ग्रामीण इलाकों के एक लोकप्रिय सुपरस्टार थे।

हम यहां फिल्म समीक्षाएं नहीं लिखते हैं। हालांकि यह फिल्म हमें विवश करती है कि हम उस हकीकत से जुड़ें जिसे हम भुलाना चाहते हैं। जो लोग असहज करने वाली हकीकतों को भुलाना चाहते हैं उन्हें उसे दोबारा जीना पड़ता है। आगे बढ़ते हुए तीन बातें:

■ समकालीन इतिहास पर केंद्रित अन्य फिल्मों की तरह यह फिल्म भी बहुत अधिक और अनैतिक रूप से गलत है। यह पूरी तरह संदर्भ से कटी हुई है। इसमें 1988 में पंजाब में फैले आतंकवाद का हल्का फुल्का जिक्र है लेकिन मोटे तौर पर इसमें उसे नजरअंदाज कर दिया गया है।

■ मैं इस बात के संदर्भ को आगे के पैराग्राफ में खोलूंगा लेकिन यह हत्याकांड स्वर्ण मंदिर परिसर में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के ठीक दो महीने पहले हुआ। उसके बाद ही आतंकवादी और कट्टरपंथी वापसी नहीं कर सके। 10 मई को ऑपरेशन की 36वीं बरसी थी।

■ तीसरी और सबसे अहम बात। कनाडा ने हाल ही में चार 'भारतीय नागरिकों' (सभी पंजाबी और शायद सिख) को हरदीप सिंह निज्जर की कथित हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पंजाब में दोबारा उसी आग को भड़काने और उसे झुलसाने के लिए ठोस और समर्थित प्रयास चल रहे हैं जो कनाडा में केंद्रित हैं लेकिन जिनका संबंध अन्य एंग्लो-अमेरिकी देशों से भी है। इसे गत पखवाड़े उस समय और वैधता मिल गई जब कनाडा के प्रधानमंत्री और उसके नेता प्रतिपक्ष दोनों ने एक सिख धार्मिक आयोजन में शिरकत की जहां अलगाववादी और आपत्तिजनक नारे लगाए गए। वहां अनुचित तस्वीरें और पोस्टर भी प्रदर्शित किए गए।

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

स्पष्टता के लिए बता दें कि सन 1981 से 1993 में आतंकवाद के दौर में वहां के कुछ नेता कनाडा और ब्रिटेन चले गए थे लेकिन वहां उन्हें बहुत कम राजनीतिक समर्थन मिला और वे ज्यादातर पाकिस्तान चले गए। आज, अलगाववादी नेतृत्व केवल कनाडा में है और उसे वहां पूरा राजनीतिक समर्थन मिल रहा है।

दूसरा अंतर यह है कि 1980 के दशक के उलट ऐसे अभियान को पंजाब में कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। यह अच्छी बात है। नकारात्मक बात यह है कि यह विदेशी अभियान कनाडा की घरेलू वोट बैंक राजनीति से गहराई से जुड़ गया है। वहां अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर घृणित गतिविधियों को प्रश्रय दिया जा रहा है।

कनाडा मानता है कि निज्जर की हत्या के आरोपी भारतीय 'एजेंसियों' के इशारे पर काम कर रहे थे। इसके साथ ही हमें यह भी जानकारी है कि उक्त आरोपी स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गए थे और वे एक भी दिन स्कूल या कॉलेज नहीं गए। वे माफिया के आदमी हैं और उनका नाम तीन और हत्याओं में आया है जिनका 'भारतीय एजेंसियों' से कोई लेनादेना नहीं है।

कनाडा में हत्याएं और जवाबी कार्रवाई आम हो चुके हैं। भारत के कुछ कुख्यात हथियारबंद माफिया जिनके नेता जेल में हैं, वे भी कनाडा के इन समूहों के जरिये काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में कैद है। पंजाब माफिया, संगीत संस्कृति, नशे और बंदूक की तस्करी तथा अवैध आव्रजन आदि का मिश्रण खतरनाक है। इसका पोषण सुस्त (बल्कि मिली हुई) कनाडाई व्यवस्था कर रही है।

यह तो कनाडा के लोगों को पूछना चाहिए कि उनका देश भारतीय पंजाब से ऐसे बेरोजगार युवाओं को क्यों आने दे रहा है जो उनके देश में माफिया का काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे पंजाब में 'कबूतरबाजी' का रैकेट है यानी अवैध तरीके से लोगों को दूसरे देशों में पहुंचाने वाला गिरोह।

उन्हें वीजा किस तरह मिलता है? क्या जी7 और फाइव आइज के सदस्य देश की वीजा प्रणाली इतनी ढीली है कि इतने सारे 'छात्र' वहां पहुंचते रहते हैं? या फिर यह किसी खास दल के लिए वोटों की जरूरत की वजह से है? कनाडा भारत से माफिया आने दे रहा है। ज्यादातर तो वे आपस में लड़ते हैं। अब इसका असर भारत तक हो रहा है। गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या इसका उदाहरण है।

मूसेवाला की हत्या ने पूरे देश का ध्यान आकृष्ट किया क्योंकि वह राष्ट्रीय स्तर की सितारा हैसियत रखते थे। अमर सिंह चमकीला एक दलित थे जिनका असली नाम धनी राम था और जब उनकी हत्या हुई तो वह केवल 28 साल के थे। उनकी छवि एकदम स्थानीय थी। वह मेहनतकश वर्ग के थे, उनके गीत एकदम देसी थे और ज्यादातर लोग उन्हें जानते तक नहीं थे।

फिल्म से यह संकेत निकलता है कि उन्हें मारा गया क्योंकि 'किसी को' लगता था कि उनके बोल अश्लील थे, उसने उन्हें इससे दूरी बनाने को कहा और उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके श्रोताओं को 'वही' पसंद था। यह बात का साधारणीकरण है। या फिर शायद फिल्मकार के लिए यह बात केवल इतनी ही थी। बात यहीं पर संदर्भ से कट जाती है। परंतु मेरा मानना है कि अगर इतिहास के इतने अहम मोड़ पर केंद्रित फिल्म में संदर्भ को जानबूझकर या अपनी सुविधा से छोड़ दिया जाता है तो रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं बल्कि आपराधिक कृत्य है। फिल्म यह नहीं बताती है कि आतंकियों ने चमकीला को मारा था। फिल्म में आतंकवाद शब्द तक नहीं आता है। चमकीला के जो द्विअर्थी गीत थे, ग्रामीण पंजाब में उससे भी गंदे गीत तब भी गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं। चमकीला की शोहरत ने उनके प्रतिद्वंद्वियों को बहुत परेशान किया था जो ज्यादातर ऊंची जाति के थे। क्या किसी ने भाड़े के हत्यारों से उसकी हत्या कराई? यह बात हमें आज भी नहीं पता।

बहरहाल, अगर उन्हें अश्लीलता के लिए मारा गया तो लोकप्रिय प्रगतिशील कवि पाश (अवतार सिंह संधू) को चमकीला की हत्या के महज दो सप्ताह बाद क्यों मार दिया गया? उनकी कविताओं में तो समानता और सर्वहारा क्रांति की बातें थीं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है: सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। क्या इसके लिए उनकी हत्या कर दी गई?

वह नक्सली रह चुके थे, उन्होंने जेल में समय बिताया था और अपने प्रदेश में हो रही हिंसा के खिलाफ पंजाबी प्रवासियों की अंतरात्मा को जगाने के लिए की गई विदेश यात्रा से लौटे ही थे। विदेश में वह एंटी-47 नामक एक समूह में शामिल हुए थे। यहां 47 शब्द एके-47 राइफल से लिया गया है जो पाकिस्तानियों द्वारा आतंकियों को दी जा रही थी। पंजाब में हुई करीब 25,000 हत्याओं में उसका इस्तेमाल किया गया। पाश की हत्या उन्होंने नहीं तो किसने की?

उन सप्ताहों में हुई सामूहिक हत्याओं की सूची मैं आपको दे सकता हूं। चमकीला की हत्या के समय और उसके बाद दो महीनों में करीब 500 लोगों को जान से मारा गया। चमकीला की हत्या के पहले के सप्ताहों में भी हर दूसरे दिन हत्याएं हो रही थीं। इन सब बातों को नजरअंदाज करना अपराध नहीं तो भी बौद्धिक कायरता है। ऐसा लगता है मानो बॉलीवुड के फिल्मकार हमें यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि सन 1988 में पंजाब और सिख जो झेल रहे थे वह बस कुछ बुरे अपराध थे। जस्टिन ट्रुडो की कनाडाई सरकार अपने देश में पहुंच चुके सिख प्रवासी गैंगों को भी उसी चश्मे से देख रही है। आने वाले समय में अनेक खतरे छिपे हुए हैं।

कैसे रोकी जा सकती है येन में गिरावट?

येन की विनिमय दर में गिरावट आई है और वह 160 येन प्रति डॉलर के सन 1990 के स्तर तक फिसल गया है। ऐसा क्यों हुआ? भविष्य में यदि ऐसी स्थिति बनती है तो नीतिगत हल क्या हो सकते हैं?

बैंक ऑफ जापान ने अपनी शून्य ब्याज दर नीति को त्याग दिया है लेकिन अभी भी उसकी अल्पावधि की ब्याज दर केवल 0.1 फीसदी है। ऐसा इसलिए है कि कहीं जापान एक बार फिर कम मुद्रास्फीति या अपस्फीति और कम आर्थिक वृद्धि की दोहरी मुश्किल में न उलझ जाए। दूसरी ओर अमेरिकी फेडरल रिजर्व इस स्थिति में नहीं है कि वह रीपो दर को 5.5 फीसदी से कम करे जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था 3.5 फीसदी की मुद्रास्फीति पर अटक सी गई है जो दो फीसदी के लक्ष्य से काफी अधिक है। दोनों देशों की ब्याज दरों में काफी अंतर है और यह बात जापान से अमेरिका की ओर पूंजी प्रवाह को मजबूत कर रही है। यही कारण है कि येन में गिरावट है।

बैंक ऑफ जापान ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 35 अरब डॉलर की कमी करके हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। येन में कुछ तेजी आई लेकिन यह दीर्घकालिक उपाय नहीं साबित हुआ। इस बात को समझा जा सकता है क्योंकि वास्तविक समस्या कहीं और है। जापान और अमेरिकी की ब्याज दरों में भारी अंतर है। निकट भविष्य में इस अंतर के दूर होने की संभावना भी नहीं नजर आती क्योंकि दोनों देशों के वृहद आर्थिक हालात अलग-अलग हैं। इन सारी बातों का संदर्भ वहां की प्रचलित ब्याज दर नीति से जुड़ता है। सवाल यह है कि क्या हम एकदम अलग नीति अपना सकते हैं ताकि मुद्रा बाजार पर नीति का नकारात्मक प्रभाव न पड़े या फिर बहुत कम पड़े? हां, इससे पहले कि हम यहां प्रस्तावित ब्याज दर नीति पर वापस लौटें, वर्तमान में प्रचलित ब्याज दर नीति की दो विशिष्टताओं पर ध्यान दें।

पहली, केंद्रीय बैंक की ब्याज दर नीति में अंतर्निहित कर या सब्सिडी योजना है। फिलहाल बैंक ऑफ जापान ने कर्जदारों के लिए ब्याज दरों को कम रखा है। यह एक तरह से कर्जदारों को सब्सिडी देने के समान है। दूसरी ओर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को ऊंचा रख रहा है। यह कर्जदारों पर कर लगाने के समान है। दूसरा, ब्याज दरों में केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाने वाला बदलाव निवेश, आवासीय परियोजनाओं और टिकाऊ वस्तुओं के लिए उधारी को प्रभावित करता है। प्रयास यह है कि अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को प्रभावित किया जाए। बहरहाल, नीति की धार कुंद है और यह केवल विनिमय दर जैसे गुणकों को प्रभावित करती है।

गुरबचन सिंह

उपरोक्त दो पर्यवेक्षणों के आधार पर अब हम प्रस्तावित ब्याज दर नीति की बात कर सकते हैं। यह नीति केंद्रीय बैंक द्वारा क्रियान्वित नहीं की जाती है। इसके बजाय इसे जापान का वित्त मंत्रालय बनाता है और अमेरिका में ट्रेजरी विभाग। जापान में वित्त मंत्रालय को स्पष्ट सब्सिडी देने दीजिए और अमेरिका में ट्रेजरी विभाग को कर लगाने दीजिए। जापान में सब्सिडी या अमेरिका में कर केवल टिकाऊ चीजों की उधारी पर लगता है, यह सभी उधारियों पर नहीं लगता। आइए देखें यह कैसे काम करता है।

प्रस्तावित नीति के तहत जापान में स्पष्ट सब्सिडी के कारण फंड की मांग बढ़ेगी। ऐसे में बाजार में ब्याज दर बढ़ेगी क्योंकि जापान में टिकाऊ वस्तुओं के लिए उधारी की प्रभावी ब्याज दर में कमी आएगी। दूसरी ओर अमेरिका में फंड की मांग में कमी आएगी। इसलिए वहां बाजार की मौजूदा ब्याज दर में भी कमी आएगी जबकि प्रभावी ब्याज दर बढ़ेगी।

यह दिलचस्प है कि प्रस्तावित नीति के तहत दोनों देशों में केवल टिकाऊ चीजों के लिए उधारी की प्रभावी ब्याज दर का अंतर बढ़ेगा। परंतु दोनों देशों के बाजार में मौजूद ब्याज दरों में कमी आती है। दोनों देशों के बाजार की इस ब्याज दर में अंतर में कमी को देखते हुए पूंजी के जापान से अमेरिका जाने की प्रक्रिया हतोत्साहित होगी। इस प्रकार अगर प्रस्तावित ब्याज दर नीति होती तो येन में तेज गिरावट नहीं आती। इतना ही नहीं दोनों देशों में वृहद आर्थिक स्थिरीकरण भी हासिल होता।

जाहिर है इस विषय में बहुत सी बातें हैं जिनमें न केवल मुद्रा से जुड़ी नीति के संभावित दुष्प्रभाव शामिल हैं बल्कि परिसंपत्ति कीमतें भी शामिल हैं। ये सारी बातें मेरी आगामी पुस्तक 'मैक्रोनॉमिक्स ऐंड ऐसेट प्राइजेस-थिंकिंग अफ्रेश ऑन बेसिक प्रिंसिपल्स ऐंड पॉलिसी' में इन सारी बातों को विस्तार से स्पष्ट किया गया है। प्रस्तावित नीति बेहद साधारण है। यह केवल नई और थोड़ी अपरिचित है। लब्बोलुआब यह है कि मौजूदा ब्याज दर नीति बहुत भोथरी है और इसके कुछ दुष्प्रभाव हैं। यही वजह है कि येन में तेज गिरावट आई। प्रस्तावित ब्याज दर नीति के अधीन ऐसा नहीं हुआ होता।

(लेखक स्वतंत्र अर्थशास्त्री हैं। वह अशोक यूनिवर्सिटी, आईएसआई दिल्ली और जेएनयू में अध्यापन कर चुके हैं)

आपका पक्ष

भारत में विदेशी कंपनियों का भविष्य

इस समाचार पत्र में प्रकाशित लेख भारत में विदेशी वित्तीय कंपनियों के भविष्य पर विस्तृत चर्चा करता है। यह चर्चा केवल बैंकिंग कंपनियों तक सीमित नहीं है बल्कि विदेशी व्यापारिक संस्थानों के लिए भी चरितार्थ होती है। विदेशी कंपनियां चाहे वे वित्तीय व्यापार में हों, या खुदरा व्यापार में, भारी लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से व्यापार करती हैं। जब तक उनको घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं मिल रही थी, वे भारतीय व्यापार को सोने की चिड़िया समझ रही थीं। जब बैंकिंग में घरेलू स्तर पर विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक एवं मझोले स्तर के निजी बैंक आदि विभिन्न म्युचुअल फंड बाजार में आए तो विदेशी वित्तीय संस्थानों को यह कारोबार कम लाभकारी लगा। भारत का विदेशी व्यापार 900 अरब डॉलर पार कर गया है और विदेशी बैंकों की भारत के सभी बड़े महानगरों, व्यापारिक केंद्रों और राज्यों की राजधानियों में शाखाओं की

भारत का विदेशी व्यापार 900 अरब डॉलर पार कर गया है

आवश्यकता भी है जिससे लेनदेन की व्यापारिक सुगमता भी हो। उदाहरण के लिए एक समय था जब भारत में कच्चे तेल और गैस के ऑफ शोर व ऑन शोर खनन, सर्वे, सर्विसिंग, तकनीकी शोध और सेवाओं के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था और इन कंपनियों को बहुत मोटा भुगतान करना पड़ता था। विदेशी कंपनियों को यह समझना होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था प्राचीन काल से ही प्रचुरता की व्यवस्था है और समाज सेवा के साथ राष्ट्र हित को आगे रखकर व्यापार की संस्कृति है। भारतीय उद्योग और व्यापार कम लाभ दर पर कारोबार करते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था के सारथी होते हैं जबकि विदेशी व्यापार का मूल ही अपर्याप्तता को आगे रखकर मूल्यवृद्धि और अधिक लाभ के लिए व्यापार है। ऐसे विरोधाभास के साथ लाभार्जन के लिए विदेशी कंपनियां भारत में लंबे समय तक नहीं रुक सकतीं।

विनोद जौहरी, दिल्ली

हिमाचल में यातायात समस्या से कैसे मिले छुटकारा

गर्मियों में दूसरे राज्यों और विदेश से लोग हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू-मनाली और अन्य क्षेत्रों का रुख करेंगे। लेकिन इन क्षेत्रों में पर्यटकों को यातायात समस्या से भी जूझना पड़ता है। प्रदेश की राजधानी शिमला भी यातायात समस्या से अछूती नहीं है। रेल लाइनों के विस्तार नहीं होने के कारण पर्यटक सड़क मार्ग से ही आते हैं। इससे समय-समय पर ट्रैफिक जाम की समस्या आम होने लगी है। जाम से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां यातायात समस्या से निपटना बहुत ही कठिन राह है, क्योंकि यहां कुछ सड़कें ऐसी भी है जिनके दोनों तरफ खाई होने के कारण बाईपास निकालना मुश्किल है। कुछ सड़कें तो बीच बाजार से निकलती हैं, जैसे कि होशियारपुर से माता चिंतपूर्णी या धर्मशाला जाने के लिए पहले गगरेट, उसके बाद मुबारक के बाजार की तंग सड़क कई बार ट्रैफिक समस्या पैदा कर देती है। भविष्य में यातायात समस्या से निपटने के लिए आज से ही सरकारों को प्राथमिक तौर पर कुछ नीतियां बनाकर काम शुरू कर देना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

भारतीय नौसेना के 106 इंटीग्रेटेड ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स के तहत अधिकारियों ने समुद्र में युद्धपोत पर प्रशिक्षण प्राप्त किया।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण

छोटे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी बड़े जतन करने पड़ते हैं

दायित्व निर्वहन का अवसर

लोकसभा चुनाव में मतदान के चौथे चरण को लेकर यह जानने की प्रतीक्षा है कि मतदान प्रतिशत कितना रहता है। इसका कारण यह है कि पहले और दूसरे चरण में 2019 की तुलना में कम मतदान हुआ। तीसरे चरण में भी मतदान प्रतिशत पिछले आम चुनाव के मुकाबले तो कम रहा, लेकिन अंतर कुछ घटा। देखना यह है कि चौथे चरण के मतदान प्रतिशत में कुछ बढ़ोतरी होती है या नहीं। मतदान प्रतिशत कम रहने के कई कारण हैं। इनमें मतदाता सूचियों का सही तरह से तैयार न होना, सभी मतदाताओं का उनमें नाम न होना और एक बड़ी संख्या में मतदाताओं का अपने काम-धंधे के सिलसिले में अपने गांव और शहर से दूर रहना शामिल है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इन कारणों का निवारण किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि मतदाताओं में जो उदासीनता देखने को मिल रही है, उसके लिए एक हद तक वही उत्तरदायी हैं। विडंबना यह है कि यह उदासीनता शहरी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिल रही है। इसका अर्थ है कि पढ़ा-लिखा और विभिन्न विषयों को लेकर मुखर रहने वाला वर्ग भी मतदान के प्रति उत्साहित नहीं रहता। यह भी देखने को मिल रहा है कि देश के कुछ हिस्सों में तो मतदान प्रतिशत संतोषजनक रहता है, लेकिन कुछ हिस्सों में वह अपेक्षा से कहीं अधिक कम रहता है।

मतदान केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि यह एक अधिकार है, बल्कि इस दायित्व का निर्वहन इसलिए भी किया जाना चाहिए कि इससे सरकार गठन में लोगों की भागीदारी बढ़ने से लोकतंत्र को बल मिलता है और साथ ही राजनीतिक दलों को अपनी नीतियों का निर्धारण करने में मदद भी मिलती है। मतदान न करने वाले लोग केवल जिम्मेदार नागरिक होने के दायित्व की पूर्ति में ही पीछे नहीं रह जाते, बल्कि शिकायत करने के अधिकारी भी नहीं रह जाते। मतदान में भाग लेना एक तरह से राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदारी करना है। निःसंदेह अपेक्षित संख्या में लोगों के मतदान के लिए न निकलने के पीछे एक कारण प्रतिकूल मौसम है और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि चुनाव ऐसे मौसम में कराए जाने चाहिए जब इतनी अधिक गर्मी न पड़ रही हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि लोग प्रतिकूल मौसम के बावजूद अपनी तय दिनचर्या पूरी करते हैं और गर्मी के बावजूद अपने काम-धंधे के सिलसिले में घर से बाहर निकलते हैं। स्पष्ट है कि प्रतिकूल मौसम के स्थान पर लोगों की अनिच्छा ही पर्याप्त मतदान न होने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इस अनिच्छा के कारणों की पहचान राजनीतिक दलों को भी करनी चाहिए और साथ ही स्वयं लोगों को इसके लिए प्रेरित होना चाहिए कि लोकतंत्र को मजबूती देने में वे कैसे भागीदार बनें, क्योंकि केवल इसी तरीके से वे राजनीतिक दलों को अपनी अपेक्षाओं के प्रति सजग-सचेत कर सकते हैं।

ठगी के तरीके

इंटरनेट की दुनिया ने जीवन को बहुत आसान बना दिया है। घर बैठे ही कई सुविधाएं कुछ ही क्षण में उपलब्ध हो जाती हैं। पैसे के लेन-देन की बात हो या पढ़ाई सबकुछ इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन लोगों की छोटी सी भूल से बड़ी क्षति हो सकती है। इस बीच इंटरनेट पर शातिर भी सक्रिय हैं जो लोगों को मिलने वाली सुविधाओं में ही ठगी के तरीके भी ढूंढ लेते हैं।

इंटरनेट से जीवन जितना सुगम हुआ है उससे अधिक इसके जरिये लोगों को ठगने वाले भी सक्रिय हो गए हैं

शातिर अभी तक लोगों को बैंक का कर्मचारी बताकर लोगों के खाते की जानकारी लेते थे या ओटीपी लेकर उनके खाते में सेंध लगाते थे। बैंक प्रबंधन एवं पुलिस के निर्देशों के बाद लोग सतर्क हुए तो शातिर ने ठगी के और माध्यम ढूंढ़ लिए। हिमाचल प्रदेश में भी अब लोगों को ईमेल के माध्यम से ऐसे संदेश भेजे जाते हैं कि लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। शातिर लोगों के रिश्तेदार या बच्चों की जानकारी भी जुटा लेते हैं। इसके बाद उन्हें टेलीफोन करते हैं कि उनका बच्चा किसी गंभीर मामले में फंस गया है, उसे बचाने के लिए पैसे की मांग की जाती है। लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई उन्हें दे देते हैं। उन्हें बाद में धोखाधड़ी का पता चलता है। ऊना पुलिस के पास एक महिला ने शिकायत की है कि उसे फोन आया कि इंग्लैंड में रहने वाले उसके भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसे बचाने के लिए 80 हजार रुपये लगेंगे। महिला ने उसे पैसे दे दिए। बाद में उसे पता चला कि उसके साथ ठगी हुई है। कुछ दिन पहले कांगड़ा में एक महिला को फोन आया कि उसका बच्चा कहीं फंस गया है। जब महिला ने पता किया तो पता चला कि बच्चा स्कूल में उपस्थित है। तकनीक के विकास के साथ लोगों का जागरूक रहना आवश्यक है।

आर्थिक-सामाजिक अवसरों के द्वार

विवेक देवराय

युवा आबादी का लाभ उठाने के लिए भारत को शिक्षा सुधार, आर्थिकी को संगठित रूप देने के साथ ही स्वास्थ्य एवं पोषण के समावेशन वाली रणनीति बनानी होगी

आदित्य सिन्हा

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार चीन को पीछे छोड़कर भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। इसके साथ ही भारत एक अनूठी जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में आ गया है। देश की करीब 65 प्रतिशत आबादी कामकाज योग्य है जो केवल भारत ही नहीं, बल्कि समूचे विश्व के लिए विपुल आर्थिक एवं सामाजिक संभावनाओं के द्वार खोलती है। इन संभावनाओं को प्रभावी रूप से भुनाने के लिए भारत को मानव पूंजी में रणनीतिक निवेश करना होगा। उसे सुनिश्चित करना होगा कि इस राह में कोई कसर शेष न रह जाए। जनसांख्यिकीय लाभांश जनसंख्या की आयु के स्तर में परिवर्तन पर झलकता है। जब 15 से 64 वर्ष के आयुवर्ग वाले लोगों की संख्या 14 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक की आयु वाले लोगों की संख्या से अधिक हो जाए तो इस प्रकार के लाभांश की स्थिति बनती है, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग उपलब्ध होते हैं। इतिहास साक्षी है कि जिन देशों ने भी ऐसी स्थिति को भुनाने के लिए समय से उपाय किए तो उन्होंने प्रगति के नए मापदंड स्थापित किए। इस लाभांश के पहले चरण में कामकाजी आबादी में भारी बढ़ोतरी से रोजगार, बचत एवं आर्थिक विकास और पारिवारिक कल्याण में निवेश बढ़ता है। परिणामस्वरूप इससे प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि की राह खुलती है। हालांकि ऐसे लाभांश की स्थिति अमूमन पांच दशकों तक ही चलती है, जिसके बाद उसका दूसरा चरण आरंभ होता है। दूसरे चरण में वृद्ध होती आबादी के लिए सेवानिवृत्ति की तैयारी में संसाधन जोड़ने होते हैं, जिसमें पुनः निवेश के माध्यम से राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी का रुख नजर आता है। चूंकि जनसांख्यिकीय लाभांश के ये दोनों चरण स्वतः स्फूर्त रूप से आकार नहीं लेते तो उन्हें साकार करने के लिए प्रभावी नीतिगत कदम अपरिहार्य होते हैं।

इस समय भारत की आधी आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है और जल्द ही कामकाजी आबादी एक अरब का आंकड़ा पार कर सकती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक पत्र के अनुसार जनसंख्या के मोर्चे पर लाभ की यह स्थिति भारत की जीडीपी को हर साल दो प्रतिशत तक बढ़ाने की क्षमता रखती है। हालांकि इससे जुड़े अवसरों को भुनाने की राह में तमाम चुनौतियां विद्यमान हैं, जिन्हें दूर करना ही होगा। सबसे पहली चुनौती तो उद्योग जगत की अपेक्षाओं और शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कौशल के स्तर पर भारी विसंगति की है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि रोजगार के लिए आवश्यक कौशल और उसकी पूर्ति में शिक्षण संस्थानों की अक्षमता के बीच 2030 तक 2.9 करोड़ का अंतराल उत्पन्न हो सकता है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से इस स्थिति को सुधारने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन यह नाकाफी लगते हैं। कारण यही है कि सभी स्कूल इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दे रहे और शिक्षा की गुणवत्ता में भी भिन्नता दिखती है।

अवधेश राजपूत

रोजगार का विषय भी कई बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। यह भी देखने में आता है कि उच्च शिक्षित लोगों की अपने करियर को लेकर विशेष आकांक्षाएं होती हैं और वे उन नौकरियों के लिए प्रयास नहीं करते, जिसमें वे अपने कौशल का सदुपयोग होता न देखते हों। इससे रोजगार प्रतीक्षा की अवधि लंबी खिंच जाती है। उदाहरण के रूप में नेशनल करियर सर्विस पर वित्त वर्ष 2024 के दौरान जहां नौकरियों की संख्या में 214 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, लेकिन नौकरी के लिए पंजीकरण कराने वालों का आंकड़ा केवल 53 प्रतिशत बढ़ा। यह रोजगार बाजार से जुड़ी विसंगतियों एवं जागरूकता के अभाव को दर्शाता है। इस मोर्चे पर मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन कायम है। यह स्थिति तकनीकी एवं वैश्विक आर्थिक ढांचे में आ रहे तेज परिवर्तनों से और प्रभावित हो रही है, जो कुछ पारंपरिक कौशलों को अप्रासंगिक बनाने पर तुली है। ऐसे में, उच्च शिक्षा कई बार ऐसे हालात बना देती है, जहां उपलब्ध रोजगारों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कामकाजी आबादी के पास आवश्यक अर्हता के स्तर पर असंगति देखने को मिलती है।

इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, 2023 कुछ सुधार के संकेत करती है, जिसमें रोजगार की स्थिति 50.3 प्रतिशत बढ़ी हुई दिखती है। इसके बावजूद आधुनिक अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिहाज से यह पर्याप्त नहीं। भारत के लिए फिनलैंड के अनुभव से सीखना कुछ उपयोगी हो सकता है, जहां शिक्षण संस्थानों, सरकार और निजी क्षेत्र के बीच इस प्रकार से तालमेल बना होता है, जहां श्रम बाजार की मौजूदा एवं भविष्य की मांग को ध्यान में रखकर शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त फिनलैंड में जीवनपर्यंत सीखने पर जोर दिया जाता है जो भारत के लिए और भी अहम रणनीति हो सकती है ताकि वह समय के साथ अपनी कामकाजी आबादी को सही दिशा में उन्मुख करता रह सके।

भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से का असंगठित रूप में होना भी एक बड़ी चुनौती है। असंगठित क्षेत्र में एक बड़ी भागीदारी गैर-कृषि कामगारों की है, जिनके पास सीमित रोजगार संभावनाएं एवं सामाजिक सुरक्षा के अवसर उपलब्ध होते हैं। इससे भी जनसांख्यिकीय लाभांश की संभावनाओं पर ग्रहण लग सकता है। सतत आर्थिक लाभ के लिए इन कामगारों एवं उनके उद्यमों को उचित नीतियों के माध्यम से संगठित स्वरूप देना होगा। अतीत में बाल शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश की अनदेखी की स्थिति को अब सुधारा जा रहा है। इस दिशा में की जा रही नई पहल का उद्देश्य जन्म के समय से स्कूल पहुंचने तक बच्चों की सेहत और व्यापक क्षमताओं को सुधारने पर केंद्रित है। पोषण अभियान और मिशन पोषण 2.0 जैसे कार्यक्रमों का लक्ष्य आरंभिक जीवन के पड़ाव पर कुपोषण को दूर करना है, जो भावी आर्थिक गतिविधियों और समग्र बेहतरी के लिए अच्छी बुनियाद रखने का काम करेगा। यदि भारत जनसांख्यिकीय लाभांश की संभावनाओं को पूरी तरह भुनाना चाहता है तो उसे समग्रता से भरी ऐसी रणनीति बनानी होगी, जिसमें शिक्षा सुधार, असंगठित क्षेत्र को संगठित स्वरूप देना और स्वास्थ्य एवं पोषण समृद्धि से जुड़े कार्यक्रमों का भलीभांति समावेश हो। इस दृष्टिकोण से अपेक्षित कौशल की कमी की पूर्ति के साथ ही सतत आर्थिक वृद्धि एवं जीवनस्तर में सुधार के द्वार खुलेंगे।

(देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी-अनुसंधान हैं)

response@jagran.com

राष्ट्रवाद के लिए खतरा वोटबैंक राजनीति

इस लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवाद की खूब चर्चा हो रही है। राष्ट्र प्रेम की भावना एक सहजात भावना है। यह किसी पार्टी की मान्यताओं या सिद्धांतों से उद्भूत नहीं होती है। हां, यह हो सकता है कि किसी पार्टी में ऐसे लोगों की संख्या अधिक हो, जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हों। उसके प्रति रागात्मक भाव रखते हों। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी का समर्थन करना ही राष्ट्रवादी होना नहीं है, अपितु व्यक्ति के भीतर अपने देश, उसके प्राकृतिक परिवेश, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक मान्यताओं, भौगोलिक सीमाओं, इतिहास, साहित्य, कला आदि के प्रति एक स्वाभाविक प्रेम और निष्ठा उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। खेतों में अन्न उपजाता और राष्ट्र के लोगों को भोजन देने वाला किसान भी उतना ही राष्ट्रवादी है जितना सीमा पर सुरक्षा के लिए हर परिस्थिति में खड़ा हमारा भारतीय सैनिक राष्ट्र प्रेमी होता है। यह अतिशय राष्ट्रवाद की भावना ही थी जिसने अनगिनत बलिदानों और कठिन संघर्षों के बाद भारत को अंग्रेजी दासता से मुक्ति दिलाई। निःसंदेह उस समय भारत छोटे-छोटे राज्यों और रियासतों में बंटा हुआ था, परंतु स्वाधीनता के संग्राम में सब एक हो गए थे। यह एकता की भावना ही राष्ट्रवाद की भावना थी। यह राष्ट्रवाद का ही परिणाम था कि भारत एक राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने फिर से तनकर खड़ा हो गया। वह निरंतर सफलता एवं प्रगति के पथ पर अग्रसर भी है।

नीरजा माधव

भारत की पहचान और अस्मिता के प्रति जागरूकता की भावना ही वास्तव में राष्ट्रवाद को परिभाषित करती है

सहअस्तित्व की भावना से भरा भारतीय राष्ट्रवाद। फाइल

कुछ लोग राष्ट्रवाद को अति राष्ट्रवाद की सीमा तक ले जाकर आलोचना करने की कोशिश करते हैं। जबकि अति राष्ट्रवाद का तात्पर्य ही इस बात में निहित है कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने राष्ट्र को सर्वोच्च मानने लगता है। उसे अपने देश, वहां के नागरिकों, इतिहास, संस्कृति, परिवेश और भूखंड को लेकर अत्यधिक गर्व की अनुभूति होती है और वह इस पर किसी भी प्रकार का आघात सहन नहीं कर सकता। इसे स्थूल रूप में अति राष्ट्रवाद कह सकते हैं, परंतु इसी राष्ट्रवाद को अपने ढंग से परिभाषित करने वाले कम्युनिस्ट विचारकों, लेखकों आदि के अलग ही विचार होते हैं। वे जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर से प्रारंभ कर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक की नीतियों को अति राष्ट्रवाद की संज्ञा देते हैं और इसे मानवता के लिए घातक बताते हैं। उनके अनुसार अति राष्ट्रवाद किसी देश की सरकार को अधिनायकवादी बना देता है। उनका मानना है कि सांस्कृतिक एकरूपता के आह्वान के बीच हम आज अति राष्ट्रवाद के समय में जी रहे हैं, जहां स्वघोषित राष्ट्रवादियों और एक संस्कृति का उन्माद सामाजिक बनावट को टुकड़ों में बांटने का खतरा पैदा कर रहा है। वे यह भी मानते हैं कि यह अति राष्ट्रवाद वैश्विक चलन में आ गया है। ट्रंप से लेकर ब्रेक्जिट और यूरोप के अधिकांश अतिवादी दक्षिणपंथी समूह दूसरों के प्रति घृणा को बढ़ावा दे रहे हैं। इन अति राष्ट्रवादियों ने मुसलमानों, वामपंथियों को अपना शत्रु मान लिया। वे यह भी कहते हैं कि पिछली सदी के नौवें दशक तक भारत में राष्ट्रवाद उन्माद रहित था। यह न तो आक्रामक था और न ही विरोधात्मक।

सवाल है कि क्या राष्ट्र मात्र उन्हीं लोगों तक सीमित है, जिनके बारे में ये चिंतक अपनी दुश्चिंता प्रकट कर रहे हैं? राष्ट्रवाद की इस परिकल्पना में समस्त उत्तेजना राजनेताओं या उनके प्रशंसकों के इर्द-गिर्द ही घूमती नजर आती है। इसमें उन करोड़ों लोगों के दर्शन नहीं होते, जिनके कारण यह देश सांस्कृतिक है, धार्मिक है, दार्शनिक है, सामाजिक है और इतिहास से भी पुराना ऐतिहासिक है। राष्ट्रवाद एक भावना है, राष्ट्र के प्रति प्रेम है। भारत के भीतर और बाहर भी राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश करने वाली अलगाववादी ताकतें सदा से सक्रिय रही हैं। बाहरी शत्रुओं के साथ-साथ भारत को अपने आंतरिक शत्रुओं से भी बराबर मुठभेड़ करनी पड़ी, परंतु भारत में अंधेरे से जूझने का संकल्प बहुत पुराना है। यहां सूरज के ढलते ही दीप प्रज्वलित कर घर के बाहर देहरी पर रख देने की परंपरा रही है। सहअस्तित्व भारत की प्रधान सांस्कृतिक चेतना रही है जिसने इसे सहिष्णु और उदार बनाया। इसलिए भारत सभी प्रकार के विचारों को महत्व देता है। इसके दर्शन में आस्तिकतावादी भी हैं तो चार्वाक जैसे भोगवादी या नास्तिकतावादी भी भारतीय दर्शन ही कहलाते हैं। संकट तब खड़ा होता है जब आक्रमणकारी इस सहिष्णु संस्कृति की जड़ों पर प्रहार करते हैं। वहीं सावधान होना है। इस सावधान होने की प्रक्रिया को ही कभी-कभी इस तरह के छद्म विचारक नकारात्मक अर्थों में अति राष्ट्रवाद का नाम देने लगते हैं।

भारतीय संस्कृति मरणधर्मा संस्कृति नहीं है। यहां के लोग अमृतपथ के यात्री हैं। चेतना के सतत ऊर्ध्वारोहण के प्रति समर्पित। पश्चिम की तरह प्रकृति को जीतने की पागलपन वाली भाषा भारत नहीं बोलता। इसके लिए अपने भूखंड के हर प्राकृतिक पदार्थ-नदी, पेड़, पहाड़, जीव-जंतु, बादल और अग्नि आदि सभी पूजनीय हैं। उसके साथ ही पूरी सतर्कता और सतत सजगता के साथ वह जगत के धर्म का भी निर्वाह करता है। आपात स्थिति में आत्मरक्षा के लिए शौर्य के धर्म का पालन भी करता है। प्राणी मात्र को गले लगाना, स्नेह देना हमारा भारतीय धर्म है तो वहीं यह राष्ट्र प्रेम हमें किसी भी षड्यंत्र से सावधान रहने की शिक्षा भी देता है। कहीं हमारे प्रमाद का लाभ उठाकर हमारा ही कोई मित्र हमारे घर-परिवार पर आधिपत्य न जमा ले। वोट बैंक की राजनीति ने भारत के सांस्कृतिक आत्मा पर जितने प्रहार किए हैं, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार भारत की पहचान और अस्मिता के प्रति जागरूकता की भावना ही वास्तव में राष्ट्रवाद है, जिसे जगाने का काम इस चुनाव में किया जाना चाहिए।

(लेखिका साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आनंद

आनंद हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है, पर यह हमारा अंतिम गंतव्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है। जीवन आनंदमय हो और सतत आगे बढ़ता जाए, इसी कामना में तो सभी जिए जा रहे हैं। जीवन की यह यात्रा चार स्तरों से गुजरती है। हर स्तर पर विशिष्ट कार्यशैली की आवश्यकता होती है। हम प्रयास कर सकते हैं, पर सफलता ईश्वर की कृपा पर निर्भर है।

प्रथम स्तर है, ईश्वर की पहचान। इस स्तर पर हमारा प्रयास अधिक से अधिक लोगों को, विशेष रूप से आध्यात्मिक साधकों को, इस शुभ कर्म पथ पर साथ लाने का होना चाहिए। दूसरा स्तर है, सृष्टि से एकात्मता। इस स्तर पर चुनौतियां न केवल हमारी मानवीय और जैविक प्रवृत्तियों से आती हैं, बल्कि अजैविक शक्तियों से भी आती हैं। इस स्तर पर हमें सृष्टि की हर चीज के साथ एकात्मता का अनुभव करना होगा। हमें समझना होगा कि इस अस्तित्व का हर कण, हर परमाणु उसी परम सत्ता का अंश है। तीसरा स्तर है, मानसिक अनुभव और सिद्धियां। इस स्तर पर विकास की गति तेज होती है और साधक कुछ सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहां खतरा भी अधिक है। साधक को इन सिद्धियों का दुरुपयोग करने का प्रलोभन हो सकता है। इसलिए इस स्तर पर ईश्वर की कृपा और मजबूत मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इस स्तर पर परमात्मा परम गुरु बन जाते हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। साधक को अनुभव करना होगा कि वह ईश्वर की इच्छा से ही इस धरती पर आया है और उनकी इच्छा की प्राप्ति के लिए ही प्रयास कर रहा है। चौथा स्तर है, मन का एकाग्र होना। इस स्तर पर सभी लक्ष्य, पदार्थ, अहसास एक बिंदु में समाहित हो जाते हैं। मन एकाग्र हो जाता है और यही आनंद प्राप्ति का मार्ग है। इस स्तर पर साधक को पूर्ण आत्मज्ञान और आनंद की प्राप्ति होती है।

ईश्वर में विश्वास, समर्पण और सही मार्गदर्शन के साथ हम सभी आनंद के इस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

श्री श्री आनंदमूर्ति

एकाकीपन की त्रासदी, घुट रहा आदमी

सोनम लवंशी

लोगों में आत्महत्या और नशाखोरी के बढ़ते मामले के पीछे की वजह कहीं न कहीं बढ़ता एकाकीपन ही है

हम बचपन से यह सुनते आए हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन अब यह परिपाटी बदल रही है। आधुनिकता की चकाचौंध में इंसान न केवल स्वार्थी, बल्कि आत्मकेंद्रित भी हो गया है। मैं, मेरा और सिर्फ मेरी जिंदगी को ही जीवन का ध्येय बना लिया है। मानव स्वार्थ के मोह में अंधा हो गया है जिसकी कीमत अब एकाकीपन के दर्द से चुकानी पड़ रही है। भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अधिकांश लोग एकाकीपन के दर्द से जूझ रहे है। अकेले अमेरिका में ही करीब 61 प्रतिशत लोग एकाकीपन की पीड़ा का दंश झेल रहे हैं। मतलब हर 10 में से छह आदमी अपने जीवन में खुद को अकेला महसूस कर रहा है। आश्चर्य की बात है कि सबसे ज्यादा तादाद उन लोगों कि है जो घंटों इंटरनेट मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। विडंबना देखिए कि सोशल लाइफ का आकार तो बढ़ गया, लेकिन करीबियों का साथ छूट गया। पुरुषों में आत्महत्या और नशाखोरी के बढ़ते मामले के पीछे की वजह कहीं न कहीं बढ़ता एकाकीपन ही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की एक चौथाई आबादी से ज्यादा आबादी को प्रभावित करने वाले एकाकीपन को जन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना है।

एकाकीपन इंसान को जीते-जी मार देता है। बर्नार्ड शा के मुताबिक 'लोग मरते तो बहुत पहले हैं, लेकिन दफनाए बहुत बाद में जाते हैं। मरने और दफनाते के बीच का यह फासला ही अकेलेपन की त्रासदी है, जिसमें आदमी घुट-घुट कर जी रहा है।'' आज पूरी दुनिया यह मान रही है कि परिवार कितना जरूरी है। बिखरते परिवारों की कीमत हमारा समाज चुका रहा है। आज भले ही फेमिनिस्ट अकेली स्त्री को आजाद और आधुनिक बताकर उसका महिमा मंडन कर रहे हों, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि जब कोई मुसीबत आती है तो परिवार के सदस्य ही दुख-दर्द बांटने आते हैं। आज हमारे समाज में तलाक का ग्राफ बढ़ गया है। आज का युवा भले ही इसे चिंतामुक्त जीवन का नाम दे रहा हो, पर इसकी कीमत भावनात्मक लगाव की कमी के रूप में चुकानी पड़ रही है।

अभी चंद दिनों पहले कानपुर से एक खबर आई थी कि एक इकलौते बेटे ने कनाडा से वीडियो काल के जरिये अपने पिता को अंतिम संस्कार कर विदाई दी। सोचिए हमारा समाज किस दिशा में बढ़ चला है। जिस पिता ने अपने बेटे की सफलता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, वही जीवन के अंतिम समय में एकाकीपन और घुटन भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गया। आज हमारे समाज का यही कड़वा सच हो चला है। जो मानवीय मूल्यों के ह्रास का जीता-जागता उदाहरण है। इसे जितनी जल्दी हो सके बचाने का सामाजिक मुहिम शुरू होनी चाहिए, वरना समाज में एकाकीपन का रोग किसी महामारी से कम नहीं होगा।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

विपक्ष के पास एक मजबूत नेता का अभाव

'विपक्ष की रणनीतिक दुर्बलता' शीर्षक से लिखे आलेख में डा. एके वर्मा ने विपक्ष के महत्वहीन, भ्रामक एवं कमजोर चुनावी मुद्दों पर प्रकाश डाला है, जो कि सत्य है। विपक्ष ने 18वीं लोकसभा के इस चुनाव में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों, विदेश, प्रतिरक्षा, शिक्षा, कृषि एवं आर्थिक गतिविधियों से संबंधित स्पष्ट नीतियों को जनता के सामने नहीं रखा है। और न ही अपने सभी सहयोगी दलों की सहमति से अपने राष्ट्रीय नेता का चेहरा स्पष्ट किया है। इन सबके बीच राहुल गांधी अपनी छवि एक सशक्त, मजबूत और राष्ट्रहित में कड़े निर्णय लेने वाले नेता के रूप में अभी तक नहीं बना पाए हैं। भारतीय जनता के मानस पटल पर अभी भी उनकी छवि एक अपरिपक्व, स्वयं की कोई राष्ट्रीय विचारधारा न होना, किसी भी राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक एवं वैश्विक परिदृश्य की चुनौती से न निपट पाने वाले नेता की ही है। विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं की स्थिति भी ज्यादा मजबूत नहीं है। कुल मिलाकर कर विपक्ष जनता को भाजपा के मुकाबले एक राष्ट्रीय नेता और वैकल्पिक नीति नहीं दे पाया है। इसके उलट वे अनुच्छेद-370 को वापस लाने, जीएसटी को खत्म करने जैसे औचित्यहीन मुद्दों को लेकर जनता के बीच घूम रहे हैं। अगर विपक्ष के पास इस आम चुनाव में एक सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता होता, महंगाई नियंत्रण की सुस्पष्ट नीति होती, रोजगार सृजन का रोडमैप होता, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का विजन होता, पुरातन पड़ चुकी स्कूली एवं उच्च शिक्षा नीति, राष्ट्रीय चिकित्सा नीति, राष्ट्रीय कृषि नीति को वर्तमान जरूरतों के अनुसार बदलने की मंशा होती, समावेशी विकास को विस्तार देने की इच्छाशक्ति होती तो वह भाजपा को जरूर इस बार कड़ी टक्कर दे सकता था।

धीरेंद्र उत्तम, उन्नाव

विपक्ष की दुर्बलता

लोकतंत्र को जीवन शक्ति प्रदान करने वाले चुनाव अब चरम सीमा पर हैं। भाजपा के 'चार सौ पार' वाले विश्वसनीय आह्वान से विपक्ष तितर-बितर होता नजर आ रहा है। 'मोदी हटाओ' की ललकार अब ठंडी पड़ गई है। अंततः विपक्ष को राष्ट्रीय मुद्दों से परहेज हो गया है। मुख्य धारा को छोड़कर केवल सत्ता के लालच में अपने दायित्व से मुखर जाने वाली सियासत से मतदाता को प्रभावित करना मुश्किल है। विपक्ष के पास रेवड़ियां बांटने के अलावा कोई स्पष्ट नीति नहीं है। न तो उनके पास शिक्षा, आरोग्य, कृषि, विदेश, विकास, आर्थिक, रोजगार, उद्योग नीतियों की निश्चित रूपरेखा का कोई रोडमैप है। विपक्ष का संगठन भी मजबूत नहीं है और यह सबसे बड़ी कमजोरी है। आइएनडीआइए के सभी घटक दल कभी भी बिखर जाने की आशंका से भयभीत हैं। जातीय ध्रुवीकरण की बात करने वाले विपक्ष को समझना होगा कि सभी जाति-पंथ के लोग भाजपा से जुड़ गए हैं। विपक्ष को मजबूत संगठन के साथ, दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा तभी राष्ट्रीय राजनीति के द्वार खुल पाएंगे वरना सत्ता का सिंहासन एक स्वप्न बनकर रह जाएगा।

नूतन कुमार, नोएडा

अनावश्यक संदेह

संदेह का कोई इलाज नहीं है, बल्कि विश्वास करना ही इसका उपयुक्त विकल्प है। शिकवे-शिकायत में संदेह की कहीं जगह नहीं है। बेशक इसका निपटारा करने के लिए उसके साथ अकाट्य सुबूतों की जरूरत होती है। न्यायालय भी दुर्लभ से दुर्लभ केसों में संदेह के आधार पर आरोपियों को बरी कर देता है। चुनाव आयोग ने जिस मजबूती के साथ विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है, उससे अब लगता है कि खासकर कांग्रेस को अब चुनाव आयोग पर अंगुली उठाने से पहले जरूर विचार करना होगा। कांग्रेस को चुनाव आयोग में जाने के पूर्व उच्चतम न्यायालय के उस आदेश का अध्ययन कर लेना चाहिए था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शत-प्रतिशत वीवीपैट के मिलान की मांग खारिज करते हुए ईवीएम पर भरोसा जताया है। हालांकि अब तक राज्यों के निर्वाचन विभागों और केंद्रीय निर्वाचन आयोग को कांग्रेस के मुकाबले भाजपा ने अधिक संख्या में शिकायतें की हैं।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का 75
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

एक समय में एक काम करो, ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ।
-स्वामी विवेकानंद

विशाल घरेलू बाजार ही भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत है, जिसके बारे में यूबीएस सिक्यूरिटीज का अनुमान है कि अगले दो वर्षों में यह जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार हो सकता है।

बड़े बाजार की ताकत

आर्थिक अनिश्चितताओं और वैश्विक युद्धों के बीच यूबीएस सिक्यूरिटीज की रिपोर्ट का यह कहना कि भारत 2026 तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार हो सकता है और इस क्रम में इसके 2024 में जर्मनी और 2026 में जापान को पीछे छोड़ने की उम्मीद है, देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था के प्रति आश्वस्त करता है। पिछले एक दशक में भारत में खपत लगभग दोगुनी होकर 21 खरब डॉलर तक पहुंच चुकी है, और, 2023 में तो यह चीन, अमेरिका और जर्मनी से भी तेज गति से बढ़ी है, तो इसका श्रेय नीतिगत पहलों व संरचनात्मक सुधारों के अलावा, देश के विशाल घरेलू बाजार को भी जाता है, जिसमें उत्पादन को खपाने की विराट क्षमता मौजूद है। राजनीतिक व आर्थिक मोर्चे पर चीन ने जिस तरह से दुनिया का भरोसा खोया है, उससे चीन पर से आपूर्ति शृंखला की निर्भरता को कम करने की वैश्विक प्रवृत्ति ही दिखती है, जो भारत के लिए फायदेमंद साबित हुई है। रिपोर्ट बताती है कि देश में समृद्ध तबके (सालाना करीब साढ़े आठ लाख रुपये से ज्यादा कमाने वाले) की आबादी अगले पांच वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। लोगों के पास पैसा आएगा, तो खर्च भी होगा। एनारॉक की रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है, जिसके अनुसार, पिछले पांच वर्षों में देश में महंगे घरों की बिक्री तिगुनी हुई है। इसके अलावा, देश की करीब 33 फीसदी आबादी 20 से 33 वर्ष आयु वाले उपभोक्ताओं की है, जो स्वाभाविक ही ज्यादा खर्चीले होते हैं। बढ़ता शहरीकरण भी एक अन्य वजह है, जिससे बड़ी-बड़ी कंपनियां आसानी से उपभोक्ताओं तक पहुंच रही हैं। फिच सॉल्यूशंस कंपनी बीएमआई ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि प्रति उपभोक्ता व्यय के मामले में भारत जल्द ही इंडोनेशिया, थाईलैंड व फिलीपीन जैसी सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को पछाड़ देगा। देश में पिछले एक दशक में प्रति उपभोक्ता व्यय अवश्य ही गांवों व शहरों में दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। पर चिंता की बात यह है कि इसमें

गैर-खाद्य उत्पादों पर व्यय बढ़ा है, जबकि खाद्य उत्पादों पर घटा है। इसके अलावा, सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट भी कहती है, उपभोक्ताओं में घरेलू बचत कम करने और ज्यादा व्यय करने की भौतिकतावादी प्रवृत्ति बढ़ी है। कुल मिलाकर देखें, तो भारत में आपूर्ति को खपाने के लिए पर्याप्त मांग है। और यही चीज इसे दूसरे एशियाई और उभरते प्रतिस्पर्धी बाजारों की तुलना में महत्वपूर्ण लाभ देती है। लेकिन उपभोग में बढ़ोतरी को बनाए रखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार सृजन की जरूरत होगी, जिस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

क्या बाइडन हार की ओर बढ़ रहे हैं

बुजुर्ग बाइडन के चुनावी अभियान के साथ समस्या यह है कि उसे ऐसे चलाया जा रहा है, मानो वह पहले स्थान पर हों। मानो वह उस बढ़त की रक्षा कर रहे हों, जो उनके पास है ही नहीं। ट्रंप को हराने के लिए ट्रंप जैसा होना जरूरी नहीं।

रॉस डॉट
द न्यूयॉर्क टाइम्स

फरवरी में इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि बढ़ती उम्र और डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले कमजोर प्रतीत होते राष्ट्रपति बाइडन को क्या लड़ाई से हट जाना चाहिए। इस पर मैंने एक कॉलम लिखा था, लेकिन कुछ लोगों का तर्क था कि बाइडन को चुनावी दौर से हटने पर विचार करना चाहिए, जिसमें मतदान विशेषज्ञ नैट सिल्वर और मेरे सहयोगी एजरा क्लेन भी शामिल थे। विशेष वकील रॉबर्ट हूर की रिपोर्ट भी, जिसमें राष्ट्रपति को याददाश्त की समस्या का संकेत दिया गया था, बहस का हिस्सा थी। हालांकि, फिर स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के बाद बाइडन के मतदान प्रतिशत में मामूली सुधार हुआ, जिसे डेमोक्रेटिक पक्ष के आशावादियों ने लपक लिया और बाइडन के चुनाव से हटने की चर्चा दब गई।

अब मई आ गया है और चुनाव में छह महीने ही बचे हैं, लेकिन मूल बहस अब भी कायम है। बाइडन की बढ़त मामूली ही थी। वह राष्ट्रीय मतदान में अब भी थोड़ा पीछे ही हैं और जॉर्जिया, मिशिगन, एरिजोना, नेवादा, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में ट्रंप से पीछे चल रहे हैं, जिसने पिछली बार डेमोक्रेट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में जीत दर्ज की थी। हालांकि अंतर कम है: संभवतः तीन या चार पॉइंट। लेकिन यह लगातार जारी है। पिछली गिरावट के बाद से दोनों उम्मीदवारों के बीच बहुत कम फासला है।

हालांकि इस स्थिरता के प्रति डेमोक्रेट की प्रतिक्रिया अकारण विश्वास को अकारण भाग्यवाद से जोड़ती है। एक तरफ यह विश्वास है कि ट्रंप की बढ़त टिकाऊ नहीं है, क्योंकि उनकी भी एक सीमा है और वह 50 फीसदी से आगे बढ़ नहीं सकते (पर क्या कई प्रतिष्ठित तीसरे पक्ष के उम्मीदवारों के साथ दौड़ में यह बात मायने रखती है?), क्योंकि मतदाता अब भी बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं (लेकिन क्या वे दोनों उम्मीदवारों को पहले से अच्छी तरह से नहीं जानते हैं)। अप्रैल, 2020 में बाइडन ने 538 मतदान औसत में लगभग पांच अंकों से बढ़त हासिल की। उन्होंने

4.4 प्रतिशत की गिरावट के साथ लोकप्रिय वोट जीता, क्योंकि ट्रंप के मुकदमों का अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है। लेकिन अगर वह बरी हो गए, तो?

दूसरी तरफ 'हम क्या कर सकते हैं' जैसी चिढ़ रखने वाले लोग कहते हैं कि बाइडन को अब तक की अपनी नीति एवं राजनीतिक नजरिये से हट जाना चाहिए। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। जनता बस कृतघ्न है या भ्रमित है, मीडिया द्वारा गुमराह है या पक्षपात में अंधी है! उन्हें 10 अंकों से ऊपर होना चाहिए! यदि वह इस रिकॉर्ड के साथ नहीं जीत सकते, तो अमेरिका को जो मिलेगा, वह उसी का हकदार है!

बाइडन की स्थिति का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण है। एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि यदि आप चुनाव में ट्रंप को लगातार हराना चाहते हैं, तो आपको सतर्क रहना होगा, अपने मूल सिद्धांतों पर टिके रहकर वोट पाने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और हर अवसर पर सामान्य स्थिति दर्शानी होगी। डेमोक्रेट्स ने 2018 और 2020 में यही किया था, जब वे ट्रंप को हराने में सफल रहे थे।

दूसरी तरफ यदि आप (बाइडन) ट्रंप से हार रहे हैं, तो आप उन घटनाओं या ट्रंप के थकने पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहें, कि वे जादुई रूप से आपके बचाव में आएंगी। इसके बजाय आपको एक ऐसी रणनीति बनाने की जरूरत है, जो चुनौतियों के अनुरूप हो और ट्रंप की असामान्यता से निपटने के लिए राजनीति के सामान्य नियमों को तोड़ने के लिए तैयार रहे (जैसा कि ट्रंप के रिपब्लिकन विरोधी 2016 और 2020 में करने में विफल रहे)।

बाइडन के अभियान के साथ समस्या यह है कि उसे ऐसे चलाया जा रहा है, मानो वह पहले स्थान पर हों। मानो वह उस बढ़त की रक्षा कर रहे हों, जो उनके पास है नहीं। यानी उन्हें उन बड़े कदमों को नकारना होगा, जिसका आग्रह क्लेन और अन्य लोगों ने किया था, जिसमें शारीरिक एवं राजनीतिक सीमाओं की देशभक्तिपूर्ण पहचान अलोकप्रिय शासक को किनारे हटने के लिए प्रेरित करती है और उसकी पार्टी को चुनाव की शर्तों को फिर से निर्धारित करने का मौका देती है। इसका मतलब छोटे टिकट परिवर्तन से बचना है, जिसमें कमला हैरिस एक उम्रदराज राष्ट्रपति के लिए सबसे खराब संभावित सहयोगी हैं, उपराष्ट्रपति पद के लिए वह वास्तव में आश्वस्त करने वाली हैं और लोकप्रिय भी हो सकती हैं।

और इसका मतलब है प्रशासन की नीति-निर्धारण प्रक्रिया को स्वचालित ढंग से चलने देना। क्या एक नियामक योजना शुरू की जा सकती है, जिसका लक्ष्य गैसोलीन से चलने वाली कारों को धीरे-धीरे समाप्त करना है? बिल्कुल वही, जो वे मध्य पश्चिमी प्रांत चाहते हैं। देशभर के स्कूलों में लैंगिक भेदभाव मिटाने के लिए उनकी नीतियां चुनावी वर्ष के बिल्कुल मुफीद हैं। नया छात्र ऋण माफी कार्यक्रम, जिसकी लागत उच्च मुद्रास्फीति के बावजूद 10 खरब डॉलर से ज्यादा हो सकती है, युवा मतदाता को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि हाल ही में हार्वर्ड यूथ पोल में छात्र ऋण को 16 मुद्दों में से 16वें स्थान पर रखा गया था। क्या आव्रजन पर नया आक्रामक कार्यकारी आदेश यह साबित करने के लिए जारी किया जाएगा कि यदि रिपब्लिकन सहयोग नहीं करते हैं, तो बाइडन सीमा सुरक्षा में सुधार के लिए एकतरफा कार्य करेंगे? भविष्य में इस पर विचार किया जा सकता है।

बाइडन के पास अब भी चुनाव जीतने का मौका है, क्योंकि कुछ अंकों की कमी पूरी की जा सकती है। वह अंतिम क्षण में कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं, जिस पर मतदाता ज्यादा ध्यान देंगे। मुद्रास्फीति पर सकारात्मक खबरों और पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम से उन्हें बढ़त मिल सकती है। ट्रंप को दोषी साबित हो सकते हैं और पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में दो प्रतिशत का महत्वपूर्ण अंक गंवा सकते हैं। केनेडी के समर्थन का वामपंथी हिस्सा बाइडन के पाले में आ सकता है, जबकि ट्रंप हितैषी हिस्सा तीसरे पक्ष से चिपका रह सकता है। ट्रंप के असंतुष्ट एवं मतदान के अनिच्छुक समर्थक मतदान के दिन गायब रह सकते हैं। पर हरके कुछ महीने पर वास्तविकता की जांच करना अच्छा होगा कि वास्तव में ट्रंप को रोकने वाले उस अभियान का क्या हो रहा है, जिसे बाइडन ने तय किया था और जिसे केवल वही चला सकते हैं। फिलहाल जो हो रहा है, वह यह है कि बाइडन हार की ओर बढ़ रहे हैं।

©The New York Times 2024

https://t.me/AINewsPaperPaid

जीवन धारा

शिवानी दीदी

अपने अतीत को भूल जाएं। इसे जितना याद रखेंगे, उतने ही अधिक परेशान होंगे। भूत को भूलने के लिए मन को स्थिर करना होगा, और यहां काम आएगा-ध्यान यानी मेडिटेशन।

कड़वी यादों को भूलना सीखें

कभी-कभार कोई हमारे सामने या हमसे जुड़ी कुछ ऐसी बात बोल देता है, जिसे भूलना अत्यंत कठिन हो जाता है। वह तो यह बात दो मिनट में कह जाता है, लेकिन हमें उसे भूलने में दो महीने या दो साल तक लग जाते हैं। दो मिनट में कुछ भी होता है, आप उसे हमेशा के लिए याद रख लेते हैं। आप अपने दिमाग में उस बात को दोहराते रहते हैं। जब किसी से बात होती है, तब भी आप उस घटना का जिक्र करते हैं। आप अपने मस्तिष्क में उस दृश्य का चित्रण हर समय करते ही रहते हैं। आप हर समय उस घटना का विभिन्न दृष्टिकोण से विश्लेषण करते रहते हैं और उसे सही-गलत-बुरा-दुखद आदि जैसी बातों से जज करने लगते हैं। आप जितनी बार उस घटना पर विचार करेंगे, उतनी ही बार और उतना ही ज्यादा आप नए-नए निष्कर्षों तक पहुंचेंगे। इनमें से अधिकांश बातों का स्वभाव नकारात्मक ही होता है।

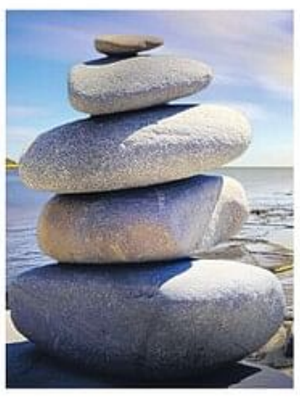

ऐसा करने से आप अपने मस्तिष्क में मौजूद इस घटना को और मजबूती प्रदान करते हैं। पहले वह आपके अवचेतन मन में रहती है और धीरे-धीर वह आपकी चेतना में घर कर जाती है। ऐसी स्थिति में वर्षों बाद भी आपको उनके द्वारा कही गई बातें याद रहती हैं। जबकि जिस व्यक्ति ने वह बात कही थी, वह तो कब का उसे भूलकर आगे बढ़ चुका है। यह कुछ ऐसा है कि आपका पड़ोसी अपने घर का कूड़ा निकालकर आपके घर में फेंककर भूल जाता है कि उसने कुछ किया था। अब उस कूड़े को साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है। वह तो ऐसा करके अपने घर को साफ कर चुका है। कोई आपसे अपशब्द कहता है और फिर इसे भूल जाता है, परंतु उन अपशब्दों का आपके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है।

हमें यह समझना चाहिए कि अतीत अब बीत चुका है। उसके साथ जुड़ी यादें भी बीत चुकी हैं। आपके पास अगर कुछ है, तो वह है वर्तमान, जिसे जीना और अपने लिए उसे खुशगवार बनाना आपकी जिम्मेदारी है।

हमें सबसे अधिक काम वर्तमान को लेकर करना चाहिए, सबसे ज्यादा सावधानी वर्तमान के प्रति रखनी चाहिए। इसी अवस्था में जीवन जीवंत है। भूतकाल में जीवन के साथ यादें हैं, भविष्य में जीवन एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान में जीवन जिंदा है। जिंदगी को जिंदा देखना हो, तो वर्तमान को ठीक से जीना सीखना होगा। वैसे तो मुर्दे के पास भी एक जिंदगी होती है। आखिरी सांस लेने के बाद जलाए या दफनाए जाने तक जो समय होता है, वह मुर्दे की जिंदगी है। हमने यदि वर्तमान को नहीं समझा, तो हमारी जिंदगी भी मुर्दे की तरह है। वर्तमान कितना बारीक है, थोड़ा इसे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान तुरंत अतीत में बदल जाता है और भविष्य शीघ्र वर्तमान में उतर आता है। अपने अतीत को भूल जाएं। इसे जितना याद रखेंगे, उतने ही अधिक परेशान होंगे। भूत को भूलने के लिए मन को स्थिर करना होगा, और यहां काम आएगा-ध्यान यानी मेडिटेशन। जब हम ध्यान में उतरते हैं, तो अपने भूतकाल को भूल रहे होते हैं।

कल से ऊंचा आज...

सूत्र

भविष्य के प्रति सबसे बड़ी सावधानी तो यह रखना है कि हमारा भविष्य भूत और वर्तमान से हमेशा ऊंचा ग्राफ लिए हो। यानी आने वाला कल, जो कि कुछ समय बाद हमारा आज बन जाएगा, इसके ग्राफ में हमेशा ऊंचाई लिए हो। सीधी-सी बात है, हर आने वाला कल आज से ऊंचा होना चाहिए। इसको लेकर बहुत सावधान रहिए।

दूसरा पहलू

बड़ी संख्या में सैनिकों की गुमशुदगी यूक्रेन के लिए बड़ा धक्का है। इससे यूक्रेनी समाज और राष्ट्रपति जेलेंस्की पर भी दबाव बढ़ा है।

लापता सैनिक और परेशान परिजन

दो यूक्रेनी सैनिकों के शव महीनों तक एक खेत में पड़े थे। उनके परिजनों को ड्रोन द्वारा लिए गए फुटेज से उनके बारे में पता चला। दूसरी ओर, यूक्रेन की सेना चार महीने बाद भी उन दो सैनिकों की तलाश में लगी थी! मारे गए दो सैनिकों में से एक जेरेटेस्की की पत्नी कहती हैं कि मोर्चे पर मारे जाने पर ब्रिगेड कमांडर को चाहिए था कि वह इस बारे में उन दो सैनिकों के परिजनों को सूचित करें। यूक्रेन की सेना के इस रवैये से वे लोग परेशान हैं, जिनके परिजन मोर्चे पर लड़ रहे हैं।

सरकार ने अब तक नहीं बताया है कि कितने सैनिक लापता हैं। हालांकि विगत फरवरी में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मृत सैनिकों का आंकड़ा लगभग 31,000 बताया, जबकि अमेरिकी आकलन के मुताबिक, करीब 70,000 यूक्रेनी सैनिक तो विगत अगस्त तक ही मारे गए थे। यूक्रेनी सैनिकों की मौत के आंकड़ों में सबसे ज्यादा दुखद यह है कि इनमें से बड़ी संख्या में सैनिकों के शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्योंकि अनेक जगह खाइयों में लड़ते हुए मारे जाने के बाद शव वहीं पड़े रहते हैं, और कई बार तो वे नजर भी नहीं आते। इसके अलावा माना जाता है कि अनेक यूक्रेनी सैनिक रूस के कब्जे में हैं।

मारिया वरन्निकोवा

फरवरी में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मृत सैनिकों का आंकड़ा 31,000 बताया। अमेरिका के मुताबिक, करीब 70,000 यूक्रेनी सैनिक तो विगत अगस्त तक ही मारे गए थे।

मारे गए या गायब सैनिकों के मामले में सेना और सरकार के रवैये से नागरिकों का धैर्य चुक रहा है। इस मामले में जेलेंस्की सरकार की भी सीमाएं हैं, क्योंकि रूस कब्जे में आए यूक्रेनी सैनिकों की सूचनाएं साझा नहीं करता।

लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में सीनियर फेलो बेन बैरो कहते हैं, 'बड़ी संख्या में सैनिकों की गुमशुदगी यूक्रेन के मनोबल के लिए धक्का तो है ही, इससे वहां के समाज, उसके सैन्य नेतृत्व और राष्ट्रपति जेलेंस्की पर भी दबाव बढ़ा है। यह एक भीषण समस्या है।'

मारे गए या गायब सैनिकों के मामले में सेना और सरकार के रवैये से नागरिकों का धैर्य चुक रहा है। क्षुब्ध नागरिकों ने पिछले अक्तूबर में राजधानी कीव में एक विशाल रैली की। उसके बाद भी नागरिकों ने कई बार विरोध प्रदर्शन कर कहा कि सरकार को ज्यादा पारदर्शिता बरतनी चाहिए। हालांकि इस मामले में जेलेंस्की सरकार की भी परेशानियां हैं, क्योंकि रूस कब्जे में आए यूक्रेनी सैनिकों के बारे में कोई सूचना नहीं देता। इससे सबसे ज्यादा परेशानी सैनिकों के परिजनों को होती है। अल्योना बोंदर का सैनिक भाई विगत सितंबर से लापता है। सेना के रवैये से हताश अल्योना ने एक ज्योतिषी की मदद ली, जिसने भाई के जीवित होने की बात कही। 'क्या मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए', हताश अल्योना कहती हैं। कुल मिलाकर, लंबे चलते युद्ध में रूस से पिछड़ने के अलावा सैनिकों के परिजनों का क्षोभ भी यूक्रेन और राष्ट्रपति जेलेंस्की को परेशान कर रहा है।

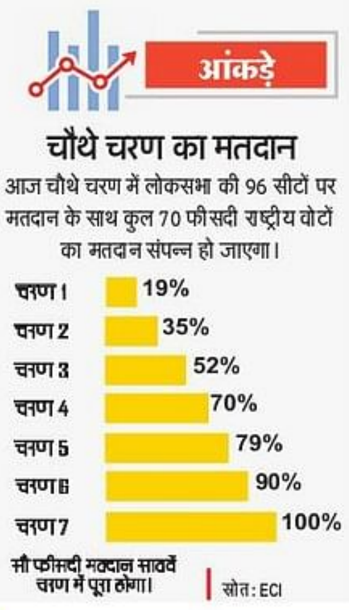

©The New York Times 2024

आंकड़े

चौथे चरण का मतदान

आज चौथे चरण में लोकसभा की 96 सीटों पर मतदान के साथ कुल 70 फीसदी राष्ट्रीय वोटों का मतदान संपन्न हो जाएगा।

चरण 1	19%
चरण 2	35%
चरण 3	52%
चरण 4	70%
चरण 5	79%
चरण 6	90%
चरण 7	100%

सौ फीसदी मतदान सातवें चरण में पूरा होगा। | स्रोत: ECI

राजा ने उस मंत्री को खोजने के लिए कहा, जो हर बात पर कहता कि भगवान की कृपा है। राजा को एहसास हो गया कि जो होता है, वह भले के लिए होता है।

भगवान की बड़ी कृपा है

अंतर्यात्रा
संकलित

एक राजा का मंत्री भगवान का भक्त था। कोई भी बात होती, तो वह कहता कि भगवान की बड़ी कृपा है। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा है। राजा को गुस्सा आया, पर वह चुप रहा। एक बार तलवार से राजा की उंगली कट गई, मंत्री ने फिर कहा, भगवान की बड़ी कृपा है। राजा ने गुस्से में मंत्री को राज्य से बाहर निकाल दिया।

एक बार राजा जंगल में शिकार करने गए, तो अकेले पड़ गए। डाकुओं ने दल ने राजा को पकड़ लिया और काली माता के सामने बलि देने के लिए ले गए। बलि देने से पहले डाकुओं के पुरोहित ने पूछा, क्या तुम्हारा बेटा जीवित है। राजा ने कहा, नहीं, तो पुरोहित बोला, इसका तो हृदय जला हुआ है, इसकी बलि कैसे दे सकते हैं? डाकुओं ने कहा, हो सकता है, यह मरने के डर से झूठ बोल रहा हो। तब पुरोहित ने राजा के अंगों की जांच की, तो उंगली कटी पाई। पुरोहित ने कहा, इसका अंग भंग है, इसकी बलि नहीं दे सकते। इसे छोड़ दो।

इसके बाद राजा को उस मंत्री की याद आई, जो कहा करता था, ईश्वर की बड़ी कृपा है। राजा ने उस मंत्री को ढूंढकर लाने के लिए कहा, क्योंकि उसे यह बात समझ में आ गई कि जो कुछ होता है, वह भले के लिए होता है।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 30 अप्रैल, 1983

इस बार मानसूनी वर्षा न होना संभावित

इस बार मानसूनी वर्षा न होना संभावित

हिमाचल प्रदेश के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजकुमार राजू ने यह आशंका व्यक्त की है कि इस वर्ष मानसून उस दर्जे का नहीं होगा, जिसकी आशा देश के कृषि वैज्ञानिक और किसान लगाए बैठे हैं।

एक महिला आईपीएस और घरेलू हिंसा

यह सोच गलत है कि घरेलू हिंसा का शिकार केवल वही महिलाएं होती हैं, जो आर्थिक रूप से पति पर निर्भर रहती हों।

ऋतु सारस्वत | समाज

बीते दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 'किसी महिला के सशक्त पद पर होने का मतलब यह नहीं है कि वह घरेलू हिंसा का शिकार नहीं हो सकती।' यह टिप्पणी सत्र न्यायालय के उस फैसले की सुनवाई करते हुए दी गई, जिसमें सत्र न्यायालय ने कहा था कि 'एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ घरेलू हिंसा नहीं हो सकती।'

अमूमन माना जाता है कि घरेलू हिंसा का शिकार वे महिलाएं होती हैं, जो आर्थिक रूप से पति पर निर्भर हों। इसके पीछे वे तमाम अध्ययन हैं, जो बताते हैं कि घरेलू हिंसा का सामना ज्यादातर निम्न आर्थिक एवं सामाजिक स्तर की महिलाओं को करना पड़ता है। परंतु आज तक कोई भी शोध यह दावा नहीं कर पाया है कि कामकाजी व सशक्त महिलाएं घरेलू प्रताड़नाओं से मुक्त हैं। एबिगेल बीट्जमैन का अध्ययन 'विमेन ऐंड मेन्स रिलेटिव स्टेट्स ऐंड इंटिमेट पार्टनर वायलेंस इन

इंडिया' बताता है कि जिन परिवारों में महिलाएं कामकाजी और पति से अधिक कमाने वाली हैं, उन्हें भी घरेलू हिंसा सहनी पड़ती है। बीट्जमैन कहती हैं कि घर की शक्ति-नियंत्रण की गतिशीलता पितृसत्तात्मक ढांचे में कुछ इस तरह आत्मसात हो चुकी है कि नियंत्रण रखने की मानसिकता इससे जरा भी प्रभावित नहीं होती है कि महिला आर्थिक रूप से सक्षम है या नहीं। अंतर सिर्फ इतना है कि आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएं कई बार प्रताड़नाओं का विरोध कर पाती हैं।

दुनिया भर के विभिन्न समाजों में महिलाओं को उनकी लैंगिक भूमिकाओं के अनुरूप समाजीकृत किया जाता है और यह प्रक्रिया आधुनिकीकरण के तमाम दावों के बीच भी सफल वैवाहिक जीवन के निर्वहन का समस्त दायित्व स्त्री के कंधों पर डालती है और बड़ी ही निष्ठुरता से यह स्वीकार करती है कि वैवाहिक जीवन के उतार-चढ़ावों के बीच महिला का धैर्य और त्याग विवाह के स्थायित्व की नींव बनता है। इस 'धैर्य' की परिभाषा में मौखिक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार को सहजता से स्वीकारना भी शामिल है। स्पष्ट है कि यह नियम कामकाजी महिलाओं पर भी लागू होता है।

पुरुष के आक्रामक व्यवहार पर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत तर्क देता है कि पुरुष अपनी भावनात्मक असुरक्ष व तनाव की भरपाई करने के लिए अति पुरुषोचित व्यवहार करता है। आवेगी स्वभाव, आक्रामकता, विषाक्त पुरुषत्व, नियंत्रण की प्रवृत्ति और असुरक्षा जैसे कारक पुरुषों को जीवनसाथी को प्रताड़ित करने के लिए उकसाते हैं। सवाल यह है कि दुनिया भर में महिलाएं क्यों खामोशी से घरेलू हिंसा को स्वीकारती आ रही हैं। निस्संदेह इसके पीछे सामाजिक व पारिवारिक प्रतिष्ठा धूमिल होने का भय है। महिलाएं शुरू में यह सोचकर प्रताड़ना सहती हैं कि यह अल्पावधि के लिए है। भविष्य में उसके साथी का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन जैसे-जैसे पीड़िता अपमानजनक व्यवहार को स्वीकार करती है, मौखिक या मनोवैज्ञानिक प्रताड़ना उसके मस्तिष्क में मजबूत हो जाती है, जिससे उसके लिए समय के साथ दुर्व्यवहार की गंभीरता को पहचानना मुश्किल हो जाता है।

अल्बर्ट बंडूरा की 'सोशल लर्निंग थ्योरी' परिवार के भीतर हिंसा के कई पीढ़ियों तक संचरण की चर्चा करती हैं। इसके अनुसार बच्चे अंतरंग साथी के बीच हिंसा को पारिवारिक वातावरण में देखने और नकल करने की प्रक्रिया के जरिये 'हिंसक व्यवहार' को आत्मसात कर लेते हैं। घरेलू हिंसा राष्ट्र के विकास को प्रभावित करती है तथा समाज के आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण को बाधित करती है। शोधों से पता चलता है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की लागत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दो प्रतिशत हो सकती है। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम पर प्रतिक्रियाएं ध्रुवीकृत हैं। एक धड़ा जहां महानगरों में रहने वाले कुलीन वर्ग द्वारा इसके दुरुपयोग की शिकायत कर रहा है, वहीं दूसरा धड़ा पितृसत्ता के कठोर ढांचे में दबी ग्रामीण महिलाओं के लिए इसकी निरर्थकता पर ठप्पा लगा चुका है। इसलिए घरेलू हिंसा से निपटने के लिए कानून से अधिक, ठोस एवं समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। घरेलू हिंसा पीड़ितों को समझना होगा कि शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रताड़नाओं को सहने से पारिवारिक वातावरण सुखद नहीं होगा और न ही भावी पीढ़ी का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है।

edit@amarujala.com

चिंतन

चीन के साथ व्यापार घाटे को नियंत्रित करे भारत

भारत और चीन का संबंध बहुत ही जटिल है। सीमा विवाद के चलते अदावत भी है और ट्रेड के मोर्चे पर बड़ा साझेदार भी है। भारत चीन के जीडीपी में बड़ा योगदान दे रहा है, फिर भी चीन भारत का हो हरसंभव नुकसान भी कर रहा है। वर्ष 2020 में गलवान की हिंसक सैन्य घटना के बाद भारत में चीनी सामान के बहिष्कार की हवा चली। अनेक संगठनों ने चीन से आयात न करने की कसमें खाईं, यह माना गया कि अगर भारत चीन से आयात नहीं करेगा तो इससे चीन को तगड़ा धक्का लगेगा और चीन के लिए भारत की नाराजगी बर्दाशत करना आर्थिक रूप से महंगा पड़ेगा, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। भारत चीन से आयात करता है। यह आयात समय के साथ बढ़ता ही गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार फिर से बन गया है। इससे पहले अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। अमेरिका के साथ व्यापार फिर भी संतुलित है, जिसमें भारत अधिक निर्यात कर रहा है, और कम आयात कर रहा है, लेकिन चीन के साथ व्यापक स्तर पर व्यापार घाटा है। भारत बहुत अधिक चीन से आयात कर रहा है और बहुत कम चीन को निर्यात कर रहा है। बीते वित्त वर्ष 2023-24 को ही लें, तो भारत और चीन के बीच 118.4 अरब डॉलर का आपसी व्यापार हुआ, जिसमें चीन से भारत का आयात 3.24 प्रतिशत बढ़कर 101.7 अरब डॉलर हो गया, वहीं चीन को भारत का निर्यात 8.7 प्रतिशत बढ़कर 16.67 अरब डॉलर हो गया। यानी चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा करीब 85 अरब डॉलर का है। यह बहुत बड़ा असंतुलन है। इस असंतुलन को ठीक करने की जरूरत है। या तो भारत चीन से आयात कम करे और अपनी आपूर्ति के लिए नया विकल्प तलाशे, या फिर भारत चीन को आयात बढ़ाने के लिए बाध्य करे। भारत और चीन के बीच व्यापार असंतुलन कई दशकों से है। भारत सरकार को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। यह सही है कि आज दुनिया ट्रेड संजाल में आपस में गुंथी हुई है, पर भारत को अपने हितों का ध्यान रखना होगा। भारत को चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए ट्रेड कूटनीति का इस्तेमाल करना चाहिए। आज हजारों चीनी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। यही स्थिति भारतीय कंपनियों के लिए भी चीन में होनी चाहिए। भारत का चीन को अयस्क, सूती धागा/कपड़े/मेडअप, हथकरघा, मसाले, फल, सब्जियां, प्लास्टिक और लिनोलियम जैसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ा है। भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक सामान, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर, ऑर्गेनिक केमिकल, फर्टिलाइजर, गाड़ियों से जुड़ा सामान, केमिकल प्रोडक्ट्स, आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील का सामान और एलुमिनियम आदि का आयात करता है। भारत का चीन व अमेरिका के साथ व्यापार के आंकड़े में मामूली अंतर है। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़ों के मुताबिक, भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 118.3 अरब डॉलर रहा है। 2021-22 और 2022-23 में अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, चीन 2013-14 से 2017-18 तक और 2020-21 में भी भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था। चीन से पहले, संयुक्त अरब अमीरात देश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। अर्थव्यवस्था की गति के लिए जरूरी है कि भारत का वैश्विक ट्रेड लगातार बढ़ता रहे, लेकिन चीन के साथ इतने बड़े व्यापार असंतुलन को नियंत्रित किए जाने की जरूरत है।

सारा संसार

हिमाचल प्रदेश में चामुंडा देवी का यह पहाड़ी मंदिर, 51 शक्ति पीठों में से एक, जो बानेर नदी के तट पर पश्चिम पालमपुर की ओर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यह हिमाचल के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में से एक है। चामुंडेश्वरी देवी को देवी दुर्गा के सबसे शक्तिशाली अवतारों में से एक कहा जाता है। इस मंदिर का खास त्यौहार नवरात्रि है, जहां हजारों की संख्या में भक्त यहां दर्शन करने के लिए आते हैं।

मजबूर नहीं, बहुमत की बने सरकार

मतदान
डॉ. भारत

अपने इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस का स्ट्राइक रेट गिर रहा है; दूसरी ओर, पिछले कुछ चुनावों में भाजपा सीटों और स्ट्राइक रेट के मामले में दोनों मोर्चों पर बढ़त का रुझान दिखा रही है। राजग के तहत लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा द्वारा लड़ी जा रही सीटों की संख्या भाजपा के प्रभुत्व को दर्शाती है, जबकि 2024 में कांग्रेस द्वारा लड़ी जा रही सीटों की संख्या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के आत्मसमर्पण को प्रतिबिंबित करती है। हालांकि गठबंधन सरकार की अंतर्निहित सीमाएं होती हैं, लेकिन मतदाताओं के सामने प्रश्न यह है कि उनका मत सामर्थ्य वाली 'मजबूत सरकार' के लिए हो या फिर 'मजबूर सरकार' के लिए हो?

लोकसभा चुनाव 2024 न केवल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरा लोकसभा चुनाव जीतने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा बनाए गए इतिहास को फिर से लिखने का लक्ष्य रख रहे हैं, बल्कि कुछ आंकड़ों के कारण भी महत्वपूर्ण हैं जो राजनीतिक दलों की भूत और भविष्य की स्थिति को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा की बढ़ती राजनीतिक शक्ति और राहुल गांधी द्वारा 'भारत जोड़ो यात्रा' और 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के प्रयासों के बावजूद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) की बदलती राजनितिक स्थिति रोचक है। इंडिया ब्लॉक के तहत एकजुट विपक्ष निर्णायक संघर्ष में लगा हुआ है क्योंकि भाजपा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के लिए 400 सीटें और स्वतंत्र रूप से 370 सीटों पर कब्जा कर दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाना चाहती है।

पहले दो-चरण का चुनाव 19 और 26 अप्रैल को हुआ था। 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के बाद 283 लोकसभा सीटों का भाग्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में कैद हो गया है। इस प्रकार से लोकसभा की कुल 543 सीटों में से आधे से अधिक पर चुनाव पहले तीन चरणों में समाप्त हो चुके हैं। चौथे चरण का भी आज मतदान है। वोट प्रतिशत पर नजर डालें तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66.14 प्रतिशत और दूसरे चरण में 66.71 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। तीसरे चरण में 64.58 प्रतिशत मतदान हुआ। तीनों का औसत 65.81 प्रतिशत आता है जो कि उत्साहवर्धक नहीं है। पूर्ववर्ती 'अखिल भारतीय जनसंघ' ने आज से 44 साल पहले भाजपा का गठन किया था। भाजपा ने 1984-1985 के लोकसभा चुनावों में 229 उम्मीदवार, 1989 में 225, 1991-92 के चुनावों में 477, 1996 में 471, 1998 में 388, 1999 में 339, 2004 में 364, 2009 में 433, 2014 में 428 व 2019 में 436 उम्मीदवार उतारे। इस बार भाजपा का 446 सीटों पर चुनाव लड़ने का साध्य है तथा अब तक उसने 424 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। यह छठी बार है जब भाजपा ने 1991, 1996, 2009, 2014 और 2019 के चुनावों के बाद लोकसभा चुनावों में 400 से अधिक उम्मीदवार उतारे हैं। 2014 के बाद से प्रभावशाली चुनावी नतीजों के साथ, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सत्ता में है। भाजपा के नेतृत्व व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के खिलाफ कड़ी टक्कर देने के लिए, कांग्रेस ने बहुत अधिक उम्मीदवार नहीं उतारकर यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया क्योंकि पिछले दो लोकसभा चुनावों में उसकी जीत का अनुपात इतना उत्साहजनक नहीं रहा है। कांग्रेस ने पहले लोकसभा चुनाव 1951-52 में 479, 1957 में 490, 1962 में 488, 1967 में 516, 1971 में 441, 1977 में 492, 1980 में 492, 1984 में 491 उम्मीदवार उतारे। 1991 में कांग्रेस ने 487, 1996 में 529, 1998 में 477, 1999 में 453, 2004 में 417, 2009 में 440 और 2014 में 464 सीटों पर चुनाव लड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 421 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने 2004 में 145, 2009 में 206, 2014 में 44 और 2019 में 52 सीटें जीतीं।

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 में 328 उम्मीदवार उतारे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार होगा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी 400 से कम सीटों पर आम चुनाव लड़ रही है। सीटों की संख्या में कमी मुख्य रूप से सबसे पुरानी पार्टी की गठबंधन प्रतिबद्धताओं के कारण है। कांग्रेस इन चुनावों में विपक्ष के इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। 2019 में लड़ी गई 101 सीटों को 2024 के आम चुनावों में इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों को दे दी गई है। अपने इतिहास में सबसे कम लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस का स्ट्राइक रेट गिर रहा है; दूसरी ओर, पिछले कुछ चुनावों पर एक नज़र डाले तो भाजपा सीटों और स्ट्राइक रेट के मामले में दोनों मोर्चों पर बढ़त का रुझान दिखा रही है। राजग के तहत लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा द्वारा लड़ी जा रही सीटों की संख्या भाजपा के प्रभुत्व को दर्शाती है, जबकि 2024 में कांग्रेस द्वारा लड़ी जा रही सीटों की संख्या इंडिया ब्लॉक के गठबंधन में कांग्रेस द्वारा उदारवादी आत्मसमर्पण को प्रतिबिंबित करती है। हालांकि गठबंधन सरकार की हमेशा अंतर्निहित सीमाएं होती हैं, लेकिन मतदाताओं के सामने आज यक्ष प्रश्न यह है कि उनका मत सामर्थ्य वाली 'मजबूत सरकार' के लिए हो या फिर 'मजबूर सरकार' के लिए हो? लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिहाज से देखें तो कम मतदान प्रतिशत अच्छी खबर नहीं है। अपितु एक गंभीर मुद्दा है। हालांकि, अभी चार चरण का मतदान बचा हुआ है। अभी भी घटनाओं और आश्चर्यों की गुंजाइश है जो चुनाव का रुख बदल सकते हैं, परन्तु खास बात है कि भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से किए गए कई प्रयासों के बावजूद कम मतदान प्रतिशत कई सवाल खड़े करता है। मतदान प्रतिशत में गिरावट का कारण क्या है? कम मतदान प्रतिशत कार्यकर्ताओं की उदासीनता है या फिर मतदाताओं की उदासीनता? कम मतदान के नतीजों से किस दल को फायदा और किस दल को नुकसान होगा? मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने की रणनीति बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, भारतीय चुनाव आयोग या राजनीतिक दल? मतदान का उच्च प्रतिशत जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। कम मतदान से किसे चुनावी फायदा होगा और किसको घाटा, वास्तव में इसका कोई हिसाब नहीं होता है। कई बार मतदान प्रतिशत गिरता है फिर भी सरकार जीत कर वापसी करती हैं और कई बार मतदान प्रतिशत कम होने से सरकारों को हार का भी सामना करना पड़ता है। भारतीय संविधान देश के नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है जो राजनीतिक राय व्यक्त करने का एक माध्यम है। मतदान नागरिकों को नागरिकता के महत्व का एहसास करने में मदद करता है। मतदान का अधिकार सामाजिक जागरूकता को सक्रिय करता है और राजनीतिक सहयोग को सशक्त बनाता है। बहुत से मतदाता यह सोचते हुए मतदान नहीं करते कि एक मत से कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश के रूप में, भारत चुनाव की नींव पर बना है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र माने जाने वाले भारत की चुनाव प्रणाली हमेशा कारगर और सही साबित हुई है। मतदान करना भारतीय नागरिक का न सिर्फ अधिकार है बल्कि मौलिक कर्तव्य भी है।

मतदाता के अंतर्मन में क्या चल रहा है, उसकी अंतरात्मा की आवाज क्या पुकार कर रही है, यह न तो कोई जानता है और न ही कोई ठोस अनुमान लगा सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता हमेशा राजा होता है क्योंकि उसका मत भावी सरकार के भाग्य का फैसला करने में निर्णायक होता है। 4 जून 2024 को सूर्यास्त तक वोटों की गिनती के साथ ही लोगों की राजनीतिक इच्छा सार्वजनिक हो जाएगी और नई सरकार के लिए अगले पांच वर्षों के लिए सत्ता की बागडोर संभालने का सूर्योदय होगा। लेकिन लोग बहुमत की सरकार जरूर चुनेंगे।

(लेखक वरिष्ठ विधि व्याख्याता हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

आनंदमय कोष की प्राप्ति

संकलित
दर्शन

अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष के पश्चात प्रवेश होता है आनंदमय कोष में। अन्न से उत्पन्न यह शरीर त्वचा, मांस, चर्म और रुधिर युक्त है। यह आत्मा नहीं है। प्राणमय कोष भी आत्मा नहीं, क्योंकि प्राण वायु के रूप में शरीर में आता-जाता है। मनोमय कोष व्यक्ति को विषयों में आसक्त करता है और आत्मभाव में स्थित नहीं होने देता है, इसलिए यह भी आत्मा नहीं है। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, सुख-दुख, जन्म-मरण, लाभ-हानि विज्ञानमय कोष में रहते हैं, इसलिए यह भी आत्मारूप आनंदमय कोष नहीं हो सकता है। श्रीरामचरितमानस में मात्र श्रीभरत इन कोषों का उपादान रूप में उपयोग करते हुए भी आनंदमय कोष हैं, जिनका राम से सर्वथा ऐक्य है। सारा संसार भरत की इस महत भूमिका के कारण ही दीपावली का प्रकाश पर्व मनाता है।दीपावली सनातन संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहार है। पूरा कार्तिक माह घरों तथा व्यापारिक संस्थानों की स्वच्छता व सजावट में लग जाता है। दीपावली के इस दृष्ट बाह्य और लौकिक रूप में कौन-सा आंतरिक तत्व छिपा है, जिसे जानने के पश्चात दीपावली हमें हमारे मूल वैदिक परंपराओं की नींव से जोड़ देती है। श्रीरामचरितमानस में भक्ति के सोपानों का वर्णन अरण्यकांड में है, जिसका विश्लेषण भगवान श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण की जिज्ञासा-समाधान में करते हैं। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के सोपानों का वर्णन मानस के अंतिम उत्तरकांड में काकभुशुंडि जी गरुड़ जी के समक्ष करते हैं।

भगवान जी आप अपना ध्यान रखना

संकलित
प्रेरणा

एक बच्चा रोज अपने दादा जी को सायंकालीन पूजा करते देखता था। बच्चा भी उनकी इस पूजा को देखकर अंदर से स्वयं इस अनुष्ठान को पूर्ण करने की इच्छा रखता था, किन्तु दादा जी की उपस्थिति उसे अवसर नही देती थी।एक दिन दादा जी को शाम को आने में विलंब हुआ, इस अवसर का लाभ लेते हुए बच्चे ने समय पर पूजा प्रारम्भ कर दी। जब दादा जी आये, तो दीवार के पीछे से बच्चे की पूजा देख रहे थे। बच्चा बहुत सारी अगरबत्ती एवं अन्य सभी सामग्री का अनुष्ठान में यथाविधि प्रयोग करता है और फिर अपनी प्रार्थना में कहता है। भगवान जी प्रणाम ! आप मेरे दादा जी को स्वस्थ रखना और दादी के घुटनो के दर्द को ठीक कर देना, क्योंकि दादा-दादी को कुछ हो गया, तो मुझे चॉकलेट कौन देगा। फिर आगे कहता है, भगवान जी मेरे सभी दोस्तों को अच्छा रखना, वरना मेरे साथ कौन खेलेगा। फिर मेरे पापा और मम्मी को ठीक रखना, घर के कुत्ते को भी ठीक रखना, क्योंकि उसे कुछ हो गया, तो घर को चोरों से कौन बचाएगा। लेकिन भगवान यदि आप बुरा न मानो तो एक बात कहू, सबका ध्यान रखना, लेकिन उससे पहले आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि आपको कुछ हो गया, तो हम सबका क्या होगा। इस सहज प्रार्थना को सुनकर दादा की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि ऐसी प्रार्थना उन्होंने कभी नहीं की थी। हमें उन परमपिता का हमेशा आभारी होना चाहिए जिन्होनें हमें बिना माँगे सब कुछ दिया है।

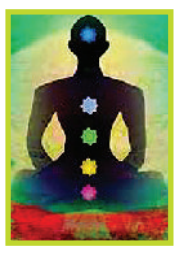

विशेष

डॉ.शंकरलाल शास्त्री

प्रेरक शक्ति स्वरुपा है मां

मां ही वह प्रेरक शक्ति स्वरुपा है, जो अपनी संतति के लिए सदा न जाने कितने ही कष्ट सहकर भी उफ़ तक नहीं रहती। मुझे याद आती हैं वे दशकों पुरानी दर्द भरी स्मृतियां जब हम छोटी कक्षाओं में पढ़ा करते थे। घर में बचे थोड़े से अनाज से हमें खाना खिलाकर मां स्वयं भूखी सो जाती। एक दिन मां से मैं पूछ बैठा- मां आपने खाना खाया? मां ने कहा - हां बेटा मैंने खाना खा लिया।/" पर सच में मां खाना न खाकर घर के दाएं-बाएं उगे गजरे-बथवे के पत्ते तोड़कर उन्हें उबालकर अपना काम चलाया था। यह प्रसंग तब का है जब मैं महज बारह वर्ष का था तभी पिताजी ने इस कलियुगी दुनिया को अलविदा कह दिया था । ऐसे में मां कभी फूली दादी से तो कभी मौहल्ले की बीनणियों से पैसे उधार लेकर हमारे स्कूल की फीस चुकाती। मां प्रायः कहती-बेटा अपने दुःख -दर्द को कागज पर उतार कर अपना मन हल्का करो । कागज पर उकेरे गए ये शब्दचित्र ही लोगों की प्रेरणा का आधार बनेंगे। ईश्वर को शायद अब कुछ और ही मंजूर था जो शब्द भोजन के लिए हम मां से पूछा करते थे। अपने जीवन के आखिरी शब्दों में जब मां को भोजन की थाली परोसी तब मां ने कहा था - बेटे आप सभी ने खाना खाया। हमने कहा था- हां मां हमने खाना खाया। तब मां ने थोड़ा सा खाना खाया था। ये वे ही शब्द थे जो दशकों पूर्व मां से हमने पूछे थे पर वे ही शब्द मां अपने जीवन के अंतिम पड़ाव के आखिरी शब्दों के रुप में पूछ कर यह सिद्ध कर दिया कि प्रतिकूल स्वास्थ्य और अपनी सांसारिक इहलौकिक यात्रा से पारलौकिक विदाई के कुछ क्षणों पूर्व तक भी अपनी संतति के प्रति मां की स्नेहवृष्टि और ममतामयी छांव की महक मातृस्वरूपिणी पक्ष को प्रगाढ़ करती परिलक्षित हो रही थी। यह उनकी शालीनता की खनकती आवाज ही तो थी।

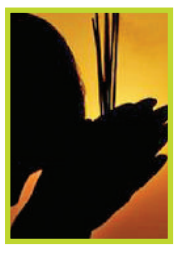

कौन जानता था कि ये मां के आखिरी शब्द होंगे। सच है मां के चरणों में स्वर्ग है। स्वरचित ये पंक्तियां मां के वैशिष्ट्य को बखूबी दर्शाती हैं - ममता के आंचल में / यादों के झरोखे में /पल-पल जो तेरी यादें /हमें शुभ सीख देती हैं/ प्रेम रस की सुधा वृष्टि / दृष्टि की नई सृष्टि/ मा तेरे चरणों में स्वर्ग है/ मां तेरी हर सीख में एक नया संदेश है। घर में यदि मां है तो समझिए हम स्वर्ग की सैर कर रहे हैं ।मातृ वियोग की मनोव्यथा को सहते जो शाब्दिक अभिव्यक्ति दी है इसमें यथार्थता की दर्द भरी मार्मिक प्रेरणास्पद कथाएं चित्रित हैं।

मां का वह स्वरूप जो सदा घर की छत पर कलरव करते और मंडराते पक्षियों के बीच उन्हें कभी दाने डालते तो कभी उनके लिए पानी की व्यवस्था कर प्रकृति प्रेम की अनूठी मिसाल दी है। दादी- नानी के नुस्खों के लिए मशहूर आज भी मां की ममतामयी वह मूरत आंखों के सामने प्रकट हो जाती है। वहीं उनकी किस्सागोई की कला भी परसेवा की अनूठी मिसाल है।

यक़ीनन मां दुनिया की दिव्य शक्ति है तथा हमारी पहली पाठशाला भी । भगवान् श्री गणेश ने मातृ-पितृ शक्ति की परिक्रमा कर मातृशक्ति वंदन का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। मां की सेवा में ही ईश्वरीय सेवा निहित है।

(लेखक एवं साहित्यकार)

अंतर्मन

आज की पाती

पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम

हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति परोपकार की शिक्षा देती है। प्राणी जाति की सेवा हमारा परम धर्म होना चाहिए। मानव जाति के साथ अन्य जीवों की सेवा करना भी सबसे बड़ा कर्त्तव्य होना चाहिए। प्राणी जाति को गर्मियों में सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत पड़ती है, वो है पानी। हमने आधुनिक भौतिक सहूलियतों को पाने के लिए ऐसे ऐसे काम करने शुरू किए हैं जो पानी के प्राकृतिक संसाधनों पर भी भारी पड़ रहे हैं और इस कारण हमें गर्मियों में कभी-कभी देश के कुछ राज्यों में पानी के संकट का सामना करना पड़ता है। इनसान तो फिर भी कोई न कोई बंदोबस्त करके पानी का इंतजाम करके अपनी प्यास बुझा लेता है, लेकिन पक्षियों के लिए खुद पानी का इंतजाम करना मुश्किल ही नहीं, बल्कि नामुमकिन है।

- रमेश तिवारी, रायगढ़

करंट अफेयर

रीता शेरपा ने 29 वीं बार एवरेस्ट पर की फतह

नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने रविवार को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार चढ़ाई की। इस तरह उन्होंने एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया। पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में पर्यटन विभाग के निदेशक राकेश गुरुंग के अनुसार, अनुभवी पर्वतारोही शेरपा (54) रविवार को स्थानीय समयानुसार सुबह सात बजकर 25 मिनट पर 8,849 मीटर ऊंची चोटी पर पहुंचे थे। नेपाल के 'सेवन समिट ट्रेक्स' के एक वरिष्ठ अधिकारी थानी गुरगैन ने बताया कि सेवन समिट ट्रेक्स ने इस पर्वतारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया था और इसमें 20 पर्वातारोही शामिल हुए थे। उन्होंने रविवार की सुबह एवरेस्ट फतह किया। 'सेवन समिट ट्रेक्स' ने एक बयान जारी कर बताया, 'कामी सहित सेवन समिट ट्रेक्स के कम से कम 20 पर्वतारोहियों ने रविवार सुबह माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की।' पर्वतारोही दल में नेपाल के 13 पर्वतारोहियों के अलावा शेष अमेरिका, कनाडा और कजाकिस्तान से थे। कामी ने 1994 में पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। पिछले साल उन्होंने एक ही सीजन में 27वीं और 28वीं बार एवरेस्ट फतह किया था और इस तरह वह एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाले शख्स बन गये थे।

ऑफ बीट

50 हजार साल पहले से आग का इस्तेमाल किया जा रहा

2,50,000 साल पहले स्पेन में एक स्थान पर मनुष्यों के पूर्वजों या वनमानुष द्वारा आग के नियंत्रित इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। यह यूरोप में आग नियंत्रण के शुरुआती सबूतों से 50,000 साल पुरानी बात है। यह अध्ययन 'नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स' में प्रकाशित हुआ है। मनुष्यों के पूर्वजों तथा आग के अवशेषों का एक ही स्थान पर मिलना वाकई खास है। यूरोप के बाहर मनुष्यों द्वारा प्राकृतिक आग का इस्तेमाल करने के सबसे पुराने सबूत दक्षिण अफ्रीका में स्वार्टक्रान गुफा से मिलते हैं जहां 10 से 15 लाख वर्ष पहले पशुओं की सैकड़ों जली हुई हड्डियों के साथ वनमानुष के अवशेष पाये गये। मनुष्यों द्वारा जलाई आग के सबसे शुरुआती सबूतों से लगभग एक लाख साल आगे : इजराइल में 7,90,000 साल पुरानी ग्रेशर बेनोट याआकोव नामक एक खुली जगह है। इस स्थान पर मिले साक्ष्यों में जले हुए पौधे और पत्थर के जले हुए औजार शामिल हैं। इजराइल में क्वेसेम गुफा और ताबुन गुफा जैसे अन्य स्थानों पर ही आग जलाये जाने के ऐसे ही सबूत मिले हैं। यूरोप में आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि वनमानुष ने कम से कम 3,50,000 साल पहले आग का नियमित रूप से इस्तेमाल किया। कुछ संकेत मिले हैं कि अग्नि नियंत्रण का संबंध एश्यूलिन नामक पत्थर औजार तकनीक के विस्तार से जुड़ा है।

ट्रेंड

विकसित भारत देना चाहता हूं

हमारे पूर्वजों ने 500 साल तक राम मंदिर के लिए संघर्ष किया है। टीएमसी और कांग्रेस वालों, अपने पूर्वजों के त्याग, तपस्या और बलिदान का तो अपमान मत करो! परिवार का मुखिया जैसे अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़कर जाना चाहता है। वैसे ही मैं भी विकसित भारत बनाकर देना चाहता हूं।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

अंतरराष्ट्रीय प्रयास की जरूरत

मैं सूडान में चल रहे युद्ध को लेकर बहुत चिंतित हूं। अंततः, हम जानते हैं कि इस संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है। हमें एक राजनीतिक प्रक्रिया प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता है जो देश को वापस पटरी पर ला सके।

-एंटोनियो गुतरेस, यूएन महासचिव

तब वे मौन क्यों हो गए

नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं शबरी का पुजारी हूं। मोदी जी ने सैकड़ों शबरियों का अपमान क्यों होने दिया? जब उनकी अस्मिता पर हमले हुए, तब अपना मुंह क्यों बंद रखा? हाथरस, उन्नाव, ओलंपिक विजेता बहनें जब न्याय की गुहार लगा रही थीं, तब वे मौन क्यों हो गए?

-प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव

आत्मविश्वास बढ़ाएं

हर दिन कुछ ऐसा करके अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं जिससे आप डरते हैं - एक साहसिक निवेश करें, एक कठिन व्यायाम दिनचर्या करें, एक जटिल किताब पढ़ें, एक नई भाषा बोलने का प्रयास करें, एक पेचीदा पहेली को हल करें।

-हर्ष गोयनका, उद्योगपति

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

छोटे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी बड़े जतन करने पड़ते हैं

दायित्व निर्वहन का अवसर

लोकसभा चुनाव में मतदान के चौथे चरण को लेकर यह जानने की प्रतीक्षा है कि मतदान प्रतिशत कितना रहता है। इसका कारण यह है कि पहले और दूसरे चरण में 2019 की तुलना में कम मतदान हुआ। तीसरे चरण में भी मतदान प्रतिशत पिछले आम चुनाव के मुकाबले तो कम रहा, लेकिन अंतर कुछ घटा। देखना यह है कि चौथे चरण के मतदान प्रतिशत में कुछ बढ़ोतरी होती है या नहीं। मतदान प्रतिशत कम रहने के कई कारण हैं। इनमें मतदाता सूचियों का सही तरह से तैयार न होना, सभी मतदाताओं का उनमें नाम न होना और एक बड़ी संख्या में मतदाताओं का अपने काम-धंधे के सिलसिले में अपने गांव और शहर से दूर रहना शामिल है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इन कारणों का निवारण किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि मतदाताओं में जो उदासीनता देखने को मिल रही है, उसके लिए एक हद तक वही उत्तरदायी हैं। विडंबना यह है कि यह उदासीनता शहरी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिल रही है। इसका अर्थ है कि पढ़ा-लिखा और विभिन्न विषयों को लेकर मुखर रहने वाला वर्ग भी मतदान के प्रति उत्साहित नहीं रहता। यह भी देखने को मिल रहा है कि देश के कुछ हिस्सों में तो मतदान प्रतिशत संतोषजनक रहता है, लेकिन कुछ हिस्सों में वह अपेक्षा से कहीं अधिक कम रहता है। मतदान केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि यह एक अधिकार है, बल्कि इस दायित्व का निर्वहन इसलिए भी किया जाना चाहिए कि इससे सरकार गठन में लोगों की भागीदारी बढ़ने से लोकतंत्र को बल मिलता है और साथ ही राजनीतिक दलों को अपनी नीतियों का निर्धारण करने में मदद भी मिलती है। मतदान न करने वाले लोग केवल जिम्मेदार नागरिक होने के दायित्व की पूर्ति में ही पीछे नहीं रह जाते, बल्कि शिकायत करने के अधिकारी भी नहीं रह जाते। मतदान में भाग लेना एक तरह से राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदारी करना है। निःसंदेह अपेक्षित संख्या में लोगों के मतदान के लिए न निकलने के पीछे एक कारण प्रतिकूल मौसम है और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि चुनाव ऐसे मौसम में कराए जाने चाहिए जब इतनी अधिक गर्मी न पड़ रही हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि लोग प्रतिकूल मौसम के बावजूद अपनी तय दिनचर्या पूरी करते हैं और गर्मी के बावजूद अपने काम-धंधे के सिलसिले में घर से बाहर निकलते हैं। स्पष्ट है कि प्रतिकूल मौसम के स्थान पर लोगों की अनिच्छा ही पर्याप्त मतदान न होने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इस अनिच्छा के कारणों की पहचान राजनीतिक दलों को भी करनी चाहिए और साथ ही स्वयं लोगों को इसके लिए प्रेरित होना चाहिए कि लोकतंत्र को मजबूती देने में वे कैसे भागीदार बनें, क्योंकि केवल इसी तरीके से वे राजनीतिक दलों को अपनी अपेक्षाओं के प्रति सजग-सचेत कर सकते हैं।

कड़ाई से हो जांच

पहले बिहार लोकसेवा आयोग (बीपीएससी) शिक्षक नियुक्ति परीक्षा-3 का प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सामने आया। इसके बाद देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में एक नीट-यूजी में धांधली का मामला सामने आया। पुलिस की जांच में अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, उससे प्रतीत हो रहा कि नीट-यूजी का प्रश्नपत्र लीक हुआ है, हालांकि पहले दिन से ही परीक्षा लेने वाली एजेंसी एनटीए इससे इन्कार कर रही है। पकड़े गए अभ्यर्थी ने भी पुलिस को दिए बयान में बताया है कि उन्हें रात में ही प्रश्न एवं उत्तर रटने के लिए दिए गए थे। अभ्यर्थी को जब केंद्र पर प्रश्नपत्र मिला तो शत-प्रतिशत वही प्रश्न थे, जो रटने के लिए दिए गए थे। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही, नए-नए तथ्य उजागर हो रहे। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती, बीपीएससी टीआरई-3 और नीट-यूजी धांधली में एक ही गिरोह के होने की बात सामने आ रही है। पूर्व की दो परीक्षाओं उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती और बीपीएससी टीआरई-3 के प्रश्नपत्र को जिस गिरोह ने लीक किया था, उसी ने यदि नीट-यूजी का पेपर लीक किया है, तो सवाल उठना लाजिमी है कि कहीं न कहीं परीक्षाएं आयोजित करने वाले तंत्र में सब ठीक नहीं है। कैसे एक गिरोह परीक्षा दर परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक करता जा रहा है और वह जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर है। सभी परीक्षाओं के पूर्व तमाम तरह की कड़ाई के निर्देश जारी किए जाते हैं। प्रश्नपत्रों को लेकर विशेष सजगता और सतर्कता बरतने की बातें होती हैं। फिर भी प्रश्नपत्र का लीक होना सिस्टम में सुराख की ओर इशारा करता है। बड़ी समस्या यह भी है कि जो सरगना या गुर्गे दबोचे जाते हैं, वे साक्ष्यों के अभाव या किसी अन्य कारण से छूट जाते हैं और फिर से इस धंधे में लग जाते हैं। प्रश्नपत्र लीक होने या फिर परीक्षा रद किए जाने से जो मानसिक आघात पहुंचता है, उसे परीक्षार्थी या फिर उनके स्वजन ही समझ पाते हैं।

प्रश्नपत्र लीक से जुड़े तंत्र को जब तक पूरी तरह ध्वस्त नहीं किया जाएगा, तब तक परीक्षार्थियों को हताशा ही हाथ लगती रहेगी।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या टी-20 विश्व कप में विराट कोहली को ओपनिंग करना चाहिए?

आज का सवाल

क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि प्लेआफ से पहले आइपीएल से किनारा करने वाले खिलाड़ियों की फीस काटी जानी चाहिए?

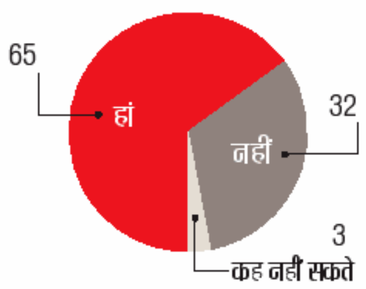

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आर्थिक-सामाजिक अवसरों के द्वार

विवेक देवराय और आदित्य सिन्हा

युवा आबादी का लाभ उठाने के लिए भारत को शिक्षा सुधार, आर्थिकी को संगठित रूप देने के साथ ही स्वास्थ्य एवं पोषण के समावेशन वाली रणनीति बनानी होगी

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार चीन को पीछे छोड़कर भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। इसके साथ ही भारत एक अनूठी जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में आ गया है। देश की करीब 65 प्रतिशत आबादी कामकाज योग्य है जो केवल भारत ही नहीं, बल्कि समूचे विश्व के लिए विपुल आर्थिक एवं सामाजिक संभावनाओं के द्वार खोलती है। इन संभावनाओं को प्रभावी रूप से भुनाने के लिए भारत को मानव पूंजी में रणनीतिक निवेश करना होगा। उसे सुनिश्चित करना होगा कि इस राह में कोई कसर शेष न रह जाए। जनसांख्यिकीय लाभांश जनसंख्या की आयु के स्तर में परिवर्तन पर झलकता है। जब 15 से 64 वर्ष के आयुवर्ग वाले लोगों की संख्या 14 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक की आयु वाले लोगों की संख्या से अधिक हो जाए तो इस प्रकार के लाभांश की स्थिति बनती है, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग उपलब्ध होते हैं। इतिहास साक्षी है कि जिन देशों ने भी ऐसी स्थिति को भुनाने के लिए समय से उपाय किए, तो उन्होंने प्रगति के नए मापदंड स्थापित किए। इस लाभांश के पहले चरण में कामकाजी आबादी में भारी बढ़ोतरी से रोजगार, बचत एवं आर्थिक विकास और पारिवारिक कल्याण में निवेश बढ़ता है। परिणामस्वरूप इससे प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि की राह खुलती है। हालांकि ऐसे लाभांश की स्थिति अमूमन पांच दशकों तक ही चलती है, जिसके बाद उसका दूसरा चरण आरंभ होता है। दूसरे चरण में वृद्ध होती आबादी के लिए सेवानिवृत्ति की तैयारी में संसाधन जोड़ने होते हैं, जिसमें पुनः निवेश के माध्यम से राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी का रुख नजर आता है। चूंकि जनसांख्यिकीय लाभांश के ये दोनों चरण स्वतः स्फूर्त रूप से आकार नहीं लेते तो उन्हें साकार करने के लिए प्रभावी नीतिगत कदम अपरिहार्य होते हैं।

इस समय भारत की आधी आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है और जल्द ही कामकाजी आबादी एक अरब का आंकड़ा पार कर सकती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक पत्र के अनुसार जनसंख्या के मोर्चे पर लाभ की यह स्थिति भारत की जीडीपी को हर साल दो प्रतिशत तक बढ़ाने की क्षमता रखती है। हालांकि इससे जुड़े अवसरों को भुनाने की राह में तमाम चुनौतियां विद्यमान हैं, जिन्हें दूर करना ही होगा। सबसे पहली चुनौती तो उद्योग जगत की अपेक्षाओं और शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कौशल के स्तर पर भारी विसंगति की है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि रोजगार के लिए आवश्यक कौशल और उसकी पूर्ति में शिक्षण संस्थानों की अक्षमता के बीच 2030 तक 2.9 करोड़ का अंतराल उत्पन्न हो सकता है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से इस स्थिति को सुधारने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन यह नाकाफी लगते हैं। कारण यही है कि सभी स्कूल इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दे रहे और शिक्षा की गुणवत्ता में भी भिन्नता दिखती है।

अवधेश राजपूत

रोजगार का विषय भी कई बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। यह भी देखने में आता है कि उच्च शिक्षित लोगों की अपने करियर को लेकर विशेष आकांक्षाएं होती हैं और वे उन नौकरियों के लिए प्रयास नहीं करते, जिसमें वे अपने कौशल का सदुपयोग होता न देखते हों। इससे रोजगार प्रतीक्षा की अवधि लंबी खिंच जाती है। उदाहरण के रूप में नेशनल करियर सर्विस पर वित्त वर्ष 2024 के दौरान जहां नौकरियों की संख्या में 214 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, लेकिन नौकरी के लिए पंजीकरण कराने वालों का आंकड़ा केवल 53 प्रतिशत बढ़ा। यह रोजगार बाजार से जुड़ी विसंगतियों एवं जागरूकता के अभाव को दर्शाता है। इस मोर्चे पर मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन कायम है। यह स्थिति तकनीकी एवं वैश्विक आर्थिक ढांचे में आ रहे तेज परिवर्तनों से और प्रभावित हो रही है, जो कुछ पारंपरिक कौशलों को अप्रासंगिक बनाने पर तुली है। ऐसे में, उच्च शिक्षा कई बार ऐसे हालात बना देती है, जहां उपलब्ध रोजगारों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कामकाजी आबादी के पास आवश्यक अर्हता के स्तर पर असंगति देखने को मिलती है।

इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, 2023 कुछ सुधार के संकेत करती है, जिसमें रोजगार की स्थिति 50.3 प्रतिशत बढ़ी हुई दिखती है। इसके बावजूद आधुनिक अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिहाज से यह पर्याप्त नहीं। भारत के लिए फिनलैंड के अनुभव से सीखना कुछ उपयोगी हो सकता है, जहां शिक्षण संस्थानों, सरकार और निजी क्षेत्र के बीच इस प्रकार से तालमेल बना होता है, जहां श्रम बाजार की मौजूदा एवं भविष्य की मांग को ध्यान में रखकर शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त फिनलैंड में जीवनपर्यंत सीखने पर जोर दिया जाता है जो भारत के लिए और भी अहम रणनीति हो सकती है ताकि वह समय के साथ अपनी कामकाजी आबादी को सही दिशा में उन्मुख करता रह सके।

भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से का असंगठित रूप में होना भी एक बड़ी चुनौती है। असंगठित क्षेत्र में एक बड़ी भागीदारी गैर-कृषि कामगारों की है, जिनके पास सीमित रोजगार संभावनाएं एवं सामाजिक सुरक्षा के अवसर उपलब्ध होते हैं। इससे भी जनसांख्यिकीय लाभांश की संभावनाओं पर ग्रहण लग सकता है। सतत आर्थिक लाभ के लिए इन कामगारों एवं उनके उद्यमों को उचित नीतियों के माध्यम से संगठित स्वरूप देना होगा। अतीत में बाल शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश की अनदेखी की स्थिति को अब सुधारा जा रहा है। इस दिशा में की जा रही नई पहल का उद्देश्य जन्म के समय से स्कूल पहुंचने तक बच्चों की सेहत और व्यापक क्षमताओं को सुधारने पर केंद्रित है। पोषण अभियान और मिशन पोषण 2.0 जैसे कार्यक्रमों का लक्ष्य आरंभिक जीवन के पड़ाव पर कुपोषण को दूर करना है, जो भावी आर्थिक गतिविधियों और समग्र बेहतरी के लिए अच्छी बुनियाद रखने का काम करेगा। इसलिए यदि भारत जनसांख्यिकीय लाभांश की संभावनाओं को पूरी तरह भुनाना चाहता है तो उसे समग्रता से भरी ऐसी रणनीति बनानी होगी, जिसमें शिक्षा सुधार, असंगठित क्षेत्र को संगठित स्वरूप देना और स्वास्थ्य एवं पोषण समृद्धि से जुड़े कार्यक्रमों का भलीभांति समावेश हो। इस दृष्टिकोण से अपेक्षित कौशल की कमी की पूर्ति के साथ ही सतत आर्थिक वृद्धि एवं जीवनस्तर में व्यापक सुधार के द्वार खुलेंगे।

(देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी-अनुसंधान हैं)

response@jagran.com

राष्ट्रवाद के लिए खतरा वोटबैंक राजनीति

इस लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवाद की खूब चर्चा हो रही है। राष्ट्र प्रेम की भावना एक सहजात भावना है। यह किसी पार्टी की मान्यताओं या सिद्धांतों से उद्भूत नहीं होती है। हां, यह हो सकता है कि किसी पार्टी में ऐसे लोगों की संख्या अधिक हो, जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हों। उसके प्रति रागात्मक भाव रखते हों। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी का समर्थन करना ही राष्ट्रवादी होना नहीं है, अपितु व्यक्ति के भीतर अपने देश, उसके प्राकृतिक परिवेश, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक मान्यताओं, भौगोलिक सीमाओं, इतिहास, साहित्य, कला आदि के प्रति एक स्वाभाविक प्रेम और निष्ठा उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। खेतों में अन्न उपजाता और राष्ट्र के लोगों को भोजन देने वाला किसान भी उतना ही राष्ट्रवादी है जितना सीमा पर सुरक्षा के लिए हर परिस्थिति में खड़ा हमारा भारतीय सैनिक राष्ट्र प्रेमी होता है। यह अतिशय राष्ट्रवाद की भावना ही थी जिसने अनगिनत बलिदानों और कठिन संघर्षों के बाद भारत को अंग्रेजी दासता से मुक्ति दिलाई। निःसंदेह उस समय भारत छोटे-छोटे राज्यों और रियासतों में बंटा हुआ था, परंतु स्वाधीनता के संग्राम में सब एक हो गए थे। यह एकता की भावना ही राष्ट्रवाद की भावना थी। यह राष्ट्रवाद का ही परिणाम था कि भारत एक राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने फिर से तनकर खड़ा हो गया। वह निरंतर सफलता एवं प्रगति के पथ पर अग्रसर भी है।

कुछ लोग राष्ट्रवाद को अति राष्ट्रवाद की सीमा तक ले जाकर आलोचना करने की कोशिश करते हैं। जबकि अति राष्ट्रवाद का तात्पर्य ही इस बात में निहित है कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने राष्ट्र को सर्वोच्च मानने लगता है। उसे अपने देश, वहां के नागरिकों, इतिहास, संस्कृति, परिवेश और भूखंड को लेकर अत्यधिक गर्व की अनुभूति होती है और वह इस पर किसी भी प्रकार का आघात सहन नहीं कर सकता। इसे स्थूल रूप में अति राष्ट्रवाद कह सकते हैं, परंतु इसी राष्ट्रवाद को अपने ढंग से परिभाषित करने वाले कम्युनिस्ट विचारकों, लेखकों आदि के अलग ही विचार होते हैं। वे जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर से प्रारंभ कर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक की नीतियों को अति राष्ट्रवाद की संज्ञा देते हैं और इसे मानवता के लिए घातक बताते हैं। उनके अनुसार अति राष्ट्रवाद किसी देश की सरकार को अधिनायकवादी बना देता है। उनका मानना है कि सांस्कृतिक एकरूपता के आह्वान के बीच हम आज अति राष्ट्रवाद के समय में जी रहे हैं, जहां स्वघोषित राष्ट्रवादियों और एक संस्कृति का उन्माद सामाजिक बनावट को टुकड़ों में बांटने का खतरा पैदा कर रहा है। वे यह भी मानते हैं कि यह अति राष्ट्रवाद वैश्विक चलन में आ गया है। ट्रंप से लेकर ब्रेक्जिट और यूरोप के अधिकांश अतिवादी दक्षिणपंथी समूह दूसरों के प्रति घृणा को बढ़ावा दे रहे हैं। इन अति राष्ट्रवादियों ने मुसलमानों, वामपंथियों को अपना शत्रु मान लिया। वे यह भी कहते हैं कि पिछली सदी के नौवें दशक तक भारत में राष्ट्रवाद उन्माद रहित था। यह न तो आक्रामक था और न ही विरोधात्मक।

सवाल है कि क्या राष्ट्र मात्र उन्हीं लोगों तक सीमित है, जिनके बारे में ये चिंतक अपनी दुश्चिंता प्रकट कर रहे हैं? राष्ट्रवाद की इस परिकल्पना में समस्त उत्तेजना राजनेताओं या उनके प्रशंसकों के इर्द-गिर्द ही घूमती नजर आती है। इसमें उन करोड़ों लोगों के दर्शन नहीं होते, जिनके कारण यह देश सांस्कृतिक है, धार्मिक है, दार्शनिक है, सामाजिक है और इतिहास से भी पुराना ऐतिहासिक है। राष्ट्रवाद एक भावना है, राष्ट्र के प्रति प्रेम है। भारत के भीतर और बाहर भी राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश करने वाली अलगाववादी ताकतें सदा से सक्रिय रही हैं। बाहरी शत्रुओं के साथ-साथ भारत को अपने आंतरिक शत्रुओं से भी बराबर मुठभेड़ करनी पड़ी, परंतु भारत में अंधेरे से जूझने का संकल्प बहुत पुराना है। यहां सूरज के ढलते ही दीप प्रज्वलित कर घर के बाहर देहरी पर रख देने की परंपरा रही है। सहअस्तित्व भारत की प्रधान सांस्कृतिक चेतना रही है जिसने इसे सहिष्णु और उदार बनाया। इसलिए भारत सभी प्रकार के विचारों को महत्व देता है। इसके दर्शन में आस्तिकतावादी भी हैं तो चार्वाक जैसे भोगवादी या नास्तिकतावादी भी भारतीय दर्शन ही कहलाते हैं। संकट तब खड़ा होता है जब आक्रमणकारी इस सहिष्णु संस्कृति की जड़ों पर प्रहार करते हैं। वहीं सावधान होना है। इस सावधान होने की प्रक्रिया को ही कभी-कभी इस तरह के छद्म विचारक नकारात्मक अर्थों में अति राष्ट्रवाद का नाम देने लगते हैं।

नीरजा माधव

भारत की पहचान और अस्मिता के प्रति जागरूकता की भावना ही वास्तव में राष्ट्रवाद को परिभाषित करती है

सहअस्तित्व की भावना से भरा भारतीय राष्ट्रवाद ● फहल

भारतीय संस्कृति मरणधर्मा संस्कृति नहीं है। यहां के लोग अमृतपथ के यात्री हैं। चेतना के सतत ऊर्ध्वारोहण के प्रति समर्पित। पश्चिम की तरह प्रकृति को जीतने की पागलपन वाली भाषा भारत नहीं बोलता। इसके लिए अपने भूखंड के हर प्राकृतिक पदार्थ-नदी, पेड़, पहाड़, जीव-जंतु, बादल और अग्नि आदि सभी पूजनीय हैं। उसके साथ ही पूरी सतर्कता और सतत सजगता के साथ वह जगत के धर्म का भी निर्वाह करता है। आपात स्थिति में आत्मरक्षा के लिए शौर्य के धर्म का पालन भी करता है। प्राणी मात्र को गले लगाना, स्नेह देना हमारा भारतीय धर्म है तो वहीं यह राष्ट्र प्रेम हमें किसी भी षड्यंत्र से सावधान रहने की शिक्षा भी देता है। कहीं हमारे प्रमाद का लाभ उठाकर हमारा ही कोई मित्र हमारे घर-परिवार पर आधिपत्य न जमा ले। वोट बैंक की राजनीति ने भारत के सांस्कृतिक आत्मा पर जितने प्रहार किए हैं, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार भारत की पहचान और अस्मिता के प्रति जागरूकता की भावना ही वास्तव में राष्ट्रवाद है, जिसे जगाने का काम इस चुनाव में किया जाना चाहिए।

(लेखिका साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आनंद

आनंद ही हमारे जीवन का एक मुख्य लक्ष्य है, पर यह हमारा अंतिम गंतव्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है। जीवन आनंदमय हो और सतत आगे बढ़ता जाए, इसी कामना में तो सभी जिए जा रहे हैं। जीवन की यह यात्रा चार अलग-अलग स्तरों से गुजरती है। हर स्तर पर विशिष्ट प्रेरणा और कार्यशैली की आवश्यकता होती है। हम प्रयास कर सकते हैं, पर सफलता ईश्वर की कृपा पर निर्भर है।

प्रथम स्तर है, ईश्वर की पहचान। इस स्तर पर हमारा प्रयास अधिक से अधिक लोगों को, विशेष रूप से आध्यात्मिक साधकों को, इस शुभ कर्म पथ पर साथ लाने का होना चाहिए। दूसरा स्तर है, सृष्टि से एकात्मता। इस स्तर पर चुनौतियां न केवल हमारी मानवीय और जैविक प्रवृत्तियों से आती हैं, बल्कि अजैविक शक्तियों से भी आती हैं। इस स्तर पर हमें सृष्टि की हर चीज के साथ एकात्मता का अनुभव करना होगा। हमें समझना होगा कि इस अस्तित्व का हर कण, हर परमाणु उसी परम सत्ता का अंश है। तीसरा स्तर है, मानसिक अनुभव और सिद्धियां। इस स्तर पर विकास की गति तेज होती है और साधक कुछ सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहां खतरा भी अधिक है। साधक को इन सिद्धियों का दुरुपयोग करने का प्रलोभन हो सकता है। इसलिए इस स्तर पर ईश्वर की कृपा और मजबूत मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इस स्तर पर परमात्मा परम गुरु बन जाते हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। साधक को अनुभव करना होगा कि वह ईश्वर की इच्छा से ही इस धरती पर आया है और उनकी इच्छा की प्राप्ति के लिए ही प्रयास कर रहा है। चौथा स्तर है, मन का एकाग्र होना। इस स्तर पर सभी लक्ष्य, पदार्थ, अहसास एक बिंदु में समाहित हो जाते हैं। मन एकाग्र हो जाता है और यही आनंद प्राप्ति का मार्ग है। इस स्तर पर साधक को पूर्ण आत्मज्ञान और आनंद की प्राप्ति होती है।

ईश्वर में विश्वास, समर्पण और सही मार्गदर्शन के साथ हम सभी आनंद के इस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

श्री श्री आनंदमूर्ति

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

विपक्ष के पास एक मजबूत नेता का अभाव

'विपक्ष की रणनीतिक दुर्बलता' शीर्षक से लिखे आलेख में डा. एके वर्मा ने विपक्ष के महत्वहीन, भ्रामक एवं कमजोर चुनावी मुद्दों पर प्रकाश डाला है, जो कि सत्य है। विपक्ष ने 18वीं लोकसभा के इस चुनाव में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों, विदेश, प्रतिरक्षा, शिक्षा, कृषि एवं आर्थिक गतिविधियों से संबंधित स्पष्ट नीतियों को जनता के सामने नहीं रखा है। और न ही अपने सभी सहयोगी दलों की सहमति से अपने राष्ट्रीय नेता का चेहरा स्पष्ट किया है। इन सबके बीच राहुल गांधी अपनी छवि एक सशक्त, मजबूत और राष्ट्रहित में कड़े निर्णय लेने वाले नेता के रूप में अभी तक नहीं बना पाए हैं। भारतीय जनता के मानस पटल पर अभी भी उनकी छवि एक अपरिपक्व, स्वयं की कोई राष्ट्रीय विचारधारा न होना, किसी भी राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक एवं वैश्विक परिदृश्य की चुनौती से न निपट पाने वाले नेता की ही है। विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं की स्थिति भी ज्यादा मजबूत नहीं है। कुल मिलाकर कर विपक्ष जनता को भाजपा के मुकाबले एक राष्ट्रीय नेता और वैकल्पिक नीति नहीं दे पाया है। इसके उलट वे अनुच्छेद-370 को वापस लाने, जीएसटी को खत्म करने जैसे औचित्यहीन मुद्दों को लेकर जनता के बीच घूम रहे हैं। अगर विपक्ष के पास इस आम चुनाव में एक सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता होता, महंगाई नियंत्रण की सुस्पष्ट नीति होती, रोजगार सृजन का रोडमैप होता, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का विजन होता, पुरातन पड़ चुकी स्कूली एवं उच्च शिक्षा नीति, राष्ट्रीय चिकित्सा नीति, राष्ट्रीय कृषि नीति को वर्तमान जरूरतों के अनुसार बदलने की मंशा होती, समावेशी विकास को विस्तार देने की इच्छाशक्ति होती तो वह भाजपा को जरूर इस बार कड़ी टक्कर दे सकता था।

धीरेंद्र उत्तम, उन्नाव

संदेह का उपचार नहीं

संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित 'अनावश्यक संदेह' शीर्षक आलेख पढ़ा। यह निर्विवाद सत्य है कि संदेह का कोई उपचार नहीं है, बल्कि विश्वास करना ही इसका उपयुक्त विकल्प है। शिकायत के साथ अकाट्य सबूतों की जरूरत होती है। न्यायालय भी दुर्लभ मामलों में संदेह के आधार पर आरोपितों को बरी कर देता है। चुनाव आयोग ने जिस मजबूती के साथ विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है, उससे लगता है कि विशेष कर कांग्रेस को अब चुनाव आयोग पर उंगली उठाने से पहले अवश्य विचार करना होगा। कांग्रेस को चुनाव आयोग में जाने के पूर्व उच्चतम न्यायालय के उस आदेश का अध्ययन कर लेना चाहिए था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शत प्रतिशत वीवीपैट के मिलान की मांग खारिज कर दी थी और ईवीएम पर भरोसा जताया है। बावजूद इसके कतिपय लोग इन आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। चुनाव आयोग के जबाव पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। खरगे ने कहा कि इंडिया गठबंधन को लिखे गए मेरे पत्र का जवाब तो चुनाव आयोग ने दिया, लेकिन शिकायतों को नजरअंदाज किया। दो चरणों के मतदान के आंकड़े जारी करने में चुनाव आयोग की देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए खरगे ने एक खुला पत्र इंडिया गठबंधन के नेताओं को लिखा था। इस पर आयोग ने आरोपों को तथ्यहीन बताया था और खरगे को नसीहत दी थी।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

अनर्गल टिप्पणी से बचे कांग्रेस

संजय गुप्त द्वारा लिखित आलेख 'कांग्रेस की मुसीबत बने बड़बोले नेता' पढ़ा। चुनाव का वक्त जनता से संवाद का होता है। राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र और मुद्दों को जनता के बीच रखते हैं। नेतागण अपने विचारों के साथ जनता से संवाद स्थापित करते हैं। गत दस वर्षों से कांग्रेस केंद्र की सत्ता से दूर है। सत्ता में आने के लिए पार्टी के नेता लालायित हैं, एवं स्वयं को चर्चा में बनाए रखने के लिए विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। अनर्गल टिप्पणियों से कांग्रेस पार्टी को सदैव नुकसान उठाना पड़ा है, फिर भी पार्टी कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। पूर्व में सोनिया गांधी ने नरेन्द्र मोदी को मौत का सौदागर की उपमा दी थी तो कांग्रेस पार्टी को गुजरात विधानसभा में करारी पराजय का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी ने मोदी को चौकीदार चोर है की उपमा दी, इसके बाद वे अमेठी से स्वयं चुनाव हार बैठे। मणिशंकर अय्यर एवं सैम पित्रोदा के बयानों से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब पार्टी आलाकमान ही अनर्गल टिप्पणी पर भरोसा करते हैं, तो अन्य नेताओं को कौन मार्गदर्शन देगा? आज भी राहुल गांधी नरेन्द्र मोदी के ऊपर व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, लेकिन उन अनर्गल टिप्पणियों से कांग्रेस पार्टी को हमेशा नुकसान उठाना पड़ रहा है। पार्टी नेताओं को अपनी पार्टी की विचारधारा से जनता को अवगत कराना चाहिए, एवं विवादित बयान से बचना चाहिए, अन्यथा जनता हर किसी का आकलन करने में सक्षम है।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

पोस्ट

इतनी लंबी चुनाव प्रक्रिया के बीच एक सुझाव यह भी दिया जा रहा है कि जिन राज्यों में चुनाव निपट चुके हों, वहां आचार संहिता हटाना कैसा रहेगा? लोग शिकायत कर रहे हैं कि अधिकारीगण संहिता के बहाने से काम टालने में लगे हैं। लाला @Lala_The_Don

केकेआर बनाम मुंबई इंडियंस मैच के परिणाम में केकेआर की जीत और मुंबई की हार की आदत नजर आई। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों का फार्म चिंता का सबब बन गया है।

सुशील दोशी @RealSushilDoshi

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तरह समझें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में ही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है।

कमलेश सिंह @kamleshksingh

अरविंद केजरीवाल को जिन कारणों और शर्तों पर जमानत मिली है, वह अक्षरशः हेमंत सोरेन पर भी लागू होती हैं। हालांकि कोर्ट ने उन्हें कानूनी पेचीदगियों में उलझाया हुआ है। जबकि वह कहीं बड़े जनाधार वाले नेता हैं। आशा है कि उन्हें भी जमानत मिलेगी। अन्यथा एक गलत संदेश जाएगा।

द सोशल साइंटिस्ट @socially321

जनपथ

मंत्री थे इक पाक के श्री 'चौधरी मवाद',
फोड़ा फूटा हो गए बेचारे वह बाद।
बेचारे वह बाद उन्हें याद आते राहुल,
जिनकी बत्ती आज दिख रही है चहुंदिश गुल।
मणिशंकर अरु सैम बने हैं जिनके तंत्री,
बन पाएंगे आप किस तरह प्रधानमंत्री!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 31

****